राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

अंक १] चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र का ४२ वां दिवस [संख्या २२

मंगलवार, दिनांक जून १३, १९६७

विधान सभा की बैठक म. पू. ११:१ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(योजना, पुनर्वास, खाद्य, वित्त, राजस्व, सहकारिता, आबकारी, अकाल सहायता, कृषि राजस्व, पंचायत, विकास, उपनिवेशन विभाग)

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये धनराशि का प्रावधान

४३९. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

राजस्थान की चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए कुल कितनी धनराशि का प्रावधान रखा गया है तथा उसकी उपलब्धि किस किस प्रकार से होगी ?

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : नवम्बर १९६६ में योजना आयोग से विचार विमर्श के पश्चात् राज्य की चौथी योजना का आकार रु० ३१३ करोड़ निश्चित किया गया था जिसमें केन्द्रीय सहायता रु० २२७ करोड़ और राज्य के अपने साधनों से योगदान को पिछले वर्ष अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। अतः ऐसी आशा है कि योजना आयोग बदली हुई स्थिति में केन्द्रीय सहायता और राज्य के साधनों पर पुनः विचार कर राज्य की चतुर्थ योजना का आकार तय करेगा।

श्री केदार नाथ ; चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में होते हुए भी आपने पंचवर्षीय योजना के ड्राफ्ट को फाइनल टच नहीं दिया।

श्री मथुरादास माथुर : नहीं। राज्य सरकार ने चौथी योजना का ड्राफ्ट फाइनल करके प्लानिंग कमीशन को भेज दिया। प्लानिंग कमीशन ने टेन्टेटिवली ३१३ करोड़ प्लान सीलिंग मुकर्रर किया। उसमें राज्य सरकार का पारटीसिपेशन ८६ करोड़, बाकी सेन्ट्रल एसिस्टेंस। उसके बाद सेक्टोरियल एलाटमेंट नहीं हो पाया। उसके बाद हालात ऐसी पैदा हो गई कि प्लान सीलिंग फाइनल नहीं हो पाया। किसी राज्य का फाइनल नहीं हुआ है। इस बीच में कई घटनायें घटी हैं जिनकी वजह से यह पेंडिंग है।

Page No. 2

श्री भीमसेन : आपने पर ईयर कितना पर कैपीटा इन्कम ग्रोथ रखा है ?

श्री मथुरादास माथुर : जब तक प्लान सीलिंग फाइनल नहीं हो जाता है, तब तक पर कैपीटा इन्कम ग्रोथ और जितने प्लान के अन्दर सोशल आब्जैक्टिस को फुलफिल करने के लिए प्रावधान हैं, वे नहीं बता सकते ।

श्री भैरोंसिंह : प्लान का ड्राफ्ट जो यहां सदस्यों को सक्यूलेट हुआ, उसके बाद दूसरा बना क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : जो ड्राफ्ट यहां सक्यूलेट हुआ था वह राज्य सरकार ने बनाया था । उसके बाद केन्द्र में जाने के बाद काफी परिवर्तन हुए हैं । जब तक सीलिंग फाइनल नहीं होती........

श्री भैरोंसिंह : यहां जो ड्राफ्ट सक्यूलेट किया गया वही प्लानिंग कमीशन को भेज दिया गया ।

श्री मथुरादास माथुर : बेसिस वही है । कुछ आँकड़े जो दिखाए गए हैं, उनमें परिस्थितियों की वजह से कमी की है वरना बेसिस वही है ।

श्री केदार नाथ : स्टेट लेविल की प्लानिंग कमेटी बैठक आपने क्यों बुलाना उचित नहीं समझा ?

श्री मथुरा दास माथुर : इसलिये कि जब तक चौथी योजना का फाइनल सीलिंग तय नहीं हो जाता है और उसमें कितना पार्टीसिपेशन स्टेट का और कितना सैन्टर का होगा, जब तक प्लान को फाइनल करके उसका सेक्टोरियल एलाटमेंट नहीं होता तब तक प्लानिंग बोर्ड के सामने कैसे आयेंगे ?

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि प्लानिंग कमीशन और सरकार के बीच में उस विवाद को लेकर जो बातचीत चल रही है, उसके बारे में राज्य प्लानिंग बोर्ड को विश्वास में लें ?

श्री मथुरा दास माथुर : वैसे प्लान तो इसी बेसिज पर बनाई गई है जो प्लानिंग बोर्ड की पहले बैठकें हुईं उनके आधार पर साधनों को मैच करते हुए यह रिपोर्ट बनाई गयी थी । अभी तक तो ड्राफ्ट रिपोर्ट है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं ड्राफ्ट की नहीं कह रहा हूं । ड्राफ्ट के बाद में योजना आयोग और राज्य सरकार के बीच में जो बात चीत चली है उन मुद्दों पर मतभेद हुए हैं, कुछ निर्णय हुए हैं, तो क्या उस संबंध में राज्य सरकार प्लानिंग बोर्ड को विश्वास में लेना उचित नहीं समझती ?

श्री मथुरादास माथुर : प्लानिंग बोर्ड को विश्वास में लेने में हमें एतराज नहीं है । माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है तो बोर्ड की बैठक बुलाकर यह प्लान डिस्कस की जा सकती है ।

श्री भीमसेन : राज्य को कितने साधन रेज करने पड़ेंगे ?

श्री मथुरा दास माथुर : जो बात चीत चल रही है उसमें बताया गया कि ३१३ करोड़ का प्लान होगा, ८६ करोड़ स्टेट पारटीसिपेशन होगा और बाकी २२७ करोड़ सेन्ट्रल

Page No. 3

(श्री मथुरादास माथुर)

एसिस्टेंस होगी । ८६ करोड़ नवम्बर के महीने में जब प्लान डिस्कस हुआ था तब तय हुआ था । उसके बाद महगाई भत्ता वगैरह कई इकोनोमिक फैक्टर्स सामने आए हैं । इसलिए इस पर पुनः विचार करना पड़ेगा और जिन दिनों भारत के वित्तमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक हुई थी जिन दिनों राजस्थान में राष्ट्रपति शासन था, उन दिनों उप प्रधान मंत्री ने कहा था कि सेन्ट्रल एसिस्टेंस को रिवाइज कर सकते है क्योंकि केन्द्र में पैसे की कमी है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या मंत्री महोदय यह नहीं समझते कि चौथी योजना के संबंध में जो सरकार द्वारा अनिश्चितता है, इस बात का द्योतक है कि आपका प्लानिंग फेल हो चुका है । क्या वह इस बात का द्योतक नहीं है कि चौथी योजना, पहली दूसरी और तीसरी योजना के अनुसार न बनकर और उसमें आमूलचूल परिवर्तन होने की संभावना है ?

श्री मथुरादास माथुर : बेसिज तो प्लान का वही है । सोशल रिफ्लेक्शन प्लान का वही है जो पहली, दूसरी और तीसरी योजना का है । प्लान में देरी हुई है, इसके लिए कई फैक्टर्स हैं । इकॉनामिक, जाग्राफीकल और हास्टिलटीज । इसलिए इस योजना का फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है । इसका मैंने यह नहीं है कि प्लान फेल हो चुका है या उसमें आस्था कम है । यह इस बात का द्योतक है कि प्लानर्स वास्तविकता के आधार पर प्लान करते हैं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह जो प्लान बनेगा वह फाइव ईयर प्लान निर्मित होगा या एक, दो या तीन साल का प्लान बनने की संभावना है ? क्या इस पर प्रकाश डाल सकते हैं ?

श्री मथुरा दास माथुर : अब तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है । ऐसी थिंकिंग है देश में । कोई कहता है कि एक साल प्लानिंग का निकल गया है या दो साल निकल गए हैं तो आने वाले पांच वर्षों के लिए बनाया जाय ताकि यह सात साल की योजना हो जाय । अलग अलग राज्यों की अलग-अलग राय है और अलग अलग इकोनोमिस्ट्स की अलग अलग राय है । जब तक योजना आयोग इसको बैठकर नेशनल डेवलपमेंट काउन्सिल के अन्दर तय नहीं करता है तब तक कोई निर्णय राज्य सरकार की राय देने से संभव नहीं है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या सरकार यह अनुभव करती है कि अब की वर्तमान स्थिति में कम से कम ६ महीने या १० महीने तक प्लान हालीडे ले लें ।

श्री मथुरादास माथुर : कतई नहीं । प्लान हालीडे नहीं है । अपन वर्क कर रहे हैं, चौथी योजना ऐनयूअल बना चुके हैं । इसलिए टोटल फाइव-ईयर प्लान का रिफ्लेक्शन नहीं है, एयूनअल बना चुके हैं जो बजट के अन्दर आपके सामने पेश कर चुके हैं । We are actually busy and engaged.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह एनफोर्स्ड हालीडे है ।

श्री मथुरादास माथुर ; आप आर्गेनाइजेशन वालों को मैटरनिटी लीव मिल गई है ।

Page No. 4

महारावल श्री लक्षमण सिंह : हमारी प्रेक्टीकेबुलेटी को आपने एक्सेप्ट किया है।

श्री अध्यक्ष श्री जुझारसिंह।

राणा प्रताप सागर बांध को डूब में आने वाले विस्थापितों का पुनर्वास

४४०. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राणा प्रताप सागर बांध को डूब में आने वाले विस्थापितों को रामगंज मंडी तहसील में किन किन स्थानों पर बसाया गया है और सरकार द्वारा उन्हें क्या क्या सहूलियतें उपलब्ध करने का वायदा किया हुआ है ?

(२) क्या यह सही है कि ग्राम मदनपुरिया काल्या खेड़ी को चेचट से सड़क से जोड़ने का आश्वासन है ? यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

(३) क्या यह सही है कि मदनपुरिया ग्राम वासियों ने इस गांव का तहसील के सदर मुकाम रामगंज मंडी से जोड़ने के लिये सड़क की मांग की हुई है जिसकी लम्बाई चेचट मदनपुरिया की लम्बाई से करीब करीब बराबर है ?

(४) बिजली से नजदीक विस्थापित गांवों में बिजली देने का क्या प्रोग्राम है व मदनपुरिया में बिजली दी जा सकने की क्या संभावना है ?

उप-मंत्री, पुनर्वास (श्री मनफूलसिंह) : (१) राणा प्रताप सागर बांध में डूब में प्रभावित होने वाले विस्थापितों को निम्न ११ स्थानों पर तहसील रामगंज मंडी में बसाया गया है :

१. काल्या कुंडी
२. काल्या खेड़ी
३. भटवाड़ा
४. गुर्जरिया खेड़ी
५. मोतीपुरा
६. खन्न आलोद
७. गुलाबपुरा
८. रूद्धा क खेड़ा
९. जामून्या
१०. कूंकड़ा
११. देवली

सरकार द्वारा निम्न सुविधायें विस्थापितों को दी गई हैं :

(क) काश्त हेतु निर्धारित शरह के मुताबिक प्रत्येक परिवार को भूमि निःशुल्क आवंटित की गई।

(ख) प्रत्येक विस्थापित परिवार को मकान निर्माण हेतु प्लाट निःशुल्क दिये गये।

(ग) पानी पीने के लिये नवीन कुओं का निर्माण किया गया है।

(घ) कच्ची सड़कों का निर्माण कराया गया है।

(च) आवश्यकतानुसार पाठशालाएं एवं औषधालय खोले गये हैं एवं चौपाल बनाये गये हैं।

(२) जी हां। माह अप्रेल १९६७ में यह सड़क बनकर पूर्ण हो गई है।

(३) जी हां।

Page No. 5

(श्री मनफूलसिंह)

(४) इसका सम्बन्ध उपनिवेशन विभाग से नहीं है। स्थापित विस्थापितों को प्रार्थना पर बिजली दिलाने के सम्बन्ध में विभागों को लिखा जाता रहा है।

श्री जुझारसिंह : तीसरे का क्या जवाब दिया ?

श्री मनफूलसिंह : जी हाँ।

श्री जुझारसिंह : उनकी माँग है क चेचट के बजाय रामगंज मंडी से जोड़ी जाय। वहाँ एस० डी० ओ० हैडक्वार्टर है, तहसील हैडक्वार्टर है। चेचट तो एक गाँव है। इसलिये इसको रामगंज मंडी से जोड़ा जाय ताकि तहसील हैडक्वार्टर से जुड़ जाय ! आपने बताया कि रामगंज मंडी से नहीं जोड़ा है तो इसको कब तक कर देंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (पुनर्वास मन्त्री) : कुछ लोगों ने माँग की थी कि यह सड़क रामगंज मंडी से जोड़ी जाय। वैसे चेचट से जोड़ी हुई हैं। चेचट से रामगंज मंडी पक्की सड़क है। थोड़ा डिस्टेन्स पड़ता है। अभी आर्थिक संकट के कारण इस पर विचार नहीं किया जा रहा है।

श्री जुझारसिंह : दो साल पहले भी मैंने इस प्रश्न को उठाया था। मिनिस्टर महोदय से इस विषय में मुझे अधिक जानकारी है। मदनपुरिया से पाँच मील की दूरी है। काम शुरु नहीं हुआ था। उस वक्त सरकार ने आश्वासन दिया था। मदनपुरिया को रामगंज मंडी से जोड़ने में अधिक फायदा है। मदनपुरिया रामगंज पक्की सड़क से नहीं जुड़े हुए हैं। चेचट से भी मदनपुरिया नहीं जुड़ा हुआ है। इसलिये इसको रामगंज मंडी से कब तक जोड़ने का विचार है ? चेचट से जोड़ने में कोई फायदा नहीं हुआ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मदनपुरिया से चेचट ५ मील है और मदनपुरिया से रामगंज मंडी पाँच मील है। एक स्थान से जुड़ जाने के बाद दूसरे स्थान से जोड़े जाने की अधिक आवश्यकता नहीं है।

श्री जुझारसिंह : चेचट तहसील हैडक्वार्टर नहीं है। रामगंज मंडी तहसील और एस० डी० ओ० हैडक्वार्टर्स है। लोगों ने माँग की इसको चेचट से जोड़ कर पैसा खराब नहीं किया जाय। आप कहते हैं कि जरूरत नहीं रही है। चेचट से जोड़ने में फायदा नहीं हुआ है। यहाँ आपने काम किया बावजूद रिक्वेस्ट के वह बेकार किया। इसको रामगंज मंडी से जोड़े बगैर कोई फायदा नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहाँ तक स्थिति का सम्बन्ध है मैंने निवेदन किया कि पहले चेचट से जोड़ने की प्रार्थना की थी और उनकी प्रार्थना पर ही चेचट से जोड़ा गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री लाभचन्द वैद।

श्री विजयसिंह (मकराना) : एक बात जरूरी पूछना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

श्री विजयसिंह : बहुत ही इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय। राजस्थान का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर। आॅर्डर प्लीज। मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

पडिहारा में गेहूँ व चीनी वितरण

४४१. **श्री लाभचन्द वैद्य (सुजानगढ) :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पडिहारा (तहसील रतनगढ) में विदेशी गेहूँ व दानेदार चीनी का वितरण बन्द कर दिया है ? यदि हाँ तो क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : यह सही है कि पडिहारा (तहसील रतनगढ) में विदेशी गेहूँ का वितरण बन्द कर दिया गया है। परन्तु दानेदार चीनी बराबर दी जाती रही है।

श्री लाभचन्द वैद : किस कारण बन्द कर दिया गया ?

श्री परसराम : सितम्बर १९६६ से।

श्री लाभचन्द : किस कारण से बन्द कर दिया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : सितम्बर १९६६ से।

श्री अध्यक्ष : क्या कारण है कि बन्द कर दिया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : आयातित गेहूँ की मात्रा नहीं थी और सितम्बर में राजस्थान के बहुत से इलाके ऐसे थे जहाँ अकाल पड़ गया। जहाँ ज्यादा अकाल था वहाँ इम्पोर्टेड वीट का वितरण किया। जहाँ अकाल नहीं था और खरीफ की फसल अच्छी हुई थी इसलिये वहां बन्द कर दिया।

एक माननीय सदस्य : चीनी का क्या हुआ ?

श्री लाभचन्द वैद : खरीफ की फसल कब हुई थी और बन्द कब किया ?

श्री परसराम मदेरणा: सितम्बर १९६६ में।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल हादी।

तिलवाड़े मेले से बिक्री कर

४४२. **श्री अब्दुल हादी (चौहटन) :** क्या कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तिलवाड़े मेले में इस वर्ष कर के कितने रुपये वसूल हुए ?

(२) क्या यह सच है कि पूंजासर गाँव के व्यापारियों से बैलों का बिक्री कर वसूल कर लेने के बाद भी मेले में नियुक्त संबंधित बिक्री कर अधिकारियों ने अपनी बदनियती से उन व्यापारियों के माल को रोका व उन्हें हैरान किया तथा उनके द्वारा रिश्वत नहीं मिलने पर उनसे दुबारा बिक्री कर व पैनेल्टी वसूल की और उनके पशुओं को रोक कर उन्हें खर्चे का व रेल्वे वेंगन की डिपोजिट का नुकसान पहुँचाया ?

(३) क्या यह सच है कि इस बाबत उन व्यापारियों ने कर विभाग में व सरकार से शिकायत की है ?

(४) यदि हाँ, तो इस बाबत क्या कार्यवाही की गई तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

मंत्री, कर विभाग (श्री मथुरादास माथुर) : (१) तिलवाड़ा मेले में इस वर्ष कर से वसूल हुइ धनराशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

पशुओं पर क्रय कर	रु०	६७,९११.००
अन्य बिक्री कर	रु०	१,२१४,००
राजस्थान यात्री व माल कर	रु०	९,८४५.००
कुल	रु०	७८,९७८.००

(२) इस बारे में जांच की जा रही है।

(३) वाणिज्य कर विभाग में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(४) जांच के परिणाम आने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री रामानन्द अग्रवाल।

अलवर जिले के सिवाय चक घोषित कुएं

४४३. **श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार को मालूम है कि अलवर जिले में बहुत से किसानों के कुएं गत बन्दोबस्त में सिवाय चक घोषित कर दिये हैं और ऐसे किसानों को कुएं के रुपये जमा कराने के नोटिस जारी कर दिये गये हैं?

(२) किसी कुए को सिवाय चक घोषित करने के बन्दोबस्त विभाग के आधार क्या क्या हैं?

(३) क्या यह सही है कि अलवर जिले की अधिकतर कृषित भूमि बिस्वेदारी सिस्टम में थी और थोड़ी भूमि जागीरी सिस्टम में थी जिनमें कुए बिस्वेदारों अथवा जागीरदारों द्वारा बनाये गये थे तथा इस सिस्टम में राज्य द्वारा कुए बनाने का सवाल ही नहीं पैदा होता था?

(४) क्या सरकार सिवाय चक कुओं की कीमत की वसूली अलवर जिले में बन्द करने और बन्दोवस्त में की गई गलतियों का सही इन्द्राज करने का आदेश जारी करने का विचार रखती है?

उपमंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) जी हां। यह बात ठीक है कि बन्दोबस्त के दौरान कुओं को सिवाय चक घोषित किया गया है पर रुपये जमा कराने के नोटिस केवल तहसील बहरोड़ में जारी किये गये हैं। परिपत्र संख्या एफ ४ (१०) राज। ख। ६५ दिनांक ४-६-६५ के अन्तर्गत किसानों को २५ रुपया प्रति कुआ के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कुए का पट्टा यानी सनद लेने एवं एक रुपया देकर उसका नामान्तरण कराने की सुविधा उपलब्ध कर दी गई है।

(२) जागीरदारी बिस्वेदारी प्रथा समाप्त होने पर जमीन अथवा कुए या अन्य जो मकबूजा जागीरदार या मकबूजा बिस्वेदार के नाम से इन्द्राज था वह अब मौजूदा बन्दोवस्त में मौके स्थिति के अनुसार कृषक के नाम अथवा सिवाय चक का इन्द्राज किया गया।

(श्री गंगाराम चौधरी)

(३) यह सही है कि अलवर जिले में अधिकांश बिस्वेदारी प्रथा थी और कम जागीरदारी अथवा अन्य किन्तु यह नहीं कहा जा सकता है कि जिले की समस्त बिस्वेदारी एवं जागीरदारी ग्रामों में कुए बिस्वेदारी ने बनाये थे अथवा जागीरदारों ने या सरकार तथा कृषकों ने।

(४) सिवाय चक कुओं की कोई कीमत वसूल नहीं की जा रही है। केवल कुओं के पट्टे यानी सनद की फीस ली जाकर उनको स्वामित्व प्रदान किया जा रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आपने जो उत्तर दिया है कि केवल बहरोड़ तहसील में ऐसा किया जा रहा है एक तरह यह सही नहीं है। अलवर तहसील में भी ऐसे नोटिसेज काफी गांवों में जारी हुए हैं। दो गांवों का तो मुझे पता है। माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूँगा कि बिस्वेदारी इलाके में या जहाँ पर जागीरदारी इलाका था उनमें कुए किसानों के या बिस्वेदारों के खुद के बनाये हुए थे, ये क्षेत्र अलग थे कुछ अमलदार थे यह सरकार की ओर से बनाये गये होंगे। अलवर जिले में फीस के पच्चीस रुपया लेना अनुचित है। यह सिस्टम जयपुर या उदयपुर में लागू हो सकता है। वहां सिवाय चक किन्ही कुओं को घोषित किया है। गलत घोषित किया है क्या मंत्री जी इस बात की पुनः जांच करायेंगे और इस प्रकार के कुओं को सिवाय चक घोषित किया गया है जो मालिकान के होने चाहिये। इन्डिविजुअल केसेज का सवाल है जिनमें किसानों से नाजायज रूप से पच्चीस पच्चीस रुपये वसूल हो रहे हैं। दुबारा जांच करायेंगे मंत्री महोदय ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री) : सेटलमेन्ट में सिवाय चक में दर्ज हो जाने के बाद अमुक आदमी को दे दिया जाय या दर्ज होना चाहिये था यह दूसरा प्रश्न है। सेटलमेन्ट में दर्ज हुआ तो फीस लेकर जिस खाते में कुआ है जैसा राजस्थान में अमल है वैसा ही अमल अलवर में भी लागू किया जाना मैं उचित समझता हूँ। किसी व्यक्ति का कुआ सिवाय चक में था दर्ज हुआ तो कार्यवाही करनी चाहिये थी। सेटलमेन्ट में वह चीज आयी है तो अलवर के लिये विचार किया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अलवर भरतपुर का प्रश्न ऐसा है कि यहाँ पर मुसलमान उजड़ कर पाकिस्तान चले गये थे और पुरुषार्थी वहाँ आकर बसे। कुओं के मालिक थे वे चले गये मौजूद नहीं थे दूसरे लोग बसे उनको जमीनों का अलाटमेंट हुआ। उनमें कुओं के नाम नहीं लिखे हुए होंगे। उनको सिवाय चक घोषित किया होगा। एक दो केस नहीं हजारों केसेज हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो इसलिये यह उचित नहीं है। गवर्नमेन्ट बन्दोबस्त पर फिर से विचार करे तो इस पर भी विचार कर ले। इन्डिविजुअल तो हजारों में है कहाँ तक उनको ठीक करावेंगे ?

श्री मुकुटबिहारीलाल : मैं सूचना दूं कि इसी प्रकार की स्थिति भरतपुर में भी है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जैसा मैंने निवेदन किया कि अलवर के सेटलमेंट में गलतियाँ हुई हैं उसका मामला पुनर्विचार का विचाराधीन है। उस एरिया में ऐसे कुए आते हैं तो उन पर भी विचार कर लिया जावेगा। ये जमींदार और बिस्वेदारों के बनाये हुए नहीं होने से सिवाय चक में शामिल किये गये हैं जहाँ तक मेरा इलम है ! अगर वे स्वयं के बनाये साबित कर देते तो उनकी खातेदारी में दर्ज हो जाते।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जमींदार तो चले गये पाकिस्तान, दूसरे पुरुषार्थी आकर बसे थे। They should step in their shoes. एक लाख शरणार्थी बसे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उनको प्रोपरटी लैंड जिस समय दी गई तो उसमें कुछ नहीं दिये गये। अब कुए की कीमत भी चार्ज नहीं करें और २५) पट्टा फीस भी चार्ज न करें में कहता हूँ वह सरकारी प्रोपरटी है तो इस पर जैसा अमल है दूसरी जगह २५) लेकर स्वामित्व कुए का दे दिया जाता है तो अलवर में भी इसी तरह २५) देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिये।

श्री अमीलाल यादव : (बहरोड़) पट्टे पर जमीनें दीं पर कुए नहीं दिये इसके लिये रामानन्द जी ने कहा पर इसका दूसरा इस्यू भी है। बहरोड़ का मसला है। वहाँ जितने भी कुए हैं सिवाय चक में आये हैं। दो बार मिनिस्टरों का दौरा भी हुआ है। आप भी जब पधारे थे स्कूल के उद्घाटन के लिये तो हमने यह समस्या आपके सामने रखी थी। ये जितने कुए बहरोड़ में हैं सबके सब बिस्वेदारों के हैं। दस दस हजार रुपये लगाकर इन कुओं को बनाया है। हमारे उधर अमूमन एक कुए पर दस हजार खर्च होता है। आज उनको सिवाय चक डिक्लेअर कर दिया है। जिस प्रकार जमीन पर खातेदारी के पट्टे मिले हैं उसी प्रकार से कुए भी मालिकाना खाते में आने चाहिये। सिवाय चक में नहीं आने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न करिये केवल। आॅर्डर प्लीज।

श्री अमीलाल यादव : एक हजार कुए इस प्रकार के अकेले बहरोड़ में हैं। जो स्वयं के बनाये हुए हैं आप स्पेशल आॅफीसर अपोइन्ट करके इसकी जाँच करा सकते हैं। यह इम्पोर्टेन्ट इस्यू है। हजारों को इफैक्ट करने वाला है।

श्री दुर्गालाल बाडदार (हवामहल जयपुर) सैटलमेंट का कानून राजस्थान के लिये एक है। जिले के लिये अलग से नहीं बना है। अब आपने सिवाय चक में दर्ज कर लिया तो टेम्परेरिली किया है या परमानेन्टली किया है। अब निवेदन करूं कि अगर मान लीजिये किसी जमीन पर खातेदारी अधिकार किसी एक व्यक्ति को प्राप्त हो गये और उस खातेदारी की जमीन के बीच में कुआ आ जाता है और उसको आप सिवाय चक में एन्ट्री कर देते हैं तो यह मानना पड़ेगा कि कुए को आपने प्रोपरटी पर्सनल आॅफ होल्डिंग माना है। तब सिवाय चक के अधिकार कैसे हो जावेंगे जब कि जमीन खातेदारी की है। ऐसी बहुत सी समस्याएं है इन सारी समस्याओं पर सरकार को निर्णय लेने चाहिये। इनका विशेष अध्ययन कीजिये।

श्री प्रेमसिंह : इससे सम्बन्धित प्रश्न और है छबड़ा का । २५) जमा कराने पर भी पट्टा नहीं दे रहे हैं ।

श्री मदनसिंह दांता : यह २५) कौनसे कानून की तहत लिये जा रहे हैं । सीकर जिले में क्लेक्टर ने कहा है कि अपनी मरजी से दे सकते हैं । अब किसी के खेत के बीच में अगर नाल आ गई है तो वह उसी की होगी । अब अगर उसने नहीं बनाये हैं तो जागीरदार ने बनाई होगी । सरकार की तो नहीं हो सकती । उस वक्त यह फैसला भी किया गया था । नेहरू रिपोर्ट में यह है कि जागीरदारों का भी अगर है तो उन्होंने काफी दिनों तक उनको एनजोय कर लिया है इसलिये अब यह कुआ खातेदार काश्तकार का हो गया है । अब यह काश्तकार नहीं होकर सरकार का हो गया है इसके सम्बन्ध में मंत्री महोदय बोलें ।

श्री जुझारसिंह : २५ रुपये जमा कराने का नियम है । अब इसे जमा कराने के बाद कितने दिनों में खातेदारी हक दे देते हैं ? दो दो साल से लोगों का जमा कराया हुआ है पर अभी भी पेन्डिंग में हैं । इसलिये इसका भी कोई टाइम लिमिट फिक्स हो जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : श्री मन्त्री महोदय ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इन सारी स्थितियों पर विचार करके इस पर सरकार ने एक सरकुलर जारी किया था मई सन् ६५ में निर्णय लिया गया । उसके आधार पर यह २५ चार्ज किया जा रहे हैं । उस निर्णय में ही कहा गया है कि बन्दोबस्त में इस प्रकार का स्वामित्व साबित नहीं कर पाये तो सिवाय एक में या जमीदारी बिस्वेदारी में साबित नही कर सके कि कुआ उन्होंने ही बनाया था । या मान लीजिये कि पहले का बनाया हुआ हैं । तो छानबीन होकर सैटलमेंट में एक बार निर्णय हो चुका । दर्ज कर दिया गया । उसको रेगुलेराइज करने के लिये सारे कुए की कीमत नहीं लेकर सिर्फ २५ रु० पट्टा फीस कर दी । अब इसको और छानबीन करके खोलेंगे तो कुए की कीमत देने की स्थिति भी आ सकती है तो बहुत रीजनेबल है रु० २५) । अब दुबारा इसमें पड़ने से एन्क्वायरी करने से बहुत ज्यादा खर्चा हो जावेगा जो ठीक नहीं रहेगा । मैं तो यह वाजिब मानता हूँ कि २५ रु० में निपट जाता है तो कुआ उसके खाते में मंढ जावेगा ।

श्री अमीलाल यादव : एक भी कुआ इस तरह का वहां नहीं है ।

यह तो डिस्क्रिमिनेशन का सवाल है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पर जहां एक भी पैसा सरकार का नहीं लगा, वहाँ भी २५) उनसे ले लेना यह ज्यादती है । आप कहते हैं कि एन्क्वायरी में ज्यादा पैसा लग जावेगा ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सवाल यह नहीं है अलवर के बारे में स्थिति जो कुछ भी बताई है यह बार बार प्रश्न किया गया है तो इसमें एक अधिकारी को मुकर्रर करके प्राइमा फेसी प्रिलिमिनेरी एन्क्वायरी हो चुकी है सिर्फ यह निर्णय लेना है कि अलवर से सैटलमेन्ट के बारे में कैसा इन्तजाम किया जावे ताकि शिकायतें दूर हो

Page No. 11

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

सकें। तो अलवर तो रिव्यू हो जावेगा, बाकी और जगह तो शिकायत नहीं है।

श्री अमीलाल यादव : कितने दिनों में यह निर्णय हो जावेगा?

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की इच्छा है कि दूसरे माननीय सदस्यों के सवाल न लिये जावें अभी तक पांच सवाल हुए हैं। काफी बाकी हैं। अगर इसी पर सारा समय समाप्त कर दिया जावे तो मेरा ऐतराज नहीं। दूसरों के हित में आवश्यक हो तो दूसरे सवाल लिये जावें।

नेक्स्ट। श्री फूलचन्द बाफना।

(प्रश्न संख्या ४४४ नहीं पूछा गया)

शराब बिक्री की मात्रा।

४४५. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) माह फरवरी, ६७ में शराब की बिक्री राजस्थान में कितने रुपयों की हुई?

(२) माह फरवरी, ६५ और माह फरवरी, ६६ में शराब की बिक्री राजस्थान में कितने रुपयों की हुई?

वित्त मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : सूची संलग्न है।

(२) सूची संलग्न है। (कृपया परिशिष्ट १ देखिये)।

श्री फूलचन्द बाफना : जनवरी के आंकड़े भी बतलाने की स्थिति में हैं क्या?

श्री मथुरादास माथुर : आपने फरवरी के पूछे।

श्री फूलचन्द बाफना : खैर। यह बाद में पूछ लूंगा।

मोठ का निर्यात

४४६. **श्री गोरधन सोनी** (मेड़ता) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य से मोठ का निर्यात किन कारणों में रोका गया है?

अकाल सहायता उप-मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : राज्य में अकाल की स्थिति उत्पन्न होने से पशुओं के लिए चारे का अभाव हो गया। क्योंकि मोठ पशु चारे के लिए उपयोगी है अतः राज्य सरकार द्वारा मोठ के निर्यात पर रोक लगा दी गई।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या जिलाधीश बीकानेर ने बीकानेर से मोठ की दाल भेजने के लिए परमिट जारी कराये हैं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (अकाल सहायता मंत्री) : इसका संबंध फूड मिनिस्ट्री से है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री भीमसेन : क्या मोठ...

श्री गोरधन सोनी : क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि मोठ चारे के काम में नहीं आती है, मोठ तो दाल है।

Page No. 12

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मोठ चारे के भी काम में आती है।

श्री गोरधन सोनी : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि मोठ पशुओं के लिए किस तरह से उपयोग होती है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मवेशियों को देते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य (छापर) : मोठ देने से तो दूध खत्म हो जाता है मवेशी का।

श्री गोरधन सोनी : मोठ खाने से तो पशु मर जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रामचन्द्र आर्य : पशुओं के काम में नहीं आती है मोठ बिलकुल भी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पशुओं के काम में नहीं आती है तो मंत्री जी क्यों खाते हैं?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री नन्दलाल।

सीताबाड़ी, तहसील शाहबाद के पास गौशाला

४४७. **श्री नन्दलाल** (किशनगंज) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि तहसील शाहबाद में सीताबाड़ी के पास हाड़ोती खादी ग्रामोद्योग संघ के अध्यक्ष श्री ब्रह्मदत्त शर्मा द्वारा एक गौशाला खोली गई थी? यदि हां, तो उस पर कितनी धनराशि राज्य सरकार द्वारा खर्च की गई थी?

(२) क्या वह गौशाला आज भी चालू है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

कृषि मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी नहीं!

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री नन्दलाल : जवाब समझ में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : दुबारा बोल दें समझ में नहीं आया।

श्री परसराम मदेरणा : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या यह सही है कि हाड़ोती खादी ग्रामोद्योग संघ के अध्यक्ष श्री ब्रह्मदत्त शर्मा सीताबाड़ी के क्षेत्र में गायें और बछड़े खरीद कर लाये थे और अकाल के दिनों में उनको ले गए और उसमें से बहुत सी मर गईं?

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि ग्रामोद्योग संघ के अध्यक्ष कोई ब्रह्मदत्त हैं या नहीं लेकिन ऐसी जरूर सूचना दी है सरकार को कि स्टेट कौंसिल ऑफ गौसंवर्धन की एक ब्रांच थी और वह गायों को चराने के लिए जरूर सीताबाड़ी ले गये थे। वहां कुछ अर्से तक गायें रखीं और फिर वापिस ब्रान्च में ले आये।

श्री देवीदत्त गाडिया : सवाई माधोपुर से गायें और बछड़े लाये थे उनमें से कई मर गईं।

श्री परसराम मदेरणा : गौ सदन में जो गायें हैं वह ज्यादातर अनप्राडक्टिव गाये हैं लूली और लंगड़ी और दूसरी तरह की। मैं नहीं कह सकता कि उनमें से कितनी मरीं लेकिन एमी जरूर राज्य सरकार को इत्तला है कि जो गांव हिन्डौली गांव जिला सवाई माधोपुर में थी वह अकाल के दिनों में वहां से गायें सोताबाड़ी जरूर ले गये थे उनमें से कितनी गायें मरीं, कितनी नहीं मुझे पता नहीं है।

श्री नन्दलाल : इसमें राज्य सरकार को कितनी धनराशि खर्च हुई ?

श्री परसराम मदेरणा : गौ सदन में अध्यक्ष महोदय जितनी गायें होती हैं प्रति गाय प्रति माह ३ रुपये राज्य सरकार उनको सबसीडी देती है।

श्री देवीदत्त : क्या यह सही है कि जिन गायों को ब्रह्मदत्त जी लाये थे उन्होंने पशुपालन के नाम पर जमीन अलाट कराई है ?

श्री परसराम मदेरणा : मुझे जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदनकौर

लगातार तीन वर्ष तक अकालग्रस्त क्षेत्र में लगान वसूली

४४८ **श्रीमती मदनकौर** (पचपदरा): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिन गावों में गत तीन वर्षों से अकाल की स्थिति है वहां लगान वसूली के सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या नीति है ?

(२) क्या यह सही है कि पचपदरा तहसील के उन गांवों में जहां गत तीन साल से भयंकर अकाल था वहाँ पटवारियों द्वारा तीन साल के लगान की एक साथ वसूली की जा रही है ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) अकाल पड़ने पर नियमानुसार आवश्यक जांच कर क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित किया जाकर लगान स्थगित किया जाता है तथा लगातार ३ वर्ष अकाल की स्थिति रहने पर काश्तकारों की आर्थिक स्थिति व हानि का अनुमान लगाकर राजस्थान काश्तकारी नियमों के अन्तर्गत लगान माफ करने का विचार किया जाता है।

(२) जिन गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया गया है वहां अकालग्रस्त अवधि का लगान अभी वसूल नहीं किया गया है।

श्रीमती मदनकौर : पचपदरा तहसील मे कौन से गांवों में लगान की वसूली स्थगित की गई है ?

श्री गंगाराम चौधरी : पचपदरा तहसील के गांव जो अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं उनकी सूची प्रकाशित कर दी गयी है। वहां अकालग्रस्त अवधि का लगान वसूल करने का अभी निर्णय नहीं लिया है।

प्रश्न संख्या ४४९

अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्रीमती कान्ता खतूरिया

वाणिज्य कर की विचाराधीन अपीलें

४५०. **श्रीमती कान्ता खतूरिया** (कोलायत): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) बीकानेर में स्थित डिप्टी कमिश्नर कार्मशियल टैक्सेस के पास ३१ मार्च, १९६७ तक कितनी अपील दाखिल हुई।

(२) उन अपीलों में से कितनी अपीलों का फैसला कर विभाग के पक्ष में बहाल रहा ?

(३) कितनी अपीलें रिमाण्ड की गईं ?

(४) क्या जिन अपीलों को रिमाण्ड किया गया उन केसेज़ के संबंधित एपीलान्ट्स को कर की रकम वापिस अदा कर दी गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) डिप्टी कमीश्नर, कार्मशियल टैक्सेज, बीकानेर के पास ३१ मार्च, १९६७ तक २०११ अपील के मामले स्थानान्तरित होकर आये तथा ८१३ मामले सीधे ही दाखिल किये गये।

(२) कुल तय की गई ५९२ अपीलों में से १२८ में फैसला पूर्णतया विभाग के पक्ष में रहा। २३९ मामलों में अपील आंशिक रूप में स्वीकार हुई।

(३) १४६ मामले रिमाण्ड किये गये।

(४) २७ केसेज में रिफण्ड किया जा चुका है। बाकी में संबंधित व्यापारियों के प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर कर निर्धारण अधिकारी उचित कार्यवाही करेंगे प्रार्थना पत्र के बाद ६० दिन में रिफण्ड न मिलने पर व्यापारी कानून के अनुसार व्याज क्लेम कर सकता है।

श्रीमती कान्ता खतूरिया : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि एवरेज एक अपील तय होने में कितना समय लग जाता है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह अलग-अलग अपीलेंट अथारिटी के पास अलग अलग एवरेज है क्योंकि बीकानेर अपीलेंट अथॉरिटी के पास में केसेज कम थे इसलिए दूसरे अपीलेट अथारिटी के केसेज भी ट्रान्सफर हुए। जैसा मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया वैसे आर्डनिरिली ३-४ महीने लगने चाहिए एक अपील में फैसला करने के लिए। लेकिन किसी केस में कोई खास बाधा हो तो ज्यादा समय भी लग सकता है। इसलिए कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं हैं।

श्रीमती कान्ता खतूरिया : क्या यह सही है कि एवरेज अपील तय होने में साल भर लग जाता है।

श्री मथुरादास माथुर : एवरेज में साल तो नहीं लगता है लेकिन कोई बाधा हो तो हो सकता है साल भर भी लग जाये।

श्री पुखराज कालानी (सोजत) : क्या यह सही है कि कोई अपील दो साल से पहले तय नहीं होती है ?

श्री मथुरादास माथुर : हाँ, मुमकिन है जिसमें आप जैसे हों।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब तो हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह ।

इन्द्रगढ़ तहसील में अकाल राहत कार्य

४५१. **श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा)** : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कोटा जिले की नायब तहसील इन्द्रगढ के सम्पूर्ण क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित किया गया है ?

(२) यदि हां तो वहां पर क्या क्या अकाल राहत कार्य शुरू करने का विचार राज्य सरकार रखती है तथा क्या कोई कार्य इस समय शुरु है ?

(३) क्या राज्य सरकार इन्द्रगढ़ से कमलेश्वर तथा इन्द्रगढ़ से डिस्पेंसरी एवं इन्द्रगढ़ से बाबई तक सड़क निर्माण कार्य अकाल राहत कार्यों के तहत शुरू करने का इरादा रखती है ? यदि हां तो यह कार्य कब शुरू किये जावेंगे ?

अकाल राहत मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (१) जी हां, इन्द्रगढ़ सब तहसील के ८४ गा । न ग . २ गांव अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं ।

(२) हां पर निम्नलिखित राहत कार्य चालू हैं :

(१) बलघन का तालाब ।

(२) बैजपुर का बांध

(३) जी हां, कार्य शीघ्र ही चालू होने को है ।

श्री महेन्द्रसिंह : तीसरे का आपने क्या उत्तर बताया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : काम चालू हो जायेगा ।

श्री महेन्द्रसिंह : मैंने तीसरा सवाल पूछा है कि क्या राज्य सरकार इन्द्रगढ़ से कमलेश्वर तथा इन्द्रगढ़ से डीपरी, एवं इन्द्रगढ़ से बाबई तक सड़क निर्माण कार्य अकाल राहत कार्यों के तहत शुरू करना चाहती है तो इसका क्या है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जैसा मैंने अर्ज किया कि जो दो काम चालू हैं और जो दो तालाब और बांध का काम चालू है उसमें मजदूरों की संख्या एक में तो ५० है और दूसरे में १५० है और लास्ट ईयर का यह तजुर्बा है कि सड़क चालू की गई इन्द्रगढ़ से डीपरी उसमें मजदूर नहीं आये । अगर वहां पर मजदूर आने के लिए तैयार हों तो काम चालू हो सकता है ।

श्री महेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को जानकारी के लिए बता दूं कि वह कार्य बिलकुल बन्द पड़े हैं और कोई काम नहीं किया जा रहा है और तो यह दो तालाब हैं बलवंतपुरा का तालाब और मोहनपुरा का तालाब इन पर इलेक्शन के दिनों में काम शुरु किया था जो आज तक बन्द है, सो मैं पूछना चाहता हूँ कि अकाल राहत कार्य के लिए कितनी धनराशि मन्जूर की थी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह मैंने अर्ज किया कि मजदूर आने के लिए तैयार हों १ रु० २ आने पर तो काम चालू हो जायेगा ।

श्री महेन्द्रसिंह : आपने राहत कार्यों के लिए उस एरिया के लिए कितना रुपया मन्जूर किया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कोटा कलेक्टर को रुपया दे रखा है।

श्री महेन्द्रसिंह : कितना दे रखा है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : २ लाख रुपया।

श्री महेन्द्रसिंह : किस मद में ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : फेमिन रिलीफ की मद में।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री रामचन्द्र।

तहसील नोहर के गांवों में प्राइमरी पाठशालाएं

४५२. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील नोहर में करीब ५५ ग्रामों में प्राइमरी पाठशालायें नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या इन ग्रामों के बच्चों की पढ़ाई का प्रबंध करने का सरकार का विचार है ?

(२) इस वर्ष कितने ग्रामों में प्राइमरी पाठशालायें खोलने की योजना है ?

(३) क्या यह सही है कि १०-१० मील तक नजदीक प्राइमरी पाठशालायें नहीं हैं ?

(४) यदि हां, तो इतने लम्बे अरसे तक ग्रामों में प्राइमरी पाठशालाएं नहीं खोलने का क्या कारण है ?

(५) क्या सरकार इस मामले को प्राथमिकता देगी ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां।

(२) पंचायत समिति को वार्षिक योजना में २० शालायें खोलने का प्रस्ताव था।

(३) जी नहीं।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

(५) वित्तीय साधनों और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही प्राथमिकता निश्चित की जाती है।

श्री रामचन्द्र : अध्यक्ष महोदय क्या यह सही है कि तहसील नोहर में ५५ गांव ऐसे हैं कि जिनमें ५-५ और १०-१० मील के नजदीक कोई स्कूल नहीं है यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज २० साल के प्रजातंत्र में किसी गांव में........

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है कि ५-१० मील में स्कूल नहीं है ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं अपने उत्तर के भाग ३ में कह चुका हूँ। आपने पूछा है कि क्या यह सही है कि दस दस मील तक नजदीक पाठशालाएं नहीं हैं मैंने कहा है जी नहीं और यह जिला विकास अधिकारी ने इत्तला दी है और इसी आधार पर मैं सदन को इत्तला दे रहा हूँ।

Page No. 17

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, में यह जानना चाहता हूँ कि कब तक स्कूल खोले जायेंगे इन गांवों में। यह पंचायत समिति का प्रश्न नहीं है, पंचायत समिति से तो पहले ही रिपोर्ट आ चुकी है।

श्री परसराम मदेरणा : प्राथमिक स्कूल्स खोलने की योजना शिक्षा विभाग द्वारा बनाई जाती है इसलिए निश्चयपूर्वक कहना कि कितने स्कूल एजूकेशन डिपार्टमेंट द्वारा नोहर तहसील में खोले जा सकेंगे, यह मेरे लिए मुमकिन नहीं है लेकिन जो कुछ भी संकेत आज पंचायत विभाग को एजूकेशन डिपार्टमेंट से मिला है उसमें वित्तीय स्थिति के कारण असमर्थता जाहिर की है और यह कहा गया है कि सम्भावना कम ही है।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग ३ में उत्तर दिया गया है कि दस दस माईल तक नहीं है। मैं, इसकी लिस्ट पेश कर सकता हूँ कि इन गांवों में शिक्षा की कोई भी सुविधा नहीं है। मैं इतनी बड़ी लिस्ट है गांवों की, उसको पेश करना चाहता हूं। इतने बड़े तादाद में गांवों को शिक्षा से वंचित रखना यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यह कहा जाय कि दस दस माईल के अन्दर स्कूल हैं तो इतना बड़ा वहां का रेगिस्तानी इलाका है, वहां पानी का भी अभाव है और शिक्षा विभाग....

श्री अध्यक्ष : आप लिस्ट पेश कर दीजिए।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं लिस्ट पेश करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप रख दीजिए।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, प्राईमरी एजूकेशन कम्पलसरी कर चुकी है सरकार राजस्थान में और फिर इतनी इतनी दूर दूर तक नहीं होना कहां तक उचित है। इसे आप फिर देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह !

केन्द्रीय भण्डार क्रय संगठन द्वारा स्टील फरनीचर की खरीद

४५३. **श्री भैरोंसिंह शेखावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सेन्ट्रल स्टोर्स परचेज ओरगेनाईजेशन ने फरवरी सन् १९६६ में स्टील फरनीचर की खरीद के लिए टेण्डर्स स्वीकार किये थे ? यदि हां, तो कुल कितनी कीमत का माल खरीदा गया ?

(२) क्या यह सही है कि इस खरीद की प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं के कारण राज्य सरकार को काफ़ी हानि हुई है ? यदि हां, तो कितनी ?

(३) क्या यह सही है कि राज्य सतर्कता आयोग ने इस सम्बन्ध में जांच करके अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ? यदि हां, तो कब ? इस प्रतिवेदन पर राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की? कृपया उस प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) यह सही है कि सैन्ट्रल स्टोर्स परचेज ओरगेनाइजेशन ने फरवरी, १९६६ मे स्टील

Page No. 18

(श्री मथुरादास माथुर)

फरनीचर के लिए रेट कान्ट्रेक्ट्स जारी किये थे। सेन्ट्रल स्टोर परचेज ग्रोरगेनाइजेशन द्वारा सामान नहीं खरीदा जाता है।

(२) प्रश्न के तीसरे भाग में बताये गये कारणों की वजह से प्रश्न के इस भाग का उत्तर इस समय नहीं दिया जा सकता।

(३) यह सही है कि एक टेन्डरर की शिकायत पर राज्य सतर्कता ग्रायुक्त ने सरकार को इस मामले में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। यह प्रतिवेदन राज्य सरकार को दिनांक १८-२-६७ को प्राप्त हुग्रा। यह प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है ग्रौर राज्य सतर्कता ग्रायोग के साथ इस बारे में पत्र व्यवहार चल रहा है। चूंकि राज्य सरकार इस मामले में कोई ग्रन्तिम निर्णय नहीं ले पाई है इसलिए इस प्रतिवेदन की प्रति को सदन की मेज पर रखना समय से पूर्व (प्रिमेच्योर) होगा।

श्री भैरोंसिंह : विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट के ग्रनुसार राज्य सरकार को कितना घाटा होने का ग्रनुमान है ?

श्री मथुरादास माथुर : विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट ग्रभी विचाराधीन है ग्रौर परचेज ग्रोरगेनाइजेशन ग्रभी परचेज नहीं करता है बल्कि डिमाण्डिंग ग्राथोरिटी परचेज करती है इसलिए इस घाटे के लिए इस वक्त कुछ बता देना ठीक नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो केवल यही पूछना चाहता हूँ कि विजिलेंस कमीशन का जो प्रतिवेदन राज्य सरकार को मिला है उस प्रतिवेदन के ग्रनुसार राज्य सरकार को इस खरीद के मामले में कितने रुपये की हानि होने का ग्रनुमान है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह तो जब इसके ऊपर विचार होकर फैसला हो जाएगा तभी बताया जा सकेगा।

श्री भैरोंसिंह : विजिलेंस कमीशन ने ग्रपने प्रतिवेदन में कितना ग्रनुमान बताया है ? मैं राज्य सरकार के फैसले की बात नहीं कह रहा हूँ।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने ग्रर्ज किया कि विजिलेंस कमीशन के प्रतिवेदन पर फाइनल निर्णय नहीं हो पाया है। ग्रभी कोरसपांडेंस चल रही है।

श्री भैरोंसिंह : राज्य सरकार के निर्णय की जानकारी मैं नहीं मांग रहा हूं। मैं तो इस बात की जानकारी चाहता हूं कि विजिलेंस कमीशन ने जो ग्रपना प्रतिवेदन दिया उस प्रतिवेदन के ग्रनुसार राज्य सरकार को कितनी हानि होने का ग्रनुमान है ? ग्राप चाहे उसमें फाइनल निर्णय लेते वक्त कह दें कि एक रुपये की भी हानि नहीं हुई है।

श्री मथुरादास माथुर : इस वक्त मैं बताने में मजबूर हूं।

श्री भैरोंसिंह : इसकी जानकारी नहीं है या बताना नहीं चाहते ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं जानकारी देना नहीं चाहता। क्योंकि मान लीजिए कि एक्स ग्राइटम में उन्होंने घाटा बताया है ग्रौर उस पर राज्य सरकार की विजिलेंस कमीशन

Page No. 19

(श्री मथुरादास माथुर)

से कोरसपांडेंस चल रही है और मुमकिन है कि वह खुद अपने विचार को बदल ले।

श्री भैरोंसिंह : मैं यही तो कह रहा हूं कि आप अपने निर्णय को मत बताइए लेकिन विजिलेंस कमीशन ने जो रिपोर्ट आपको दी है उसमें कुल कितनी हानि होने का लिखा है, यह बता दीजिए ?

श्री मथुरा दास माथुर : अध्यक्ष महोदय, वह रिपोर्ट अभी तक भी फाइनल नहीं हुई है क्योंकि राज्य सरकार और विजिलेंस कमीशन के बीच में कोरसपांडेंस चल रही है। इसके बारे में अभी कुछ कहने को मैं तैयार नहीं हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : यह जवाब ही लीपापोती का है। आप जवाब नहीं देना चाहते हैं यह इससे स्पष्ट है।

श्री अध्यक्ष : यह अभी नहीं बताना चाहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं इस समय बताने में मजबूर हूं।

श्री भैरोंसिंह : क्यों मजबूर हैं ?

श्री अध्यक्ष : नहीं बताना चाहते हैं इस वक्त।

श्री भैरोंसिंह : क्या प्रिविलेज क्लेम किया है इन्होंने........

श्री अध्यक्ष : This is just........

श्री भैरोंसिंह : Let him say, Sir.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : Unless he claims privilege, he should be compelled to answer.

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय मंत्री को कम्पेल नहीं कर सकता यदि वह जवाब नहीं देना चाहते हैं तो।

श्री भैरोंसिंह : या तो मिनिस्टर प्रिविलेज क्लेम करे या प्रिविलेज क्लेम नहीं करते हैं तो जवाब देना चाहिए। इस तरह से अगर जवाब नहीं देते हैं तो यह हाउस का अपमान होता रहेगा।

श्री अध्यक्ष : जैसा उन्होंने कहा है कि यह विचारणीय है उनके सम्मुख और इस वक्त वे उचित नहीं समझते हैं बतलाना। मेरे पास कोई ऐसा नियम नहीं है जिससे मैं कम्पेल कर सकूं कि वे बतायें ही।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि रिपोर्ट में इस बात का हवाला दिया गया है कि राजस्थान सरकार के भूतपूर्व यातायात मंत्री श्री चन्दनमल वैद के भाई को लाभ पहुंचाने के लिए गलत टेंडर्स काल कर और गलत रेट बताकर लाखों रुपयों का सामान खरीदा गया ?

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर चुका हूं कि इस वक्त.......

श्री भैरोंसिंह : आप निवेदन कर चुके हैं इसलिए कि एक मंत्री को बचाया जा रहा

(श्री भैरोंसिंह)

है। राजस्थान सरकार को चार लाख रुपये का घाटा पहुंचाया गया और आप रिपोर्ट को दबा कर बैठे हुए हैं। फरवरी में रिपोर्ट आपके पास आ गई लेकिन आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया........

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट फरवरी में आई उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से विजिलेंस कमीशन को लिखा गया अप्रेल के एण्ड में और उसके बाद विजिलेंस कमीशन ने फिर जवाब दिया और उस जवाब के बाद में उस रिपोर्ट पर "Read with the latest letter of the Commission" ऐसा हो सकता है। सरकार विचार कर रही है। मई के एण्ड में या जून में ही वह जवाब प्राप्त हुआ है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह सब लीपापोती की कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : अभी तक उस पर विचार करके निर्णय नहीं किया जा सका है। इसमें किसी मंत्री का भाई हो चाहे और कोई मंत्री हो, उसको बचाने का प्रश्न नहीं है। सरकार इस रिपोर्ट पर विचार कर रही है, अभी तक फैसला नहीं कर पाई है इसलिए इस स्टेज पर रिपोर्ट के बारे में मैं कुछ भी कहना ठीक नहीं समझता।

श्री भैरोंसिंह : क्या मंत्री महोदय ने विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ा भी है ?

श्री मथुरादास माथुर : मेरे पढ़ने या नहीं पढ़ने का प्रश्न नहीं है। विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट मौजूद है और वह अभी भी यहां पर मौजूद है।

श्री भैरोंसिंह : आपने उसे पढ़ा है या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : पढ़ा है तभी तो जवाब दे रहा हूं आपको।

श्री भैरोंसिंह : जवाब तो आपके सेक्रेट्री, डिप्टी सेक्रेट्री ने दिया है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह निवेदन करता हूं कि माननीय सदस्य समझते हैं कि वे ही पढ़ते हैं दूसरे तो पढ़ते ही नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है, मेरे सेक्रेट्री ने भी पढ़ा है और जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब दिया गया है। मैं कह रहा हूं कि इसमें तीन कोरसपांडेंस लेटर्स हैं और जो ओरिजिनल रिपोर्ट आई है रेड विद लेटेस्ट रिपोर्ट उसके जवाब के आधार पर निर्णय करना पड़ेगा और चूंकि यह जून में ही प्राप्त है इसलिए इस पर निर्णय करने में समय लगेगा। निर्णय होने पर मैं, आप चाहेंगे तो, रिपोर्ट को सदन की मेज पर रख दूंगा। आप हाफ एन हावर डिस्कशन कर सकते हैं उस पर।

श्री भैरोंसिंह : हाफ एन हावर डिस्कशन तो पहले भी कर चुके हैं। पिछली विधान सभा के अधिवेशन में जब इस प्रश्न को सदन में उठाया गया था तो सरकार की

Page No. 21

(श्री भैरोंसिंह)

तरफ से तो यह कहा गया था कि इसमें कोई अनियमितता नहीं है। मैंने इसे हाफ एन हावर के डिस्कशन में उठाया था कि इसमें अनियमतताएँ हैं और उसके बाद यह मामला विजिलेंस कमीशन के सामने गया और विजिलेंस कमीशन ने कहा कि चार लाख रुपये की राज्य सरकार को हानि हुई है और इसमें केवल एक ही कारण है कि चन्दनमलजी वैद के भाई की फर्म को प्रोटेक्शन दिया गया है। इसके लिए राज्य सरकार कागजों को दबाने की कोशिश कर रही है। अगर कोई दूसरा होता, किसी दूसरे आदमी का मामला होता तो इस पर एक्शन ले लिया गया होता।

श्री मथुरादास माथुर : मैं माननीय सदस्य को बताता हूं कि आपने यह मामला अप्रेल ६६ में एडजोर्नमेंट मोशन के द्वारा रखा था और विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट बाद में आयी है....

श्री भैरोंसिंह : पहले तो जांच ही नहीं हुई थी। मैंने मामला रखा तब जांच हुई। १८ दिन के बाद एप्लीकेशन दी तब जांच कराई गई।

श्री मथुरादास माथुर : मैं बताता हूं कि माननीय सदस्य अग्रवाल और पहले जो माननीय सदस्य अब्दुल जब्बार थे उन्होंने एडजोर्नमेंट मोशन के द्वारा इस मामले को उठाया था और उसके बाद में विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट आई फरवरी १९६७ में। उसके बाद राज्य सरकार और कमीशन के बीच में कोरसपांडेंस होती रही और लेटेस्ट लेटर उनका ६ या ७ जून का प्राप्त हुआ है। उसकी पूरी जांच पड़ताल कर सरकार उस पर निर्णय करेगी। अब उसमें किसका कसूर है, कितना लौस है वह चार लाख का है या कम है ज्यादा है, यह कुछ भी कहना प्रिमेच्योर होगा और इसलिए अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री भैरोंसिंह : क्या राज्य सरकार यह उचित नहीं समझती कि इस मामले में जब एक भूतपूर्व मंत्री से सम्बन्धित फर्म का मामला होने और उस फर्म से सामान खरीदने के कारण सदन के अन्दर और सदन के बाहर जो वातावरण बन गया है उसको शुद्ध करने के लिए उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रख दिया जाय ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने निवेदन किया कि राज्य सरकार अभी उस पर डिसिजन ले रही है। विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट पर डिसिजन हो जाने के बाद यह आपका प्रिविलेज है कि आप उसकी डिमाण्ड कर सकें। लेकिन यह आज तो प्रिमेच्योर है। गवर्नमेंट ने अभी डिसिजन लिया नहीं है। यह तो आप कुछ भी कह सकते हैं कि यह मंत्री का भाई है या कोई भी है। रिपोर्ट में तो मंत्री का भाई लिखा नहीं है........

श्री भैरोंसिंह : फर्म उनके भाई की है, यह दुनियां जानती हैं।

श्री मथुरादास माथुर : फर्म के नाम पर कोई मंत्री का भाई नहीं लिखा होता....

श्री भैरोंसिंह : यह तो आप भी जानते हैं कि किस की फर्म है। सदन में खड़े होकर

(श्री भैरोंसिह)

अनभिज्ञता बता रहे हैं तो इससे क्या होता है।

श्री अध्यक्ष : श्री दौलतराम !

श्री मदनसिंह दांता : आपने फर्म के बारे में आधी बात कही और आधी नहीं कही इससे तो शंका ही बढ़ी है।

श्री मथुरादास माथुर : उन सब शंकाओं का समाधान किया जायगा, माननीय सदस्य!

श्री भैरोंसिह : रिपोर्ट सामने आ जायगी तो शक तो सबको हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : Next ! श्री दौलत राम सारण!

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार के समक्ष जो इस सम्बन्ध में प्रश्न विचाराधीन है, वह जो विजिलेन्स कमिश्नर के द्वारा दी हुई रिपोर्ट है उनके एक्शन लेने का प्रश्न विचाराधीन है या फेक्ट्स का विषय विचाराधीन है ?

श्री मथुरादास माथुर : फेक्ट्स के बारे में भी है और एक्शन लेने के बारे में भी है। फेक्ट्स में कमी है इसलिए तो पूछा गया है। अब फेक्ट्स आ जायेंगे और उसके बाद भी जरूरत पड़ी तो दुबारा हम पूछेंगे। मैंने कहा कि अभी यह प्रिमेच्योर है, इसलिए आपको कुछ बता कर राज्य सरकार कमिट नहीं करना चाहती।

श्री अध्यक्ष : Next ! श्री दौलत राम सारण!

श्री चुन्नी लाल : प्रश्न संख्या ४५४ !

चुरू जिले के अभाव ग्रस्त क्षेत्र

४५४. **श्री चुन्नीलाल (नोखा)** (श्री दौलतराम सारण की अनुपस्थिति में) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(१) चूरू जिले में इस वर्ष कितने गांव अभाव ग्रस्त घोषित किये गये हैं तथा कौन कौन से ?

(२) क्या पंचायत समिति सरदार शहर और डूंगरगढ़ ने तथा अन्य किसी पंचायत समिति अथवा पंचायतों ने प्रस्तावों व प्रतिवेदनों द्वारा अन्य गाँवों में भी अभाव की स्थिति बतलाते हुए उन्हें अभावग्रस्त घोषित करने की मांग की थी ? यदि हाँ, तो ऐसे कौन कौन से गांव थे ?

(३) क्या जिला परिषद् ने भी इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पारित किया था ? यदि हां, तो उस प्रस्ताव की और उपरोक्त पंचायत समितियों के प्रस्तावों तथा पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(४) उन प्रस्तावों और प्रतिवेदनों में किये गये निवेदन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई तो क्यों नहीं ?

(५) क्या शिमला व बोधेरा, ढाणी तेतरवाल के ग्रामीणों ने जिलाधीश चुरू को यह भी प्रार्थना पत्र दिया था कि उनका गांव अभाव ग्रस्त नहीं है जबकि अभाव ग्रस्त दिखा दिया गया है ?

(६) शिमला और बोधेरा में पटवारी ने गिरदावरी में कितनी फसल दिखलाई थी ?

Page No. 23

(श्री चुन्नीलाल)

गिरदावर, तहसीलदार तथा एस. डी. ओ. ने निरीक्षण पर कितनी मानी ?

(७) क्या अभाव ग्रस्त ग्रामों के लोगों के लिए कोई राहत कार्य चालू किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(८) क्या अन्य कोई सुविधा दी गई है ?

उप मंत्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी): (१) चूरू जिले में इस वर्ष ४५ गांव अभाव ग्रस्त घोषित किये गये हैं। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(२) पंचायत समिति सरदार शहर ने अपने पत्र दिनांक २-११-६६ द्वारा उन गांवों की सूची जिन्हें वह अभाव ग्रस्त घोषित कराना चाहती थी, जिलाधीश कार्यालय में प्रस्तुत की। पंचायत समिति, डूंगरगढ़ अथवा अन्य पंचायत समितियों की ओर से कोई प्रस्ताव इस सम्बन्ध में प्राप्त नहीं हुए। पंचायत समिति डूंगरगढ़ को ग्राम पंचायत पुनरासर एवं बरजांगसर द्वारा प्रस्ताव अवश्य पेश किये गये हैं। इसके अतिरिक्त किसी पंचायत द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं भेजे गये।

(३) जी हां, प्रतिलिपियां सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं।

(४) पंचायत समिति सरदारशहर द्वारा प्रेषित प्रस्तावों की जांच उपखण्ड अधिकारी चूरू द्वारा करवाई गई। जिनके प्रतिवेदन के आधार पर जिलाधीश द्वारा सूचित किया गया कि अभावग्रस्त घोषित ११ गांवों के अलावा उक्त तहसील में कोई भी गांव ८ आने से अधिक नुकसान वाला नहीं है। पंचायत बजरांगसर द्वारा प्रस्तावित ३ गांवों में से बजरांगसर के अतिरिक्त तथा ग्राम पंचायत पुनरासर में बीजरासर व पुनरासर के अतिरिक्त शेष गांवों में ८ आने से कम अभाव होने के कारण उन्हें अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया।

(५) शिमला, बोथेरा व ढाणी तैतरवाल के ग्रामीणों ने इस कार्यालय को इस आशय का कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया कि उनके ग्राम अभावग्रस्त नहीं हैं। इन गांवों में से सिर्फ एक बोथेरा को अभाव ग्रस्त घोषित किया गया था, शेष दो गांवों को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया है।

(६) पटवारी ने ग्राम शिमला व बोथेरा की गिरदावरी में क्रमशः ६९ पैसे एवं ३७ पैसे फसल दिखाई थी। गिरदावर ने अपनी पड़ताल में क्रमशः ६२ पैसे एवं ३७ पैसे दिखाई थी। तहसीलदार ने इन गांवों की गश्त गिरदावरी की चैकिंग नहीं की थी।

(७) कोई राहत कार्य शुरू नहीं किया गया। जिले के कुल ४५ अभावग्रस्त गांव थे, उनमें से ३५ गांवों में, जिनमें उत्पादन ४ आने से अधिक और ६ आने से कम था उन गांवों में किसानों एवं उनके परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध था और कोई राहत कार्य की आवश्यकता नहीं थी। शेष १० गांव जिनमें उत्पादन ४ आने से कम हुआ है वे जिले भर में बिखरे हुए हैं। ये गांव निम्नलिखित तहसीलों में उनके सामने अंकित संख्या में स्थित हैं :—

(श्री गंगाराम चौधरी)

नाम तहसील	तादाद गांव जहां उत्पादन ४ आने से कम है
डूंगरगढ़	३
तारानगर	१
चूरू	४
सरदारशहर	२

(८) उपरोक्त ४५ गांवों में वितरण करने के लिए ३ किलो प्रति व्यक्ति की मात्रा में अनाज यानि आयातित गेहूँ माह अप्रेल में ७२३ क्विन्टल गेहूँ तथा मई, १९६७ में ६४० क्विन्टल गेहूँ आवंटित किया गया हैं। इसके अलावा निःशुल्क सहायता देने के लिए जो तहसीलों से रिपोर्ट प्राप्त हुई, उसके अनुसार ऐसे निःशुल्क सहायता पाने के योग्य व्यक्तियों की संख्या ७० है और उनको ८ किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह निःशुल्क सहायता देने हेतु आयातित गेहूँ आवंटित कर दिये गये हैं। यह निःशुल्क सहायता १-४-६७ से शुरू की गई है और फेमिन कोड के अनुसार ३१-७-६७ तक दी जा सकती है।

(सूचियाँ विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : Next ! श्री हीरा !

श्री हीरा : ४५५ ।

पंचायत समिति सज्जनगढ़ के (बांसवाड़ा) काश्तकारों के लिये पतरों का कोटा

४५५. श्री हीरा :-क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत समिति सज्जनगढ़ (जिला बांसवाड़ा) के नाम काश्तकारों के लिये वर्ष १९६५-६६ व ६७ में पतरों का कितना कोटा एलाट हुआ था तथा किस किस तारीख को कितना कितना हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उक्त कोटे में से किस काश्तगार को कितने कितने पतरों का वितरण हुआ ? गांव के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि जिन्हें पतरे दिये गये थे उन्होंने अपने मकानों पर नहीं चढा कर उन्हें काले बाजार में बेच दिया ? यदि नहीं तो किन किन काश्तकारों ने पतरों का सही उपयोग किया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : इसमें जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है ! श्री हीरा ! पंचायत मंत्री !

श्री हीरा : अध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी जानकारी सरकार को कर लेनी चाहिये थी।

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, इसकी अभी सूचना आयी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : सूचना आना बाकी है। स्थगित किया जाता है।

प्रश्न संख्या ४५६

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत ।

(अनुपस्थित--कृपया आगे देखिये)

श्री मदनसिंह !

मूण्डवा लाइम्स पर ग्राम पंचायत व पंचायत समिति द्वारा टैक्स

४५७ **श्री मदनसिंह दांता** (दांता रामगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि नागौर जिले के ग्राम मारवाड़ मूण्डवा की ग्राम पंचायत व पंचायत समिति ने अपने प्रस्ताव पास कर

(श्री मदनसिंह दांता)

केमीकल लाइम्स पर कुछ टैक्स लगाया था ? अगर हां, तो वो टैक्स वसूल हुआ ? और टैक्स वसूल नहीं हुआ, तो क्यों ?

(२) क्या पंचायत के टैक्स को वसूल कराने के लिये राज्य सरकार पंचायत की मदद करने की तैयारी कर रही है ?

(३) क्या यह सही है कि ग्राम मूण्डवा पंचायत समिति ने गांव के निवासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर एक प्रस्ताव द्वारा सरकार से मांग की थी कि केमीकल लाइम्स के इन भट्टों के धुएं से बचाव हेतु इन पर चिमनी का निर्माण करवाया जाय ? यदि हां, तो पंचायत समिति की इस मांग पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

(४) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मूण्डवा के पास जो केमिकल लाइम्स नगर का निर्माण हुआ है उसकी स्वीकृति सरकार से ली गई है ? अगर हां, तो किस आधार पर, और नहीं तो इस गलत कदम के विरुद्ध सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

(५) किसी भी नव निर्माण के लिये ग्राम पंचायत से आज्ञा अनिवार्य है, तो क्या मूण्डवा पंचायत से केमीकल लाइम्स ने अपने भवनों के निर्माण व परकोटे के निर्माण के लिये स्वीकृति मांगी थी ? यदि हां, तो कब ? नहीं तो, कानून की अवहेलना के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (१) पंचायत समिति मूण्डवा ने उद्योग कर लगाया किन्तु वसूल नहीं हुआ, क्योंकि तहसीलदार द्वारा वसूली नहीं की गई। पंचायत ने चूने पर टैक्स लगाया, किन्तु वसूली के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं की।

(२) पंचायत ने टैक्स वसूली के लिए राज्य से कोई सहायता नहीं ली। अन्यथा राज्य सरकार सहायता करने को सदैव तैयार रहती है।

(३) पंचायत समिति ने भट्टों पर चिमनियां बनाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया, किन्तु आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई !

(४) जमीन एलाट करने के आदेश राज्य सरकार उद्योग विभाग द्वारा हो चुके हैं। गृह उद्योग को बढ़ावा देने के आधार पर यह स्वीकृति हुई है।

(५) नव निर्माण की स्वीकृति पंचायत से लेना आवश्यक है, किन्तु केमीकल लाइम्स कम्पनी ने कोई स्वीकृति नहीं मांगी। कानून की अवहेलना के सम्बन्ध में जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु उप जिला विकास अधिकारी को लिखा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री भीमसेन !

रेगिस्तानी हिस्सों में भूमि आवंटन

४५८. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :—

क्या यह सही है कि राज्य के रेगिस्तानी हिस्सों में सरकारी भूमि का आवंटन केवल तीन वर्ष के लिये होता है ? अगर हां, तो

Page No. 26

(श्री भीमसेन)

क्या सरकार राजस्थान भू आवंटन (कृषि प्रयोजनार्थ) नियम, १९५७ में संशोधन करके दस साल के आधार पर भूमि का आवंटन करने का इरादा रखती है ?

राजस्व उप मंत्री, (श्री गंगाराम चौधरी) : राज्य के रेगिस्तानी हिस्सों में सरकारी भूमि का आवंटन तीन वर्ष के लिये किया जाता है।

राजस्थान भू आवंटन (कृषि प्रयोजनार्थ) नियम, १९५९ में संशोधन का मामला राजस्थान सरकार के विचाराधीन है।

श्री भीमसेन : क्या राजस्व मंत्री ने अपनी राजस्व की मांग पर हुई बहस का जवाब देते हुए इस सम्बन्ध में आश्वासन दिया था कि इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये जायेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री) : जी हां, आदेश जारी करने के लिए फाइल पर आर्डर कर दिये हैं और प्रारूप तैयार हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजय सिंह।

पंचायत समिति उनियारा द्वारा काश्तकारों को ऋण

४५९ श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति, उनियारा, जिला टोंक द्वारा श्री घासीलाल पुत्र श्री गणेश दरोगा को ३०००) रु० का अनुदान किया गया है ? यदि हां, तो कब और किस कार्य हेतु ?

(२) क्या यह सत्य है कि नियमानुसार ऋण देने से पूर्व उस व्यक्ति की मिलकियत या उसकी स्वयं की खातेदारी की तस्दीक की जाती है ? यदि हां, तो क्यों इस मामले में ऐसा नहीं किया गया ?

(३) क्या यह सत्य है कि इस व्यक्ति के पास तीन बीघा आगाजी एलाटेड है और उसी पर यह ऋण दिया गया है तथा और कोई खातेदारी की जमीन नहीं है ? यदि हां, तो क्या यह ऋण दिया जाना नियमानुकूल है ?

(४) क्या यह भी सत्य है कि अभी तक इस ऋण में से एक भी किश्त जमा नहीं करवाई गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(५) क्या सरकार ऐसे ऋण को मान्यता देती है ? यदि नहीं, तो अब वसूली की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(६) क्या यह सही है कि पंचायत समिति उनियारा ऐसे कई व्यक्तियों को ऋण दे चुकी है जिनके स्वयं की कोई भूमि नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या यह नियमानुसार है ?

(७) क्या यह भी सत्य है कि ऋण की वसूली पंचायत समिति द्वारा नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं तो अब तक कुल ऋण में से कितना वसूल कर लिया गया है ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी नहीं। १५००) रु० का ऋण दिया गया।

(२) तस्दीक नियमानुसार कराई गई।

(३) रिपोर्ट पटवारी में जमीन १३ बीघा ७ विस्वा ऋण लेने वाले के खाते में होना दर्ज हुआ। इससे ऋण देना नियमानुकूल है।

(४) जी हां, अकाल की स्थिति के कारण वसूली नहीं हुई।

(५) जी हां।

(६) जी नहीं।

(७) जी हां। डिमाण्ड तहसील में भेज दो गई है। अब तक १३,११०.९३ पैसा वसूल हो चुके हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : क्या यह सही है कि जो ऋण दिया गया है वह एक ही इन्स्टालमेंट में दे दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : ऋण एक इन्स्टालमेंट में दिया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : ऋण एक नया कुआ बनाने के लिए दिया गया। अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी नहीं है कि एक में दिया गया या दो में दिया गया। रु० १५०० का ऋण कुआ बनाने के लिए दिया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

सांचोर तहसील में म्यूटेशन्स

४६०. **श्री रघुनाथ विश्नोई** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील सांचोर में इस वक्त कितने म्यूटेशन्स होने बाकी हैं ? कितने म्यूटेशन्स किस किस अर्से के बाकी हैं ?

(२) बाकी रहे म्यूटेशन्स कब तक कर दिये जावेंगे ? निश्चित तिथि बताने का कष्ट करें।

(३) म्यूटेशन्स शीघ्र कराने के लिए क्या राज्य सरकार कोई नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है ? अगर हाँ, तो क्या ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी)-(१) तहसील सांचोर में इस वक्त १४६ म्यूटेशन बाकी हैं। ५६ म्यूटेशन माह अप्रेल ६७ में भरे गये व ९० पहले के बाकी हैं।

(२) बाकी रहे म्यूटेशन शीघ्र समाप्त किये जाने के लिये आदेश दिये जा रहे हैं।

(३) म्यूटेशन शीघ्र करने के लिए राज्य सरकार ने पहले ही नियम बना दिये हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या नियम बनाये हैं, अभी तक कितने अर्से से पेंडिंग हैं ? आपने समय नहीं बताया, ९० कब से पेंडिंग हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : पहले से पेंडिंग हैं, अब कब से पेंडिंग हैं इस सम्बन्ध में पूरी सूचना नहीं है।

Page No. 28

श्री रघुनाथ विश्नोई : म्यूटेशन का मामला पहले भी उठाया जा चुका है। जो म्यूटेशन के मामले होते हैं उनका निराकरण कई वर्षों तक नहीं होता है। जो प्रार्थना पत्र पटवारी को दिये जाते है उनके उपर वह कार्यवाही काफी अर्से तक नहीं करता है। इसलिए कोई न कोई अवधि होनी चाहिए कि इतने समय में वह पंचायत को पेश कर दे ताकि इतनी इसमें डिले नहीं हो। इस बारे में राज्य सरकार क्या सोच रही है ?

श्री गंगाराम चौधरी : पहले से ही जो नियम जारी कर दिये हैं, १९-४-६४से, उनमें इस सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान है कि सबसे पहले प्रार्थी पटवारी को प्रार्थना दे, वह बीस दिनके अन्दर रेवेन्यू इन्सपेक्टर के पास आगे भेज दे और इन्सपेक्टर उसको बीस दिन तक अपने पास रख सकता है, उसके बाद वह पंचायत को भेज देता है। वह भी बीस दिन से अधिक नहीं ले सकते। अगर इसमें कोई शिकायत हो तो प्रार्थी तहसीलदार को प्रार्थना पत्र दे सकता है।

(१२ मध्यान्ह)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने बताया कि इतने अर्से से विचाराधीन है तो जब इतने लम्बे अर्से से विचाराधीन हैं तो आपको कुछ न कुछ एक्शन लेना चाहिये।

श्री रोशनलाल (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय,.......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ऑर्डर। जो प्रश्न उठाया गया है उसका जवाब आने दीजिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : (राजस्व मंत्री) जितने समय की अवधि है उससे ज्यादा अर्से तक पेन्डिग मामले रहते हैं तो खास तौर से तहसीलदार को लिख दिया जावेगा।

श्री रोशनलाल : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : मैं अध्यक्ष हूँ।

श्री रोशनलाल : अध्यक्ष महोदय, बार बार जिला परिषदों द्वारा उनका ध्यान आकर्षित किया गया मगर कोई ध्यान नहीं देते।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आपने मंत्री का ध्यान आकर्षित कर दिया है।

एक माननीय सदस्य : क्या ऐसे इन्सट्रक्शन्स हैं कि ५ एकड़ भूमि है उनके इन्द्राजात नहीं किये जावेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मुझे यह निवेदन करना है कि यह आम शिकायत है। यह सिद्धान्त का प्रश्न है। अगर पटवारी समय में नामान्तरकरण नहीं करता तो पटवारियों के खिलाफ सरकार को कुछ न कुछ कार्यवाही करनी चाहिये। अगर सरकार उनके खिलाफ कुछ भी कार्यवाही नहीं करती है तो मेरे ख्याल से इससे जनता में असंतोष बढ़ेगा और आपकी इनएफिसियेन्सी बढ़ेगी।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

रायपुर तहसील में सरकार द्वारा अनाज वितरण

४६१. **श्री पुखराज कालानी** : क्या खाद्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(१) रायपुर तहसील में अकालग्रस्त गांव कितने व कौन कौन से है ?

(२) क्या रायपुर तहसील में सरकार की तरफ से अनाज वितरण की पिछले चार महीनों से कोई व्यवस्था रही है ? यदि हां, तो पहली जनवरी, १९६७ के बाद कौन कौन से गांव में कितना कितना अनाज सरकार के कोटे से दिया गया ?

(३) क्या यह सही है कि पिछले चार महीने में रायपुर तहसील के सेन्दड़ा रेवेन्यू सर्किल के गांवों में ही अनाज वितरण सरकार द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो पहली जनवरी के बाद कुल कितना अनाज इन गांवों में सरकार के कोठों से दिया गया व अनाज वितरण किन की मारफत हुआ व इन गांवों की क्या आबादी है ?

(४) इसी तहसील के दूसरे रेवेन्यू सर्किल रायपुर के गांवों की कितनी आबादी है ? इन गांवों में अनाज वितरण क्यों नहीं किया गया जब कि सम्बन्धित अधिकारियों व जिलाधीश को समय समय पर यह बताया गया कि इन गांवों में अनाज की विकट समस्या हैं ?

क्या सेंदड़ा रेवेन्यु सर्किल रायपुर रेवेन्यू सर्कल के गांवों में अनाज की हालत में कोई फरक है ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी, कोई गांव नहीं है।

(२) जी हां सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(३) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है। सम्बधित अधिकारियों ने वहां के हालात को दृष्टि में रखते हुए उचित नहीं समझा।

(५) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट संख्या २ देखिये)

श्री पुखराज कालानी : आपने इस लिस्ट का बेसिस क्या रखा है (साफ सुनाई नहीं दिया)।

श्री अध्यक्ष : लिस्ट का बेसिस क्या रखा है।

श्री परसराम मदेरणा ; वितरण का बेसिस रेवेन्यू इन्स्पेक्टर सर्कल्स व अधिकारियों ने बताया कि इतने खाद्यान्नों का वितरण किया गया हैं। जैसा कि वहां के अधिकारियों ने जिलाधीश और दूसरे अधिकारियों ने इत्तिला भेजी है कि सेंदड़ा सर्कल पहाड़ी इलाका है और उस क्षेत्र में अनाज की कमी है इसलिये वहां पर माइलो और गेहूँ का प्रबन्ध किया गया है।

श्री पुखराज कालानी : आपने व्योपार का बेसिस रखा है।

(अश्रव्य)

Page No. 30

श्री परसराम मदेरणा : इससे व्यापार का क्या सम्बन्ध है ?

श्री देवीदत्त : अध्यक्ष महोदय, लाखों रुपयों का ...(श्री अध्यक्ष, देवीदत्त व कालानी के एक साथ बोलने से अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर । माननीय सदस्य

श्री पुखराज कालानी : आपने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें किसी १५० और किसी को २५० इसका क्या कारण है और सेन्दड़ा में.......

(अश्रव्य)

श्री परसराम मदेरणा : सेंदड़ा सर्कल में वहां के जिला अधिकारियों ने यह उचित समझा कि वहां खाद्यान्नों की कमी को देखते हुए उस एरिया में दिया जाय। अगर माननीय सदस्य कहते हैं कि रायपुर में खाद्यान्नों की कमी है, कितना खाद्यन्न उपलब्ध है उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। रिपोर्ट आने के बाद कह सकते है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

कोटा जिले में ओला वृष्टि से हानि

४६२ **श्री बृजवल्लभ** (दीगोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने कृपा करेगें।

(१) क्या यह सही है कि कोटा जिले को तहसील लाडपुरा के कई ग्रामों में दिनांक २७ : २८ मार्च, १६६७ को ओला वृष्टि हुई ? यदि हां, तो कौन कौन से ग्रामों में कितने कितने एकड़ भूमि की फसल को क्षति हुई ?

(२) क्या सरकार ओला अत्र वृष्टि से क्षति ग्रस्त एरिया का लगान माफ करके राहत देने का इरादा रखती ? यदि हां, तो किस प्रकार से और कब तक राहत पहुंचा दी जावेगी ?

उप मंत्री राजस्व : (श्री गंगाराम चौधरी) तहसील लाडपुरा में दिनांक २७:२८ मार्च को ओला वृष्टि में २३ ग्रामों की फसल रबी सं० २०२३ में १६ आना २२७ एकड़, १२ आना ४०८ एकड़, आठ आना १४२७ एकड़, ४ आना ६१० एकड़ कुल २६७२ एकड़ रकबे में हानि हुई है। जिसकी ग्रामवाइज सूची संलग्न है जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री बृजवल्लभ : अध्यक्ष महोदय इसमें कुछ के नाम नहीं दिये गये है........

(साफ सुनाई नहीं दिया)

श्री गिरधारीलाल व्यास : प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है और साफ सुनाई नहीं देता है।

श्री अध्यक्ष : (श्री गिरधारीलाल व्यास से) आपने इसको और भी कन्फ्यूज्ड कर दिया। (श्री बृजवल्लभ से) आप अपने इस प्रश्न का अन्त कर दीजिये।

श्रीबृजवल्लभ : ठीक तरह से रिपोर्ट पटवारियों से नहीं आई है क्योंकि फसल कट चुकी थी। मैंने देखा है गेहूं बिल्कुल नहीं थे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ठीक तरह से रिपोर्ट नहीं आई है तो रिपोर्ट मंगाई जावेगी।

श्री बृजवल्लभ : क्या लेवी उनसे वसूल की जावेगी ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है ।

श्री भेरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां फसल इतनी खराब हो गई है तो जहां पर फसल खराब हुई है वहां पर लेवी लेने का प्रश्न ही कैसे रहता है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां अकाल है वहां लेवी लेने का प्रश्न नहीं है और जो वैयक्तिक फसल खराब हुई है उसका कितना वसूल करना है या नहीं यह अलग से तैयार होते हैं। अगर अभावग्रस्त क्षेत्र है तो लेवी लेने का प्रश्न नहीं है ।

श्री बृजवल्लभ : कई लोगों को बराबर १९६६ से तंग किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

पंचायत समिति निवाई द्वारा कम्प्रेशर मशीन की खरीद

४९३. **श्री जयनारायण सालोदिया** : क्या पंचायत मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति निवाई ने कम्प्रेशर मशीन खरीदी है ? यदि हाँ, तो कब व कितने रुपयों में ?

(२) क्या इस खरीद से पूर्व नियमानुसार विभाग से टेक्निकल राय ली थी ? तथा सम्बन्धित सब कमेटी या पंचायत समिति की स्वीकृति ली थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या यह सच है कि पंचायत समिति ने शिक्षा कर इस उद्देश्य से लगाया था कि इस रकम से स्कूल भवन बनवाये जायेंगे ? यदि हाँ, तो फिर इस प्रकार की धनराशि को कम्प्रेशर मशीन खरीदने में बिना किसी की राय के किसके द्वारा खर्च किया गया ?

(४) क्या इस की कोई जाँच कराई गई है ? यदि हाँ, तो जांच का क्या परिणाम रहा ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): (१) जी हां। ३१.१२.१९६५ को २४,२५०) में।

(२) उत्पादन स्थाई समिति से स्वीकृति ली गई, किन्तु विभाग से तकनीकी स्वीकृति नहीं ली गई।

(३) शिक्षा कर वसूल भवन निर्माण के लिए लगाया गया। इस कर की धन राशि में से कम्प्रेशर नहीं खरीदा गया।

(४) कम्प्रेशर मशीन की खरीद में अनियमितता (यदि हो) जिसकी जांच उप जिला विकास अधिकारी के द्वारा की जा रही है।

श्री जयनारायण सालोदिया : इस कमेटी से राय कब ली खरीदने से पहले या बाद में ?

श्री परसराम मदेरणा : कमेटी ने अपना प्रस्ताव खरीदने के १५ रोज पहले १६.१२.६५ को सर्व सम्मति से पास किया था ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

स्थगित प्रश्न

(६.६.१९६७)

भाखरा नहर क्षेत्र में मुजारों को खातेदारी हक

२५३. **श्री हंसराज आर्य** : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या भाखरा से टी. बी. परगना के उन सभी मुजारों को हकूक खातेदारी दे दिये गये हैं जो कि जमीदारी उन्मूलन के समय जमींदारों की भूमि को वर्षो से काश्त करते चले आ रहे थे ?

(२) यदि हाँ, तो उन मुजारों को किस समय तक के कब्जा काश्त के आधार पर उन्हें हकूक खातेदारी दिया गया है ?

(३) खातेदारी की आराजी की मात्रा कितना बीघा तक रखी गयी है और उस खातेदारी भूमि की क्या कीमत रखी गई है और साथ ही उस कीमत को किसानों से कितनी किश्तों में वसूल किया जावेगा ?

(४) क्या जिन मुजारों को हकूक खातेदारी दिये गये हैं उन सबसे कीमत बराबर ली जायगी ?

(५) ऐसी भूमि का जमींदारों को क्या मुआवजा प्रति बीघा दिया जायेगा ?

(६) कितने एकड़ ऐसी भूमि है जिसे जमींदारों से लेकर मुजारों को हकूक खातेदारी दिया गया और उसकी कुल क्या कीमत होगी ?

(७) ऐसी भूमि का जमींदारों को कुल कितना मुआवजा मिलेगा ?

(८) कितने एकड़ ऐसी भूमि है जो जमींदारों से तो ली गई है परन्तु मुजारों को इस भूमि में हकूक खातेदारी नही मिलेगी ?

उप मंत्री उपनिवेशन (श्री मनफूलसिंह): (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता ।

( ) जो भूमि सरकार में निहित हुई है उस भूमि का २) रुपये प्रति बीघा मुआवजा बनता है ।

(६) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(७) काश्तकारान के नीचे जो बिस्वेदारान की भूमि है उसमें करीब रुपया २,८०,०००) बिस्वेदारान को मिलेगा ।

(८) कुल ८७,५५३ एकड़ भूमि है ।

श्री हंसराज आर्य : क्या खातेदारी के लिये सरकार विचार कर रही है और कब तक दे देगी ?

Page No. 33

श्री मनफूलसिंह : यह सरकार के विचाराधीन है।

श्री हंसराज आर्य : यह कब तक विचाराधीन चलेगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह कानूनी मसला है। मगर अभी कानून बना है उससे ऐसी पैदा नहीं है, उनको नहीं मिलेगा।

श्री हंसराज आर्य : कितना समय लगेगा ? क्या सरकार की यह नीति है कि खातेदारी देगीं या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री हंसराज आर्य : नीयत सरकार की उनको देने की है या नहीं ?

एक माननीय सदस्य : नीयत नहीं है अगर नीयत होती तो इसको तय कर देते।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कल भी मेरे महत्त्वपूर्ण प्रश्न थे वे रह गये और आज भी मेरा बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न है वह रह गया है। २३७ गांवों में अकाल पड़ा है, उन अकाल क्षेत्रों में सस्ते अनाज की दुकानें सरकार की तरफ से नहीं खोली गई हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका पोइन्ट ऑफ ऑर्डर क्या है यह समझ में नहीं आया। आप किस प्रश्न की बात कहते हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : मेरा एक प्रश्न बहुत महत्व का है वह रह गया है।

श्री अध्यक्ष : कुछ प्रश्न छूट गये हैं। अवशेष प्रश्न हैं उनका उत्तर लिखित में, आपके पास पहुंच जावेगा। पूरी कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आजावें। मगर माननीय सदस्य सहयोग नहीं करते। थोड़े से प्रश्न आवें मगर फिर भी कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का उत्तर हो। मगर फिर भी रह जाते हैं।

एक माननीय सदस्य : दिल नहीं भरता है.......

श्री अध्यक्ष : थोड़ा सा दिल को मसोसिये।

श्री देवीदत्त : मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां पर एक महीने सस्ते नाज की दुकानें खोली गई और बाद में बन्द कर दी गई और तीन महीनों से लोग भूखों मर रहे हैं और सरकार की तरफ से वहां सस्ते नाज के गल्ले की दुकानें नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री आपसे चैम्बर में मिलकर बात कर लें।

(शेष प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सहकारी विभाग के अमले में वृद्धि

श्री शोभाराम : (रामगढ़) क्या सहकारी मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(श्री शोभाराम)

(१) क्या सहकारी क्षेत्र के विस्तार के लिए सहकारी विभाग के अमले में वृद्धि किये जाने का सरकार फैसला कर चुकी है ? यदि हां, तो कितनी नई नियुक्तियों का फैसला किया है ? कितनी नियुक्ति की जा चुकी हैं और शेष रिक्त स्थान कितने समय में भर दिये जावेंगे ।

उत्तर

(१) सहकारी विभाग के मेहता कमेटी ऑफ कोपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के आधार पर पुनर्गठन हेतु राज्य सरकार ने जो समिति बनाई थी उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है उसके फलस्वरूप विभिन्न स्तर पर राज्य कर्मचारियों की पोस्टें कम अधिक होने की संभावना है ।

बोरिंग मशीनों द्वारा कुओं की खुदाई

४४६ श्री शंकरलाल (जैतारण) क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कुओं की खुदाई के लिये बोरिंग मशीनों की बहुत मांग है ।

(२) क्या यह सही है कि कुओं की खुदाई पर पानी प्राप्त न होने पर भी बोरिंग मशीनों के चार्जेज काश्तकार से वसूल कर लिये जाते हैं ?

(३) क्या यह सही है कि यह चार्जेज बहुत ऊंचे हैं इसलिये कई काश्तकार बोरिंग मशीन के उपयोग से वंचित रह जाते हैं ?

(४) क्या सरकार चार्जेज कम करने अथवा सबसिड़ी देने का बिचार रखती है ताकि किसान बोरिंग मशीनों का उपयोग करने में समर्थ हो सकें ?

उत्तर

१: जी हां ।

२: जी हां ।

३: बोरिंग या ब्लास्टिंग का कार्य विभाग 'बिना लाभ बिन हानि' के आधार पर करता है । आज कल मशीनरी, पुर्जे, डीजल आदि की कीमत बहुत बढ़ गई है । खुदाई के चार्जेज उस हिसाब से कम ही है ।

(४) काश्तकारों को २५ प्रतिशत सबसिड़ी अब भी दी जाती है । चार्जेज कम करने का कोई विचार नहीं है ।

अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों को सहायता

४५६. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अकाल ग्रस्त क्षेत्र में वृद्ध, विकलांग एवं अशक्त व्यक्तियों को नकद रूप में सहायता देने का नियम है ?

(२) यदि हां, तो क्या इस वर्ष भीम क्षेत्र में ऐसी सहायता दी गई है ? यदि हां, तो कितनी और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(अकाल सहायता मन्त्री)

(२) खरीफ सं० २०२३ की अभाव ग्रस्त स्थिति में तहसील भीम के ४ व्यक्तियों को असहाय सहायता दी गई है। इन ४ व्यक्तियों को माह जनवरी ६७ से ४०० ग्राम गेहूं व २५ पै० प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से स्वीकृत किये गये हैं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य के लिये ट्यूब वैल्स योजना

१२ श्री शंकरलाल (जैतारन) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में ट्यूब वैल्स की आवश्यकता व सम्भावित सफलता पर सरकार द्वारा कब कब और कहां कहां प्रयास किये गये ?

(२) क्या सरकार द्वारा समूचे राज्य में ट्यूब वैल्स की आवश्यकता की पूर्ति के लिये कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसकी क्या रूप रेखा है ?

(३) यह योजना कब तक कार्यान्वित की जायेगी ?

उत्तर

(१) राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी भागों में कई जगह राजस्थान भू जल मंडल और भारत सरकार द्वारा ट्यूब वैल्स बनाये गये और काफी जगह इसमें सफलता भी मिली।

(२) राजस्थान में ट्यूब वैल्स की आवश्यकता की पूर्ति के लिये राजस्थान ग्राउन्ड वाटर बोर्ड द्वारा भूजल का सर्वेक्षण व अन्वेषण करने की योजना चालू की गई है।

होने के बाद ही ट्यूब वैल्स बनाने के लिये एक विस्तृत योजना तैयार की जावेगी।

(३) योजना इसी साल चालू की गई है।

कोलायत निर्वाचन क्षेत्र में अनाज की खपत व पैदावार

१३ श्रीमती कान्ता कथूरिया : (कोलायत)—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) विधान सभा के कोलायत निर्वाचन क्षेत्र में पिछले वर्ष कितना अनाज पैदा हुआ था ?

(२) पैदावार के मुकाबले में अनाज की खपत कितनी रही और कमी की पूर्ति सरकार ने किस प्रकार की ?

उत्तर

(१) अनाज के उत्पादन का अनुमान राज्य स्तर पर एवं जिला स्तर पर ही लगाया जाता है, निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर नहीं। अतः यह सूचना देना सम्भव नहीं है।

(२) खपत के अनुमान निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार नहीं लगाए जाते हैं। इसही कारण कमी पूर्ति पर भी सूचना देना सम्भव नहीं है।

सवाई माधोपुर सब डिवीजन में चीनी वितरण

१४. श्री हरिबल्लभ शर्मा : (सवाई-माधोपुर)—क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) माह अप्रेल, १९६७ में सवाई माधोपुर सब डिवीजन में वितरण हेतु कुल कितनी चीनी का स्टाक उपलब्ध था ?

(२) उक्त कोटे में से सवाई माधोपुर तहसील में अरबन एरिया को कितनी बोरी चीनी दैनिक उपभोग हेतु अलाट की गई तथा ग्रामीण क्षेत्र इस ही तहसील के, को कितनी ?

(३) इस ही प्रकार खण्डार एव बौंली तहसीलों को क्रमशः कितनी कितनी बोरियां चीनी दैनिक उपभोग हेतु अलाट की गई ?

(४) उक्त अलाटमेंट क्रम संख्या (२) तथा (३) के पश्चात् कितना स्टाक सवाई माधोपुर सब डिवीजन हेतु वितरण योग्य शेष रहा ?

(५) खण्डार, सवाई माधोपुर एवं बौंली तहसीलों की क्रमशः जनसंख्या क्या है ?

(६) अप्रेल के कोटे की सवाईमाधोपुर सब डिवीजन की शेष चीनी किस हिसाब से कितने आवेदन-पत्रों पर किस कारण से विशेष परमिटों द्वारा किस किस अधिकारी द्वारा हर तहसील के लिये वितरित की गई ? खण्डार, बौंली एव सवाई माधोपुर तीनों तहसीलों का विस्तृत ब्यौरा देने की कृपा करें ?

उत्तर

१. चीनी का कुल ८९८ क्विन्टल ८५ किलो स्टाक था।

२. अरबन एरिया में ५३१ बोरी व ग्रामीण क्षेत्र में २२५ बोरी चीनी वितरण हेतु अलाट की गई थी।

३. तहसील खण्डार को १७७ बोरी तथा बौंली को २०५ बोरी अलाट की गई थी।

४. अप्रेल के कुल चीनी के स्टाक में से वितरण करने के पश्चात् ७३० क्विन्टल ८५ किलो शेष रही।

५. सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार जनसंख्या निम्न है :—

१. सवाई माधोपुर तहसील	१४०,००३
२. खण्डार तहसील	४५,०००
३. बौंली	८१,४४९

६. माह अप्रेल ६७ में विवाह सम्बन्धी कार्यों के लिये कुल ६४७ आवेदन पत्रों पर विशेष परमिट जारी किये गये :—

१—जिला कार्यालय से	३४८
२—तहसील सवाई माधोपुर से	१९९
३—तहसील खण्डार से	२६
४—तहसील बौंली से	११४

इटावा पंचायत समिति द्वारा कुओं के लिए तकावी

श्री महेंद्रसिंह : (पीपलदा) क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति इटावा द्वारा सन् १९६६-६७ में सिंचाई के लिये कुओं की तकावी दी गई थी ? यदि हाँ, तो कितनी तथा कितने व्यक्तियों को ?

(२) उक्त कुओं में से कितने कुए तैयार हुए तथा कितने अधूरे पड़े हैं ?

(३) कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने तकावी प्राप्त करने के बाद भी कुओं का निर्माण शुरू नहीं करवाया ? नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(४) क्या यह भी सही है कि इस क्षेत्र के कई व्यक्तियों ने पंचायत समिति के प्रधान एवं विकास अधिकारी के जबानी आश्वासन पर कुए खोद लिए हैं ?

(५) क्या यह सही है कि उन व्यक्तियों को कोई तकावी पंचायत समिति द्वारा न मिलने के कारण कुए अधूरे पड़े हैं व उनके इस बरसात में समाप्त होने का अन्देशा है ?

उत्तर

(१) सिंचाई के कुओं के लिए १५७ काश्तकारों को तकावी दी गई।

(२) पूर्ण रूप से कोई भी कूआ तैयार नहीं हुआ। सभी कुओं पर काम चालू है।

(३) ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया।

(४) जी नहीं।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाली पंचायत समिति क्षेत्र में गोचर भूमि

१६. **श्री मूलचन्द डागा** : (पाली) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पाली पंचायत समिति के किन-किन गांवों में गोचर-भूमि मुकर्रर है और कितनी कितनी बीघा और किन किन खसरों में ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या सरकार जिन गांवों में गोचर नहीं है उन गांवों में शीघ्र ही गोचर मुकर्रर कराने की कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

उत्तर

(१) पाली पंचायत समिति के कुल ग्राम ७२ में से आज तक ५३ ग्रामों में गोचर घोषित की जा चुकी है। खसरान व रकबा संलग्न तालिका में व्यक्त हैं।

(२) शेष ग्रामों में जहाँ अभी तक गोचर भूमि घोषित नहीं हुई है, वहाँ शीघ्र गोचर घोषित करने संबन्धी कार्यवाही सम्पूर्ण करने हेतु तहसीलदार पाली व उप जिलाधीश पाली को निजी तौर से निदेश दिये जा चुके हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No. 38

धौलपुर उप जिले से राजस्व आय

१७. **श्री प्रद्युम्न सिंह :** (राजाखेड़ा) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान के कौन कौन से जिलों की राजस्व से होने वाली आमदनी, धौलपुर उप जिले से होने वाली ऐसी आमदनी के बराबर या उससे कम है ?

उत्तर

निम्नलिखित जिलों की राजस्व से होने वाली आय धौलपुर उप जिले से होने वाली आमदनी से कम है:—

१. बाडमेर
२. सिरोही
३. जैसलमेर
३. बीकानेर
५. चूरू
६. बूंदी
७. डूंगरपुर
८. बांसवाड़ा

तहसील निवाई में पेन्डिंग मामले

१८. **श्री जयनारायण सालोदिया :** (निवाई) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील निवाई में हर प्रकार के कितने केस अभी पेन्डिग हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि तहसील में करीब ५-६ सालों से हजारों केस पेन्डिग पड़े हैं और उनमें बार बार पेशियां बदली जाने के कारण सम्बन्धित किसानों को दूर दूर से बार बार अपना काम छोड़ कर आना पड़ता है ?

(३) तहसील निवाई में रोजाना कितने केसों का फैसला किया जाता है ? गत एक साल के आँकड़ों के अनुपात के आधार पर बताने की कृपा करें

उत्तर

(१) तहसील निवाई में तारीख १. ६. ६७ तक निम्न प्रकार के केसेज पेंडिंग हैं:—

(१) धारा ६१ के ३२४३ (२) लावारिश ८ (३) मुतफरिक ८९ (४) पा. डी. आर ३६ इस तरह कुल ३३७८।

(२) तहसील में ५-६ सालों की मुकदमात की स्थिति इस प्रकार है:—

सन	सा० बाकी	दौरान साल रजू	मीजान	दौरान साल फसल	साल के अन्त में बाकी
१९६२	१९	३१०९	३१२८	३११६	१२
१९६३	१२	५७४	५८६	१९५	३९१
१९६४	३९१	१८२१	२२१२	१११	२१०१
१९६५	२१०१	११७९	७२८०	२३३८	४९२२
१९६६	४९४५	६८७८	११८२०	८४४४	३३७६

(श्री राजस्व मन्त्री)

जिन मुकदमात की सुनवाई तहसील हैडक्वार्टर पर की जाती है उन्हीं में ही पार्टीज को पेशी पर आवश्यकतानुसार आना पड़ता है तथा परिस्थिति अनुसार कार्यवाही मुकदमात बदली जाती है। किसानों को अनावश्यक आना जाना नहीं पड़ता है।

(३) तहसील में रोजाना ३० फैसले किये जाते हैं। गत वर्ष के आँकडे इस प्रकार है जिनके अनुपात के आधार पर उपरोक्त तादाद फैसले एक दिवस दर्ज किया गया है:—

जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रेल	मई	जून	जौलाई
१६५	?६०	४२८	२१७	१०५१	–	१०११

अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	कुल
४२१०	६४२	–	–	–	८४४४

साल के ३६ दिन में से ८२ दिन छुट्टियों के बाद देने के पश्चात् प्रतिदिन निर्णीत मामलों की संख्या का औसत ३० रहा।

चन्देरिया स्टेशन, तहसील गंगरार में मकानों का निर्माण

श्री राम कुमार: (चित्तौड़गढ़) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(१) क्या यह सही है कि चन्देरिया स्टेशन, तहसील गंगरार, पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में काफी लम्बे समय से पुराने मकान बने हुए हैं? यदि हाँ, तो कितने?

(२) क्या यह सही है कि पिछले दो तीन साल से वहाँ और भी कई एक मकान अवैधानिक ढंग से बन रहे हैं? यदि हाँ, तो ऐसे मकान कितने बने हैं?

(३) क्या यह सही है कि इन अवैधानिक मकानों के निर्माण के संबंध में कलेक्टर चित्तौड़गढ़ को पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ एवं ग्राम पंचायत पुठोली द्वारा सूचना दी गई है यदि हाँ, तो उस पर कलेक्टर द्वारा क्या एक्शन लिया गया है?

(४ क्या यह सही है कि वहाँ नई आबादी के लिए बिलानाम सरकार काफी भूमि पड़ी है तथा इस भूमि के लिए ग्राम पंचायत द्वारा आबादी में कनवर्ट किये जाने के लिए तहसील गंगरार के मारफत कलक्टर चित्तौड़गढ़ को निवेदन किया है? यदि हाँ, तो क्या यह भूमि आबादी में कनवर्ट करदी गई है? यदि कनवर्ट नही की तो इसके क्या कारण हैं?

(५) क्या यह सही है कि इस भूमि का मौका कलेक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा देखा जा चुका है और इस भूमि के लिये कोई मास्टर प्लान बना है या ऐसी कोई योजना है जिस कारण यह भूमि आबादी में कनवर्ट होने में दिक्कत आ रही है? यदि कोई दिक्कत नहीं तो यह भूमि कब तक कनवर्ट कर दी जावेगी?

उत्तर

ऊत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

पीपलखूंट पंचायत समिति क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य

२०. **श्री बिट्ठल** : (पीपलखूंट) क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति क्षेत्र, पीपलखूंट में १६६२ से अब तक अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत कौन कौन सी सड़कों का निर्माण हुआ है ?

(२) प्रत्येक सड़क का कितने कितने मील का कार्य हुआ और उन पर कितनी कितनी धन राशि खर्च हुई ?

उत्तर

(१) (अ) पंचायत समिति पीपलखूंट क्षेत्र में सन् १६६२ ६३ और १६६३-६४ में कोई भी ग्राम अभावग्रस्त घोषित नहीं हुआ था, अतः इन दो वर्षों में उक्त पंचायत समिति क्षेत्र में अकाल सहायता चलाने का प्रश्न ही नहीं होता है।१६६४-६५ में केवल १० ग्राम अकालग्रस्त घोषित किये गये थे। इन ग्रामों में सड़कों के सहायता कार्य नहीं चलाये गये।

(ब) पंचायत समिति पीपलखूंट में १६६५-६६ एवं १६६६-६७ में अधिक अकाल की स्थिति होने से अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत निम्न सड़कों के सहायता कार्य करवाये गये है:—

(१) दानपुर से घोड़ीतेजपुर

(२) कटुम्बी से पीपलखूंट

(३) दानपुर से फेफर

(४) सोडलपुर से कुशलपुरा

(५) सोडलपुर से सेमलिया

(२) उपरोक्त सड़कों पर निम्नानुसार कार्य हुआ है और उनके सामने अंकित धन राशि खर्च हुई है:—

क्र० सं०	नाम सड़क	कार्य हुआ	रकम खर्च
१.	दानपुर से घोड़ी तेजपुर	१३ मील	१६,७२४-५१
२.	कटुम्बी से पीलखूंट	३० मील	२६,०००-००
३.	दानपुर से फेफर	६ मील	१०,०००-००
४.	सोडलपुर से कुशलपुरा	$\frac{3}{4}$ मील	३,०००-००
५.	सोडलपुर से सेमलिया	$\frac{1}{2}$ मील	३,०००-००

टोंक जिले में अकाल राहत कार्य

२१ श्री **दिग्विजयसिंह** : (उनियारा) क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला टोंक में वर्ष १६६५-६६ में कितने ग्राम रबी व खरीफ में अकालग्रस्त घोषित किए गए ? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) उक्त वर्ष में अकाल सहायता के लिये जिला टोंक के लिये कितनी धनराशि दी गई थी ?

(३) उक्त वर्ष में जिला टोंक में कितने

(श्री दिग्विजयसिंह)

राहत कार्य चालू किए गए ? कृपया उनकी सूची तहसीलवार व मदवार सदन की मेज पर रखें।

(४) उक्त वर्ष में चालू किए गए कार्यों में से कितने कितने कार्य पूर्ण होगए एवं कितने बाकी हैं ? कृपया सूची विभागवार सदन की मेज पर रखें।

(५) क्या जो कार्य चालू किए गए हैं वे नियमानुसार ही किए गए हैं?

उत्तर

(१) सं० २०२२ (सन् ६५-६६) की खरीफ व रबि में टोंक जिले में क्रमशः ७१४ एवं १७१ गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये थे जिनकी सूची तहसीलवार संलग्न है जो सदन की मेज पर रखी गई।

(२) वर्ष ६५-६६ में राज्य सरकार द्वारा टोंक जिले के लिए निम्न प्रकार धन राशि स्वीकृत की गई थी:—

(अ) राहत कार्यों के लिए:—

(i) पी० डब्लू० डी० ४१५०००

(ii) सिंचाई कार्यों २७५६५६

(ब) पेय जल व्यवस्था हेतु ३७६००

(स) निशुल्क सहायता हेतु १००००

(द) राजस्व विभाग के अभिकरण हेतु १००००

(इ) तकावी हेतु १०००००

(३) ३८ राहत कार्य चलाये गये जिनकी सूची संलग्न है जो सदन की मेज पर रखी गई।

(४) ३८ में से ६ राहत कार्य पूर्ण हुए जिनकी सूची संलग्न है जो सदन की मेज पर रखी गई।

(५) जी हां।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

डीडवाना के नमक का आवंटन

२२श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : (किशनपोल जयपुर) क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) सन् १९६५-६६ व ६६-६७ में डीडवाना के नमक का कितने कितने वेगन्स का किन किन को कब कब आवंटन किया गया ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) इन एलाटीज में किन कितने किस किस एलाटमेंट की नियमानुसार एलाटमेंट के १५ दिन की अवधि में नमक की कीमत की २० प्रतिशत धन राशि जमा नहीं कराई ?

किन किन ने एलाटमेंट के अनुसार नियमों के अन्तर्गत ६ माह की अवधि में कितने कितने वैगन नमक उठाया ?

(ग) उपरोक्त दृष्टि से इन नियम भंग करने वालों में से किन किनकी कितनी कितनी सीक्योरिटी जब्त की गई, किन किन को ब्लैक लिस्ट किया गया और किन किन के विरुद्ध

(श्री भैरोंसिह)

अन्य कार्यवाही की गई ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों ?

उत्तर

(क) सन् १९६६ व ६६-६७ में डीडवाना नमक का जिर्नाजन को जब जब आवटन किया गया उसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(ख) इन एलोटीज में जिन जिन ने एलोटमेंट के नियमानुसार १५ दिन की अवधि में नमक की कीमत की २०% धनराशि नहीं जमा कराई उनकी सूची तालिका (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है। एलोटमेंट के नियमानुसार इनका एलोटमेंट रद्द कर दिया गया था। एलोटमेंट के अनुसार जिन जिन ने ६ माह की अवधि में नमक नहीं उठाया उनकी तालिका (ग) सदन की मेज पर रख दी है।

(ग) जैसा तालिका (ग) में बताया गया है जिन जिन एलोटीज ने ६ माह के अन्दर माल नहीं उठाया उनको प्रधान प्रबन्धक ने नियमानुसार एक्सटेनशन दे दी थी एवं उस समय में उन्होंने माल उठा लिया अतः विरुद्ध कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

डीडवाना नमक उत्पादन केन्द्र से
नमक की चोरी

२३. श्री भैरोंसिह शेखावत : (किशनपोल, जयपुर) क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) डीडवाना नमक उत्पादन केन्द्र से सन् ११६२ से लेकर अब तक किस किस वर्ष में कितने कितने नमक की चोरी हुई है ?

(ख) इस चोरी का कितना नमक बरामद हुआ है ?

(ग) इस चोरी के संबन्ध में किन-किन के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(क) कोई चोरी नहीं हुई।

(ख) प्रश्न कभी नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र।

(१२.१० म. प.)

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सतर्कता आयोग का प्रथम प्रतिवेदन (जुलाई, १९६४ से मार्च १९६६ तक) सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट सर्कुलेट होगी या नहीं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह विजिलेंस कमिशन की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी गई है यह सर्कुलेट होगी या नहीं।

श्री अध्यक्ष : होनी चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : जरूर की जायगी, आपकी इच्छा है तो।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था।

Page No. 43

जिला बांसवाडा के अकाल राहत कार्यों में काम करने वाले मजदूरों को वहां के कलेक्टर द्वारा अलग कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हीराभाई ने एक स्थगन प्रस्ताव को सूचना दी है।

अकाल राहत के प्रश्न पर कई बार यह प्रश्न सदन में उठाया जा चुका है अतः मैं इस पर अनुमति नहीं देता परन्तु जिस घटना का उल्लेख श्री हीराभाई ने अपने स्थगन प्रस्ताव में किया है उसके स्पष्टीकरण के लिये मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री महोदय इस पर एक वक्तव्य दें।

२. दिनांक २१-५-१९६७ को ग्राम पंचायत आंबासर, तहसील बीकानेर के सरपंच को वहां के थानेदार द्वारा बिना राज्य सरकार की आज्ञा के हथकड़ी लगाने संबंधी मामले पर श्री जसराज ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस संबन्ध में राज्य सरकार से तथ्यों की जानकारी की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर इस स्थगन प्रस्ताव पर निर्णय दिया जायगा।

३. पशु पालन विभाग द्वारा सिलीसेड, काला खो, सैंथल व बारेठ बन्धों में मछलियों को निकालने का ठेका दिये जाने सम्बन्धी मामले पर श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्त्व का न होने के कारण मैं इस प्रस्ताव पर अपनी अनुमति नहीं देता हूँ।

मैं चाहूँगा कि स्थिति के स्पष्टीकरण के लिये मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

४. गंगानगर जिले में लेवी की वसूली के मामले पर सर्व श्री देवीदत्त गाडिया, वृज वल्लभ बोहरा, प्रेमसिंह, एवं महेन्द्रसिंह ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला ऐसा नहीं है कि जिस पर बहस करने के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित की जाये। अतः मैं इस प्रस्ताव पर अपनी अनुमति नहीं देता।

५. जयपुर गोली काण्ड जांच कमिशन के लिये सरकार द्वारा नियुक्त एडवोकेट्स के सम्बन्ध में श्री रामानन्द अग्रवाल ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इससे पूर्व श्री भैरोंसिंह ने भी इस विषय पर एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

मैं इस मामले को इतना अविलम्बनीय लोक महत्त्व का नहीं समझता कि इस पर बहस करने के लिये सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही स्थगित करदी जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ५ हजार रुपये रोज खर्च हो रहे हैं........

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

माननीय सदस्य इस मामले को सदन में किसी अन्य तरीके से उठा सकते हैं, अतः मैं इन प्रस्तावों पर अपनी अनुमति नहीं देता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट हो जाय। मैंने इस सम्बन्ध में एक शोर्ट नोटिस क्वेश्चन भी दिया था, उसे गवर्नमेंट दबा कर बैठ गई। यह बड़ा महत्त्वपूर्ण मामला है, ५००० रु० रोजाना सरकार का खर्च होता है, ३०००

(श्री सतीशचन्द्र अग्रलाल)

रु० रोजाना वकीलों पर खर्च करते हैं। इस सम्बन्ध में सरकार को कुछ न कुछ स्टेटमेंट देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार के पास गवर्नमेंट एडवोकेट हैं, फिर भी वकीलों पर इतना रुपया खर्च किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जहां जनता पर गोलियां चली हैं, जनता के आदमी मरे हैं, वहां जनता का पक्ष प्रस्तुत करने के लिये सरकार की ओर से कोई वकील मुकर्रर नहीं किया गया है तो इस तरह एक तरफ........

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

मैं सूचना देना चाहता हूँ इस प्रश्न पर शोर्ट नोटिस क्वश्चन है, वह दो तीन दीन में आ जायगा, आप उस पर प्रश्न कर लीजियेगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा प्रश्न है गंगानगर से संबंधित करते हुए कोटा जिले के बारे में क्या... ....

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी।

(१२.१७ म. प.)

मांगों पर विचार

मांग संख्या १६

श्री दामोदरलाल व्यास (चिकित्सा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९ चिकित्सा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष के किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु० ७,११,६४,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या १७

श्री नाथूराम मिर्धा (जनस्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३० जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रू० ६,०४,११,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या ३८

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं कि मांग संख्या ३८ मुख्य शीर्षक ९४ जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को रु० [illegible],३०,५१,००० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : मांगे प्रस्तुत हुई।

इन मांगों पर निम्न लिखित कटोती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए--

मांग संख्या १६

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर)

१. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १०० रुपया कम कर

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

दिया जाय (चिकित्सा विभाग की प्रशासनिक दुर्व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

२. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा विभाग में नियुक्तियों एवं स्थानान्तरण में राजनैतिक दृष्टि से पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

श्री हीरालाल (कुम्भलगढ़)

३. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (देहाती क्षेत्रों के अस्पतालों में डाक्टरों की व्यवस्था लम्बे समय तक नहीं की जाती है, इस संबंध में चर्चा के लिए)।

श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा)

४. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य के अस्पतालों में इक्विपमेन्ट की कमी के कारण होने वाली असुविधा एवं जनता की कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

५. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जायँ (जोधपुर के अस्पताल में बीमारों के रहने के लिये बैड्स की कमी पर चर्चा के लिये।

६. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चिकित्सालयों में सुव्यवस्था करने के सम्बन्ध में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

७. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

श्री मुकुट बिहारीलाल : (बयाना)

(८) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक, २९ चिकित्सा में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (जनरल अस्पताल, भरतपुर के आई विभाग में डाक्टर न होने व E. N. T. विभाग के डाक्टर के सेवा निवृत्ति के बाद स्पेशलिस्ट उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

(९) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९ चिकित्सा में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (कस्बा रुदावल, तहसील रुपवास, जिला भरतपुर, में डाक्टर न भेजने पर चर्चा के लिये)।

(१०) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९ चिकित्सा में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर अस्पताल की स्पेशल स्थिति को देखते हुये 'ए' श्रेणी का घोषित करने पर चर्चा के लिये।

(११) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९ चिकित्सा में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर अस्पताल व जनाना अस्पताल का एकीकरण करके उसको 'B' श्रेणी का घोषित करने पर चर्चा के लिये)।

Page No. 46

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

(१२) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९ चिकित्सा में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कम क्वालीफिकेशन के डाक्टरों को पदोन्नति करने तथा हाई कोर्ट के फैसला हो जाने के बाद उस पर अमल करने पर चर्चा के लिये)।

(१३) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९ चिकित्सा में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (जनरल अस्पताल, भरतपुर, के वार्डों की टट्टियों व नालियों के रुके होने तथा उनसे गन्दगी फैलने से पैदा होने वाली परेशानी पर चर्चा के लिये)।

(१४) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३० जन स्वास्थ्य में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (कस्बा उच्चैन में पेय जल हेतु नल लगाने पर चर्चा के लिये)।

(१५) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३० जन स्वास्थ्य में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (कस्बा धौलपुर में नलों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

(१६) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३० स्वास्थ्य में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (कस्बा बयाना में पेय जल हेतु नल योजना चालू करने पर चर्चा के लिये)।

(१७) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३० जन स्वास्थ्य में से १०० रु० कम कर दिया जाय (भरतपुर शहर में नियमित रूप से पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

(१८) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३० जन स्वास्थ्य में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (कस्बा रूपवास में पीने के पानी की जल प्रदाय योजना चालू करने पर चर्चा के लिये)।

(१९) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३० जन स्वास्थ्य में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (भरतपुर शहर की नहर की सफाई व मरम्मत न होने पर चर्चा के लिये)।

श्री गिरधारीलाल व्यास : (आसीन्द) : (२०) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३० जन स्वास्थ्य में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (गावों में पेय जल के लिये कुएं खोदते हैं उसकी Rates Irrigtion के मुताबिक होनी चाहिये, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : (२१) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९ चिकित्सा में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (राजकीय चिकित्सालयों में मरीजों की भर्ती के संबन्ध में दोष पूर्ण पद्धति पर चर्चा के लिए)।

(२२) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९ चिकित्सा में से १०० रुपये कम कर दिया (अलवर जनरल अस्पताल में मरीजों के लिए व्यवस्था में कमियों पर चर्चा के लिए)।

(२३) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक

Page No. 47

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

२९ चिकित्सा में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (अस्पतालों में मरीजों को दाखिल करने में अपनाए जा रहे अनुचित तरीकों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

(२४) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (अलवर वाटर वर्क्स में पानी की आवश्यक बढ़ोतरी करने में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ३८

(२५) मांग संख्या ३८ मुख्य शीर्षक ६४—जन—स्वास्थ्य-सुधार पर पूंजी की लागत में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (पानी के मीटर्स सप्लाई करने में राज्य सरकार की असमर्थता के कारण जनता को तकलीफ पर चर्चा के लिये)।

(२६) मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६४—जन-स्वास्थ्य-सुधार पर पूंजी की लागत में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अलवर वाटर वर्क्स के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

श्री रावत राम (छापर)

(२७) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १७

(२८) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन-स्वास्थ्य में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (कस्बा बीदासर—छापर चाड़वास की जल प्रदाय योजना पर चर्चा के लिये)।

(२९) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन-स्वास्थ्य में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन के सम्बन्ध में विचार करने पर चर्चा के लिये)।

(३०) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन-स्वास्थ्य में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (चूरू जिले की ग्रामीण जल प्रदाय योजना पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

श्री भीम सेन (लूनकरणसर)

(३१) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (बीकानेर चिकित्सालयों के ऑपरेशन थियेटर्स को वातानुकूलित कराने पर चर्चा के लिए)।

(३२) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (पूर्व नापासर डिस्पेंसरी का पंचायत समिति, बीकानेर को स्थानान्तरण करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

(३३) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन-स्वास्थ्य में से १०० रुपये कम

(श्री भीमसेन)

कर दिया जाय (गांव कानोंनाई, शेरपुरा (तहसील लूण करणसर व मूंडसर, रामसर, पेमासर (तहसील बीकानेर की देहाती जल: योजनाएं स्वीकृत करने पर चर्चा के लिए) ।

(३४) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन-स्वास्थ्य में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (भिखमंगों एवं लाइलाज छूत की बीमारी वाले लोगों का Compulsory Sterilisation करने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३८

(३५) मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ९४—जन-स्वास्थ्य-सुधार पर पूंजी की लागत में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (गांव नोरंगदेसर व वमलू में पेयजल हेतु व्यवस्था में विलम्ब पर चर्चा के लिये

मांग संख्या १६

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद)

(३६) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (नसीराबाद में 'बी' ग्रेड चिकित्सालय खोलने पर चर्चा के लिये) ।

(३७) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (साधारण मजदूर—किसान को सुलभ व सस्ती चिकित्सा नहीं मिलती, इस पर चर्चा के लिये) ।

(३८) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (दवाइयां चिकित्सालयों में उपलब्ध करने में घोटाले व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए) ।

(३९) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (क्षय रोग के चिकित्सालयों में खाटों का कोटा बढ़ाने व मरीजों को विशेष राहत देने पर चर्चा के लिए) ।

(४०) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९ चिकित्सा में से १०० रुपया कम कर दिया जाय दवाखानों के अभाव में विदेशी मिशनरीज द्वारा निजी दवाखानों से दवा दिलवा कर धर्म परिवर्तन की कार्यवाहियां करने पर चर्चा के लिये) ।

(४१) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (क्षयरोग, हृदयरोग एवम् ६५ वर्ष से ऊपर आयु वालों को चिकित्सा सुविधाएं देने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १७

(४२) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम जल प्रदाय योजना की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

(४३) मांग संख्या १७ मुख्य शीर्षक ३०-जन- स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अपूर्ण योजनाओं से शुद्ध पीने का पानी प्राप्त नहीं होने से स्वास्थ्य की गिरावट पर चर्चा के लिये) ।

Page No. 49

(श्री विजयसिंह रावत)

(४४) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०--जन--स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गाँवों में प्रसूति एवं शिशु कल्याण केन्द्र के अभाव में डिलीवरी के समय ग्रामीण महिलाओं के प्राण संकट में रहने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर):

(४५) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९--चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बाड़मेर नगर की जनता को उचित चिकित्सा सुविधा दिलाने में सरकार की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

(४६) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (डॉक्टरों द्वारा झूठे प्रमाण-पत्र एवं झूठी इन्जरी रिपोर्ट देकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

(४७) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०--जन--स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था करने में सरकार द्वारा घोर उपेक्षा की गई है, इस पर चर्चा के लिये)।

(४८) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०--जन स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बाड़मेर नगर में पेय जल की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

(४९) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०--जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बाड़मेर में ग्रामीण क्षेत्र में पेय जल की समस्या के प्रति सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

श्री मोतीलाल (खेरर):

(५०) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९--चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सिरोही सरकारी अस्पताल में आवश्यक सुधार एवं उचित व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन)

५१. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन- स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (असनावर में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में दवाईयों आदि पर चर्चा के लिये)।

५२. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन- स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (रटलाई में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर नहीं खोले जाने पर चर्चा के लिये)।

५३. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बकानी में ग्रामीण जल योजना पेय जल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

श्री कल्याणमल (जहाजपुर):

५४. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १०० रुपया कम कर

Page No. 50

(श्री कल्याणमल)

दिया जाय (जहाजपुर क्षेत्र में सेरगढ़ में आयुर्वेदिक औषधालयों में दवाइयों की व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) :

५५. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (शफाखानों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण बीमारों की देख रेख ठीक से नहीं होती है, इस पर चर्चा के लिए)।

५६. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शफाखानों में दवाओं के अभाव पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

५७. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नगरपालिका क्षेत्र निवाई में जल योजना लागू करने में देरी पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

५८. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (हॉस्पीटलों व छोटे अस्पतालों की अव्यवस्था के कारणों पर चर्चा के लिये)।

५९. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को जो चिकित्सा सुविधा दी गई है उसका दुरुपयोग व उस सम्बन्धी भारी खर्चों पर चर्चा के लिए)।

६०. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (डॉक्टरों द्वारा झूठे सर्टीफिकेट देने पर चर्चा के लिए)।

६१. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय [बांगेड़ (पाली) अस्पताल में अच्छे सर्जन व Eye Specialist की व्यवस्था पर चर्चा के लिए]।

६२. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बड़े बड़े अस्पतालों में सभी रोगियों के लिए एकसी सेवा की व्यवस्था होनी चाहिये, इस पर चर्चा के लिए)।

६३. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली हॉस्पीटल में पानी की अव्यवस्था व अन्य अव्यवस्थाओं के कारणों पर चर्चा के लिये)।

६४. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (डॉक्टरों को प्राइवेट Practice करने की इजाजत नहीं होनी चाहिये, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

६५. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर

(श्री मूलचन्द डागा)

दिया जाय (पाली पंचायत समिति में गांव खेरवा में जल प्रदाय योजना लागू करने हेतु चर्चा के लिये)।

६६. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००, रु० कम कर दिया जाय (जिला पाली के गाँवों में पीने के पानी की कमी पर चर्चा के लिये)।

६७. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००, रु० कम कर दिया जाय (पाली तहसील के गाँवों में नारू की बीमारी से छुटकारा दिलाने पर चर्चा के लिये)।

६८. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (पाली की जल प्रदाय योजना की अक्षमता एवं उसकी कमियों पर चर्चा के लिये)।

६९. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००, रुपया कम कर दिया जाय (गाँव जैतारण तहसील पाली के तालाब का पानी पीने से बीमारियाँ फैलती हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

७०. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००, रुपया कम कर दिया जाय (पाली तहसील के गाँवों में पीने के पानी की व्यवस्था करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या ३८

७१. मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ९४-जन-स्वास्थ्य-सुधार पर पूंजी की लागत में से १००, रुपया कम कर दिया जाय (पाली शहर में Drainage Scheme चालू न करने के कारण गंदगी के भारी फैलाव पर चर्चा के लिये)।

७२. मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ९४-जन-स्वास्थ्य-सुधार पर पूंजी की लागत में से १००, रुपया कम कर दिया जाय (पाली की Water Supply Scheme शहर की आज की मांग को पूरी करने में असमर्थ है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) :

७३. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००, रुपया कम कर दिया जाय (सुजानगढ़ जल प्रदाय योजना अधूरी पड़ी है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) :

७४. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००, रुपया कम कर दिया जाय (गांवों में मनुष्य और मवेशियों के लिये पीने का पानी नहीं मिल रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़)

७५. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सालय के अन्तर्गत इस माँग को घटा कर एक रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा की नीति में परिवर्तन करने के बारे में नीति का अनुमोदन)।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल) :

७६. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अस्पतालों में मरीजों के लिए पलंग आदि का समुचित प्रबन्ध नहीं होने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १७

७७. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जयपुर में विशेष तौर से पुरानी बस्ती में जल वितरण व्यवस्था की ओर राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के के लिये) ।

श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी) :

७८. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गुल्ताना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला झुन्झुनू में ७ वर्ष से डाक्टर न होने से स्वास्थ्य केन्द्र की कोई उपयोगिता न होने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १६

श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) :

७९. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (डिस्पेन्सरी मांढन, नीमराना बहरोड़ में दवाइयों और चिकित्सकों का पूर्ण अभाव, है इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १७

८०. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय [कुतीना, गिगलाना, रोडवाल (तहसील बहरोड़, जिला अलवर) में नल योजना चालू करने एवं मांढन नीमराना, बहरोड़ में नल योजना चालू होने के बावजूद भी पानी न मिलने पर चर्चा के लिये] ।

श्री चुन्नीलाल (नोखा)

८१. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पांचू के पेयजल के कुएँ पर पानी दिलाने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

८२. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बेरासर के पेयजल के कुए पर पानी दिलाने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

८३. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (उदासर के पेयजल के कुए पर पानी दिलाने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

८४. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नोखा मण्डी के पेयजल के कुए पर पानी दिलाने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १६

श्री फतहसिंह (ब्यावर) :

८५. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर

(श्री फतहसिंह)

दिया जाय (बड़ा खेड़ा गांव के एक आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

श्री खेतसिंह (शेरगढ़)

८६. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चिकित्सा महा-विद्यालय जोधपुर की अव्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

८७. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (आयुर्वेदिक औषधालयों में औषधियों की कमी पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १७

८८. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन स्कीम की असफलता पर चर्चा के लिये)।

८९. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (समस्त्रेशो नल कूप रेगिस्तानी इलाकों खास तौर से शेरगढ़ क्षेत्र में खोदने की चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

श्री रामकिशन (वैर) :

९०. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चुनावों में खोले गये अस्पताल तथा एड-पोस्ट्स पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १७

९१. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन के लिए उचित वातावरण तैयार करने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये)।

९२. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कस्बा वैर में पीने के पानी की कमी पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

श्री केदरनाथ (गंगानगर) :

९३. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गंगानगर शहर में सरकारी होस्पिटल की अव्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) :

९४. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला जालोर में चिकित्सा की व्यवस्था में सरकार की उदासीनता के बारे में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १७

९५. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला जालोर के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के बारे में चर्चा के लिये।

Page No. 54

मांग संख्या १६

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर)

६६. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भरतपुर के जनरल अस्पताल को अ. (प्रथम) श्रेणी के अस्पताल में न करने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिए)।

६७. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भरतपुर अस्पताल में नर्सों को निःशुल्क आवास व्यवस्था के प्रावधान के बावजूद उनकी पूरी मंहगाई भत्ता किराये के रूप में काटे जाने के कारण व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १७

६८. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भरतपुर शहर में पेय-जल की विकट समस्या से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) :

६६. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर अब तक डिस्ट्रिक्ट हास्पीटल न बनाये जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १७

१००. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील हैडक्वार्टर खण्डार में अब तक वाटर वर्क्स नल-योजना पूरी न कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

१०१. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन—स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय [संप-शहर, (तहसील बामनवास नादोती) में पेय पानी की व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये]।

मांग संख्या १६

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) :

१०२. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चिकित्सालयों में पूरी दवाइयां उपलब्ध नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

१०३. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (उदयपुर जिले के वाटर वर्क्स ओफिस की दुर्व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

श्री श्रवण लाल (हिण्डौन) :

(१०४) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य के ग्रामीण व कस्बों के चिकित्सा केन्द्रों पर दवाई उपलब्ध करने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

(श्री श्रवणलाल)

१०५. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १००, रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान की जनता को रोग से छुटकारा दिलाने के लिये अच्छे डाक्टर व नर्सेज होस्पीटल्स में भेजने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

१०६. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १००, रु० कम कर दिया जाय (हिन्डौन में जनता को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा दिलाने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १७

१०७. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००, रु० कम कर दिया जाय (वाटर सप्लाई स्कीम्स, जो स्वीकृत की गई हैं, उन्हें पूरी कराने पर चर्चा के लिये)।

१०८. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०--जन--स्वास्थ्य में से १००, रु० कम कर दिया जाय (हिन्डौन शहर की नल योजना के स्वीकृत होने पर भी कार्य चालू करने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

१०९. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०--जन--स्वास्थ्य में से १००, रु० कम कर दिया जाय (हिन्डौन शहर के जल-संकट को दूर करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

(११०) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन—स्वास्थ्य में से १००, रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में परिवार नियोजन व लूप पद्धति को कार्य में लाने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

१११. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन—स्वास्थ्य में से १००, रु० कम कर दिया जाय (जिला सवाई माधोपुर की अधिकांश तहसीलों में जल-संकट को दूर करने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

११२. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन—स्वास्थ्य में से १००, रु० कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल दिये जाने की सुव्यवस्था के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

११३. माँग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन—स्वास्थ्य में से १००, रु० कम कर दिया जाय (जिला सवाई माधोपुर में चेचक रोग की रोक थाम में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

११४. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन—स्वास्थ्य में से १०० रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में पीने का पानी का मुहैया करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

श्री देवीदत्त गड़िया (बारां)

११५. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १००, रु० कम कर दिया जाय (बारां अस्पताल में सुयोग्य डाक्टर के न होने तथा दवाइयों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

Page No. 56

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

मांग संख्या ७

११६. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन—स्वास्थ्य में से १००, रु० कम कर दिया जाय (पेयजल योजना को लागू किये जाने में किये गये पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

११७. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन—स्वास्थ्य में से १०० रु० कम कर दिया जाय (बारां नगर में पेयजल योजना लागू किए जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

श्री हीरा (कुशलगढ़) :

११८. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १०० रु० कम कर दिया जाय (गरीब मरीजों को मुफ्त दवाइयों की व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) :

११९. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १००, रु० कम कर दिया जाय (कोटा भीमसिंह अस्पताल में बेड्स बढ़ाने के बारे में चर्चा के लिए)।

१२०. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १००, रु० कम कर दिया जाय (जन-साधारण को चिकित्सा का सीधा फायदा न मिलने पर चर्चा के लिये)।

श्री केसरी सिंह (हिण्डोली) :

१२१. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १०० रु० कम कर दिया जाय (बूंदी राजकीय चिकित्सालय में १९४७ से कोई उन्नति नहीं हुई तथा एक भी रोगी शैया में वृद्धि न करने पर चर्चा के लिये)।

१२२. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १००, रु० कम कर दिया जाय (जयपुर राजकीय जनाना चिकित्सालय में अपर्याप्त स्टाफ होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

१२३. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १००. रु० कम कर दिया जाय (सवाई मानसिंह अस्पताल के कर्मचारियों के मेडिकल के बिलों पर अनावश्यक रोड़े अटकाने एवं समय पर उन्हें पास न करने के बारे में चर्चा के लिये)।

१२४. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १००. रु० कम कर दिया जाय (शासकीय आदेश होने पर भी नर्सिंग स्टाफ से प्रतिदिन ८ घन्टों से अधिक कार्य लेने पर एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउन्स न देने पर चर्चा के लिये)।

१२५. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १०० रु० कम कर दिया जाय (बड़े-बड़े डाक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रेक्टिस को तरफ ज्यादा ध्यान देना और

Page No. 57

(श्री केसरीसिंह)

सामान्य ड्यूटी की परवाह न करने के बारे में चर्चा के लिये) ।

१२६. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मेडिकल कॉलेज से सम्बन्धित हाउस जोब करने वाले डाक्टरों द्वारा बिना किसी अवकाश के रात-दिन ड्यूटी देने के कारण C A S. ग्रेड का स्टाईपेण्ड देने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १७

१२७. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (हिन्डोली ग्राम व नैन...ा में जल प्रदाय योजना के उद्घाटन के पश्चात् कोई भी कार्य न होने पर चर्चा के लिये) ।

१२८. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन--स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कापरेन प्राइमरी हैल्थ सैन्टर के भवन चिकित्सा विभाग द्वारा निर्माण न कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१२९. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन—स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्राइमरी हैल्थ सैन्टर कापरेन में दवाइयों व डाक्टर की सुव्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये ।

१३०. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन--स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जा. (सरकार की परिवार नियोजन योजना की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १६

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) :

१३१. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (उनियारा अस्पताल जिला टोंक में मरीजों की संख्या देखते हुए कम्पाउण्डरों एवं अधिक बैड्स की व्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १७

१३२. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (उनियारा कस्बे के लिये नल योजना स्वीकार होने पर भी आज दिन तक उसका कार्य चालू न करने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३८

१३३. मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ९४-जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (उनियारा कस्बे के लिए नल योजना राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत होते हुए भी उस सम्बन्धी कार्य न होने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १६

श्री सहदेव (आमेर) :

१३४. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९ चिकित्सा में से १००) रु० कम कर

Page No. 58

(श्री सहदेव)

दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों के औषधालयों में औषधियों की समुचित व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १७

१३५. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में राज्य सरकार द्वारा चलाई गई परिवार नियोजन योजना के अन्तर्गत फोलो-अप की व्यवस्था के अभाव पर चर्चा के लिये)।

१३६. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा) :

१३७. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया दिया जाय (कस्बा दौसा में लेडी डाक्टर के अभाव पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १७

१३८. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कस्बा दौसा में पीने का पानी कम मिलने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर) :

१३९. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सामें से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर शहर के वार्ड नं० २० के बीच में टी० बी० क्लीनिक है, इसे बस्ती से हटाकर बाहर दूर ले जाया जाये, इस पर चर्चा के लिए)।

१४०. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर शहर के पुरानी बस्ती के वार्ड नं० १ से ४ तथा ७ से ११ तथा १८ से २१ तक की करीब ७० हजार की आबादी के लिये कोई औषधालय व डिस्पेंसरी नहीं है, अतः डिस्पेन्सरी खुलवाई जाय, इस पर चर्चा के लिए)।

१४१. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर अस्पताल में ब्लड बैंक द्वारा निर्धारित रेट से १० गुना ज्यादा कीमत लेकर बीमारों को खून दिया जाता है, इस अव्यवस्था व अनैतिकता को रोकने पर चर्चा के लिए)।

१४२. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर हॉस्पीटल में जो दवाइयों स्टाक में रहती हैं, वह भी वार्ड में भर्ती हुए गरीबों को नहीं दी जाकर उन्हें बाहर से खरीदने को कहा जाता है इस पर चर्चा के लिए)।

१४३. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

दिया जाय (बीकानेर हास्पीटल में आने वाले बीमारों को डाक्टर घर पर देखने के लिये बुलाते हैं, इस पर चर्चा के लिए)।

१४४. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर होस्पीटल में बीमारों की देख रेख में बरती जाने वाली लापरवाही के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार)

१४५. मांग संख्या, १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा की जाने वाली खरीद में अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १७

१४६. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन—स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में पीने के पानी की समस्या पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

श्रीमती सुमित्रा (झुन्झुनूं)

१४७. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भगवानदास खेतान राजकीय चिकित्सालय, झुन्झुनूं में पंखों के अभाव पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १७

१४८. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन—स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्रामीण जनता के लिये पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

श्री पी०के० चौधरी (फुलेरा) :

१४९. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया दिया जाय (ग्राम भोजपुरा में डिस्पेंसरी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

१५०. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९–चिकित्सा में से १००) रु० कम कर जाय (ग्राम भोजपुरा तथा कालख तहसील फुलेरा में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३८

१५१. मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६४-जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कस्बा जोबनेर में जल प्रदाय योजना के शीघ्र क्रियान्वयन के बारे में चर्चा के लिये)।

१५२. मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६४-जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील फुलेरा में मंडा भीमसिंह और भैंसलाना में जल प्रदाय योजना के शीघ्र क्रियान्वयन के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

श्री देवीलाल (मराड़ा) :

१५३. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९ चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया

(श्री देवीलाल)

जाय (ग्राम सेमारी, तहसील सराड़ा, में आयुर्वेदिक औषधालय को 'बी' श्रेणी में परिवर्तित किये जाने पर चर्चा के लिये)।

१५४. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९ चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में आदिवासी पिछड़े क्षेत्र में आयुर्वेदिक औषधालय खोला जाये, इस पर चर्चा के लिये।)

१५५. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा, नटाराकीपाल, खरबर थाना में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १७

१५६. माँग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में हैल्थ सेन्टर झाडोल में लम्बे समय से डॉक्टर नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

माँग संख्या १६

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा) :

१५७. माँग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कोटड़ा गोगुन्दा तहसील, जिला उदयपुर की डिस्पेन्सरियों में दवा की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

माँग संख्या १७

१५८. माँग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन स्वास्थ्य में से १००) रु०कम कर दिया जाय (ऋषभदेव प्राइमरी हेल्थ सेन्टर में दवाइयों का बजट बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

माँग संख्या १६

श्री विद्यासागर (खेरवाड़ा) :

१५९. माँग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (खेरवाड़ा तहसील, जिला उदयपुर की डिस्पेन्सरी में दवाइयों की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री शिवचरणसिंह (महुआ) :

१६०. माँग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य में चिकित्सा सुविधाओं के बँटवारे में असमानता पर चर्चा के लिये)।

श्री सांवरमल बासोतिया (नवलगढ़) :

१६१. माँग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९ चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजकीय अस्पताल नवलगढ़ में लेडी डॉक्टर के न होने पर चर्चा के लिये)।

१६२. माँग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नवलगढ़ सरकारी अस्पताल में लेडी डॉक्टर व अन्य स्टाफ आदि की कमी पर चर्चा के लिए)।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) :

१६३. माँग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अस्पतालों में बीमारों को दवाइयां

Page No. 61

(श्री पृथ्वीसिंह)

मिलने के सम्बन्ध में कठिनाइयों पर चर्चा के लिये) ।

१६४. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १०० रु० कम कर दिया जाय (सादड़ी महिला चिकित्सालय में महिला डॉक्टर की नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १७

१६५. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (खाद्य सामग्री में मिलावट पर नियंत्रण करने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

१६६. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सड़ी गली वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगाने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १६

श्री रामकुमार (चित्तौडगढ़) :

१६७. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९ चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चित्तौड़ रेफरल होस्पिटल की व्यवस्था ठीक किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

१६८. मांग संख्या १६ मुख्य शीर्षक २९ चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय(चितोड़गढ़ जिले में अन्य जिलों की अपेक्षा डॉक्टर कम हैं तथा कई अस्पताल बिना डॉक्टर के चल रहे हैं, इस पर चर्चा के लिये)

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) :

१६९. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कस्बा नोहर में डिस्पेन्सरी को अस्पताल के रूप में परिवर्तित किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

(१७०) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कस्बा नोहर में जनाना अस्पताल नहीं है जिससे जनता को बड़ा कष्ट है, इस पर चर्चा के लिये) !

मांग संख्या १७

१७१. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र, जिला श्री गंगानगर में पानी पीने की डिग्गी P.W.D. की मारफत बन रही है उन डिग्गियों में पानी नहीं ठहर रहा है, इस पर चर्चा के लिये) ।

१७२. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील नोहर के बारानी इलाके गांवों में एवं नोहर कस्बे में पीने का पानी खारा है । अतएवं उन गांवों को राजस्थान नहर से पानी दिया जावे, इस पर चर्चा के लिये) ।

१७३. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील नोहर के गांव पांडुसर का वाटर वर्क्स ३ साल से बन्द पड़ा है व

(श्री रामचन्द्र आर्य)

जनता पानी के अभाव में भारी कष्ट उठा रही है उसे सरकार द्वारा चालू करवाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

श्री महेन्द्रसिंह (पीपलदा) :

१७४. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टर, नर्सेज व औषधालयों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

१७५. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (औषधालयों में डाक्टर्स व कम्पाउन्डरों द्वारा बरती जाने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

१७६. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (औषधालयों में दवाइयों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

१७७. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों द्वारा बरती गई लापरवाही के कारण की जा रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

१७८. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सालयों में दवाइयों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

१७९. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सालयों व चिकित्सकों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री रामचन्द्र (खण्डेला) :

१८०. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सीकर अस्पताल में एक दम अव्यवस्था है इस पर चर्चा के लिये)।

१८१. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (आयुर्वेदिक औषधालय आवश्यकता के आधार पर न खोल कर राजनैतिक आधार पर पक्षपातपूर्ण तरीके से खोले जाते हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

१८२. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्रामों में पीने के जल की समस्या को हल करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

श्री नन्दलाल (किशनगंज) :

१८३. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम लाखेरी में चिकित्सालय की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्रीमति मदन कौर (पचपदरा)

१८४. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चिकित्सालयों में पर्याप्त स्टाफ और दवाइयां उपलब्ध नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

१८५. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बाड़मेर के अस्पताल में लेडी डाक्टर की नियुक्ति नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

१८६. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में परिवार नियोजन की उचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

श्री किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा):

१८७. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग की आन्तरिक कार्य प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा):

१८८. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (झुंझुनूं में D.M.H.O. का कार्यालय खोले जाने पर चर्चा के लिये)।

१८९. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (घमोरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं में डिस्पेन्सरी खोले जाने पर चर्चा के लिये)।

१९०. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अस्पतालों में दवाइयों की कमी तथा अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार पर चर्चा के लिये)।

१९१. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी कर्मचारियों को Medical Bills का रुपया नहीं दिया जाकर Medical सुविधाओं के लिये निश्चित राशि तय करने पर चर्चा के लिये)।

१९२. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा झुंझुनूं जिले की चिकित्सा सुविधाओं की दृष्टि से अवहेलना किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

१९३. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय [आपोली तथा भौडे के ग्रामों (जिला झुंझुनूं) में Water Supply scheme चालू करने पर चर्चा के लिये]।

मांग संख्या १६

श्री बृजप्रकाश (हनुमानगढ़)

१९४. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर

Page No. 64

(श्री बृजप्रकाश)

दिया जाय (हनुमानगढ़ में 'A' क्लास अस्पताल की कमी पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

१९५. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (हनुमानगढ़ जंक्शन मण्डी क्षेत्र में इकट्ठे हो जाने वाले पानी को निकालने के लिये Drainage का प्रबन्ध करने पर चर्चा के लिये)।

१९६. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय [डबली जंडावली पक्का सारणाम व लालगढ़ गांवों (जिला गंगानगर) में पेयजल योजनाओं पर कार्य शुरु करने में देरी पर चर्चा के लिये]।

१९७. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सादूल शहर भादरा मण्डी में पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं होने से जनता की कठिनाइयों पर चर्चा के लिए)।

१९८ मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (हनुमानगढ़ टाउन तक हनुमानगढ़ जंक्शन मण्डी की वाटर सप्लाई योजना में पाइप लाइन डालकर पीने के पानी के प्रबन्ध पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १६

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) :

१९९ मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (योगिक केन्द्र, जयपुर के कार्य में सुधार के प्रस्ताव पर सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

२००. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम हमीरपुर, तहसील बानसूर जिला अलवर में निर्माण किये हुए वाटर वर्क्स को चालू करने में विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

श्री आलम अली (फतेहपुर) :

२०१. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (फतेहपुर, जिला सीकर तथा अन्य गांवों में राजकीय डिस्पेन्सरियों के अभाव तथा डिस्पेन्सरीज में दवाई के अभाव से उत्पन्न कनाइयों पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती कान्ता खतूरिया (कोलायत) :

२०२. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चिकित्सा महाविद्यालयों को चलाने निमित्त आयोजन के धनराशि के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

श्री जुझारसिंह (रामगंजमंडी) :

२०३. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (आंवा प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में मकान व डाक्टर की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये)।

(श्री जुझारसिंह)

२०४. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (रामगंज मण्डी नल योजना का कार्य जानबूझकर चालू नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

२०५. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा सांगोद नल योजना चालू नहीं कर सकने पर चर्चा के लिये)।

श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) :

२०६. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बिचून के प्राइमरी हैल्थ सेन्टर की व्यवस्था को सुधारने पर चर्चा के लिये)।

२०७. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्राइमरी हैल्थ सेन्टर बिचून के भवन का निर्माण नहीं होने व सब सेंटरों का कार्य शुरु नहीं करने से बिमारों को दवा नहीं मिलती, इस पर चर्चा के लिये)।

२०८. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (दूदू तहसील मे सहस्रों बच्चों की चेचक से मृत्यु पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३८

२०९. मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ९४-जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नल योजना स्कीम में नरेना में नल योजना की नींव लगाकर कार्य शुरू नहीं किया, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना) :

२१०. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र डेगाना की शोचनीय दशा पर चर्चा के लिये)।

२११. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कई गांवों में ट्यूब वेल्स खोद कर भी पम्पों की व्यवस्था न करने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री शिवचरण माथुर (मांडल) :

२१२. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केन्द्रों में डाक्टर्स के नितान्त अभाव के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री शंकरलाल (जैतारण) :

२१३. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले में जल प्रदाय योजनाओं के निर्माण में अन्य पर चर्चा के लिये।

श्री आदित्येन्द्र (डीग) :

२१४. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर

(श्री आदित्येन्द्र)

दिया जाय (डीग के कस्बा में स्थित तालाबों की सफाई व मरम्मत न होने व उनमें पानी की कमी से पैदा हुई स्थिति पर चर्चा के लिये)।

२१५. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कस्बा डीग में चुनाव के दौरान मुख्य मन्त्री द्वारा जल प्रदाय योजना का शिलान्यास करने पर भी उसका काम शुरु न करने पर चर्चा के लिये) ।

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) :

२१६. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बढ़ते हुये रोगों के उन्मूलन में सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री लक्ष्मणसिंहजी ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा के सम्बन्ध में मेरा कटौती प्रस्ताव सदन के समक्ष रखते हुए निवेदन करता हूँ कि मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा । सर्व प्रथम मैं मन्त्री महोदय का ध्यान नसीराबाद के अस्पताल की ओर आकर्षित करना चाहूँगा । जो जानकारी मुझे मिली है, उसके अनुसार नसीराबाद जैसे एक महत्वपूर्ण शहर के अन्दर अस्पताल जो है उसमें केवल मात्र २ बेड्स की व्यवस्था है। नसीराबाद की जनसंख्या २७ हजार है और कम से कम ब्यावर और किशनगढ जो पड़ोस में हैं, नसीराबाद के महत्व को अगर इन दोनों शहरों के मुकाबले में सरकार के ध्यान में लाया जाय तो नसीराबाद का महत्व भी किसी हालत में कम नहीं है और माननीय सदस्य जो नसीराबाद से आये हुए हैं, वे विशेष रूप से इस सम्बन्ध में निवेदन करेंगे पर मैं समझता हूँ कि अस्पताल का अभाव, चिकित्सा का अभाव नसीराबाद महसूस कर रहा है, उस पर मैं सरकार का ध्यान पुरजोर तरीके से आकर्षित करना चाहूँगा ।

इसके साथ ही साथ निवेदन है कि डूंगरपुर एक पुराना कस्बा है और पहाड़ों से तीन ओर से घिरा हुआ है। आबादी बढ़ने के कारण लोग पहाड़ में से पत्थर निकालते हैं और पत्थर खोदने के कारण मिट्टी बिखरती है और वह बिखरी हुई मिट्टी, वर्षा होती है तो वर्षा के पानी के साथ बह कर शहर में फैल जाती है । हर साल यह कूड़ा कर्कट, मलबा, सारे शहर में फैल जाता है, उसे उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उठाने में समय भी बहुत लगता है और खर्चा भी बहुत अधिक लगता है । मैं यह अनुभव करता हूँ कि आज राजस्थान के अन्दर जो दुष्काल की परिस्थिति है, और यह बजट जिस समय आया है उसे ध्यान में रखते हुए मैं यह तो निवेदन नहीं करता कि डूंगरपुर में ड्रेनेज या नाली की व्यवस्था तुरन्त करने के लिये अर्ज करूं, मेरा सुझाव है कि आयन्दा बजट में इसके लिये व्यवस्था करें और शहर के उत्तरपूर्वी भाग में एक्सपेरिमेन्टल बेसिस पर अगर यह ड्रेन ८० हजार या लाख रुपया खर्च कर के खुदवायें तो सारी सड़के जो शहर में सीमेंट की हैं, वे खराब नहीं होंगी, टूटेंगी नहीं, अस्पताल के पास मलबा नहीं

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

भरेगा, गरीब और आदिवासी बस्तियों में जो कूड़ा कर्कट, मिट्टी, पत्थर हर साल वह कर आ जाता है, वह भी नहीं आयेगा और एक्सपेरिमेंट कर के, आजमायश कर के देखें कि अगर यह स्कीम उत्तर र्वी हिस्से में सफल होती है तो फिर पश्चिमोत्तर हिस्से में भी यही व्यवस्था करें।

जब डूंगरपुर में १ करोड़ से अधिक अकाल के सम्बन्ध में खर्च किया है और अधिकांश आदिवासियों के ऊपर खर्च किया है तो मेरा विनम्र निवेदन है कि डूंगरपुर शहर के लिये भी उसका १०० वां हिस्सा भी खर्च करें तो कोई अधिक नहीं होगा।

दूसरी बात में यह निवेदन करना चाहूँगा कि पुराने जमाने से डूंगरपुर के अस्पताल में लेडी डाक्टर का क्वार्टर ही डाक्टर यानि भक्त डाक्टर ने लेडी डाक्टर के क्वार्टर को ओक्यूपाई कर रखा है। वहां डाक्टर अवश्य रहे रात को पर वहां लेडी डाक्टर का रहना भी आवश्यक है। इसमें तो आपको एक पैसा भी खर्च करने की बात नहीं है। केवल व्यवस्था ही करनी है। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करके निवेदन करूंगा कि लेडी डाक्टर का क्वार्टर लेडी डाक्टर के रहने के लिये बनाया गया है, उसका उपयोग लेडी डाक्टर को रहने की इजाजत दे कर करना चाहिये। यह व्यवस्था करें तो लेडी डाक्टर की कमी है वह पूरी होगी।

मैंने यह सुना है, निश्चित रूप से तो मैं नहीं कह सकता, एक डाक्टर महोदय हैं जो पी० एम० ओ० तो नहीं हैं दूसरे डाक्टर हैं उनके बारे में मेरे पास काफी शिकायतें आयी हैं। उनका व्यवहार इस प्रकार का है कि किसी भी व्यक्ति को एडमिट करने से पहले एक तरह से उनका नजराना बन्धा हुआ है, जो वह माँगते हैं। जब उनको नजराना दे दिया जाता है तब वे एडमिट करते हैं। जब यहां पर केअर टेकर गवर्नमेंट थी मैंने उसका इस ओर ध्यान आकर्षित किया था। जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ यहां जो एडमिनिस्ट्रेटर्स आये उनका भी ध्यान आकर्षित किया गया। कहां तक यह कहना ठीक है, सुना था डाक्टर महोदय के तबादले के आर्डर्स हो चुके हैं। लेकिन उत्तरदायी सरकार के स्थापित हो जाने के बाद उनका तबादला स्थगित हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ इस तरह के तबादलों से काम नहीं चलेगा। वह डाक्टर यदि इस प्रकार से रिश्वत लेते हैं और लोगों को एडमिट नहीं करते हैं तो ऐसे डाक्टर के बारे में दरियाफ्ती होनी चाहिए और उसके बाद हिदायत होनी चाहिये। सरकार का तो यह तरीका हो गया है कि केवल मोटा अपराध कोई करे तो उसका तबादला करना पर्याप्त समझा जाता है। यह तबादला करने की व्यवस्था ठीक नहीं। डाक्टर अपना तरीका छोड़ देता है तो वह यहीं बना रहे। और यदि रिश्वत लेता है और लोगों का उत्पीड़न बढ़ाता है तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। और उसके बाद वह अपराधी साबित हो तो उसको हिदायत के रूप में कहना चाहिये। मेरी शिकायतें पर मैं आशा करता हूँ कि मंत्री महोदय कोई न कोई जाँच करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर अस्पताल में टी० बी० वार्ड्स हैं वह अस्पताल शहर के

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

अन्दर होने के कारण उपयुक्त नहीं है। बीस पच्चीस वर्ष पहले लोगों की सहायता से उस समय जो शासन था उसने व्यय करके टी० बी० वार्ड शहर के बाहर उपयुक्त स्थान पर बनाये थे। इसके बारे में मैं लम्बे चौड़े बयान में जाना नहीं चाहता कोई भी कारणवश सरकार ने दबाव में आकर उन टी० बी० वार्ड्स में गान्धी आश्रम की स्थापना की। यह ठीक है कि गान्धी आश्रम वहाँ से हटाया नहीं जा सकता लेकिन जिस स्थान पर टी बी. वार्ड्स बने हुए हैं वह भी अनुपयुक्त स्थान है। शहर के अन्दर टी. बी. वार्ड्स का होना मेरे ख्याल से घातक है। सिद्धान्तः सरकार से इसलिए मैं चाहता हूँ कि वहां टी. बी. वार्ड्स न रहें। बिल्कुल ही नहीं रखना तो प्रतिक्रियावादी कदम होगा इस कारण मैं निवेदन करूंगा कि टी. बी. वार्ड्स उपयुक्त स्थान पर बनाने की व्यवस्था करिये।

अध्यक्ष महोदय, वहाँ के वैद्यजी की व्यक्तिगत शिकायत नहीं करूंगा गत विधान सभा में भी मैंने यह निवेदन किया था वे वहां पर लगातार बीस बरस से विद्यमान हैं। वे वहाँ के जिला प्रमुख के रिश्तेदार हैं, जिला प्रमुख के संभवतः कृपा पात्र भी हों। वे लगातार बीस वर्ष से एक ही स्थान पर हैं, अगर आप मेरी इस मांग को ठुकराते हैं तो सरकार की मरजी। सिद्धान्तः बात यह होनी चाहिये कि जनतंत्र में पांच वर्ष तक कर्मचारी एक स्थान पर रह सकता है उसके बाद उसको वहाँ नहीं रखा जाना चाहिये। बीस वर्ष एक एक स्थान पर कोई रह जाता है तो उसके वेस्टेड इन्टरेस्ट उत्पन्न हो जाते हैं वे हानिकारक होते हैं। संभवतः सरकार की यह परम्परा हो कि मुख्य मंत्री महोदय जब बीस वर्ष रहना चाहते हैं तो उसी प्रकार कर्मचारी भी बीस वर्ष से पहले हटना अपनी प्रतिष्ठा का हनन मानते हों। लेकिन इसी तरह से प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर के इसको नहीं चलाया जा सकता कि मुख्य मंत्री की परम्परा का वे अनुसरण करें। सरकार से मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ भिषगाचार्य धन्वन्तरी की डिग्री पास शुदा वैद्य काफी सीनियर है। सरकार उनका तबादला कर जनतन्त्र की स्वस्थ परम्परा का अनुसरण करेगी।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं आसपुर के संबंध में भी निवेदन करना चाहूँगा आसपुर तहसील हैडक्वार्टर है वहां पर हैल्थ सेन्टर और डिस्पेन्सरी नहीं है। आयुर्वेदिक औषधालय जरूर है मुख्य मन्त्री जी से वहां के नागरिकों ने मांग भी की थी। वे आसपुर की जनता से खास तौर पर प्रसन्न नहीं, उसके लम्बे चौड़े कारण हो सकते हैं। केवल मात्र मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि मैंने सन् ६२ में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था। आसपुर की बस्ती बहुत छोटी है वहाँ हैल्थ सेन्टर और अस्पताल कायम हों यह अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन मेरा निवेदन है कि आसपुर के पाँच मील के रेडियस को देखा जाय और उसके साथ साथ इस सिद्धान्त को भी ध्यान में रखा जाय कि वह तहसील हैडक्वार्टर है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मेरा निवेदन है कि आसपुर की जो हैल्थ सेन्टर की मांग है उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार होना चाहिये। इसके साथ-साथ डेन्सिटी ऑफ पापूलेशन की वजह से

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

दस हजार आदमियों को लाभ दे सकता है। मैं यह नहीं कहता कि इसकी तत्कालीन व्यवस्था करें आयन्दा बजट के अन्दर प्रावधान रख कर विचार करें और मेरी मांग के संबंध में कोई न कोई निर्णय लें।

अध्यक्ष महोदय मेरे पास यह भी शिकायत आयी है और इस सम्बन्ध में वहां चर्चा भी की गई थी हमारे दल के श्री भानुप्रसाद कनाडिया किसी रूप में जल गये उनको यहाँ अस्पताल में एडमिट किया गया उनकी मृत्यु हुई ब्लड ट्रान्सफ्यूजन की व्यवस्था नहीं होने से उनकी मृत्यु हुई। उनकी लाश की मांग की गई लेकिन पोस्टमार्टम की व्यवस्था समय पर नहीं की जा सकी। तीन दिन के पश्चात् उनका पोस्टमार्टम हुआ फिर उनकी लाश उनके वारिसों को दी गई। यह राज्य सरकार के लिये अशोभनीय व्यवस्था है। जयपुर में एम० एल० ए० के साथ इस प्रकार की दुर्घटना होती है तो साधारण जनता के लिये क्या आशा करके चल सकते हैं। मेरे ख्याल से ऐसी दुर्घटनायें भविष्य में न हों इस सम्बन्ध में व्यवस्था करनी चाहिये।

इतना ही निवेदन कर मैं अपने कटौती के प्रस्ताव विचारार्थ रखता हूँ।

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने कटौती के प्रस्ताव चिकित्सा की मांग पर ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की काफी लम्बे समय तक व्यवस्था नहीं की जाती है इसके सम्बन्ध में रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह डिस्पेन्सरीज हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं वे काफी लम्बे समय से चल रहे हैं लेकिन वहां कई स्थानों पर डाक्टर नहीं हैं और कई जगह डाक्टर तो दूर रहा, कम्पाउन्डर और नर्स तक भी नहीं हैं। मैं आपके सामने उदयपुर जिले की कुछ ऐसी जगहों के नाम प्रस्तुत करूंगा जिससे स्पष्ट जाहिर होगा कि केवल एक या दो साल से ही नहीं, बल्कि करीब करीब ५ और ६ साल से ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जहां पर उनके कायम होने से आज दिन तक डाक्टर नहीं भेजा गया। वे हैं :

प्रा० चि० कें०	रीछेड़
	खमनोर
	सामरा
	भाड़ोल
	देवगढ़
	कुरावड़
डिस्पेन्सरीज	छाली
	कोटड़ा
	ताल

और चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़।

व इन जगहों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और डिस्पेन्सरीज खोले गये थे तो यह खयाल था कि डाक्टर उपलब्ध होंगे और लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वहां पर काफी समय से डाक्टर नहीं हैं। १९६० में खोले गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आजतक कोई डाक्टर उपलब्ध नहीं हुआ। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलते हैं वहां पर डाक्टर की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये। कई बार माननीय

(श्री हीरालाल देवपुरा)

मंत्री महोदय से भी कहा गया पहले भी कहा गया था तो जवाब मिलता है कि डाक्टरों की कमी है। डाक्टरों की कमी है यह हम महसूस करते हैं पर यह डाक्टरों की कमी केवल रूरल एरियाज के लिये ही क्यों है? वहां पर ही डाक्टर नहीं पहुँचते। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज भी डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स पर बड़े बड़े होस्पीटल्स हैं, वहां पर हमने कई डाक्टर्स रख छोड़े हैं। जहां तक स्पेशलिस्टों का सवाल है, विशेषज्ञों का सवाल है, उनके सम्बन्ध में कुछ निवेदन नहीं करना चाहता, उनकी उन बड़े होस्पीटल्स में आवश्यकता है, लेकिन वहां पर जो बाकी के डाक्टर्स रहते हैं उनकी संख्या में कमी करके अगर इन्टीरियर में उनको भेजा जाय तो आज जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिना डाक्टरों के पड़े हुए हैं वहां पर उनकी उपयोगिता हो सकती है।

शहरों में कई हास्पीटल्स है और वहां के लोगों को सुविधायें मिल सकती हैं लेकिन देहातों में ये सुविधायें नहीं हैं। आज शहरों में कोई हास्पीटल खोलने का प्रश्न आता है तो वहां के लोगों से कोई अग्रिम राशि नहीं मांगी जाती, लेकिन गांवों में जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का सवाल आता है तो लोगों से पहले १० हजार रुपये लिये जाते हैं तब जाकर आदेश आता है। एक जगह डिस्पेन्सरी है और उसको अगर दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की मांग आती है तो भी उनसे बिल्डिंग के लिये रुपया मांगा जाता है। इतना सब होते हुए भी गांव के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और डिस्पेन्सरीज में डाक्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। और दूसरी तरफ अर्बन एरियाज में जहां लोगों की कोई लागत नहीं लगती उनको यह सुविधा बराबर मिलती रहती है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि यह बहुत आवश्यक है कि इस बात की तरफ वे ध्यान दें और इसका समाधान करें।

डाक्टरों की कमी राजस्थान में है और काफी समय तक और रहेगी शायद, लेकिन जैसे आपने आवश्यक तौर पर रोटेशन का तरीका डाक्टरों के भेजने का कर रखा है, तो यह रोटेशन केवल देहात के लिये न करके शहरों और कसबों के लिये भी रखा जाये तो मैं समझता हूं उन डाक्टरों को देहात में भेजा जा सकता है। आप देहातों में डाक्टरों का पोस्टिंग करते नहीं और पोस्टिंग करते हैं तो वह आर्डर बाद में मुल्तवी किया जाता है इसलिये कि वे लोग शहरों में रहना चाहते हैं। आपको इस बात में सख्ती से काम लेना चाहिये। आखिर देहात के नागरिक को शहर के नागरिक से अलग तरह से नहीं रखा जा सकता। उनको इस फैसिलिटी से महरूम नहीं रखा जा सकता। अगर आप चाहें तो डाक्टरों को देहात में जाने पर कुछ ज्यादा फैसिलिटीज दे सकते हैं। डाक्टरों को अर्बन एरियाज में ज्यादा प्राइवेट प्रेक्टिस होती है इसलिये भी वे लोग देहाती एरियाज में नहीं जाना पसन्द करते। तो आप उनको कुछ कन्शेसन देकर देहात में जाने का अट्रेक्शन बढ़ा सकते हैं। इस तरह से गांववालों को भी डाक्टर की सुविधा उपलब्ध हो सकती है।

दूसरा अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि फैमिली प्लानिंग पर काफी

(श्री हीरालाल देवपुरा)

जोर दिया जा रहा है । कहा जाता है कि यह राष्ट्रीय आवश्यकता है और हमारे यहां के कृषि उत्पादन को देखकर यह बहुत ही आवश्यक है कि इस फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाये । लेकिन देखा यह गया है कि हमारा इस बारे में प्रचार केवल अर्बन एरियाज तक ही सीमित है । आप गुजरे सेंसस के फिगर्स देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि जो जन संख्या दस सालों में १९५१ से १९६१ तक बढ़ी है वह अर्बन एरियाज में इतनी मात्रा में नहीं बढ़ी जितनी कि रूरल एरियाज में और खास तौर से आदिवासी एरियाज में तो वास्तव में फैमिली प्लानिंग का प्रचार इन देहाती और आदिवासी एरियाज के लिये ज्यादा जरूरी है । उन एरियाज में आपको उचित प्रबन्ध इसके लिये करना पड़ेगा ।

वहां की अस्पतालें आपकी पूरी इक्विप्ड हैं, केवल इन्सट्रुमेंट्स से नहीं, परसोनेल से इक्विप्ड हैं, विशेषज्ञों से इक्विप्ड हैं. तभी अच्छी तरह से वहां इलाज हो सकेगा फेमिली प्लानिंग की समझायश की जा सकेगी और जिस आन्दोलन को हम गति देना चाहते हैं, उसको भी हम बल दे पायेंगे ।

मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे और देहातों के अन्दर ग्रामीण जनता जो राहत चाहती है, उनको नहीं मिल पा रही है । इसकी ओर आप जल्दी से जल्दी ध्यान देंगे ।

डाक्टर ओमदत्त : अध्यक्ष महोदय, आज मैं मेडीकल और हेल्थ के विषय पर बोल रहा हूं । मैं किसी विशेष डिस्पेन्सरी या विशेष विषय को लेकर नहीं कहूंगा । बल्कि जनरल बातें बोलने की कोशिश करूंगा । मुझे खुशी है कि चिकित्सा के क्षेत्र में फायदा हुआ है, उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता लेकिन जितनी रकम खर्च की गई है उसकी ४०-५० प्रतिशत ही यूटीलाइज हुई होगी, दूसरी वेस्ट गई होगी । इसका कारण क्या है ? राष्ट्रीयता की भावना न होने के कारण भ्रष्टाचार और दूसरी बातें हो रही हैं । मूल आधार को न पकड़ने के कारण ये सब बातें हुई हैं । वहां कई कटौती के प्रस्ताव आए हैं, कोई कहता है कि अस्पताल नहीं है, अस्पताल है तो डाक्टर नहीं है । अगर डाक्टर है तो दवाइयां नहीं हैं । दवाइयां हैं तो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, डाक्टर पैसे कमाते हैं । मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है, हरएक विभाग में भ्रष्टाचार होता रहता है । इसका कारण यह है कि राष्ट्रीयता

(श्री पूनमचन्द-उपाध्यक्ष, पदासीन)

(१२.३० म. प.)

की भावना नहीं है । चुनाव का सिस्टम ऐसा है कि पार्टी जो पावर में है उसको चुनाव में जीतने के लिए गलत तरीकों से काम होते हैं । जो चीज होनी चाहिए थी, एक डिस्पेन्सरी के लिए एलोकेशन, वह नहीं की जाती है । पार्टी के प्रश्न को लेकर एलोकेशन हो जाता है । इसलिए मैं यह सुझाव देता हूं चिकित्सा मंत्री को कि एक समिति बनाई जाय जिसमें उस क्षेत्र का विधायक हो, आपोजीशन पार्टी का विधायक हो, डाइरेक्टर आफ मेडिकल सर्विसेज का प्रतिनिधि हो और कलैक्टर हो । ये सब मिलकर इस चीज को देखें कि फलानी जगह डिस्पेन्सरी या अस्पताल की जरूरत है या नहीं ।

Page No. 72

(श्री ओमदत्त)

दूसरी बात यह है कि जिला अस्पतालों को डेवलप करना बहुत जरूरी है, जिला अस्पताल जहाँ कलेक्टर रहता है, वहां डाक्टर तो मैं देखता हूं एक की जगह ६-६ डाक्टर हो गए हैं लेकिन दूसरी सुविधायें नहीं दी जाती हैं। एक सरजन हो, एक ऐनेस्थेटिस्ट हो, रेडियोलाजी का तेक्नीशन हो और लेबोरेटरी टेक्नीशन होना भी जरूरी है। इन चारों के न होने की वजह से सर्जीकल साइड सुधर नहीं सकता।

दूसरा ब्लड बैंक होना जरूरी है। ब्लड बैंक के बारे में मुझे कहना है कि जो बड़े बड़े शहर हैं वहां भी ब्लड की व्यवस्था ठीक नहीं है। मद्रास के लोग घूमते हैं भूख के मारे २०-३० रुपए लेकर ब्लड देते हैं लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस संबंध में जिसका आपरेशन होता है उसके रिश्तेदार देखने को सैकड़ों के नम्बर में आते हैं लेकिन ब्लड का नाम लेते हैं तो भाग जाते हैं। ब्लड दूसरे का खरीदकर देना चाहते हैं लेकिन रिश्तेदार नजदीक नहीं आते।

तो मैं आपको संजेस्ट करूंगा ब्लड बैंक को डेवलप करने के लिये, ब्लड देना नुकसान देह नहीं है, एक आदमी की हैल्थ अच्छी होतो है वह छः महीने में ब्लड दे सकता है, ईसके लिये मैं सुझाव दूंगा कि एम. एल. एज. मिनिस्टर्स गवर्नमेंट अधिकारी हेल्दी होते हैं वे ब्लड देना शुरू करें और उसके बाद पब्लिक में यह चेतना पैदा करें कि ब्लड देने में नुकसान नहीं होता है।

तीसरी बात मैं कहूँगा कि यह कहा जाता है कि डाक्टरों में भ्रष्टाचार है। लेकिन मैं कहूँगा कि मेडिकल डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट्स से फार बेटर है। भ्रष्टाचार मिटाना है तो आप प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द कीजिये। केसइ लिये आप उनको ५० प्रतिशत अलाउन्स दीजिये तो यह बन्द हो सकता है। हैल्थ मिनिस्टर फरमायेंगे कि इतनी रकम नहीं है। मैं उनको यह सुझाव दूंगा कि स्टेजेज बाई स्टेज करें। इस पर क्यों नहीं विचार करते। पहले प्रवीण निश्चेतक (एनेस्थेटिस्ट) से शुरू करें। हरएक आदमी चाहता है कि उसका स्टेटस हो। फाइनेन्शियल कन्डीशन अच्छी हो। डाक्टर होते हुए भी उसको इन्फीरियर क्यों गिना जाय। इसलिये इसको स्टीमुलस देने के लिए अलाउन्स देना जरूरी है। लेबोरेटरी व एक्सरे चार्जेज क्यों? डाक्टर गरीब आदमी जिसकी सिफारिश नहीं है उनसे चार्ज करेगा। पैसे वाले और इन्फ्लूयुएन्शल आदमी यों ही मुफ्त में करा ले जावेंगे। इसलिये होस्पिटल में जो आये उनका मुफ्त में इलाज करना चाहिये।

दूसरी बात यह देखी जाती है कि इशेन्शियल ड्रग्स की कमी होती है। इन्स्ट्रूमेंट्स कम होते हैं। इसके लिये इसेन्शियल ड्रग्स की एक लिस्ट रखी जाय। कोमन ड्रग्स हैं। हरएक होस्पिटल्स, डिस्पेन्सरी, एडपोस्ट्स में ये चीजें मिलनी चाहिये। एस्प्रिन, सोडा बाई कार, बेन्डेज, स्प्रिट इत्यादि इनका होना बहुत जरूरी है। कभी स्प्रिट नहीं है तो कभी बेन्डेज नहीं है। कभी सोडा बाई कार नहीं है। मुझे यह कहते हुए दुख होता है। इसी असेम्बली में डाक्टर कहते हैं। उनके पास ये चीजें नहीं हैं तो वे काम में नहीं ला सकते। लोकल

(श्री ओमदत्त)

मेडीशन नहीं मिलती है। डॉक्टरों पर अधिक खर्चा किया जाता है और ड्रग्स पर कम किया जाता है। गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स मुझे माफ करेंगे। रिएम्बर्समेंट इतना चला है कि इससे भ्रष्टाचार फैला है। यदि दवाइयें आप मंगवा कर रखें तो वह सब को बराबर मिले। इससे गरीबों का भी भला हो।

अब मैं व्यक्तिगत तौर पर जोधपुर के लिये कहूँगा। जोधपुर शहर वर्ल्ड के नक्शे में था। वह आज कल बहुत ही पीछे रह गया है। जहाँ से मैं आया हूँ, उत्तर भारत में इस होस्पिटल का नाम बहुत ऊंचा था। आज उस हॉस्पिटल को आपने बी क्लास कर दिया है। हमारे यहां से ढेर के ढेर मंत्री महोदय पता नहीं इस काम में तो इम्पार्टेंट ही रहे, चाहे दूसरे कामों मे वे पोटेन्ट रहे हो, जोधपुर म उन्होंने कोई काम नहीं किया। जब जोधपुर म दूसरे नम्बर पर मेडिकल कालेज वहां होना चाहिये था यह बात कही गई तो हमारे यहाँ के मेडीकल कौंसिल के मेम्बर और मिनिस्टर कहने लगे कि जोधपुर में जमीन नहीं है इसलिये असम्भव है। दस वर्ष पहले जमीन नहीं थी तो आज कहां से आगयी। डाक्टरों के लिये एक ही चीज आवश्यक होती है और वह है क्लीनिकल मेटिरियल। राजस्थान में पांच कालेज खोल दिये। दो या तीन से अधिक कालेज खोलने की जरूरत नहीं थी। न तो पूरा स्टाफ है और न ही पूरे एपरेटस हैं। होल हिन्दुस्तान में एपरेटस नहीं मिलते। आपने कालेज खोल दी तो उसको खोलने की चाहे गलती आपने कर ली हो लेकिन चलाने की ड्यूटी आपकी है। कल मैंने सवाल पूछा था। मुझे जवाब मिला, बड़े दुख की बात है, कि ओपरेशन गैलरी नहीं है। मंत्री महोदय कहने लगे ओपरेशन गैलरी होगा। मिसरा है।

Putting the cart before the horse, not putting the horse before the cart. यह सब नहीं मिला तो मेडीकल कालेज बन्द कर दी जावेंगी ? मेडीकल कालेज शुरू कर दी है वह बन्द नहीं होगी। मुख्य मंत्रीजी से कहता हूँ कि उदयपुर एक छोटी सी जगह होते हुए भी आप स्टेटिस्टिक्स की किताब देख लीजिये, कितने होस्पिटल्स हैं, कितने प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स हैं। सारी स्टेटिस्टिक्स की बुक में लिखा हुआ है मैं उसको नहीं दोहराऊँगा। विरोधी दल ने कहा कि चुनाव के कारण हा Famine में आपने बहुत पैसा वहां लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव के कारण नहीं लगाया। बेकवर्ड कम्युनिटी थी इसलिये लगाया। स्कूल, होस्पिटल्स की ज्यादा जरूरत होगी, पब्लिक टेलीफोन भी ज्यादा लगेंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि मुख्य मंत्रीजी ने अन्याय के साथ उदयपुर में ज्यादा पैसा लगाया और दूसरी जगह नहीं लगाया। अजमेर और जोधपुर के कालेजेज को आप डेवलप करें यही मेरी रिक्वेस्ट है।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय....

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुकुट बिहारी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्तुत मांगों

Page No. 74

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

पर अपने सब ही कटौती प्रस्तावों को मूव करता हूं। जब मैं अपने कट मोशन्स का वर्गीकरण करता हूं तो प्रमुख तरीके से जनरल अस्पताल भरतपुर की तरफ हमारे जो मेडीकल के माननीय मन्त्री महोदय हैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर का जनरल अस्पताल अपनी एक विशेषता रखता है। चूंकि राजस्थान के वह पूर्वी द्वार पर बसा हुआ है तो यह बात मानकर चलनी चाहिये कि उस स्थान की पापुलेशन को ध्यान में रख कर उसकी ग्रेडेशन आंकी जाती है तो यह मत देखिये। विशेषता इसलिये रखता है कि आंकड़े उठा कर देखें तो यू. पी. के पड़ौसी जिले हैं, मथुरा आगरा, अलीगढ़, एटा, मेनपुरी, धौलपुर या मध्य प्रदेश के इन जगहों से लगे आस पास के इलाके और खास कर राजस्थान के करोली, सपोटरा, गंगापुर, आदि इलाकों के लोग भरतपुर के अस्पताल में चिकित्सा की सुविधा के लिये आते हैं। भरतपुर के अस्पताल के लिए जहां तक सुविधा देने का सवाल है आस पास के दूसरे प्रान्तों के लोगों को सुविधा मिलती थी, यह अस्पताल उनकी सेवा करता था और इसी कारण से इसकी बड़ी शान रही है। डाक्टर जोशी जैसे प्रसिद्ध डाक्टर यहां रहे हैं और उन्होंने सेवा की है। इसकी बड़ी प्रसिद्धि रही है। आज इसकी दयनीय स्थिति को देखकर में अपने कटौती प्रस्ताव के द्वारा माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि वहां पर कुछ विभाग ऐसे हैं जो खाली पड़े हुए हैं जिनमें स्पेशियेलिस्टस की ज्यादा जरूरत है। कायदा यह होना चाहिये कि भरतपुर की एक यूनीक स्थिति है और इसकी पूर्व सेवाओं को देखते हुए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा और यह मांग करूंगा कि इसको ए श्रेणी का अस्पताल बना दिया जाय। यदि इसको 'ए' श्रेणी का अस्पताल बना दिया जाता है तो काफी सुविधायें 'ए' श्रेणी के अस्पताल को मिलती हैं वे ही सुविधायें इस अस्पताल को भी मिलने लग जावेगी। यह मैं मानता हूं कि डाक्टरों की कमी है लेकिन यह मैं नहीं मानता कि इतनी ही कमी है। मैं विशेष तौर से उन मोटी मोटी बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा जिनकी व्यवस्था अविलम्ब सरकार को करनी चाहिये।

उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि आपने एक आज्ञा निकाली है कि भरतपुर में ३०० के करीब बैड्स की व्यवस्था है। पर प्रैक्टिकली तो आज भी पांच सौ साढ़े पांच सौ इन्डोर पेशेन्ट्स वहां रहते हैं। कुछ बरामदे में कुछ पेड़ों तक के नीचे। तो उसे तो श्रेणी तक का अस्पताल घोषित करने मात्र का सवाल है। राज सरकार इस पर अत्यन्त सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

रेडियोलोजिस्ट का पद है वहां पर। पर काफी अरसे से खाली पड़ा है। इतने अस्पताल में उसका पद भरा जाना आवश्यक है।

वहां पर पहले बोन एक्सपर्ट भी था। पर उसका अब तबादला हो गया। दूसरा आज तक नहीं आया।

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

वहां पर दो फिजिशियन होने चाहिये। एक ही है। वही नहीं, अभी अभी एक एडीशनल सर्जन पहुंचे। इससे आपरेशन के काम में तो जरूर राहत मिली है पर कितने ही अरसे से आई वार्ड खाली पड़ा है। आई स्पेशियेलिस्ट अपोइन्ट नहीं किया गया अभी तक।

यही हाल ई. एन. टी. विभाग का है। वर्तमान डाक्टर आगामी जुलाई में रिटायर हो जावेगा तो वह भी खाली हो जावेगा। इस ओर विशेष तौर से ध्यान दें। अगर काई नया डाक्टर इसके लिये न मिले तब तक वर्तमान डाक्टर को आप एक्सटेन्शन दे दें।

मैं मिनिस्टर महोदय से निवेदन करूंगा कि वे कुछ समय निकाल कर उधर का दौरा करें और अस्पताल का निरीक्षण करें और वहां के लोगों से मिलकर उनकी शिकायतें और सुझाव सुनें।

वहां के पुराने वार्ड गन्दे हो गये हैं। टट्टियां भर गई हैं। नालियां टूट फूट गई हैं। उनको साफ करावें। इसमें केवल थोड़े से पैसे की जरूरत है। आज तो केवल वहां गन्दगी का साम्राज्य है। चारों तरफ बाउन्ड्री वाल टूट गई है, लोगों ने रास्ते निकाल लिये हैं। उनको बन्द करके उसे आप कम्पेक्ट बना सकते हैं।

तो मैं समझता हूं इन सारी बातों की तरफ ध्यान देंगे।

धोलपुर के बारे में निवेदन करूं। वहां दो अस्पताल हैं। जनाना व मर्दाना। बीच में सड़क है। अगर उनको एक कर दिया जावे सड़क हटाकर जैसा कि वह पहले था तो स्वयं ही बी श्रेणी का वह अस्पताल हो जावेगा। धौलपुर की हालत देखते हुए इन दोनों का एकीकरण करके उसे बी श्रेणी का अस्पताल घोषित किया जावे। यह अतीत काल में भी एक हो रहा है। मत्स्य के जमाने में भी पहले एक ही अण्डर में था।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि धौलपुर के अस्पताल को बी श्रेणी का अस्पताल घोषित करें।

भरतपुर जिले में वृंदावन नाम का कस्बा है। वहां एक धनी मानी व्यक्ति ने ढाई लाख रुपया लगाकर एक बहुत अच्छी बिल्डिंग अस्पताल के लिये बनाई है। पर अभी तक वहां डाक्टरों का स्टाफ नहीं पहुंचा है। मैं इस बारे में व्यक्तिगत रूप से मिनिस्टर महोदय से मिलने की सोच रहा हूं। अगर इसमें ऊंचे दरजे की पोलिटिक्स रन नहीं कर रही हो तो इसका लाभ सरकार को लेना चाहिये और वहां स्टाफ भेजना चाहिये।

दूसरी बात, मांग संख्या ३० मेरी जन-स्वास्थ्य के बारे में है। इस बारे में पांच छ कट मोशन्स हैं। मास्टर आदित्येन्द्रजी का भी है। इन पर एक एक दो दो मिनिट में मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। मैं बहुत थोड़ा समय लूंगा। वैसे मैं पार्टी का समय ले रहा हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सारे दिन भर बोलियेगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कोई आपत्ति नहीं है, बोलियेगा आप।

श्री मुकुटबिहारीलाल : चुनावों के दिनों में जहां मास्टर आदित्येन्द्रजी चुनाव लड़ रहे थे तो वहां पर एक नल योजना का उद्घाटन करने के लिये मुख्यमन्त्री जी पहुँचे तो उस नल योजना का वहां शिलान्यास किया मतदाताओं को भ्रमित करने के लिये या किस लिये और इसके पीछे उनकी क्या मशा रही यह वे ही जानें। चुनाव के दिनों में इस तरह के शिलान्यासों के पीछे क्या भावना रहती है यह सभी जानते हैं! पर खेद है कि उनकी वह मंशा पूरी नहीं हुई और मास्टर आदित्येन्द्रजी वहां से जीत कर आ गये। रिजल्ट सबके सामने आ गया। जिन भाई को शायद चाहते थे वे नही आ सके और उनके मन की बात पूरी नहीं हुई। तो अब मैं समझता हूं कि शिलान्यास के बाद उस नल योजना का काम अब रुकना नहीं चाहिये। यह स्वस्थ परम्परा भी नहीं होगी। अगर रुक गइ तो लोग क्या कहेंगे? इसे तो मैं राजनैतिक धोखेबाजी ही कहूँगा फिर राजनैतिक मक्कारबाजी होगी यह।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इसको मोहनजाल कहता हूँ।

श्री मुकुटबिहारीलाल : सरकार का एक चीफ मिनिस्टर इस तरह की बात करे और यह धारणा लोगों की बने तो इसे नहीं पनपने देना चाहिये।

जहां तक डीग का सवाल है, मैं निवेदन करूं कि वहां सात बड़े बड़े तालाब है। उत्तर भारत में शायद ऐसे तालाब और जगह नहीं मिलेंगे। डीग के ये तालाब कहलाते हैं। लाला बाबू का तालाब है और आज उनकी ये हालत देखिये कि पानी भरने की उनमें कोई व्यवस्था नहीं है। पानी जो था वह सूख गया है। कुछ बदबूदार पानी जो बच गया वह सड़ रहा है। हजारों देहातों के आदमी उसमें नहाते हैं और दूसरी तरह की सुख सुविधाओं का उपभोग करते है। भरपुर के राजा उनका स्पेशल कन्सीडरेशन करते थे कि वे तालाब विशेष तौर से भरे जाने चाहिये लोगों को आराम मिलना चाहिये। पर आज उसकी कोई देखभाल नहीं होने से पानी गन्दा हो गया है। स्वास्थ्य कर होने की जगह बीमारी फैलाने वाला रह गया है। तो उस ओर ध्यान दिलाता हूँ सरकार का। दस पन्द्रह सालों से उसकी सार सम्भाल नहीं ली गई है। उस को साफ पानी उसमें भरे जाने की व्यवस्था के लिये सरकार को विशेष प्रावधान करना चाहिये।

भरतपुर की जल योजना के बारे में पिछली बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। एडजोर्नमेंट मोशन के रूप में सरकार से निवेदन किया गया था। पुरानी केपिटल के नाते सरकार उसके महत्व को बनाये रखने के बचनबद्ध है। पर आज पानी की हालत वहां की बहुत खराब है। जो पानी दिया जाता है वह भी केवल आधा घटा सुबह और आधा घंटा शाम दिया जाता है। इस सी स्कीम पर सरकार ने १६ लाख रुपया खर्च किया बताया, पर उस पर भी यह दुखदायी स्थिति है।

यही बात नहीं है कि वहां बन्ध बारहट से ही पानी आवे। दूसरे भी साधन हैं वहां। दूसरे भी सुझाव दिये जा सकते हैं। समया-

Page No. 77

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

भाव से मैं यहां अधिक सुझाव नहीं देना चाहता। कम से कम आप वहां लोगों को पानी उपलब्ध करा दीजिये। पुरानी नहर है सुजानगंज नाम की। वह वहां के जन जीवन के साथ जुड़ी हुई है। अगर भरतपुर में नहर का पानी सूख जावेगा तो वहां का जन जीवन ग्रस्त व्यस्त हो जावेगा। तीन चार कुएं हैं नहर के किनारे। नल की पूरी सुविधा है नहीं, उस पर अगर यह नहर भी ग्रस्त व्यस्त हो गई तो वहां की स्थिति और भी दयनीय हो जावेगी। पिछले २५—३० वर्षों में नहर की सफाई के लिये एक पैसा खर्च नहीं किया गया। इस बार तो आप इसके लिये कुछ विशेष प्रावधान करें।

(१ म. प.)

कम से कम इस तरह के शुद्ध पानी की उपलब्धि करायें जिसके ऊपर हजारों आदमी रात और दिन नहाते हैं आप उस शहर की प्राईमरी नेसेसिटी की तरफ अवश्य ही ध्यान देंगे, ऐसी मुझे आशा है।

इसके अलावा मैं निहायत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि धौलपुर का भी वही हाल है। आज वहां पर पानी उपलब्ध नहीं है। यह ठीक है कि कुछ बड़े बड़े लोगों ने जो मेन वाटर लाइन जा रही है उसमें मोटर लगा रखी है और मोटर से पूरा पानी खीचकर अपनी सुविधायें उपलब्ध कर ली हैं लेकिन ग्राम जनता में रात दिन झगड़े होते हैं। आज इसी तरह की हालत रूपवास के अन्दर है। मैं निहायत नम्रता के साथ सदन के माननीय सदस्यों को सूचना देना चाहता हूं कि पानी की कमी के कारण कस्बा रूपवास में एक आदमी भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर गया। वहां पर सब लोगों ने इस बात के लिए कहा कि यह केवल पानी से तड़प तड़प कर मरा है। आज जहां रूपवास में पानी नहीं हो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि तालाब सूख गया, वहां के कुओं से रात के ३ बजे जाकर रूपवास में लोग पहुंचते हैं और ४ बजे पानी खत्म हो जाता है दिन भर लोग बैठे रहते हैं। जहां पीने के लिये पानी नहीं है तहसील का सदर मुकाम हो और जहां मुकद्दमों के लिये लोग जाते हों वहां पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं हो क्या सरकार की अपने आप में हास्यास्पद व्यवस्था नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निहायत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर बावड़ी है, नल योजना भी है, पंचायत समिति और स्थानीय पंचायत अपने हिस्से का रुपया भी देने के लिये तैयार है और भी कर्जा दे सकते हैं लेकिन वह वाटर स्कीम पूरी नहीं है वह अपने आप में ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर माननीय मन्त्री महोदय स्वयं विचार करेंगे।

इसी तरह से बयाना की स्कीम के लिये कहना चाहता हूं कि बयाना सब डिवीजन आफिस है, म्युनिसिपल एरिया है और वहां म्युनिसिपल एरिया में नहीं है वह तो नहीं कहना चाहूंगा। मैं अलवर का नाम आसानी से ले सकता हूं पर अब नहीं लूंगा और इसलिए नहीं लूंगा कि अलवर और भरतपुर का सवाल खड़ा कर देंगे मगर प्रतापगढ़ जैसी जगह में जहां केवल १७ कनेक्शन्स हैं वहां पर नल योजना चालू कर दी जाये विशेष कारणों से उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं लेकिन बयाना जो कि सब डिवीजन

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

का आफिस है, व्यापारिक केन्द्र है और रेलवे का स्टेशन और जंक्शन है और तीन-चार तहसीलों का कामपेक्ट एरिया है वहां नल उपलब्ध नहीं है यह एक विचारणीय विषय है। मैं निहायत नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि इस स्कीम के ऊपर काम चालू होना चाहिये।

इसके साथ ही मैं परिवार नियोजन के लिए कहूंगा और फिर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। परिवार नियोजन के लिए मैं लम्बी चौड़ी थ्योरी में नहीं जाना चाहता हूँ कि मालथूशन ने पापुलेशन के लिए क्या कहा था या किस तहर से पापुलेशन किस रेश्यो में बढ़ रही है और हमारे साधन कम गति से बढ़ रहे हैं और हमारी आबादी किस गति से बढ़ रही है। मालथूशन ने कहा था कि या तो आप इस बढ़ती हुई आबादी को चेक कीजिए और आप इस बढ़ती हुई आबादी को चैक नहीं करेंगे तो हालत वह होगी कि परमात्मा अपनी तरफ से उसको कट डाउन करके लेवल बना देगा। उन्होंने इसके लिए दो तरह के मैजर्स बताये। एक तो प्राकृतिक मैजर्स हैं कि जब आबादी ज्यादा बढ़ जायेगी और जीवन निर्वाह के साधन कम रेशो में बढ़ेंगे तो हालत यह होगी कि परमात्मा अपनी तरफ से महायुद्ध, महामारी, प्लेग, झगड़े, भूकम्प आदि भेज देगा और आबादी को नष्टभ्रष्ट करके बराबर में ले आयेगा और दूसरा मैजर उन्होंने यह बताया कि कृत्रिम तरीकों से मनुष्य कुछ तरीके अपना सकता है। मैं समझता हूं कि अब दूसरे तरीके पर ध्यान दिया जा रहा है। मैं इस संबंध में ज्यादा बात नहीं कहना चाहता हूँ। मैं विशेष बात तो कोई इस संबंध में यदि मंत्री महोदय चाहें या फिर डिपार्टमेन्ट कोई गोष्ठी अरेन्ज करे और हमारे मत लेना चाहे, हमारी राय और सुझाव लेना चाहें तो हम उस समय रख सकते हैं। मैं इस समय तो केवल इतना सा निवेदन करना चाहूंगा कि अभी मौजूदा हालत में केवल आपरेशन, लूप या गोलियों के अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं अपनाया गया है। मैं वह बात भी नहीं कहना चाहूंगा कि कम्प्यूटर्स आपने लगा रखे हैं लूप वगैरह के सिलसिले में। क्या है कम्प्यूटर उस समय भी तैनात किया जा रहा है जहाँ कि डाक्टर भी नहीं है, जहां लेडी डाक्टर भी नहीं है तो लूप कौन लगायेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि कम्प्यूटर क्या काम करेगा। मैं कहता हूं कि पब्लिक मनी का वेस्टेज है। चाहे इसके लिए स्टेट से पैसा दिया जाता हो या सेन्टर की तरफ से एड मिलती हो। मैं समझता हूँ कि जनशक्ति का ह्रास नहीं करना चाहिए। मैं तो इस संबध में एक दो सुझाव देना चाहूंगा जिनके ऊपर गंभीरतापूर्वक विचार होना चाहिये। आखिर यह आबादी जो ज्यादा बढ़ती है वह किस श्रेणी के लोगों में बढ़ती है। जो गरीब लोग हैं उनमें यह आबादी ज्यादा बढ़ रही है। जो जितना ज्यादा गरीब होगा उसके यहां उतने ही ज्यादा बच्चे होंगे जो जितना अमीर होगा, सुखी होगा उसके उतने ही कम बच्चे होंगे। आखिर यह है क्या ? किसान हमारा रात और दिन मेहनत करता है। सुबह दिन नहीं निकलता है उससे पहले मेहनत करने के लिए खेत पर रवाना हो जाता है और दिन छिप जाता है तो मूंड पर गठ्ठर लादकर और पसीना

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

पसीना होकर घर को लौटता है। जब वह घर लौटता है तो आखिर एक मजदूर के लिए, सख्त मेहनत करने वाले के लिए और धरती का पेट चीरकर पैदा करने वाले मजदूर के लिए कम से कम जिन्दगी के कुछ क्षण तो ऐसे होने चाहिए ही जिससे कि वह अपने गम को गलत कर सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जिससे खुशहाली के साथ, अपने प्रेम के साथ जीवन की दूसरी अनुभूतियों का आनन्द ले सके। आखिर क्या साधन हैं उसके पास ? मैं कहता हूँ कि आबादी क्यों नहीं बढ़े। बेचारे मजदूर के पास अपनी औरत के साथ प्रेम कर लेने के सिवाय और है ही क्या, इसी से उसके जीवन की कुछ अनुभूति पूर्ण हो जाता है। (हंसी) मैं मजाक की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं बड़ी गम्भीरता के साथ कहना चाहता हूँ। उसका नतीजा यह होता हैं कि बच्चों पर बच्चे पैदा होते चले जाते हैं। गरीब आदमी को आप देखें १ बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, पांचवा बच्चा गोदी में होगा और छठा बच्चा पेट में बैठा तैयार है। इस तरह से आबादी बढ़ती है। आपने किसी अमीर के यहां पैसे वाले के यहां या शिक्षित व्यक्ति के यहां संतान बढ़ते देखा है ? मैं कहूंगा कि इसका कारण हमें सोचना पड़ेगा। और हम इसके कारणों में जायेंगे तो वह थ्योरी अब फेल हो गयी है जो दूसरे देशों की धारणा थी कि जिस तेजी के साथ साधन बढ़ेंगे उतनी ही तेजी के साथ आबादी भी बढ़ेगी। लेकिन यह थ्योरी हिन्दुस्तान में फेल हो गयी। हिन्दुस्तान के अन्दर यह थ्योरी आई कि जितना ज्यादा स्टेन्डर्ड आफ लिविंग बढ़ेगें उतने ही कम बच्चे पैदा होंगे।

(समय-समाप्ति-सूचना घंटी)

एक ही मिनट में अभी समाप्त करता हूं। जितना स्टेन्डर्ड आफ लिविंग लोगों का बढ़ेगा उतने ही बच्चे कम होंगे और जितनी गरीबी और स्टेन्डर्ड आफ लिविंग लोअर होगा उतने ही बच्चे ज्यादा पैदा होंगे। मैं हिन्दुस्तान के अन्दर बताऊंगा कि यह बेसिक चीज है। इसके लिए जहां आप कम्प्यूटर्स बढ़ाना चाहते हैं मैं सुझाव दूंगा कि इस चीज पर आप काबू पाना चाहते हैं तो किसान के लिए आपको मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे। शहरों के अन्दर लोग सिनेमा जाकर, रास और दूसरी चीजों में जाकर अपना समय निकाल देते हैं। लोग क्लबों में जाते हैं, गोष्ठियों में जाते हैं, टहलने के लिए चले जाते हैं लेकिन गाँवों के अन्दर आपने क्या साधन मनोरंजन के पैदा किये हैं ? कम से कम और नहीं करें तो कीर्तन मण्डली ही चालू कर सकते हैं, रसिया मण्डली ही चालू कर सकते हैं, गाना बजाने की ही मण्डली चालू कर सकते हैं कुछ कदम मण्डली ही चालू कर सकते हैं या कुछ इस तरह की प्रतियोगिता चालू करें गावों के अन्दर गीत गाने की मण्डली इस गाँव में हो रही है कभी और कभी उस गाँव में हो रही है जिससे कठिन परिश्रम करने के बाद, मेहनत करने के बाद एक किसान जब घर लौटे तो कम से कम घन्टे दो घन्टे के लिए अपने दिनभर की थकावट को निकाल सके और अपने में

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

तब्दीली महसूस कर सके और थोड़ा उस पर चैक भी हो सकेगा तो मैं मंत्री महोदय से विशेष तौर से इस सम्बन्ध में विस्तार ले कुछ चीजें निवेदन करना चाहता था लेकिन अब चूंकि घण्टी बज चुकी है इसलिए अन्त में एक आधा मिनिट में ही यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने भरतपुर के अस्पताल के बारे में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया, मैंने धौलपुर के बारे में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया और मैंने दूसरे दूसरे प्रश्नों के बारे में निवेदन किया। नलों की योजना के बारे में, भरतपुर के बारे में, डीग के बारे में, धौलपुर के बारे में और रूपबास के बारे में विशेष तौर से आप से निवेदन किया कि इन स्थानों की हालत बिगड़ती जा रही है। और मैंने परिवार नियोजन के बारे में निवेदन किया कि इस योजना पर दूसरे दृष्टिकोण से आपको सोचना पड़ेगा, राजस्थान के दृष्टिकोण से आपको सोचना पड़ेगा। अभी तक जनसंख्या कम करने के लिए, छोटे परिवार बनाने के लिए केवल लूप का सिस्टम और आपरेशन का सिस्टम ही जो अपना रखा है वह कारगर नहीं होगा।

हां एक बात और रह गई। छोटी छोटी जगह पर अस्पताल की सुविधा नहीं है और जो सुविधा है भी तो वहां पर दवाइयां नहीं मिलतीं, दवाइयां लाने के लिए बाजार भेज दिया जाता है लेकिन वहां पर बाजार भी नहीं है। तो इन सब चीजों के बारे में महरबानी करके विचार करेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कट मोशन मूव करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रामीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय जो मांग चल रही है उसके सम्बन्ध में मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आजादी के बाद चिकित्सा की व्यवस्था भारत में हुई है वह काफी प्रशंसनीय हैं। मगर ज्यों ज्यों इस देश की स्थिति को देखते हैं और अब तक जो परिस्थितियां चल रही हैं और जिन परिस्थितियों में हमारा यह चिकित्सा विभाग चल रहा है वह काफी संतोषजनक प्रतीत नहीं होती। क्योंकि हमारे देश में गरीब ज्यादा हैं और अमीरों की संख्या तो उंगुलियों पर गिनी जा सकती हैं। अमीर लोग तो हर प्रकार से चिकित्सा सुविधायें प्राप्त कर सकते हैं। चाहे हमारी सरकारी अस्पताल हो तो वहां से प्राप्त कर सकते हैं और चाहे प्राइवेट अस्पताल हों तो वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। वह किसी तरह से भी चिकित्सा सुविधायें प्राप्त कर सकते हैं। मगर जहां तक गरीब परिवारों का सम्बन्ध है, जहां तक उनके एडमीशन्स का प्रश्न है, वहां तक उनकी दवाइयाँ मिलने का प्रश्न है, इन सब बातों में गम्भीर अनियमिततायें बतों जा रही हैं। सरकार को चाहिये कि इस ओर ज्यादा ध्यान दें। यह पचास करोड़ की जनसंख्या का देश है। और इस पचास करोड़ की जनसंख्या को और इनमें भी जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको दवाइयाँ और जरूरी जो इसके साधन हैं वे

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

सरकार को देने चाहिये। वह अवश्य रूप में मिलें तब तो हम अपने रास्ते पर जिस रास्ते पर सरकार ले जाना चाहती है और वह सही रास्ता है, उस रास्ते पर पहुंच सकते हैं वरना तो यह जिस प्रकार की व्यवस्था चल रही है उसमें तो कामयाबी दिखाई नहीं पड़ती। तो मैं यह अर्ज करूं कि राजस्थान की सरकार और हिन्दुस्तान की सरकार चिकित्सा के सम्बन्ध में जो प्रयत्न कर रही है और जो काम किए हैं वे तो प्रशंसनीय हैं जो पहले संक्रामक रोग फैला करते थे, महामारी फैला करती थी, प्लेग, हैजा, मलेरिया, चेचक वगैरा से जो हर साल लाखों इन्सान मर जाया करते थे उनकी रोकथाम में तो काफी काबू पा लिया गया है, मगर इससे ही सन्तोष नहीं हो जाना चाहिये। हमें इसके आगे भी बहुत सारे काम करने हैं।

जहां तक डॉक्टरों का प्रश्न है, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि हमारा देश इस प्रकार का गरीब देश है जिसमें आप डॉक्टरों को प्राइवेट प्रेक्टिस अलाऊ करते हैं वह एक भयंकर चीज है। क्योंकि यहां पर प्रायः यह देखने में आता है कि शहरों में ही डाक्टर लोग रहना चाहते हैं ताकि शहरों में रहकर वे प्राइवेट प्रेक्टिस से हजारों लाखों रुपया प्राप्त कर सकें। आप जब तक के इस प्राइवेट प्रेक्टिस को समाप्त नहीं करते तब तक गरीबों को इस प्रकार की सुविधायें आसानी से प्राप्त नहीं हो सकतीं। आज आप बड़े बड़े अस्पतालों में देखें वहां किस प्रकार की हालत बिमारों की होती है। डॉक्टरों के घर घर जा कर नुस्खा लिखाये बिना तो एडमीशन नहीं मिल सकता अस्पताल में। वे लोग मरीजों को एडमिट करने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन गरीब लोगों के पास इनको देने को कहाँ से पैसा आए, किस प्रकार पैसा आय। इस तरफ आपको खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है। जो आप देश में समाजवाद लाना चाहते हैं तो जिस प्रकार अन्य देशों में होता है, रूस में होता है या दूसरी जगहों पर व्यवस्था है कि हर एक डाक्टर को कुछ जन संख्या की देखभाल करनी पड़ती है। इसी प्रकार की व्यवस्था हमारे देश में भी आपको करनी चाहिए। इसमें आप दोनों व्यवस्थाओं को भी शामिल कर सकते हैं। होम्योपैथीक और आयुर्वेद दोनों को मिलाकर भी जनसंख्या के आधार पर उस जनसंख्या को हरएक डॉक्टर के लिए निर्धारित कर दें कि हजार या पांच सौ लोगों के लिए एक एक डाक्टर को निर्धारित कर दें कि उनकी देखभाल का तुम्हारा जिम्मा है। जब तक इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती, करोड़ों रुपया चिकित्सा के मद में खर्च करने के बाद भी आप वांछित फल प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपको इसमें आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। आज की जो आपकी व्यवस्था है वह किसी भी तरह से ठीक प्रतीत नहीं होती है। एक मालदार आदमी तो किसी भी प्रकार की सुविधा कैसे भी प्राप्त कर सकता है, हम उनके लिए साधन बढ़ा रहे हैं लेकिन जो सुविधायें हम गरीब आदमियों को देना चाहते हैं उन सुविधाओं को वह पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सकता। आज किसी भी डिस्पेन्सरी या बड़े अस्पताल में चले जावें तो उनमें गरीब लोगों को दवाइयां नहीं मिलती हैं। बड़ी

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

कीमती दवाइयाँ और पेटेंट दवाइयाँ ठीक प्रकार से नहीं मिलती हैं । गरीब आदमियों को भी चिट लिखकर दे दी जाती है कि बाजार से खरीद कर लाओ । आप दवाइयों के लिए लाखों रुपयों का बजट रखते हैं और इस प्रकार का प्रावधान बड़े२ अस्पतालों के लिए रखते हैं कि वे दवाईयाँ जो महंगी हैं, पेटेंट दवाइयां हैं और इंजेक्शन हैं वे ऐसे लोगों के लिए हैं जो बाजार से खरीद कर नहीं ला सकते हैं । ये दवाइयाँ भी मालदारों को तो मिल जाती हैं लेकिन गरीब आदमियों को नहीं मिलती हैं, जिसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है इस प्रकार के लोगों को तो उनसे वंचित रखा जाता है । पिछली दफा मैंने सवाल पूछा था कि आपकी डिस्पेन्सरीज में, आपके डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल्स में और आपके जनरल होस्पिटल में कितनी इस प्रकार की कीमती मेडिशन्स साल के अन्त में रह जाती हैं जो आउट ओफ डेट हो जाती हैं जिनकी तारीखें निकल चुकी होती हैं । इस प्रकार की हजारों रुपयों की दवाइयां आपके होस्पिटल्स में पड़ी रह जाती हैं । सैकड़ों रुपयों के इंजेक्शन और कीमती दवाइयां वे इस प्रकार के जो कि कमीशन प्राप्त करने के लिए उनको नुस्खा लिखकर दे दिया जाता है कि अमुक २ मेडिकल स्टोर्स से खरीद कर लाओ और वे लोग उन कीमती दवाइयों को खरीदते हैं । जो गरीब आदमियों को समय पर मिलनी चाहिए, नहीं मिलती है और साल के अन्त में हजारों रुपयों की दवाइयां बच जाती हैं । जिन दवाइयों को मरिजों के काम में लेना चाहिए जिनसे गरीबों को फायदा होना चाहिए, वे दवाइयां यों ही अस्पतालों में पड़ी रह जाती हैं और उनकी तारीखें निकल जाने के बाद किसी प्रकार से किसी आदमी को फायदा नहीं मिलता । तो मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आप इस प्रकार की व्यवस्था करें कि आपके यहाँ पर तारीख निकलने के बाद कोई दवा बचत में न रहे और बड़ी २ डिस्पेन्सरीज क्या करती हैं कि अपनी गलती किसी प्रकार से न लगे इसलिए उन दवाइयों को छोटी २ डिस्पेन्सरीज में इश्यू कर देते हैं और इश्यू करने के बाद में अगर कोई नुक्स निकले तो छोटे डिस्पेन्सरीज के डाक्टर पर आंच आती है । और उनसे जो सुविधा गरीब लोगों को प्राप्त होनी चाहिए थी वह भी उनको प्राप्त नहीं होती है । इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि साल के अन्त में इस प्रकार की कोई दवाई बचत में न रहे और सारी इस्तेमाल कर ली जायें ।

दूसरा मेरा निवेदन है कि आपने प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स तो बहुत सारे खोल दिये हैं और उनके लिए नर्सेज और मिडवाईव्स की व्यवस्था आप करते हैं । मिडवाईफ तो आप सब जगह पर देते हैं लेकिन नर्सेज की व्यवस्था पूरी तौर से नही है । सुना है कि आप नर्सिंग कालेज बन्द करने जा रहे हैं । जहां आपने राजस्थान में पांच पांच मेडिकल कालेज खोल दिए हैं लड़कों को डाक्टर बनाने के लिए वहाँ पर नर्सेज कालेज को बन्द करने जा रहे हैं ऐसा सुना गया है । नर्सिंग कालेज को आप बन्द करने का प्रबन्ध कर रहे हैं, ऐसा सुना गया है । इसमें आपका लाख डेढ़ लाख का खर्चा होता है । हमको नर्सेज की सख्त आवश्यकता है जब तक नर्सेज वगैरा पूरी नहीं होती है इलाज वगैरा का समुचित प्रबन्ध

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

नहीं होता है । मुझे जानकारी मिली थी कि आपको वर्ल्ड हैल्थ ओर्गेनाईजेशन से भी स्टाफ मिला था मगर उस स्टाफ को भी आपने रवाना कर दिया है । लाख डेढ़ लाख की बचत के लिए नर्सिंग कालेज बन्द करते जा रहे हैं यह बिल्कुल गलत बात है, इससे हमको बहुत भारी असुविधा होगी । हमको पहले ही नर्सेज की बड़ी भारी कमी महसूस होती है और दूसरी जगहों से लाकर यहाँ रखना पड़ता है, हम अपने राजस्थानियों को जिनको हम चाहते हैं कि ट्रेंड करके यहां पर नर्सेज तैयार करके अपने यहां पर रखें, उसके बदले में हमें दूसरे लोगों को लाकर राजस्थान में रखना पड़ेगा । हमारे यहां की नर्सेज सब ट्रेंड नहीं हो सकेंगी और बेकार हो जायेंगी । इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस बारे में वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाईजेशन और रोकफेलर ओर्गेनाईजेशन या और किसी से भी सहायता प्राप्त करना चाहें, वह प्राप्त करें । इसमें लाख डेढ लाख का ही सवाल है, अगर आप चाहें तो आप स्वयं भी खर्चा कर सकते हैं । इससे हमको बहुत बड़ा फायदा है ।

दूसरी मेरी यह अर्ज है कि जहां प्राईमरी हैल्थ सेन्टर में सब सेन्टर कायम करते हैं, वहां पर मिड वाइव्स रख रखी हैं, और वह इस प्रकार की होती हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन मिनट और बोलना चाहता हूँ । तो जहां तक इन सब सेन्टर्स का सम्बन्ध है मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि वहाँ मिड वाइव्स इस प्रकार की होती हैं कि न तो वह बच्चा जनाना जानती हैं और न और प्रकार से दवाइयां ही दे सकती हैं । मेरा सुझाव है कि इस प्रकार के सब सेन्टर्स के अन्दर यदि आप कोई एक्सपीरियेन्स्ड कम्पाउन्डर रखेंगे तो लोगों को दवा मिल सकेगी और दूसरी चिकित्सा के सम्बन्ध में सुविधायें भी मिल सकेंगी । हमारा देश एक गरीब देश है, इसमें इस प्रकार की परिस्थिति नहीं रह सकती है कि हर गांव में, हर जगह पर एलोपेथी की डिस्पेंसरी चालू रख सकें । मेरा निवेदन है कि आयुर्वेदिक पद्धति एक सस्ती व्यवस्था है जिसको देश के कोने कोने में पहुँचा कर लोगों को सस्ता इलाज की व्यवस्था दे सकते हैं । इस प्रकार की परिस्थिति लाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप देश के अन्दर आयुर्वेद को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दें और आयुर्वेद की गाँव गाँव में डिस्पेंसरी खोल दें तो ज्यादा से ज्यादा पोपूलेशन को लाभ होगा और सस्ती से सस्ती दवा भी मिल सकेगी । यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचा सकते हैं । आयुर्वेद के सम्बन्ध में १४ हजार के उपर एक डिस्पेंसरी खोलने का प्रावधान किया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में लेकिन उसकी भी पूर्ति नहीं हुई है । बहुत से ऐसे स्थान हैं, जहाँ जनसंख्या के आधार पर पंचायत समिति वाइज इसकी पूर्ती नहीं हो सकी है । बरसोड़ो स्थान पर आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोलने की आवश्यकता है । मैं निवेदन करूंगा कि वहाँ जल्दी से जल्दी इस प्रकार की व्यवस्था करें । इसके अलावा निम्बाड़ा और शम्भुगढ़ में सी टाइप के आयुर्वेदिक औषधालय हैं, उनको बी टाइप बना देंगे तो उससे लोगों को लाभ मिलेगा ।

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

जिला परिषद् ने बदनोर और दौलतगढ़ की एक स्कीम स्वीकृत कर दी लेकिन वह चालू नहीं हो पाई है। मंत्री महोदय को उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। वहाँ नल और पाइप पड़े हैं। लेकिन पैसा नहीं होने के कारण काम नहीं चालू हुआ है। अब आपको दो करोड़ रुपये मिल रहे हैं तो आशा है कि आप इस योजना को जल्दी पूरा करेंगे। इसके अलावा जो कुए खुदवाते हैं उसके लिए आप पंचायत समिति को पैसा देते हैं, लेकिन रेट में फर्क है। मैंने कल निवेदन किया था, पंचायत मंत्री को आज मैं जल प्रदाय मंत्री को निवेदन करना चाहता हूँ कि कुए खुदवाने की रेट्स पी० डब्ल्यू० डी० के तहत देते हैं वह रेट ठीक नहीं पड़ती है इसलिए कुए गांव गांव में अधूरे पड़े हैं। इसलिए आपको इर्रिगेशन की रेट से कुओं के लिए पैसा देना चाहिए, जिससे यह कुए खुद जायं और जो कुए अधूरे पड़े हैं, वह हजारों की तादाद में पड़े हुए हैं, वह भी पूरे हो जायेंगे। मेरा निवेदन है कि इर्रिगेशन की रेट्स इन कुओं के सम्बन्ध में दिलवायें ताकि यह काम जल्दी से जल्दी पूरा हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के सम्बन्ध में मैंने कुछ कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। आज राजस्थान में हम चिकित्सा में चाहे कुछ अस्पताल की तादाद में बढ़ोतरी हुई है लेकिन सारे हिन्दुस्तान में जो स्थिति है, और जो राजस्थान को है उसमें आज भी हम लोग सभी प्रान्तों में पोपूलेशन के लिहाज से जो बैड्स हमारे पास हैं उसमें सबसे पीछे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो आज अस्पतालों में दाखिले के बारे में मरीजों को जो दिक्कत आती है जो आज अव्यवस्था है उसके बारे में आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, आज जो सिस्टम अस्पतालों में दाखिले का इवाल्व किया गया है, जो मैं समझता हूँ कि अब कम से कम सारे अस्पतालों में रहता है वह यह है कि अस्पतालों में चाहे सर्जिकल डिपार्टमेंट हो चाहे मेडीकल हो, मुख्तलिफ कार्य के यूनिट्स बनाये हुए हैं और प्रत्येक यूनिट में दिन उनके बटे हुए हैं और जिस यूनिट का नम्बर है उस यूनिट में उन यूनिट के इन्चार्ज को दाखिला करने का अधिकार है। इसका मतलब यह हुआ कि अस्पताल में आउट डोर में बैठने वाले डॉक्टर किसी को दाखिला नहीं दे सकते है, और उस पर्टीक्यूलर यूनिट में भी इन्चार्ज के तहत काम करने वाले डाक्टर भी दाखिला नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार से दाखिला करने में यूनिट इन्चार्ज की मेनोपोली बन गई। और उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत बड़ा करप्शन का कारण है। मैं समझता हूँ कि यह ओपन सीक्रेट हैं, जिसको मेरे ख्याल में, माननीय मंत्री महोदय और हमारे चिकित्सा डिपार्टमेंट के हैड्स हैं वह प्राइवेट में खुद स्वीकार करते हैं कि डाक्टरों ने यह धन्धा बनाया हुआ है। जो भी डाक्टर सरकारी अस्पतालों में हैं, बड़े से बड़े डाक्टर पी एम. ओ. इन्चार्ज, होस्पिटल सुपरिंटेन्डेन्ट जिस मरीज को भी अस्पताल में दाखिल होना है, वह पहले डाक्टर के घर पर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जाकर प्राइवेट रूप से अपना मुलाहिजा करायें, डाक्टर को फीस दे तब जाकर उसके दाखिले की गारन्टी हो सकती है। इतना ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, जो अस्पताल में मरीज हैं उन लोगों को भी टरकाया जाता है, तारीख लगाई जाती है, कहा जाता है, अभी तुम्हारा आपरेशन नहीं हो सकता और उनको कम्पाउन्डर्स के जरिये असिस्टेन्ट्स के जरिये कहलवाया जाता है कि डाक्टर साहब की फीस पहुंचाओ, डाक्टर साहब को दिखाओ। और कई डाक्टर तो इतने ज्यादा खुल गये हैं कि वह अस्पताल की मेज पर फीस ले लेते हैं। कुछ शर्म लिहाज रखते हैं, वह जो लोग उनको घर पर आकर दिखाते हैं उनसे फीस ले लेते हैं और फिर उनको दाखिला देते हैं। यह बीमारी जो कि पहले नहीं थी, मैं यह समझता हूं कि अब पूरी तरह से हर प्रान्त में, हर प्रकार के अस्पताल में पूरी तरह से फैल गई है। चाहे जयपुर हो, चाहे अलवर हो, चाहे जोधपुर उदयपुर हो-सब जगह जहां हमें जाने का मौका मिला है, हमें इस प्रकार की शिकायतें देखने को मिली हैं। और इसके गम्भीर परिणाम हो रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं इसमें मरीजों को भारी दिक्कत होती है, क्योंकि जो बगैर पैसे वाले मरीज हैं उन मरीजों को दाखिला नहीं मिल सकता है। अभी तीन दिन हुए। एक कोई सज्जन थे, उनको मैंने देखा, उनके एक छोटे बच्चे की टांग टूट गई थी। उपाध्यक्ष महोदय, वह अलवर के अस्पताल में दाखिल हुआ। तो आर्थोपिडिक डाक्टर ने कहा कि यहां इसका इलाज नहीं हो सकता, इसको जयपुर ले जाओ। वह सज्जन उसे यहां ले आये तो डाक्टर ने कहा कि दस पन्द्रह रोज लगेंगे इसलिये आप इसको छोड़कर घर पर चले जाइये। वह सज्जन उसे छोड़कर घर चले गये लेकिन उनके पीछे से उस बच्चे को उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया क्योंकि वहां जगह नहीं थी। बाद में उस सज्जन के आने पर मैंने उन्हें माननीय मंत्री के घर पर भेजा था। शायद उनके नोटिस में यह मामला आया होगा। तो गवर्नमेंट सर्वेन्ट, जो इस प्रकार आफिस से छुट्टी लेकर, अस्पताल में दाखिला कराने को आये और उसको दाखिला न मिले, और दाखिला होने के बाद में उसको डिस्चार्ज कर दिया जाय-यह सारी जिन्दगी उस बच्चे की खराब हो सकती थी, उसकी टांग खराब हो सकती थी। तो यह इनह्यूमन एटीट्यूड बिकाज आफ वियूनिअरी फायदे के कारण बढ़ती जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यह डाक्टरों में एक हर्ट बर्निंग का कारण भी बन गया है, क्योंकि जो हैड आफ यूनिट है, इन्चार्ज है, उसकी मानोपोली दाखिला करने की है। इस कारण उसकी मनोवृत्ति यह बनती है कि यह आपरेशन का काम भी मैं ही करूं। मेरे जो सबोर्डिनेट्स हैं वह कोई आपरेशन का काम न करें। इस तरह की जो प्राइवेट प्रेक्टिस चलती है, प्राइवेट प्राफेशन चलता है इस कारण एक यूनिट में जो छोटे छोटे डाक्टर होते हैं, उनको आपरेशन करने का मौका न देकर हैड यह चाहेगा कि मैं ही आपरेशन करूं ताकि मुझे प्राइवेट प्रेक्टिस में फायदा मिले। इसका नतीजा यह है कि नीचे के डाक्टर हैं उनकी प्रेक्टिस नहीं हो पाती है। मेरे नोटिस में एक केस ऐसा आया है कि एक डाक्टर यहां से बाहर कहीं ट्रेनिंग के लिये गये तो वह आपरेशन के इन्स्ट्रूमेंट्स की अलमारी में ताला लगा गये थे और वह इसलिए कि उनके पीछे से उनके सबोर्डिनेट्स

Page No. 86

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उनको आपरेशन करने के काम में न लें। जब तक वह डाक्टर साहब वापिस नहीं आये तब तक उनके पीछे कोई भी आपरेशन नहीं हो सका, क्योंकि सब इन्स्ट्रूमेंट्स तो ताले में बन्द थे। मैं समझता हूं कि इसके कारण एक बहुत बड़ी सर्बोडिनेट सर्विस के अन्दर और डाक्टर्स के अन्दर एक हर्ट बर्निंग है। इस तरह से जो लोग इस प्रकार यूनिट इन्चार्ज बन जाते हैं वह फिर इस तरह से अपने नीचे के डाक्टर्स को एक्सप्लाइट करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि इस सम्बन्ध में तुरन्त सरकार को आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है।

एक मेरा यह सुझाव है कि जैसा आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि प्राइवेट प्रेक्टिस जहां तक सम्भव हो बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिये क्योंकि जिनको सरकारी नौकरी मिल गई है वे सरकारी नौकरी भी करते रहें और प्राइवेट प्रेक्टिस भी करते रहें यह उचित नहीं होगा। इसीलिये वे सरकारी नौकरी ही करें और प्राइवेट प्रेक्टिस नहीं करें। इसीलिए सरकार उन लोगों के लिये जो होस्पिटल में नौकरी करते हैं उनके लिये गवर्नमेंट मेन्डेटरी करार करादे कि ऐसी जगह पर जो डाक्टर हों और उन डाक्टर को तनख्वाह दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में कम हो तो उनकी तनख्वाह बराबर कर दी जावे और उनको नोन प्रेक्टिसिंग अलाउन्स, जैसा कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, दे दिया जावे। मगर उनको किसी भी हालत में प्राइवेट प्रेक्टिस अलाउ नहीं करें। इससे एक तरफ गरीब लोगों को फायदा होगा और दूसरी ओर सरकार को भी फायदा होगा और नये हैंड तैयार कर पावेंगे। अभी नये हैंड तैयार नहीं हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में एक एडवाइजरी कमेटी आम तौर से होस्पिटल में देखने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई थी। उसकी मीटिंग हुई या नहीं यह मेरी जानकारी में आया कि उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई। मेरे खयाल से इस प्रकार की कमेटी बहुत उपयोगी हो सकती है। इसको पब्लिक ओपिनियन से कोओरडीनेट रखा जावे। मैं यह निवेदन करूंगा कि स्टेट लेवल पर ही नहीं बल्कि स्टेटलेवल पर भी जहां अस्पताल हैं वहां पर विजिलेन्स के रूप में एडवाइजरी के रूप में चुने हुए लोगों की कमेटी मुकर्रर करे जिसमें पब्लिक के नुमायन्दों के सहयोग से अच्छी तरह से काम चला सकें और उनको गाइडेन्स सही तौर से मिल सके। इससे जनता को और होस्पिटलों को दोनों को फायदा होगा।

दूसरी बात मैं अलवर के होस्पिटल के बारे में कहूंगा। अलवर में जनरल होस्पिटल है उसमें प्राइवेट वार्ड में सरकार ने बढ़ोतरी की है उसमें एक बात की बहुत बड़ी कमी है। प्राइवेट वार्ड में किसी किस्म का बरामदा नहीं है और होस्पिटल में जाने के लिये कोई एप्रोच नहीं है। जो भी मरीज प्राइवेट वार्ड से एक्सरे के लिये जावे तो उनको या तो पीठ पर रख कर ले जाना पड़ता है या स्ट्रेक्चर पर ले जाया जाता है। ये वही पुराने बैकवर्ड तरीके हैं। मरीजों को किसी प्रकार से ट्रौली में ले जाया जावे इसका प्रबन्ध नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

माननीय मन्त्रीजी ने इस जनरल हॉस्पिटल को देखा है और उनको यह भी मालुम होगा कि यह बीच का रास्ता है वह ८० गज या १०० गज का होगा। १०० गज से कम ही होगा। इसमें कवर्ड बरामदा बनाइें तो उसमें मरीज आराम से वर्षा से भी बच सकेगा और कवर्ड होने से ट्रोली में जा सकता है और इस समय जो दिक्कत पेश आती है उससे छुटकारा मिल सकता है।

इसके अलावा वहां का आउट डोर है वहां पर जो मरीज गाँव से या बाहर से आते हैं उनके लिये खाने पीने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं है और न उनके लिये कोई लेटरिन का या युरिनल का प्रबन्ध है। इसके अलावा ड्यूटी डॉक्टर है उसमें कोई अलग रूम नहीं है। प्राइवेट वार्ड में जाकर अपनी जरूरतों को पूरा करना पड़ता है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह बहुत जरूरी चीज है और इसकी तरफ गवर्नमेंट का फौरन ध्यान देकर इस जरुरत को पूरा करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि एक पब्लिक हेल्थ लेबोरटरी का देश। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से इसका सम्बन्ध है लेकिन कोरडीनेट हैल्थ से है। हमारे प्रान्त में १३ हेल्थ लेबोरटरीज और उनमें से १० प्राइमरी हैल्थ लबोरेटरीज जो ५६ से ६४ के बीच में बनी और ये जो १३ हैल्थ लेबोरेट्रीज हैं उनका कर्तव्य यह है कि मिलावट को रोकें और देखें कि कोई किसी चीज में मिलावट तो नहीं करता है और टेस्टिंग हो। मगर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन १३ हैल्थ लेबोरेट्रीज में....

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने विषय से बहुत दूर जा रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय में पब्लिक हैल्थ की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। और मैंने पहले भी माननीय मन्त्री को इसके लिये ध्यान दिलाया है। इसका खर्चा गलत तरीके से हो रहा है १० हैल्थ लेबोरेट्रीज तो ऐसी है जिनमें एक भी टेस्ट नहीं हुआ है। इससे हमारे लाखों रुपयों का फालतू खर्चा होता है। यह हमारे लाखों रुपये जो इसमें खर्च हो रहे हैं अगर इनका सही उपयोग नहीं होता है तो इनको बन्द कर दीजिये या अगर आप चलाना चाहते हैं तो अलग से क्यों चलाते हैं ? जनरल होस्पिटल में किसी भी डॉक्टर को इसके लिये अलाउन्स देकर रख दीजिये और उसको इसकी जिम्मेदारी दे दीजिये जिससे इन लाखों रुपयों के खर्चे को, जिसका कोई उपयोग नहीं होता है, बन्द करिये।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं दो चार बातें वाटर वर्क्स के बारे में 'निवेदन करना चाहूँगा। आज वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जाता है कि मीटर नहीं मिलते और इस वजह से कि मीटर नहीं मिलते हैं, पब्लिक में दिक्कत आ रही है और इससे सरकार को काफी नुकसान हो रहा है। इसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और यह निवेदन करूंगा कि सरकार की उपेक्षा की दृष्टि रही है।

Page No. 88

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पहले तो मीटर यों ही बहुत कम लगे हैं और इसलिये सरकार फिक्स रेट चार्ज करती है और इससे ऐसे लोगों को इस बात का मौका मिलता है कि वे ज्यादा से ज्यादा पानी का उपयोग करें और उनको मिनिमम चार्जेज देने पड़ते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि मीटर कोई ऐसी चीज नहीं है जो उपलब्ध नहीं हो सकते हों। इसलिये गवर्नमेंट को लोगों को मीटर उपलब्ध करने चाहिये ताकि सही पैसे जो हो वह मिल जावें।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहूंगा कि ७० परसेन्ट मीटर बन्द पड़े हैं और उनके चार्जेज पिछले साल की जो भी उस माह की रीडिंग थी उसके बुनियाद पर इस साल भी पैसा वसूल किया जाता है। मैं समझता हूँ कि इससे भी यह वाटर वर्क्स लौस में रहता है और यह एक उसके लौस में जाने का बहुत बड़ा कारण है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इस बात की जानकारी करेगी कि कितने मीटर चालू हालत में हैं और कितने खराब हालत में हैं और जो खराब हालत में हैं उनको क्या ठीक कराने का प्रबन्ध किया जावेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट अपनी उपेक्षा पूर्ण नीति को छुपाने की कोशिश करता है। आज भी मैं यह कहूँगा कि मीटर वाटर वर्क्स में बहुत रखे हुए हैं। वे मीटर खराब हैं। उनको ऐसे ही ले लिया गया था और उनका प्रोपर टेस्टिंग नहीं कराया गया। और प्रोपर टेस्टिंग नहीं होने से काम में नहीं आ सकते हैं इसलिये वे पड़े हुए हैं मेरी जानकारी के अनुसार कामानी के मीटर का कारखाना है वहाँ से खरीदे गये और अलीपुर में उनका टेस्टिंग होना चाहिये, नहीं हुआ और उनकी सप्लाई ले ली गई उसका नतीजा यह हुआ है कि जनता को तकलीफ होती है और मीटर नहीं लगते हैं और मीटर नहीं लगने से वाटर वर्क्स को भी नुकसान होता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बात कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ और वह है अलवर में मीटरों के बारे में। इसके लिये दो तीन बार प्रश्न उठाये गये और कल प्रश्न काल में इसका उत्तर दिया गया। मगर मैं यह कहूंगा कि अलवर में वाटर वर्क्स को लगे ११ वर्ष हो गये मगर उसकी स्थिति वैसी ही है जैसी पहले थी। वहां ९ बजे बाद पानी आना शुरू होगा और दो घन्टे बाद बन्द हो जाता है। पानी का प्रेसर बहुत कम रहता है और ऊपर की मंजिल में तो पानी पहुंचता तक नहीं। सरकार ने अभी एक ट्यूब वेल खोद रखा है। उसमें विशेष पानी नहीं आया और स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और वास्तव में पानी की सप्लाई में कोई बढोतरी नहीं हुई। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि वाटर की सप्लाई के लिये बिजली विभाग को यह कहना चाहिये सबसे पहले प्रायोरिटी वाटर वर्क्स को दी जानी चाहिये और इसके लिये बिजली में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिये। बावजूद मंत्री महोदय के इस बात के आश्वासन के कि सरकार इस में बिजली की कमी नहीं करेगी मगर आज पानी

Page No. 89

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पूरी तरह से सप्लाई नहीं होने का एक कारण बिजली की सप्लाई पूरी नहीं होने के कारण है और दूसरी बात इस डिपार्टमेंट की खामियें और कमजोरियें हैं।

अलवर को वाटर सप्लाई पूरी करने को जो योजना गवर्नमेंट ने बनाई है वह ३८ लाख की योजना है। पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस योजना को लागू करने के लिये क्या प्रोग्राम है। क्या गवर्नमेंट ने इसके लिये कोई फेज प्रोग्राम बनाया है। यह योजना कब शुरू होगी और कब समाप्त हो जावेगी क्या इसका कोई सरकार ने ब्रेक अप किया है। इस बात को हम बहुत अर्से से कहते आ रहे हैं कि रूपारेल के पास से ट्यूब वेल्स से पानी लावेंगे। हमारे यहां अलवर के राजाजी जो पहले थे और जिनका स्वर्गवास हो चुका है वे भी इसी बात को कहा करते थे कि ट्यूब वेल्स से अलवर की जनता को पानी पिलाऊंगा मगर मैं कहूँगा कि उनका यह स्वप्न पूरा नहीं हुआ और वह एक मात्र उनका स्वप्न ही रह गया। मैं माननीय मन्त्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि आपका भी यह कहीं सपना ही न रह जावे। वास्तविक रूप आपने इसके लिये किस प्रकार का लेना तय किया है, आप इसके लिये क्या इन्तजाम करते हैं।

मैं यह निवेदन करूंगा कि अभी पिछले वर्ष वाटर वर्क्स की प्रोपर्टी को आपने अपने ही हाथ में ले लिया है। यह एक वाटर वर्क्स की तानाशाही का रवैया देखें। आप किसी चीज को एक्वायर करना चाहते हैं आपको चाहिये कि उसके लिये पहले नेगोशियेशन करें, बातचीत करेंगे मगर आपने उसकी कोई जरूरत नहीं समझी। गवर्नमेंट का आउट स्टेन्डिंग मनी था गवर्नमेंट ने ओर्डर निकाल दिये कि गवर्नमेंट इसकी मालिक बन सकती है। हो सकता है कि कुछ भी पैसा म्यूनिसिपैलिटी ने नहीं लगाया हो लेकिन वाटर वर्क्स हैं उसमें म्यूनिसिपैलिटी ने केपिटल के रूप में २ लाख ३८ हजार इन्वेस्ट किया था। आज जो अलवर म्यूनिसिपल बोर्ड की प्रोपर्टी है वह पब्लिक प्रोपर्टी है और हाउसिंग के लिये जो पैसे दिये थे उसको वापिस न दें यह उचित नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

आज आपके मन पसन्द के लोग म्यूनिसिपैलिटी में हैं और वे आपकी धांधली से ऐसा नहीं करें तो इल्लीगल कार्यवाही अपने मन पसन्द लोगों के द्वारा करने से वह लीगल नहीं हो सकती। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि यह आपका म्यूनिसिपल बोर्ड के साथ अन्याय है। यह केपिटल एमाउन्ट तो आपको वापिस देना चाहिये और फिर आप वाटर वर्क्स को अपने हाथ में ले सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रावतराम।

श्री रावतराम (छापर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पहले पूर्व वक्ताओं ने काफी इस के सबन्ध में कह दिया है। मैं भी इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आज जब हम सोचते हैं तो हमको खास तौर से गांवों के रहनेवाले लोगों की हालत है उसकी तरफ ध्यान देना होगा। आज हम देखते हैं कि इतने दिनों के बाद भी उन गांवों के रहने वाले लोगों की हालत में कोई सुधार नहीं और सरकार

(श्री रावतराम)

की तरफ से सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। एक वर्ग जो आज राज्य चला रहा है उस वर्ग को यह समझना चाहिये और यह मान कर चलना चाहिये कि गांवों में रहनेवाले लोग भी इन्सान होते हैं और इन्सान की तरह से उन पर भी सरकार को ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज हम इस बात को सोचें कि आज राजस्थान का ही हम प्रश्न लें जहां तक अरबन पोपुलेशन का सवाल है, रूरल का प्रश्न है, इस बात को सोचें तो यह मान कर चलें कि आज अरबन पोपूलेशन को जो फेसिलिटीज मिल रही हैं, जो सुविधा मिल रही है वे गांव में बसने वाले किसान को नहीं मिलती है। सरकार की ओर से बड़े जोरदार स्लोगन्स दिये जाते हैं 'जय जवान, जय किसान'। यह कहा जाता है सरकार की तरफ से कि किसान देश की रीड की हड्डी है। वह अन्न देता है, अन्न पैदा करके देता है। लेकिन जब उस किसान को कुछ सहूलियतें देने का प्रश्न आता है, फेसिलिटीज, पानी देने का प्रश्न आता है, उसको दवाइयें देने का प्रश्न आता है तो उस समय गांव के लोगों को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया जाता है। मैं तो यह कहूँगा कि उनको निग्लेक्ट ही नहीं करते बल्कि उनकी उपेक्षा करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हमें गांव के लोगों के लिये दवाई, पानी का माकूल प्रबन्ध करना होगा। जहां तक एलोपैथिक ट्रीटमेंट का प्रश्न है, सरकार कहती है कि डाक्टरों की कमी है इसलिये होस्पिटल गांव गांव में नहीं खोल सकते। ठीक है। इसके लिये मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ जब आप मेडिकल डिस्पेन्सरीज नहीं खोल सकते हैं तो कम से कम आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरीज तो खोल ही सकते हैं। हम आयुर्वेद को प्रोत्साहन दें। हमें कुछ तो उनके लिये प्रबन्ध करना है। आज हम आयुर्वेद का बजट देखें और एलोपेथी का बजट देखें तो मालूम होगा कि उनमें बहुत बड़ा अन्तर है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां पर आपने एलोपेथी के लिये बजट रखा है चिकित्सा के लिये ६४.९३ लाख वहां आपने आयुर्वेद के लिये ११.५८ लाख रखा है। तो आज आप आयुर्वेद को प्रोत्साहन नहीं देते हैं। इससे प्रकट होता है कि हमारी आस्था आयुर्वेद में नहीं है।

लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हम डिस्पेन्सरीज गांवों में नहीं खोल सकते, अगर हम उनको खर्चीला समझते हैं तो हमें आयुर्वेदिक औषधालयों को प्रोत्साहन देना चाहिये और ज्यादा से ज्यादा संख्या में उनको गांवों में खोलना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में लगभग ३२ हजार गांव हैं, हम एक लक्ष्य रख कर चले थे कि तृतीय योजना के पूरी हो जाने के बाद प्रत्येक १३ गांवों पर एक औषधालय खोल देंगे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज तक हम २५ गांवों के पीछे एक औषधालय भी नहीं खोल पाये हैं। इसके अलावा आपने जहां भी आयुर्वेदिक औषधालय खोले हैं उनमें आपने चुरू जिले को नेगलेक्ट किया है। वह एक रेगिस्तानी इलाका है। बड़े दूर दूर तक गांव फैले हुए हैं, जहां आवागमन का साधन नहीं है। आप अनुमान लगाइये जब एक शहर में

(श्री रावतराम)

रहने वाला व्यक्त जहां अस्पताल है, एक्स रे मशीन है और सब तरह की चिकित्सा सुविधा हैं। आप उनके मुकाबले गांवों की कल्पना कीजिये गांव का व्यक्ति बीस मील चल कर आने पर तहसील हैड क्वार्टर पर या जिला हैड क्वार्टर पर आकर वह कहीं मरहम प्राप्त कर सकता है। जहां हम यह समाजवादी नारा देते हैं लोक कल्याणकारी राज्य हम जिसे कहते हैं हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा चिकित्सा सुविधाएं किस प्रकार दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी जैसा कि मैंने चुरू जिले का जिक्र किया, मैं सदन के सामने आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। चुरू जिले के जो ६३-६४ के आंकड़े मिले उसके अनुसार चुरू जिले की पोपूलेशन ६.६१ हजार है और वहा ३८ औषधालय हैं। बांसवाड़ा जिला जहां ४.७१ लाख है, वहां ४१ औषधालय हैं हालांकि चुरू के मुकाबले वहां पोपूलेशन दो लाख कम है। डूंगरपुर में ४.७ लाख औषधालय ४५। झुंझनू में ७.२० लाख पोपूलेशन औषधालय २६ और सवाई माधोपुर पोपूलेशन ६ लाख और औषधालयों की संख्या ११० है। मैं इन आंकड़ों को प्रस्तुत कर यह निवेदन करना चाहता हूं कि औषधालयों का डिस्ट्रीब्यूशन हरेक जगह पर ठीक से होना चाहिए।

इसके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम चाहते हैं कि गांव के आदमियों को रिलीफ मिले। मेरा आपसे निवेदन है कि आपको कम से कम दस दस गांवों की एक यूनिट बनानी चाहिए ऐसे गांवों के लिए मोबाइल डिस्पेन्सरीज की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर आप हरेक गांव में डिस्पेन्सरीज या औषधालय नहीं खोल सकते तो दस गांवों के पीछे या पन्द्रह गांवों के पीछे इस तरह का प्रोग्राम बनाकर मोबाइल डिस्पेन्सरीज चालू कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं आज गांवों की क्या हालत है इन पर भी विचार करना चाहिये। आज शहर में मेटरनिटी होम्स हैं। शिशु औषधालय हैं और हर प्रकार की सुविधाएं हैं आप कल्पना कीजिये गांवों की जहां आपकी इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। इसके कारण हर साल गांवों में सैकड़ों प्रसूता औरतों की मृत्यु हो जाती है आज आप उनको इस युग में भी रिलीफ देना नहीं चाहते। मैं आपसे निवेदन करता चाहता हूं कि यह आपका फर्ज है प्रत्येक गांव में एक दाई और नर्स का रखना जरूरी है। आपने जहां कस्बे में डिस्पेन्सरी खोलकर उनके सम्भाल करने की व्यवस्था की है। पशुओं के लिए व्यवस्था की है। लेकिन इन्सान के लिए कोई व्यवस्था नहीं है वहां यह भी कह सकता हूं कि प्रसूता औरतों के लिए गांवों में सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। यह हमारे लिए सोचने की बात है इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना जरूरी है।

इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा आयुर्वेदिक को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए चौथी प्लान में कम से कम यह टारगेट करेंगे कि हरेक पंचायत में एक औषधालय जरूर हो।

मेरा दूसरा कटौती का प्रस्ताव जन स्वास्थ्य के बारे में है। मैं जल प्रदाय योजना

(श्री रावतराम)

के बारे में कई बार इस हाउस में ध्यान आकर्षित कर चुका हूं। चुरू, बीदासर और चाड़वास ये कस्बे ऐसे हैं जहां की आबादी दस हजार प्रत्येक कस्बे की है चाड़वास की कुछ कम आबादी है कोई भी व्यवस्था पानी की नहीं है। इन तीनों कस्बों में पानी की ऐसी हालत है कि गर्मियों में बड़ी परेशानी का अनुभव करना पड़ता है। बीदासर में एक कुआ है उस कुएं पर आप देखेंगे सैकड़ों की संख्या में औरतें क्यू बनाकर खड़ी हुई आपको दिखाई देंगी वे पानी के लिए सुबह से लगाकर शाम तक खड़ी रहती है। जो सम्पन्न व्यक्ति हैं वे बाहर से दस पन्द्रह माइल दूर से पानी मंगवाते हैं। सरकार ने कई बार आश्वासन दिया है, मुख्य मंत्री महोदय तो तीन बार गए हैं उन्होंने यह कहा भी है कि इस साल कर देंगे, पहले सर्वे करायी गई, पानी का स्रोत मिल गया पनवासर के गांव में पर्याप्त रूप से पानी मिला है। इसके लिए बीदासर के नागरिक २.५० हजार रुपये भी देने को तैयार हैं सरकार उनको स्वीकार नहीं कर रही है। इसी तरह से छापर के लोग भी दो लाख रुपया जमा कराने को तैयार है लेकिन सरकार कहती है कि हमें समय नहीं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि वे इन्कार क्यों करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय छापर में जो लोग बसते हैं वे व्यास हैं वे सब पानी की कमी से पीड़ित हैं। मैंने वहां के लोगों से कहा कि अब दामोदरजी व्यास के हाथ में है वे जरूर इस काम को पूरा करवायेंगे।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : व्यास व्यासोंका पक्ष नहीं करेंगे तो वे कैसे याद करेंगे ?

श्री रावतराम : मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मन्त्रीजी विराजमान हे उन्हें यह कार्य जितना जल्दी हो सके हाथ में लेना चाहिये अगर इस प्रकार की योजनाओं को निग्लेक्ट करके चला गया तो हम यह मानकर चलेंगे कि सरकार इसमें भी उपेक्षा वृति दिखलाती है। जब वहां के लोग जन सहयोग देने के लिये तैयार हैं इसके बावजूद भी आप इन्कार करते हैं यह शोभा की बात नहीं हैं।

इसी के साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय गांवों की जो जल प्रदाय योजनायें हैं उसके बारे में विशेष तोर से चुरू जिले के लिये निवेदन करना चाहता हूं तीसरी प्लान के बाद तो कम से कम यह गांवों में कोई योजना चालू नहीं की गई। सर्वे किया गया बड़ी बड़ी योजनायें बनाई गई लेकिन किसी गांव में भी यह योजना चालू नहीं की गई। इसके भविष्य में हम आपसे क्या आशा लेकर चलें। मैं यह जानना चाहता हूं जब आपने सर्वे कर लिया तो फिर काम चलाने में क्या लापरवाही।

चूरू जिले के पन्द्रह बीस गांवों में बिजली लगी है जहां भी बिजली गई है वहां के लोग तैयार हैं जो भी जन सहयोग आप चाहेंगे वे देने को तैयार हैं। आप वाटर सप्लाई योजना तैयार करें जहां जहां से बिजली की लाइन गई है वहां पर आप इस तरह की योजना तैयार करें।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय में यह निवेदन करना चाहता हूं हम लोग जो एक कल्पना लेकर चले थे जो गांधीजी की कल्पना थी। देश में आजादी आयेगी गांवों में राम

(श्री रावतराम)

राज्य आ जायगा शहरों और कस्बों मे रहने वाले लोग गांवों की ओर चले आयेंगे लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आज हालत इसके विपरीत हो रही है गांव का आदमी शहर की तरफ बढ़ता जा रहा है। आज इनको गांव की तरफ जाने में कठिनाई महसूस हो रही है और वह इसलिए होती है कि वहां पानी की समस्या है, गांवों में बिजली नहीं है, वहां सड़कों के साधन नहीं हैं, आवागमन के साधन नहीं हैं, डिस्पेन्सरी नहीं है, ऐज्यूकेशन के साधन नहीं है, इसलिये हर आदमी जो गांवों मे रहने वाला है वह आज शहरों की तरफ बढ़ रहा है। गांवों में रहने वाले जितने लोग थे, जिन्होंने एज्यूकेशन ली उन्होंने शहरों में आकर बंगले बना लिए और शहरों में बैठ गये क्योंकि उनको यहां शहरों में हर तरह की फैसेलिटीज है, गांवों में इस प्रकार की फैसेलिटीज नहीं हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि यह रूरल डेवलपमेंट का महकमा, रूरल वाटर सप्लाई का महकमा आपके पास है गांवों में यह सारी सुविधाएं प्रदान कीजिये, गांवों को जितना सुन्दर बनायेंगे, वहां जितनी अधिक फैसेलिटीज आप देंगे उतने ही ज्यादा गांव सुन्दर बनेंगे और गांवों में रहने वाले लोगों की जिंदगी बनेगी। आज गांवों में यातायात की बड़ी भारी समस्या है, न वहां मोटर है, न रेलगाड़ी की व्यवस्था है, आप क्यों नहीं गांवों में आवागमन के साधन बढ़ाते? आज १५ साल हो गये पंचायत समितियों को और दूसरे महकमों को, आपके इन महकमों ने गांवों मे क्या काम किया है, क्या कोई मोडल गांव आपने बनाया है, एक भी मोडल गांव आपने नही बनाया, आवश्यक सारी इस प्रकार की सुविधाएं देकर आपने एक भी मोडल गांव नहीं बसाया है, आज गांवों में लेटरिन तक जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, डेवलपमेंट के महकमों ने गांवों में कुछ नहीं किया है, सुधरे तरीके की टट्टियां गांवों में दिखाई नहीं देतीं, कोई सामाजिक कार्य गांवों में नजर नहीं आते। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आज बड़ी प्रोब्लेम हमारे सामने है कि गांवों के लोग शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको रोकने के लिए जो हमारी बुनियादी सुविधाएं हैं, उनको पूरा नहीं करेंगे तो गांवों के रहने वाले लोग शहरों की तरफ बढेंगे और एक दिन होगा कि यदि गाव के रहने वाले लोग शहरों मे आ गये तो आपके बंगले छिनने की नौबत आ जायगी समुचित सुविधाएं गांवों में प्रदान करके गांवों को सुन्दर नहीं बनायेंगे तो आपके बंगले भी नहीं बच सकेंगे, आपके बंगलों को बचाने के लिये भी गांव वालों को सब प्रकार की सुविधाएं देकर गांवों को सुन्दर बनाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ फेमिली प्लानिंग के लिये भी दो शब्द कह दूं। आज फेमिली प्लानिंग चल रहा है। १९६१ में हमारे देश की आबादी ४६ करोड़ थी, आज हम ५१ करोड़ हो गये हैं। एक साल मे एक करोड़ बढ़ते जा रहे हैं। इसको रोकने की सरकार की जिम्मेदारी है, इसे रोकने के लिये हर तरह से सोचना पड़ेगा। हम केवल डिस्पेन्सरीज के जरिये, या और तरीकों से रोकेंगे तो यह नही रुक सकेंगे, इसको रोकने के लिये लोगों का मानस बदलना पड़ेगा, लोगों का आउट लुक बदलना पड़ेगा, लोगों का दिमाग इस प्रकार का बनाना होगा।

(श्री रावतराम)

आज लोगों का दिमाग बदला नहीं है। इस सम्बन्ध में सरकार को दो तरह से काम करना चाहिये। एक तो लोगों का मानस बनाना चाहिये, यह भगवान की देन नहीं है लोग मान बैठे हैं कि जिसके ज्यादा बच्चे होते हैं वह ज्यादा भागवान् माना जाता है। हमारे गांव में एक दम्पत्ति के १३ लड़के थे, उनको गांव के लोग पूजते थे, सारी स्त्रियां उसका आदर करती थी कि यह सबसे ज्यादा बच्चों वाली है। पर आज वह स्थिति नहीं है, उन लोगों के दिमाग को बदलना है, लेकिन अफसोस है कि हमारी इसमें आस्था नहीं है, जो फेमिली प्लानिंग को चलाने वाले हैं, जो यह महसूस करते हैं कि फेमिली प्लानिंग होना चाहिये उनको भी यह चीज महसूस नहीं होती है। आज भी हमारे मन्त्रीमण्डल के भूतपूर्व मन्त्रियों के दर्जनों बच्चे बढ़ते गये हैं, भीखाभाई इसके उदाहरण हैं।....

एक माननीय सदस्य : मुख्य मंत्रीजी के कितने बच्चे हैं ?

श्री रावत राम : तो मैं आपसे निवेदन करूं कि आपको दो साइड में काम करना चाहिये एक तो लोगों का मानस बनाने के लिये और दूसरा यह कि मोबाइल डिस्पेन्सरीज खोलें, उस तरह केम्पेन चलाना चाहिये। लोगों को प्रोत्साहित किया जाय, लोगों का इस प्रकार का दिमाग तैयार किया जाय, उनका मानस बनाया जाय तो लोग आपरेशन कराने के लिये, लूप लगाने के लिये तैयार हो जायेंगे। आप यह सारे साधन लेकर गांवों में जाइये, अगर आप तय कर लेंगे कि एक हजार आपरेशन करेंगे तो वहां डेढ हजार ओपरेशन कराने के लिये लो। तैयार हो जायेंगे। मैंने देखा है कि लोग शहरों में ओपरेशन कराने के लिये जाते हैं, डाक्टरों के पास जाते हैं पर डाक्टरों के पास साधन नहीं है डाक्टर उनको यह कह देते हैं कि चूरु जाओ, रतनगढ़ जावो। आज यह स्पष्ट है कि आपके पास प्लानिंग नहीं है। आप प्लानिंग करके दो तरीके से कार्य करिये, एक तो यह कि समाज का आउट लुक बदलना पड़ेगा, और दूसरे यह कि साधन जुटाने पडेंगे।

यही कटौती प्रस्ताव रखकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव मेरे क्षेत्र की समस्याओं के सम्बन्ध में है।

एक माननीय सदस्य : सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री भीमसेन : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले १७—१६ वर्षों में विकास के कारण औषधालयों, डिस्पेन्सरियों और हास्पिटल्स की संख्या बढ़ी है, इसके साथ ही साथ नम्बर आफ बेड्स भी हमारे यहां बढा है। हिन्दुस्तान के अङ्कों से मुकाबला करें तो राजस्थान इस मामले में अग्रणी है। जहां औषधालयों, डिस्पेंसरियों अस्पतालों की संख्या और बेड्स की संख्या का प्रश्न है, हिन्दुस्तान में राजस्थान सर्वोपरि है। पर

(श्री भीमसेन)

राजस्थान बहुत बड़ा है इसलिए इनकी संख्या को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है, जगह जगह डिस्पेंसरीज, औषधालय खुलवाने की व्यवस्था करनी है, इसमें दो राय नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि बीकानेर का होस्पिटल बहुत बड़ा होस्पिटल है, उसके एक आपरेशन थियेटर को तो कम से कम अवश्य ही वातानुकूलित करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ वहां पर कोबाल प्लान्ट है, जहां कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, वह प्लान्ट ऐसा है कि गरमी में वहां आदमी बैठ नहीं सकता इसलिए उस कोबाल प्लांट को वातानुकूलित बनाने की आवश्यकता है, यह अहम समस्या है वहां की।

लूणकरणसर में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोला गया, वहां एक दानी महाशय ने एक लाख रुपया दिया। सरकार का सर्कुलर निकला हुआ है कि जहां एडीशन होता है, ३ में से एक सब्सिडरी एक एड पोस्ट हो वहीं होना चाहिए। हमारे यहां २ एड पोस्ट्स हैं, लूणकरणसर और कालू से कुम्भेड़ शिफ्ट किया जा रहा है, एक सबसेन्टर वहां होना चाहिये। हमारी पंचायत समिति और हम चाहते हे कि लूणकरणसर तहसील हैड क्वार्टर है इसलिये एक सब हैड क्वार्टर वहां होना चाहिए, पर टेक्निकल रीजन्स से यह मामला तय नहीं हो रहा है। तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के लोगों की भावनाओं को देखते हुए एक सब सेन्टर वहां करने की कोशिश करेंगे।

लूणकरणसर और बीकानेर का रेगिस्तानी एरिया है, पीने के पानी की वहां कमी है। कहीं पानी की सुविधा है तो वहां कुएं गहरे होने के कारण पानी खींचने में काफी खर्चा आ जाता है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि रूरल वाटर सप्लाई की स्कीम है, उसको रेगिस्तानी इलाकों में प्रायोरिटी देनी चाहिये क्योंकि वहां पानी खींचने के लिये बड़ा खर्चा करना पड़ता है। हमारे यहां मीठे पानी का कुआ है, उस क्षेत्र में पानी मिलना दुर्लभ है, जहां मीठा पानी है वहां वाटर सप्लाई की स्कीम को जल्दी से जल्दी अमल में लाना चाहिए। केरवाल, तादोलाई, रामसर, नापासर ये बड़े गांव हैं, वहां पशुओं की भी काफी संख्या है, वहां पीने का अच्छा पानी मिलता है। मैं समझता हूं कि सरकार इन गावों के लिए वाटर सप्लाई की स्कीम को चालू करेगी।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष जी, खास तौर से हमारे राजस्थान में पोपुलेशन है, हिन्दुस्तान की औसत पोपुलेशन से बढ़ रही है। २.१ परसेन्ट के हिसाब से पोपुलेशन हिन्दुस्तान में बढ रही है वहां राजस्थान में २.६ परसेन्ट राजस्थान में बढ रही है। इस बारे में सरकार को विशेष एफर्टस करने की आवश्यकता है। हमारे यहा की बैकवर्डनेस को देखते हुए राजस्थान की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो सकती है इसलिए सरकार को इस ओर खास एफर्ट्स करने की आवश्यकता है। खास तौर से मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि इस बारे में कानून बनाये कि

(श्री भीमसेन)

चाहता हूं कि इस बारे में कानून बनायें कि कुछ ऐसे विशेष श्रेणी के लोग जैसे भिखमंगे हैं या ऐसे हैं जो लाइलाज हैं, उनका कम्पलसरी करदें तो राजस्थान में जो आबादी की वृद्धि हो रही है और लोग अपने बच्चों को संभाल नहीं सकते कम से कम उनका कम्पलसरी स्टेरीलाइजेशन होगा, ऐसा कानून बना दे तो अच्छा है ।

हमारे यहां नापासर में डिस्पेन्सरी थी, उसकी जगह प्राइमरी हैल्थ सेन्टर कायम हो गया लेकिन वह पाँच छः वर्षों से कहां कायम हो रहा है पता नहीं । पंचायत समिति ने मांग की थी कि इसे नारोंदा में स्थापित किया जाय और गांव के लोगों ने बिल्डिंग भी बनाई लेकिन नापासर की डिस्पेन्सरी के लिए सरकार से मांग करूंगा कि उस डिस्पेन्सरी को पंचायत समिति के प्रस्ताव के अनुसार नारोंदा में कायम किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह रावत ।

श्री देवीलाल : उपाध्यक्ष महोदय मुझे बोलने का कोई समय नहीं दिया जाता है ।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे चिकित्सा और जन स्वास्थ्य की मांग पर ६ कटौती प्रस्ताव हैं जिनको मैं एक साथ मूव करता हूं, आज २० वर्ष हो गये हमारा देश आजाद हुआ। नसीराबाद एक महत्वपूर्ण स्थान है जो राजस्थान में किसी भी नागरिक से छिपा हुआ नहीं है। अगर सुरक्षा की दृष्टि से भी देखें तो वह राजस्थान में प्रथम सिक्योरिटी स्टेशन है। यहां की जनता बहुत दुखी है और दुख केवल एक बात का है कि राज्य सरकार की तरफ से केन्द्रीय सरकार को कुछ वर्ष पहले इस बात का अनुरोध किया गया था कि मिलिटरी कैन्टोमेंट होने के नाते केन्द्रीय सरकार यहां पर बी ग्रेड अस्पताल की व्यवस्था करे। केन्द्रीय सरकार ने एक लाख रुपये इसके लिये मन्जूर भी किये लेकिन किन्हीं राजनैतिक कारणों से यह दूसरी अड़चनों के कारण यहां पर अस्पताल नहीं बन सका। इस समय नसीराबाद की आबादी २७ हजार है और दो मिलिटरी के ब्रिगेड्स का एकमोडेशन है। इसके अलावा रामसर, सरवाड, केकड़ी, मसूदा मंगलियावास और श्री नगर इत्यादी रूरल एरियाज की आबादी भी लगभग एक लाख है। ऐसी हालत में नसीराबाद के अन्दर आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि इस समय केवल दो बेड्स की एक डिस्पेन्सरी है। तो बीस साल बीतने के बाद अगर आपको थोड़ा रम भी हो तो ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर सी क्लास का एक अस्पताल कायम करने की व्यवस्था करें ताकि आसपास के क्षेत्र के लोगों को लाभ मिले अजमेर आते जाते बहुत से मरीजों की मृत्यु हो जाती है। अभी हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसके बारे में स्वयं गृह मंत्रीजी जानते हैं। उस मरीज की भी जान बच सकती थी अगर तत्काल इलाज की सुविधा होती लेकिन सिर्फ दो खाट की डिस्पेन्सरी है। उसमें भी कभी डाक्टर रहता है या नहीं। अब इस आबादी के अन्दर या तो राज्य सरकार स्वयं व्यवस्था करे या राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करे या कैन्टोन्मेंट के जरिये अस्पताल की जल्दी से जल्दी व्यवस्था करे।

(श्री विजयसिंह रावत)

दूसरी बात कि जो अस्पतालों में दवाइयां दी जाती हैं उनके अन्दर अनेक प्रकार के घोटालें है जिनके बारे में माननीय गिरधारी लालजी ने प्रकाश डाला है। मैं उनसे सहमत हूं। जो दवाइयां अस्पताल में आती हैं वे डाक्टर्स और अस्पताल के स्टाफ द्वारा उनके निजी कामों के लिये या रिश्तेदारों के लिये या मित्रों के लिये काम में ली जाती हैं और जो गरीब हैं जिनको यह दवाइयां मिलनी चाहियें उनको यह दवाइयां नही मिलती हैं। अतः एव मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कारगर कदम उठाये और इस भ्रष्टाचार को खत्म करे।

तीसरी बात कि जो जल प्रदाय योजनाएं हैं गांवों के लिये, वे आज तक असफल रही हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं? सबसे बड़ा कारण स्वयं सरकार ने रख दिया है कि इन्होंने नगर पालिकाओं का साढे तीन करोड़ रुपये का जो लोन था उसको राइट ओफ कर दिया और दो करोड़ का प्रावधान उनको लोन देने के लिये और रख दिया है तो कुल वह साढ़े पांच करोड़ हो गया। जिन कस्बों में चुनाव के दौरान वरिष्ठ नेताओं ने कहा था कि हम जल योजना लागू कर देंगे। उनके लिए उन्होंने ३० लाख से लेकर ८० लाख रुपये का प्रावधान भी रखा है। लेकिन वह जनता जो राजस्थान की खेतीहर है और गाँवों में रहती है, उनके लिये जल की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर करें भी तो बजट के अन्दर जिरो पर्सेन्ट रखा है यह खेत का विषय है कि आज गाँवों के अन्दर जिन तालाबों के अन्दर वहां के रहने वाले अच्छे पानी के अभाव में जो आजकल पानी पीते हैं वह इतना दूषित हैं जिसके कारण स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसके स्किन की बीमारियां; पोलियो का रोग पाड़ा जिसमें पैर के अन्दर पीप निकल कर आदमी सदा के लिए खतम हो जाय या हाथों जैसा पैर हो जाय। इसका कारण यह है कि शहर के अन्दर १२-१३ प्रतिशत लोग रहते हैं, वहां साढे ६ करोड़ रुपये रखे हैं। वहां पर कुछ ऐसा प्रावधान रखना चाहिए कि गांवों की जनता जो ८८ प्रतिशत है, उसको कुछ न कुछ राहत मिल सके। उनके जल संकट को दूर करने के लिये प्रावधान रखें जो तालाब हैं उनके अन्दर पानी भरता है, वहां गंदा पानी हो जाता है। बहुत से ऐसे तालाब हैं जिनके मोरियां नहीं हैं, निकासी का रास्ता नहीं है। इसलिए ऐसे कदम उठाए जायें जैसे श्री रावतरामजी ने कहा कि लोग शहरों में आकर नहीं बसें और शहरों में आकर फुटपाथ पर सोने की आदत न उनको पड़ जाय और वे गांवों में रहकर खेतीहर बन सकें।

चौथी बात मेरी यह है कि अजमेर जिले में मदार में टी. बी. सैनेटोरियम है, उसके अंदर खाटे कम हैं। टी. बी. एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमको बहुत जागरुक रहना चाहिए, गांवों में लोग इतने जागरुक नहीं हैं। इस बीमारी के कई भयंकर परिणाम हो सकते हैं तो इसलिए टी. बी. के कई केसेज होते हैं। जिनको एडिमिशन नहीं मिल पाता है कमी के कारण जैसा कि जयपुर के टी. बी. सैनेटोरियम में मैं गया था, वहां के पी. एम. ओ. ने कहा

(श्री विजयसिंह रावत)

कि भवन बना हुआ है लेकिन मेरे पास स्टाफ नहीं है, खाटों की व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं मरीजों को तीन महीने से ज्यादा नहीं रख सकता। अगर वह मरीज फिर गांव में जाता है तो उस बीमारी के फैलने का डर रहता है।

पांचवीं बात गांवों में जहां खेतीहर और मजदूर जनता रहती है वहां बहुत से ऐसे गांव हैं जिनकी जनसंख्या ३ हजार से अधिक है। ऐसे गांवों में डिलीवरी के केसेज को संभालने के लिए सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। इस कारण हजारों महिलाओं की मृत्यु होती है। सरकार को जच्चाखाने खोलने चाहिए और गांवों की गरीब महिलाओं को जो समझ नहीं सकतीं कि डिलीवरी के क्या परिणाम होंगे उनको बचाने के लिए जच्चाखाना खोलकर वहां दाइयां और मिडवाइव्ज रखें जिससे ये महिलायें मृत्यु से बच सकें।

चौथा मेरा सुझाव यह है कि जो खेतीहर लोग हैं, मजदूर लोग हैं, एक प्रश्न पूछा था मैंने यहां पर लेकिन चिकित्सा मंत्री उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाये, जो कुछ भी हो मुझे जो उत्तर मिला है मैं उससे संतुष्ट नहीं था। खेतीहर लोगों को अच्छी तरह से मेडीशन नहीं मिलती है।

अस्पतालों में भ्रष्टाचार है। गांवों से लोग आते हैं। मैं डा० भाटी साहब का समर्थन करता हूं। एक्सरे प्लेट्स और लैबोरेटरी चार्जेज सरकार माफ कर दे तो भ्रष्टाचार दूर हो सकता है।

हमारे देश में भिखारी ज्यादा बनते जा रहे हैं। उसका कारण यह है कि जैसे टी. बी. की बीमारी होती है, या एक्जीमा की बीमारी होती है, या दूसरी बीमारी होती है, जो आदमी होस्पिटल में रहते हैं वे होस्पिटल में ठीक नहीं रह पाते हैं तो फिर उनका स्वास्थ्य गिर जाता है और उनकी देख रेख करने वाला कोई रिश्तेदार नहीं होता है तो सड़क पर आकर वे भीख मांगते हैं। विदेशी लोग आकर देखते हैं। इससे देश की प्रतिष्ठा भी गिरती है वे देश की प्रतिष्ठा गिराने में सहायक होते हैं। ऐसे आदमियों के लिये सरकार व्यवस्था करे कि रोग से ग्रस्त होने के बाद उनको अनाथालय या ऐसी दूसरी किसी जगह रखें। विदेशी लोग विदेशों में कहते हैं। हम विदेशों में घूमते थे तो विदेशी लोग कहते थे मेरा लैंड लोर्ड कहता था:—

In India I have seenm any beggers who veg for the piece of bread, who beg for the employment and beg for the medicines also.

कई एक केसेज वह कहते हैं................

श्री मदनसिंह दांता : वे नहीं कहते हैं। मैं कहता हूं आप अनाज भीख मांग कर खाते हैं। सबसे बड़े भिखमंगे इस कांग्रेसी राज में अपन हुए हैं।

श्री विजयसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में कहूंगा मेरे कटौती प्रस्ताव हैं वे खेतीहर लोगों को सुलभ दवाई न मिलने

(श्री विजयसिंह रावत)

और होस्पिटल्स में घोटाले होते हैं। उनके बारे में हैं।

अजमेर डिस्ट्रिक्ट में विदेशी मिशनरीज है। उन लोगों ने डिस्पेन्सरीज खोल रखी है और उनके माध्यम से धर्म परिवर्तन होते हैं। मैं इसके फेवर में नहीं हूं कि किसी को बहका कर उसका धर्म परिवर्तन कराया जायं। सहानुभूति दिखा कर और उन लोगों की विवशता को देखकर उनका बेजां फायदा उठा कर उनके साथ इस प्रकार के कारनामे विदेशी मिशनरीज कर रही हैं कि जिससे वे लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि अजमेर जिले में जहां दवाखाने नहीं हैं, विदेशी मिशनरीज के जहां दवाखाने खुले हुए हैं वहां आयुर्वेदिक औषधालय या दवाखाने जो भी आप खोल सकें, खोलें जिससे लोगों को दवाइयां चाहिए वह मिल सकें और और राहत मिल सके। स्वास्थ्य मंत्री को स्वयं को जानकारी है कि अजमेर जिले में क्या हो रहा है। ग्राम प्रदाय योजना के लिए, ग्रामीणों को दवाई सुगम तरीके से मिले इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री जो कारगर कदम उठायेंगे जिससे राजस्थान की जनता को राहत मिलेगी।

कई माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय.... ...

श्री उपाध्यक्ष : श्री लाभचन्द वैद।

डाक्टर अम्बालाल : उपाध्यक्ष महोदय.........

श्री मूलचन्द डागा : थोड़ा २ समय सबको मिल जाय।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर साहब का कटौती प्रस्ताव तो है नहीं। पहले आप बोल लीजिये फिर भी।

डाक्टर अम्बालाल जी।

डा० अम्बालाल (अजमेर पश्चिम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज का राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास से सम्बन्धित है। मेरा पचास वर्ष से इससे सम्बन्ध है। इसलिए आपके द्वारा इस सदन में ऐसे सुझाव रखूंगा कि जो देश के लिए उपयोगी हो सकें।

स्वास्थ्य राष्ट्र की बैक बोन है। स्वास्थ्य की गिरावट के तीन मुख्य कारण हैं। गरीबी, अज्ञान और करप्शन। दुर्भाग्य से हमारे यहां तीनों चीजें हैं। गरीबी इतनी है और यही मूलभूत कारण है। न अन्न मिलता है और न स्वास्थ्य के लिये साधन मिलते हैं। स्वास्थ्य की बैक बोन ही यही हैं। स्वास्थ्य कैसे रह सकता है। कई जगह गया हूं! झोंपड़ियां देखी हैं। बोम्बे में देखे हैं बड़े बड़े नरक जिनमें परिवार पैदा होते हैं। छोटी २ झोंपड़ियां बनी हुई हैं। एक झोंपड़ी में ६.८ आदमी रहते हैं। पानी नहीं मिलता है। सामने कूड़ा रहता है। वहीं टट्टियां जाते हैं, वहीं बच्चे पैदा होते हैं, वहीं मरते हैं और वहीं बीमार होते हैं और वहीं पर विवाह होते हैं। इतना वीभत्स दृश्य आपके द्वारा सदन के सामने रख रहा हूं। इसकी बेसिक मूलभूत चिकित्सा नहीं करेंगे तो स्वास्थ्य कैसे रह सकता है। यूरोप

Page No. 100

(डा० अम्बालाल)

अमेरिका में ९८ परसेन्ट चिकित्सा हो गई है। केवल हृदय रोग और कैंसर इन दोनों पर वह विजय नहीं कर पाये हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि स्टेन्डर्ड बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, स्वास्थ्य बढ़ा है या नहीं बढ़ा है यह संदेहास्पद है लेकिन नर कंकाल मनुष्य नरक जैसी जगहों में निराश पड़े मिलते हैं। दिन बदिन हालत गिर रही है। बेसिकली इस सारी प्रोब्लेम को हल करें और प्राब्लम्स हल हो जावेंगी यही मेरा निदान शुद्ध अन्न, जल और वस्त्र देने का आप सबसे है। पहले प्रबन्ध कीजिये। कल्याणकारी राज्य की मांग की गई। जहां अन्न नहीं, वस्त्र नहीं, जल नहीं मिलता, बीमार के वास्ते दवा नहीं मिलती क्या सचमुच यही कल्याण कारी राज्य है ? क्या यही समाजवाद है ? हमारा समाजवाद का लक्ष्य रहा है। हम भी चाहते हैं समाजवाद हो। लेकिन यह समाजवाद है कहां ? यह तो असमाजवाद है। एक वर्ग बढ़ रहा है और दूसरा वर्ग धीरे २ नीचे गिर रहा है। इसके लिये कितना भयङ्कर अज्ञान है। स्वास्थ्य नियम जानते ही नहीं। दुर्भाग्य से मैं भी डाक्टर हूं। डाक्टरों और वैद्यों में सबसे बड़ा करप्शन है आज। आप सब जानते हैं। यह हमारे राष्ट्र के करेक्टर का अङ्ग है। हम सब नीचे चले जा रहे हैं। १७ वर्ष में ऊपर से जितने नीचे आये हैं उसकी कोई सीमा नहीं। मेरे घर में तीन डाक्टर हैं। मेरे मित्र परिवार में बच्चे डाक्टर हैं। मैं देखता हूं निराशा भ्रष्टाचार बढता जा रहा है। डाक्टर भी उसी में हैं। निष्ठा कम होती जा रही है। अजमेर में मैंने देखा है। बड़े सर्जन हैं। लेडी डाक्टर नहीं आयी। एक ओपरेशन में ब्लड नहीं मिल सका जवान लड़की मर गयी। एक आदमी मर गया। ब्लड नहीं मिलता, खून नहीं मिलता।

मैं एक निवेदन कर रहा हूं आपसे। यह सारा वायु मण्डल ही दूषित होता जा रहा है। इसके दो कारण हैं। एक तो हमारे आज के नौजवान एं बिशश बहुत हैं, बहुत जल्दी धनवान बनना चाहते हैं। इसने उनकी कर्तव्य शक्ति को कुंठित और कुत्सित कर दिया है उनके सेवा के विचार बदल गये हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है आज सबसे बड़ा। दूसरा कारण है ठीक सुपरविजन का अभाव, नितान्त अभाव। तो इसके लिये या तो सुपर वाइजरी बोडी में स्वतः प्रेरणा का उदय होना चाहिये। वही सबसे अच्छा इसका उपाय है। वैसे प्रत्येक अस्पताल में एक आफीसियल और नान आफीसियल लोगों की सुपरवाइजरी बाडी बननी चाहिये जो अपना कर्तव्य समझे और देखे कि गरीबों को मैडिसिन मिलती है या नहीं, उनको खून मिलता है या नहीं। क्यों जरूरत हो किसी गरीब को या अन्य को अपने इलाज के लिये सिफारिश ले जाने की डाक्टर के पास।

उसका यह जन्म सिद्ध अधिकार है कि उसको पूरी डाक्टरी सहायता मिलनी चाहिये। साथ ही हमारे देश के शासन का यह परम कर्तव्य है कि वह इस बात का पता लगावे कि प्रत्येक आदमी को औषधि और उपचार आवश्यकतानुसार मिल रहा है या नहीं। अच्छी २ औषधियां बड़ों को मिल जावें या सिफारिशों से भले ही मिल जाय, पर गरीब को नहीं मिल पाती यह स्थिति असहनीय है। शासन के लिये कलङ्क है।

(डा० अम्बालाल)

सबसे बड़ा दुर्भाग्य है यह हमारा कि हमारा देश गरीब है। हम गरीबी की प्रोब्लम हल नहीं कर सके तो मैं समझता हूं कि हमारा स्वराज्य व्यर्थ है। प्रीमेच्योर मिल गया है यह हमें। हमारे परिपूर्ण होने से पहले पैदा हो गया है। हम तो कदम कदम पर यह देख रहे हैं।

तो हमारे अस्पतालों में यह बहुत आवश्यक है कि हरेक गरीब आदमी को बिना किसी सिफारश के औषधि और उपचार मिले और अच्छी से अच्छी औषधि आवश्यकतानुसार मिले।

आपका अधिक समय नहीं लूंगा।

कई जगह मजदूरों के लिये पी. एफ. आई. के अस्पताल हैं। पर उसका भी लाभ गरीब मजदूरों को नहीं मिलता। मजदूरों से मेरा सम्बन्ध है। देखता हूं कि उनका कोई इलाज नहीं होता, कोई ठीक से दवा नहीं मिलती। मैं क्या कहूं, कहते बड़ा दुख होता है। उनकी दवाइयां बाजार में बेच दी जाती हैं। और गांवों में तो हालत और भी बुरी है।

डाक्टर गांवों में जाना ही नहीं चाहता। एक माननीय वक्ता ने कहा कि अस्पतालों में प्राइवेट प्रैक्टिस को बन्द कर देना चाहिए। पर बन्द करने का मतलब यह नहीं कि उनका गला काट दिया जावे। उनको आप पूरा पैसा दें इस सम्बन्ध में कन्जूसी नहीं करनी चाहिये। गांवों की परिस्थितियों के अनुसार उनको पूरी सुविधा देनी चाहिये यह आवश्यक है।

इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात है जिसकी हम उपेक्षा करते हैं संसार में किसी भी देश में ऐसी उपेक्षा नहीं होती। प्रीवेन्शन की तरफ हम बहुत कम ध्यान दे पाये हैं, या कतई नहीं दे पाये ऐसा भी कह दूं तो गलत नहीं होगा। रोगों की रोक थाम की तरफ हमें ध्यान देना चाहिये। क्षय, कैंसर, रक्त चाप, हृदय रोग आदि बीमारियां होने के बाद तो आप इलाज करेंगे और उस पर लाखों करोड़ों खर्च कर देंगे। फिर भी बिलकुल ठीक नहीं हो सकेंगे। इसलिये आज उनकी पहले ही से रोकथाम के प्रयत्नों की जरूरत है।

इन रोगों के लिये टी. बी. के लिए खास कर हर नागरिक को चैक करने की सुविधा का विस्तार हमें करना चाहिये। अमेरिका आदि सब देशों में ऐसा होता है। प्रत्येक महिने में प्रत्येक नागरिक की स्क्रीनिंग आदि से जाँच की जानी चाहिये। इस प्रकार क्लिनिक खोले जाने चाहिये। कुछ जगह हैं, पर वहां सबकी पहुंच नहीं है। मैं ठीक निवेदन करता हूं इसी तरह उन पर सख्त सुपरविजन रहना चाहिये ताकि उनको ध्यान रहे कि अगर वे कर्तव्य पालन नहीं करेंगे तो उसका परिणाम उनको भुगतना होगा।

इसी प्रकार एक जगह है, अजमेर में भी मैं देख रहा हूं इतना बड़ा अमला है हजारों की आबादी हैं, मुसलमान और सिन्धी भाइयो की। घर घर के अन्दर क्षय रोग हैं। पर उसको रोकने के लिये पूरे साधन नहीं है। रोकने के लिये जैसा मैंने निवेदन किया हमें प्रयत्न

(डा० अम्बालाल)

करना चाहिये और फिर उनके उपचार की भी वहां पूरी पूरी आवश्यकता है।

इसके लिये प्रचार भी इसके बारे में हमें करना चाहिये, पेम्फलेट निकालने चाहिये, पुस्तकें निकलनी चाहिये और इस पर बहुत अधिक शोध भी हमें करनी चाहिये।

शोध की खोज की हमने बहुत बड़ी उपेक्षा की है। कैंसर के लिये कई कारण बताये जा रहे हैं। यह प्रतिदिन बढ़ रहा है। स्मोकिंग भी एक कारण माना जाता है। बहुत अधिक पान सुपारी खाना भी कारण माना जाता है। तो इन सब बातों का लोगों में प्रचार होना चाहिये प्रीवेन्शन हमेशा बहुत अच्छा है। कहावत भी है (Prevention is better than cure) तो आप कम से कम जन मानस में इस बात को बिठाने के लिये प्रचार के साधन को भी अपनावें।

इसी प्रकार से और बीमारियां है। अभी कुछ दिनों पहले हृदय रोग के विद्वान् दुनियां भर के यहां आये थे। कान्फ्रेन्स उनकी हुई थी। इस पर उन्होंने बहुत प्रकाश डाला। उनका मानना है कि इस रोग को रोका जा सकता है। तो इसके प्रयोग हमारे डाक्टरों को जानने चाहिये। उनके अनुभव से लाभ उठाना चाहिये।

मैं एक निवेदन और कर देना चाहता हूं आयुर्वेद के बारे में। यह एक बहुत उच्च विज्ञान है। पर दुर्भाग्य से आज इसकी प्रगति रुक गई है। इसमें भी शोध की खोज की आवश्यकता है। वह नहीं हो रही है।

आज इसके जितने कालेज हैं उनमें से कम से कम एक आदर्श कालेज बना दीजिये ताकि जितना रुपया आप इस पर खर्च कर रहे हैं उसका कुछ सदुपयोग हो सके। उसमें सारे विभाग आप रखिये। बैक्टीरियोलोजी का विभाग है, दूसरा विभाग है वह सब उसमें रखिये और उसे एक आदर्श शोध संस्थान के रूप में भी डेवलप करिये। आयुर्वेद को केवल एक छोटे से दायरे में ही सीमित रहने दिया और आज जो शास्त्र हैं चरक सुश्रुत उन्हीं को पढ़कर आपने समझ लिया कि हमने चरम प्राप्ति करली तो वह कभी नहीं कर सकेंगे।

फिर मेरा निवेदन है कि इनका वेतन भी डाक्टरों के बराबर आप करिये। इससे इनफीरियोरिटी कम्प्लेक्स नहीं रहेगा।

उदयपुर में रिसर्च औषधालय है। उसका क्या परिणाम आज तक सामने आया, हम नहीं जानते, उसका रुपया कहां जाता है, हम नहीं जानते। तो जब तक रिसर्च का फल नहीं मिले तो वह रिसर्च किस काम की और उस पर पैसा खर्च करने से क्या मतलब? हमें देखना चाहिये कि अब तक क्या रिसर्च है। उसका प्रत्यक्ष फल नहीं मिलता है तो हमें समझना चाहिये कि रुपया वेस्ट हो रहा है।

औषधि की उत्तमता के बारे में आयुर्वेद में बड़े नियम है कि अमुक समय के बाद साल भर या दो साल के बाद उस औषधि का गुण नहीं रहेगा आज दुर्भाग्य से वे बड़ी महंगी हो रही हैं, पर इसके बावजूद भी उनके गुणों की परीक्षा नहीं होती। सेम्पल जैसा हो माल वैसा ही मिलना चाहिये। तभी आयुर्वेद की सही सेवा हो सकती है।

(डा० आंबालाल)

वस्तुओं पर रिसर्च करिये। आज आप हाथ में रखने से सूंघने से करते हैं, पर यह पर्याप्त परीक्षा नहीं है। प्रत्येक चीज का प्रमाण होना चाहिये। मेरे विचार से इसका अनेलिसिस मैडिकल कालेज से हो सकता है या नहीं अगर हो सकता हो वहां से तो सन्देहास्पद स्थिति में वहाँ से निर्णय लें। इसी तरह और भी चीजें हो सकती हैं। तो इनका निर्णय हमें आज के विज्ञान से लेना चाहिये फिर इनका वेतन भी डाक्टरों के समकक्ष होना ही चाहिये इसमें भी एक वैद्य को पर्याप्त समय लगता है। पोस्ट ग्रेजुएट में भी डाक्टरों के अंग बहुत से आ गये हैं आ रहे हैं और आजावेंगे। ऐसी अवस्था में वेतन की असमानता से जो इन्फीरियोरिटी कम्पलेक्स पैदा होता है उसे मैं अनुचित समझता हूँ। उनकी स्केल आफ पे अच्छी होनी चाहिए और साथ ही वैद्यों से यह आशा करनी चाहिए कि वह आयुर्वेद की सेवाभाव से सेवा करेंगे और आयुर्वेद में इतने गुण हैं उसकी हर चीज में गुण हैं, पीपल में गुण हैं, बड़ में गुण हैं तो यह रिसर्च की चीजें हैं लेकिन दुर्भाग्य से मैं देख रहा हूँ कि वैद्य लोग क्या करते हैं। अंग्रेजी इन्जेक्शन लगा देते हैं। मुझे सचमुच बड़ा दुःख होता है और मैं इसको बहुत अधिक देखता हूँ और बहुत ही खतरनाक चीजें मैंने देखी हैं। इस तरह की चीज पर प्रतिबंध होना चाहिए। या तो फिर आयुर्वेद में ही इतने अच्छे इन्जेक्शन होने चाहिये या फिर यह नियम बना देना चाहिए कि वैद्य लोग यदि कोई इन्जेक्शन लगायें तो पहले ६-८ महीने एलोपैथी में जाकर इसको देखना चाहिए और सीखना चाहिए और जब तक इन्जेक्शन लगाने पर अच्छी तरह कमान्ड नहीं हो जाये तब तक उसे इन्जेक्शन नहीं देना चाहिए। फिर आयुर्वेद में जो वैद्य हों वे बराबर प्रेक्टिस में रहने चाहिए परन्तु हम देखते हैं कि कई वर्षों तक वह चिकित्सा नहीं करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं जैसे कोई इलेक्शन लड़ लेते हैं, कभी पंचायतों के चुनाव लड़ लिया कहीं पंच बन गये और अपने काम को छोड़ दिया और फिर पांच सात वर्ष बाद शुरु कर देते हैं तो इस तरह से लाइन आफ डीमार्केशन बड़ी निष्ठा के साथ होनी चाहिए। और भी मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूँ दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है कि टी० बी० के डाक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हो गये हैं जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ और रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य हैं वह सुना रहे थे कि वहां के डाक्टर को जब तक प्राइवेट फीस नहीं देते हैं तब तक वह नुस्खा ही नहीं लिखेगा और अगर लिखेगा तो भी इतनी महंगी दवाइयों का लिखेगा कि वह व्यक्ति की जेब के बाहर होगा। एक तो मेरा सुझाव यह है कि प्राइवेट प्रेक्टिस बिल्कुल बन्द कर देनी चाहिए और दूसरा सुझाव यह है कि करप्शन का आज हम जगह जगह कहते हैं, करप्शन हो रहा है और सचमुच हम देख भी रहे हैं। कहां भी जाइये, किसी भी क्षेत्र में जाइये हमारा वातावरण इतना विषाक्त हो गया है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। मैं दूसरा सुझाव देना चाहता हूँ कि करप्शन किस प्रकार से मिट सकता है अगर मेरे प्रस्ताव को ट्रेजरी बेन्चेज मान लें तो करप्शन नाम की चीज बहुत कम हो जायेगी और उसी कारण फोरिन कन्ट्रीज में भी ९० परसेन्ट करप्शन कम हो गया है। जहां लोकतंत्र का आरम्भ हुआ है वहां यह सब बातें होती हैं, यह अवांछनीय बातें होती जरूर है। तो वहां

(डा० अम्बालाल)

विदेशों में करप्शन किस प्रकार से समाप्त हुआ वहां पर एक विद्वान् है जिसका नाम मैं भूल गया हूँ शायद ग्रोम्बड्समेन नाम है, मैंने उनका बहुत सारा साहित्य मंगाया। उन्होंने कहा है कि वहां पर एक कमीशन है जिसके पास कि सारी शिकायतें आती हैं। हमारी सरकार कमीशन नियुक्त करे जो कि सब प्रकार की शिकायतें सुने। आज हमारी सरकार के उपर और अधिकारियों के उपर आरोप लगाये जाते हैं कहते हैं कि इनकी सम्पत्ति का पता लगाया जाये पर हमारी सम्पत्ति का ऐसे कैसे पता लगेगा। लेकिन इस प्रकार का एक कमीशन मुकर्रर कर दिया जाये तो जिस प्रकार से यूरोप में और स्वीटजरलैंड में ८५ परसेन्ट करप्शन खत्म हो गया अपने यहां भी हो सकता है। यही निवेदन करके जो सदन में सुझाव रखे है, मैंने निवेदन किया है, गरीबी की प्रोब्लम है, सारी प्राबलम्स हैं, इनकी ओर ध्यान देना चाहिए। मुझे तो जो निवेदन करना था वह मैंने निवेदन कर दिया। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बिरदीचन्द जैन।

श्री देवीलाल : हमें समय नहीं दिया जायेगा क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने सचेतक से कहें। लिस्ट के आधार पर नाम पुकारे जाते हैं।

श्री बिरदीचन्द जैन।

श्री बिरधीचन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जन स्वास्थ्य और चिकित्सा दोनों विषयों पर कटौती प्रस्ताव रखे हैं और मैं उनके बारे में अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं पहले मैं जन स्वास्थ्य के बारे में जल समस्या पर मेरे विचार प्रकट करना चाहूंगा।

बाड़मेर जिला एक रेगिस्तानी क्षेत्र है और इसका विशेष तौर से इस प्रकार महत्व है कि यह सीमावर्ती क्षेत्र भी है। इस क्षेत्र का विकसित होना देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। परन्तु पहले भी जब बजट पर सामान्य बहस थी उस समय भी मैंने अपने विचार प्रगट किये थे कि इस क्षेत्र की तरफ हम अधिक तौर से ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसको विकसित करने में जो हमारी सरकार है वह उपेक्षा बरत रही है। सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते हिन्दुस्तान पाकिस्तान के युद्ध के बाद में सड़कों का कार्य तो हमारी सरकार ने हाथ में लिया और प्राजेक्ट रोड्स का कार्य चल रहा है यद्यपि उसकी गति इतनी तेजी से नहीं है परन्तु वह कार्य चल रहे हैं और उससे हमारे देश की सुरक्षा को लाभ होगा। परन्तु उसके साथ ही साथ हमें सीमा की सुरक्षा के लिए यह भी देखना चाहिए कि इस क्षेत्र के लिए पेय जल की व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए। क्योंकि पहले भी मैंने यह कहा था कि इस पेय जल के कारण और इसकी कठिनाई के कारण इस क्षेत्र में जो मिलिट्री परसोनल्स और जो मिलिट्री के जवान लड़े थे उनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और उनकी इतनी कठिनाइयां होने के उपरान्त भी जिस युद्ध

(श्री बिरदीचन्द जैन)

को दो साल हो गए फिर भी हमने इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया है। जो बोरिंग कुछ कुओं में हुआ है जैसे धनाऊ गडरा रोड़ के पास में हुआ है.......

श्री उपाध्यक्ष : कृपया इनके नाम नहीं लें तो अच्छा रहेगा। सुरक्षा की दृष्टि से आप इनका नाम नहीं लें तो ठीक रहेगा।

श्री बिरधीचन्द जैन : अच्छा। तो वहां जो बोरिंग हुआ है उनको कमीशन करना आवश्यक है और इस क्षेत्र का सर्वे करना जरूरी है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें युद्ध हुआ था और उस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना घुस आई थी। उस क्षेत्र में अभी तक भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। वहां कोई भी बोरिंग नहीं हुआ है। तो उसके लिए सर्वे कराकर व्यवस्था करके उसकी कोशिश करनी थी और यह कार्य जैसे प्रोजेक्ट रोड्स का चल रहा है उसी तरह से युद्धस्तर पर होना चाहिए और यदि इसके लिए अपने पास में फण्ड्स नहीं हैं तो जैसे सड़कों के लिए सेन्टर व्यवस्था कर रही है उसी प्रकार से हमें मांग करनी चाहिए कि सेन्टर पानी के बारे में व्यवस्था करे। यहां युद्ध कभी भी हो सकता है हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का क्योंकि हमारे जो रिलेशन्स हैं वह खराब हैं ऐसा नहीं हो कि इसके कारण हमें नुकसान उठाना पड़े। यह बहुत गम्भीर मसला है और इसके लिए गवर्नमेन्ट को कदम उठाना चाहिए और हमारी सरकार को प्रयत्न करना चाहिए कि वह इस काम को करे और यदि नहीं कर सकती है तो सेन्टर से इस काम को कराये।

दूसरे इस क्षेत्र में पानी खारा है। बाड़मेर जिले का १।३ हिस्से में खारा पानी है और कुछ हिस्से में ऐसे पत्थर भी आ गये हैं कि जिसके कारण उस पत्थर को तोड़ना भी मुश्किल हुआ है। ब्लास्टिंग मशीन आई है और ब्लास्टिंग मशीन का उपयोग हुआ है और करीब १० साल से मैं देख रहा हूं कि इन ब्लास्टिंग मशीनों से एक दो कुओं में पानी जरूर आया है लेकिन दूसरे सक्सेसफुल नहीं हुए। ब्लास्टिंग मशीन कुछ दिनों के लिए आती है और फिर दूसरे क्षेत्र में चली जाती है और उसका सही तरीके से उपयोग नहीं होता है। ऐसा होना चाहिए कि पूरी ब्लास्टिंग मशीन एक क्षेत्र में रखनी चाहिए और कुओं की खुदाई का कार्य करना चाहिए।.......

तीसरी चीज जो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो २।३ का और १।६ का रेश्यो है वह बहुत भारी है। पंचायत जो कुआ खुदवाती है, जो गांव वाले कुआ खुदवाते हैं उसमें २।६ और १।३ का रेश्यो है यह इस क्षेत्र के लिए बहुत भारी पड़ता है। १५ हजार रुपये कुए के निर्माण में लग जाता है और पन्द्रह हजार का १।३ हिस्सा यानि फाईव थाउजण्ड देना पड़ता है। तो फाईव थाउजण्ड रुपये इस क्षेत्र के लिए देना असम्भव है। पांच हजार रुपया यह क्षेत्र का किसान दे सके यह बहुत कठिन है। इसलिए इस बारे में जिला परिषद् भी रिजोल्यूशन पास करती है और यह तय हुआ है कि १।४ शेयर कर दिया जाय, लेकिन मैं कहता हूं कि हमेशा के लिए गवर्नमेंट को यह तय कर देना चाहिए कि १।४ हिस्सा या १।५ हिस्सा ही कुओं के लिए निर्माण के लिए उन्हें देना पड़े। अगर यह नहीं करेंगे तो

(श्री बिरदीचन्द जैन)

वहां कुए खुदवाये जा नहीं सकें और पानी की तो बहुत ही आवश्यकता है और इस भाग को पूरा करना भी बहुत जरूरी है।

अब में बाड़मेर नगर की जल समस्या पर आता हूं। बाड़मेर नगर में मैंने देखा है कि अभी जो व्यवस्था है उन नलों से सिर्फ जनता को भी पांच मिनिट, कभी दस मिनिट पानी मिलता है कभी जयपुर के सदस्य बात करते हैं, कभी अलवर के सदस्य अपने यहां को पानी की समस्या के बारे में बात करते हैं, परन्तु मैं देख रहा हूं, कण्टीन्यू-असली बराबर देख रहा हूं कि बाड़मेर में पानी के लिए योजना तैयार होके पाईप लाईन की स्कीम भी तैयार हो गई, परन्तु अभी तक भी यह स्थिति है कि जो सार्वजनिक टूंटियां हैं वहां पर पांच मिनिट, दस मिनिट या पन्द्रह मिनिट से ज्यादा तो कभी भी पानी अवेलेबल नहीं होता है। बड़ी मुश्किल से एक घड़ा, दो घड़ा पानी मिलता है। यह स्थिति है बाड़मेर नगर की। तो इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि बाड़मेर से बोथिया तक पाईप लगाई है वह अच्छी तहर से बनाई हुई नहीं है। वह पाईप लाईन बहुत जगह टूटी हुई है। जो भी खराबी है उसको ठीक करना चाहिए और उसमें पानी जो कम आता है. जो भाडरवा आया उसमें भी भाडरवा से बाडका तक तीन माईल का डिस्टेंस है उसको कवर करना चाहिए और भाडरवा का जो दूसरा कुआ है उसकी जल की कैपेसिटि अच्छी है उसको कनेक्ट करके, कमीशन करके बाड़मेर के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। अभी तक शहर के अन्दर पानी के नल भी दिए हैं परन्तु बहुत ही कम पोरशन शहर का कवर हुआ है। १।१५ पोरशन ही शहर का कवर हुआ है इसलिए दूसरे पोरशन को भी कवर करना चाहिए और इसके अन्दर प्रोविजन करना चाहिये। तो मैं यह कह रहा था कि बाड़मेर नगर के बारे में, इस नगर की पानी की समस्या के बारे में पूरी व्यवस्था करनी चाहिए और इस बाड़मेर नगर की इस अव्यवस्था का मूल कारण जो है वह पावर की कमी है। अभी भी जो व्यवस्था की है, बहुत ही कोशिश करने के बाद में बोर्डर कमिश्नर के द्वारा कोशिश करने के बाद में और वहां के कलेक्टर साहब ने भी कोशिश की और सब तरफ से कोशिश करने के बाद जो दो जनरेटिंग सेट्स १०० के०वी० के हैं वे पावर देने के लिए सफिशियेंट नहीं है जब कि जो प्रोविजन है, फैमिन को मैंने पुस्तक को पढ़ा है उसमें १३ लाख ५० हजार का प्रोविजन उसमें है और २५० किलोवाट पावर के दो जनरेटिंग सेट लेने का प्रोविजन उसमें है तो वह खरीदना चाहिए और पानी की व्यवस्था को पूरी तौर से हल करने का प्रयास करना चाहिए। बाड़मेर नगर जिसकी आबादी तीस हजार की है उस नगर की पानी की समस्या के बारे में और जिले की पानी की समस्या के बारे में मैंने अपने विचार प्रगट किये। अब मैं चिकित्सा व्यवस्था पर आता हूं।

सबसे पहले मैं बाड़मेर नगर को लेता हूं बाड़मेर नगर के अन्दर यह तो हुआ है कि बहुत अच्छी अस्पताल की बिल्डिंग बहुत ही प्रयासों के बन गई है। बिल्डिंग के बाद

(श्री बिरदीचन्द जैन)

में प्रश्न आता है लेडी डाक्टर का तो इस क्षेत्र में कभी भी लेडी डाक्टर के आने का तो प्रश्न ही नहीं रहा है। मैंने इतने वर्षों तक देखा है कि कभी भी लेडी डाक्टर को नहीं भेजा गया है। अब जालोर जो है उसमें डिस्ट्रिक्ट चिकित्सा अधिकारी का आफिस है वह जालोर में है। मुझे बड़ा दुख और आश्चर्य होता है कि जालोर के अन्दर हैड-क्वार्टर क्यों है। जालोर नगर की आबादी को देखा जाय तो बाड़मेर से आधी है। जालोर की आबादी पन्द्रह हजार और बाड़मेर की आबादी तीस हजार है और उसके बाद भी डिस्ट्रिक्ट चिकित्सा अधिकारी का हैडक्वार्टर जो है वह जालोर में रखा गया है। तो यहां पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी नहीं है। डूंगरपुर, धौलपुर के अन्दर मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं परन्तु यहां पर भी प्रोविजन नहीं है। तो इस प्रकार इस जिले को पूरी तरह से निग्लेक्ट किया गया है। न तो यहां पर लेडी डाक्टर न है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, न डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है और मेडिशन्स को तो नामो निशान भी नहीं है। अब तो पट्टियां, बेंडेज तक भी वहां से सप्लाई नहीं करते हैं, लोगों को अपने आप लानी पड़ती है। दूसरी मेडिशन्स का तो प्रश्न ही क्या है। तो इसलिए इस टाउन को जो मेडिकल फेसेलिटीज हैं उन मेडिकल फेसेलिटीज के बारे में सुविधा देने के लिए सरकार को विचार करना चाहिए। हमारे यहां राजस्थान में २६ डिस्ट्रिक्ट में से २३ डिस्ट्रिक्ट्स में हैडक्वार्टर हैं तो इस बाड़मेर टाउन के अन्दर भी हैड क्वार्टर होना चाहिए और पूरी तरह से मेडिशन्स का प्रोविजन किया जाना चाहिए।

अब मैं यह जो डाक्टर्स प्राइवेट प्रेक्टिस करते हैं उसके बारे में निवेदन करूंगा। मैं डाक्टर्स के द्वारा प्राइवेट प्रेक्टिस करने के बिल्कुल विरोध में हूं। यह जितना करप्शन बढ़ता है वह उनके प्राइवेट प्रेक्टिस के कारण है। प्राइवेट प्रेक्टिस के कारण वे अपने अस्पतालों में अपने मरीजों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अपनी प्राइवेट प्रेक्टिस की तरफ ही ज्यादा ध्यान देते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

इसलिए मेरा विचार है कि प्राइवेट प्रेक्टिस को बिल्कुल बन्द कर देना चाहिये और उनका रेमुनरेशन बढ़ा देना चाहिये परन्तु प्राइवेट प्रेक्टिस बिल्कुल बन्द हो जानी चाहिये। इसके अलावा जो डाक्टर्स सर्टीफिकेट देते हैं, प्रमाण पत्र देते हैं इंजरी का, मैंने अधिकांश केसेज में देखा है, ८० प्रतिशत मामलों में देखा है, मैं २३ सालों से वकालत की प्रेक्टिस कर रहा हूं, मैंने देखा है कि ८० प्रतिशत डाक्टर्स जो इन्जरी की रिपोर्ट देते हैं वह गलत रिपोर्ट देते हैं, गलत प्रमाण पत्र देते हैं। ३२४ आई० पी० सी० की जगह ३२६ का कर देते हैं, ३२३ की जगह ३२५ का सर्टीफिकेट देते हैं। और इस प्रकार झूंठे सर्टीफिकेट देकर अनुचित लाभ उठाते हैं, नाजायज फायदा उठाते हैं। कहीं २ पर तो ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति के साथ मारपीट की जाती है और ३२३ की जगह गलत रिपोर्ट करके उसके खिलाफ जो दूसरा ३२४ का फर्जी सर्टीफिकेट प्राप्त करके

Page No. 108

(श्री बिरदीचन्द जैन)

उसका चालान हो जाता है और जिसके साथ मार पीट की गई है उसको उल्टा भुकतना पड़ता है। यह स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस स्थिति को सुधारने के लिए भी आवश्यक है कि जो उनके डाइरेक्टर्स हैं वे इस ओर विशेष तौर से ध्यान दें और इस चीज को बन्द करना चाहिये। यह हमारे देश के लिए और इस प्रकार के बड़े प्रोफेशन के लिये. मेडिकल प्रोफेशन के लिये शर्मनाक चीज है जिसको बन्द किया जाना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने कटौती के प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किये हैं उन पर मेरे विचार सदन के सामने प्रस्तुत किये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोतीलाल।

श्री मोतीलाल (रेवदर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के बारे में सिरोही के प्रति राज्य सरकार का जो सौतेला व्यवहार रहा है, उसके बारे में मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं।

सिरोही राज्य के विलीनीकरण के पश्चात व तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद सिरोही जिला मुख्यावास पर स्थित चिकित्सालयों के अन्दर राज्य सरकार ने किसी प्रकार का कोई सुधार एवं विस्तार हेतु कोई भी कार्य नहीं किया है। यह चिकित्सालय सिरोही की ४ लाख जनता व कोटड़ा सब डिवीजन, जसवन्तपुरा तहसील व बाली तहसील की तीन लाख जनता का एक मात्र सहारा है। ग्रामीण जनता को जब जनरल वार्ड में रोग शय्या की कमी के कारण प्रवेश नहीं मिलता है तब उनके दुःखों की गहराई को आप भली प्रकार समझ सकते हैं। सिरोही के चिकित्सालयों में रोग शय्या की संख्या राज्य के अनेकों चिकित्सालयों में उपलब्ध रोग शय्या से अत्यधिक कम है। इसमें सिर्फ २० बिस्तर की सुविधा उपलब्ध है यानि १ लाख जनता के हेतु ३ बिस्तर अनुपात के हिसाब से हैं। यही नहीं, लोगों को छोटे मोटे आपरेशन हेतु जयपुर और जोधपुर अस्पतालों में शरण लेनी पड़ती है जो यहां की गरीब जनता सहन नहीं कर सकती।

बड़े दुर्भाग्य की बात है कि छोटे छोटे रोग निदान की सुविधा, टी० बी० क्लीनिक, दन्त क्लीनिक, नेत्र क्लीनिक की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि करीब करीब यह सुविधा जिला मुख्यावास पर स्थित समस्त चिकित्सालयों में तीन पंचवर्षीय योजनाओं में उपलब्ध कर दी गई हैं। आज प्रति वर्ष करोड़ों रुपये चिकित्सालयों के सुधार एवं विस्तार हेतु योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार खर्च कर रही है लेकिन यह खर्चा सिर्फ जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर आदि बड़े शहरों के चिकित्सालयों पर ही व्यय किया जा रहा है। हमें इसमें कोई शिकायत नहीं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के जिला मुख्यावास पर स्थित चिकित्सालयों के सुधार एवं विस्तार पर योजना राशि का समुचित अनुपात जरूर व्यय होना चाहिये। आज यह धारणा ग्रामीण क्षेत्र में बल पकड़ती जा रही है कि राज्य सरकार शहरी जनता की सुविधाओं के प्रति जागरूक है और ग्रामीण क्षेत्र में जनता की आवश्यकताओं की घोर उपेक्षा कर रही है। आज जयपुर, उदयपुर, अजमेर इत्यादि चिकित्सालयों के भवन सुधार एवं निर्माण पर

(श्री मोतीलाल)

करोड़ों रुपया खर्च किया है और राज्य सरकार कर रही है जिसमें जनता का कोई जन सहयोग प्राप्त नहीं किया है। लेकिन आज प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोलने के लिये यह शर्त लगाई जाती है कि इतना अनुदान जन सहयोग से प्राप्त होने पर ही उसकी स्वीकृति दी जा सकती है। यह शहरी और ग्रामीण जनता के बीच में भेदभाव और पक्षपात की नीति क्यों अपनाई जाती है। राज्य सरकार को मेरा नम्र निवेदन है कि वह योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्राप्त हो सके—ऐसी नीति का निर्धारण करे।

प्रत्येक जिले को चिकित्सालयों की वार्षिक योजना सुधार एवं विस्तार हेतु प्रकाशित करे।

मेरा नम्र निवेदन है कि मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि सिरोही के चिकित्सालयों में रोग शय्या की संख्या बढ़ाने, नेत्र क्लीनिक, दन्त क्लीनिक एवं टी० बी० क्लीनिक की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु इस वर्ष राज्य सरकार ने क्या कार्यक्रम निर्धारित किया है। इस उपेक्षापूर्ण नीति से सिरोही की जनता में घोर असन्तोष है और शीघ्र ही आन्दोलन का रूप धारण कर लेगा।

जनता निरन्तर इन आवश्यकताओं की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करती रही है............

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप पढ़ें नहीं अपने भाषण को, आप देख सकते हैं लेकिन पूरा पढ़ें नहीं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : मेमोरी को रिफ्रेश कर रहे हैं, इसके लिए परमिट कर दें।

श्री मोतीलाल : लिखा हुआ पढ़ें कोई तो उसमें कोई बात नहीं है। पढ़ नहीं सकते–ऐसा नहीं हो सकता।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : लिखा हुआ पढ़ सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़ कर भाषण नहीं दे सकते। पत्र हो, उसको देखकर आप उनके ऊपर कुछ कह सकते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : मैंने पहले कहा था...........

श्री भवजलाल (हिंडौन) : जो नोट्स हों उनको देख कर सदन के सम्मुख भाषण कर सकते हैं।

श्री मोतीलाल : मगर खेद के साथ में मुझे निवेदन करना पड़ता है कि उनको न्यायोचित मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। यहां तक कि सिरोही के चिकित्सालय में आपरेशन के लिए उपयुक्त शल्य कक्ष भी नहीं है।

महिला चिकित्सालयों में रोग शय्या की कमी के कारण प्रसूति गृहों में महिलाओं को बरामदे में पड़ा रहना पड़ता है–यह जनतन्त्र में महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार व अपमान ही है।

आज तक योजनाओं का लाभ शहरों को लाभ देता ही रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में जो

(श्री मोतीलाल)

डिस्पेन्सरी है उनमें डाक्टर तक का पोस्टिंग अनादरा में न होने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के दुःख का अन्दाज आप लगा सकते हैं।

मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि सिरोही में सी० एम० ओ० की पोस्ट छः महीने से खाली पड़ी है। सिरोही के अस्पताल में कोई सर्जन नहीं है। यह घोर उपेक्षा सिरोही के चिकित्सालयों की करने से आम जनता में सरकार के प्रति असन्तोष की भावना जोर पकड़ रही है। क्या सरकार अपनी पक्षपातपूर्ण नीति को त्याग कर गरीब ग्रामीण जनता के प्रति सहानुभूति का व्यवहार कर उच्च आदर्श स्थापित करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा।

श्री हरीवल्लभ (सवाई माधोपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मैंने हर एक मांग पर कटौती के प्रस्ताव दिये, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी भी मांग पर मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : यह आप अपने दल के सचेतक से कहें कि वह लिस्ट में नाम दिया करें। यहां तीन चार दिन पहले व्यवस्था की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि हर दल की ओर से सचेतक नाम दे देंगे और उसके अनुसार नाम पुकारा जायगा।

एक माननीय सदस्य : एक दल से कम से कम दो माननीय सदस्य बोल सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामप्रसाद बोहरा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव है, दो चिकित्सा के सम्बन्ध में हैं और एक जन स्वास्थ्य पेय जल के सम्बन्ध में है।

असनावर ग्राम में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के लिये रकम दस हजार जमा हो चुकी है लेकिन वहां उसकी बिल्डिंग नहीं बनी है और जो एक तहसील का भवन था, वह खाली हुआ तो उसकी बिल्डिंग को इसके काम में लिया जा रहा है परन्तु वहां रोगियों को रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और न मांडीशन्स की व्यवस्था होती है। दूसरी चीज यह है कि रोगी को लाने के लिये प्राइमरी हैल्थ सेन्टर की ओर से जो साधन उपलब्ध होने चाहिए वह साधन उपलब्ध नहीं सुनने हो पाते है। इसके सम्बन्ध में काफी कहने के बाद में भी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। दूसरी चीज यह है कि वहां पर दवाइयां, इन्जेक्शन और स्टाफ आदि की बहुत भारी कमी है। इस प्राइमरी हैल्थ सेंटर के लिये मैंने काफी लिखा पढ़ी की परन्तु आज तक उसकी कोई व्यवस्था हो नहीं पाई है, न वहाँ पर कम्पाउन्डरस की और न नर्सेज की व्यवस्था हो पाई है। जो साधनों की कमी हैं वह भी पूरी नहीं की गई है और केवल नाम मात्र के लिये प्राईमरी हैल्थ सेन्टर खोला हुआ है मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि दस साल तक कोई भवन की व्यवस्था नहीं होगी तो क्या प्राइमरी हैल्थ सेन्टर इसी तरह से चलेगा? यह मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

दूसरे रटलाई ग्राम के अन्दर दो साल पहले दस हजार रुपया ग्राम वालों द्वारा, गाँव से पंचायत से मिलकर जमा कराया गया था प्राइमरी हैल्थ सेन्टर बनाने के लिए उसके लिए प्रस्ताव भी पास हुआ पंचायत समिति और जिला परिषद् के द्वारा परन्तु अभी तक प्राइमरी हैल्थ सेन्टर नहीं बनाया गया है। साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बकानी पंचायत समिति के हैड क्वार्टर पर उस रुपये को काम में ले लिया गया और वहां पर एक प्राइमरी हैल्थ सैन्टर खोल दिया है। इससे गांव वालों में बड़ा असन्तोष है। रटलाई वालों के द्वारा वह रुपया प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के लिए दिया गया लेकिन वह बकानी में खोल दिया है। इसके बारे में काफी कहने सुनने के बाद में यह आश्वासन दिया गया कि हम आपके यहां भी डिस्पेन्सरी खोलेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब डिस्पेन्सरी खुलने वाली है तो क्या इसका दस हजार रुपया बकानी में खर्च किया है, वह दस हजार रुपया वापिस करना चाहिए या यहां पर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोलना चाहिए।

इसी प्रकार बकानी तहसील हैड क्वार्टर था और अब सब तहसील हैड क्वार्टर है जिसकी पांच हजार की आबादी है। लेकिन वहां की जो पेयजल की योजना है वह अभी तक पड़ी हुई है। तीन चार साल से इसके बारे में तकाजा कर रहे हैं। वहां पर पानी की बहुत कमी है, पाँच हजार आदमियों के लिए केवल दो कुए हैं, इसलिए इस पानी की कमी के कारण आजकल रात भर लोग परेशान होते हैं क्योंकि दिन में पानी नहीं मिलता है। एक छोटा सा परिवार होता है उसको भी तीस रुपये मासिक पानी के लिए देने पड़ते हैं। यह स्थिति इस गाँव के लोगों की है इसलिए पानी की व्यवस्था करने की और चिकित्सा की व्यवस्था करने की सरकार की जिम्मेदारी है उसको उसे निभाना चाहिए।

जब कि वहां की योजनाएं हैं, उन योजनाओं में रुपया उन लोगों द्वारा लगाया हुआ है। तो मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार की योजनाएं ठप्प रहीं तो वहां की जनता में असन्तोष होगा। जहां पैसा दे दिया गया है, वहां आज तक काम नहीं हुआ है और जहां से पैसा नहीं दिया गया है वहां काम हो गया है, यह इस प्रकार को सरकार की व्यवस्था है, मैं तो कहूँगा कि यह अव्यवस्था है। तो मैं निवेदन करूं कि बकानी कस्बे के लिये जल योजना, वाटर सप्लाई की स्कीम है, उसको शुरू करना चाहिए क्योंकि यहां ३ साल से अकाल है, पानी की इतनी अव्यवस्था है कि लोग परेशान हैं, पास ही दो मील पर नदी में काफी पानी है, वहां से पानी देने की नल योजना शुरू करनी चाहिए पर इस ओर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है। प्रश्न पूछे जाते हैं तो जवाब मिलता है कि काम शुरू होने वाला है।

इसके अलावा मेरा निवेदन है कि चिकित्सा गरीबों के लिये नहीं है यह तो केवल अमीरों के लिये है। पैसा देने के बाद भी गरीब लोग चिकित्सा से महरूम रहते हैं और अमीरों को बिना पैसे दिये ही चिकित्सा प्राप्त हो जाती है, दवाइयां मिल जाती हैं। इसलिये

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

मैं निवेदन करूंगा कि हर डिस्पेन्सरी, हर शफाखाने पर सरकार को ध्यान देना चाहिये, गरीबों को पैसा देने पर भी इलाज नहीं मिलता है, बड़े नेता और सिफारिश वाले पहुंचते हैं तो उनको मुफ्त में दवाइयां दी जाती हैं, उनके घर पर डाक्टर पहुंच जाते हैं। तो मैं सरकार की तरफ से यह समझना चाहता हूं कि आपकी यह कैसी व्यवस्था है? जो यह कहते हैं कि सारी अच्छी व्यवस्था है, मैं तो कहता हूं कि भारी अव्यवस्था है। झालावाड़ के हॉस्पिटल में बड़ी भारी अव्यवस्था है, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफीसर के यहां भी लोगों पैसे से देखा है, बीमारों को कुछ नहीं सुनते, शिकायतें को जाती हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। जिनकी शिकायत होती है उनको पांच, पांच साल तक वहीं रखा जाता है, यह ठीक नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि बिना पक्षपात के हर कार्यवाही पर ध्यान देना चाहिये।

मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री कल्याणमल।

श्री कल्याणमल (जहाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जहाजपुर क्षेत्र में चिकित्सा की असुविधा के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहाजपुर तहसील हैड क्वार्टर है, जहाजपुर के सिवा और कहीं चिकित्सा की सुविधा नहीं है इससे जहाजपुर क्षेत्र को गरीब जनता को बड़ी असुविधा है।

शंकरगढ़ में डिस्पेन्सरी खोले हुए ५ साल होने जा रहे हैं पर मन्त्री महोदय से बार बार निवेदन करने के बाद भी आज तक वहां डाक्टर की व्यवस्था नहीं कर पाये हैं। शंकरगढ़ के आस पास कोई चिकित्सा की सुविधा नहीं है, करीब २० मील की दूरी पर जहाजपुर है, किसी मरीज को ले जाना हो तो कोई मोटर, गाड़ी का साधन नहीं है। २० मील मरीज को लेजाना बहुत मुश्किल है, जहाजपुर तहसील के क्षेत्र में बहुत गरीब जनता रहती है, इसलिये २० मील गरीब आदमी को ले जाना बड़ा मुश्किल है इसलिये शंकरगढ़ में जल्दी से जल्दी डाक्टर की व्यवस्था करें।

आयुर्वेद के सम्बन्ध में निवेदन करूं कि जहाजपुर क्षेत्र में जो आयुर्वेदिक औषधालय खुला हुआ है, उसमें भी दवाइयों की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आयुर्वेदिक औषधालय में दवाइयों की व्यवस्था करें और दूसरे शंकरगढ़ में डाक्टर भेजने की व्यवस्था करें।

जहाजपुर हैल्थ सेन्टर में १० मरीजों का वार्ड बना हुआ है, करीब एक लाख की आबादी के लिये क्या यह काफी है? मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वार्ड को गुंजायश और बढ़ा कर जहाजपुर क्षेत्र की जनता को सुविधा दें।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जन स्वास्थ्य विभाग पर मेरे कटौती प्रस्ताव हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे अस्पतालों की व्यवस्था है वह धीरे धीरे एक इस तरह की व्यवस्था होती जा रही है जिससे आम आदमी को, साधारण जनता के आदमी को, उनके द्वारा लाभ पहुंचना बहुत मुश्किल सा प्रतीत हो रहा है । यह व्यवस्था बहुत ही खर्चीली व्यवस्था होती जा रही है और इसमें भ्रष्टाचार का जो प्रवेश हुआ है उसके कारण जो यह हमारी जन सेवा की भावना से प्रेरित हो कर यह व्यवस्था का है, उस उद्देश्य की पूर्ति हम नहीं कर पा रहे है । मैंने कल या परसों शायद निवाई के अस्पताल के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा था, मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया था कि वहां जच्चाखाने की पर्याप्त व्यवस्था है, कुछ आंकड़े भी प्रस्तुत किये । पर कल ही मैं निवाई गया तो मुझे मालूम हुआ, सुनकर मुझे बड़ा दुःख हुआ कि वहां इटावा वाले मोहन के लड़का होने वाला था, उस औरत को नर्स ने शफाखाने में बुलाया और कहा कि यहां पर्याप्त साधन नहीं है, टोंक जाओ उसे टोंक ले जाया गया, टोंक पहुंचते पहुंचते उस स्त्री की मृत्यु हो गई । यह एक दर्दनाक उदाहरण मैं आपके सामने मय नाम ग्राम, तारीख के रख रहा हूं । इस माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि निवाई जैसे कस्बे में जहां आपने कई बार आश्वासन दिये, इस चुनाव के समय में आपने आश्वासन दिया था, इससे पहले वाले चुनावों के समय आपने आश्वासन दिया था, जब भी चुनाव होते हैं और आप निवाई पधारते हैं तो वहां जच्चाखाना खोलने का आश्वासन देते हैं, पर आश्वासन पूरा नहीं करते, जो जनता को परेशानी है, उसको हम यहां रखते हैं उसके बाद भी सदन में गलत आंकड़े रखकर जनता को बताना चाहते हैं कि पूरी व्यवस्था है, तो मैं यह उदाहरण पेश कर रहा हूं और निवेदन करता हूं कि वहां जल्दी से जल्दी जच्चाखाने की व्यवस्था करें तो अत्युत्तम होगा ।

इसके साथ ही साथ माननीय नेता महोदय ने जो भागप्रसाद जी कराड़िया का केस रखा, उनके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि वह भी एक शोचनीय और विचारणीय प्रश्न है कि एक विधानसभाई सदस्य को हमारे अस्पतालों में किस तरह की फेसिलिटीज दी जाती हैं उनकी किस तरह इज्जत की जाती है उनका किस तरह से इलाज किया जाता है । यह एक शोचनीय, विचारणीय बात है कि जब लापरवाही दवाइयों के अभाव और बराबर इलाज नहीं मिलने से विधान सभाई सदस्य का उदाहरण हमारे सामने है तो साधारण आदमी कैसे अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ कर सकता है । मैंने उनको जाकर देखा है, सम्बन्धित डाक्टर से मिला हूं, बावजूद दर्जनों एम० एल० एज० के मिलने के जनरल वार्ड के एक कोने में गन्दे बिस्तर में उन्हें पड़ा रखा दवाई की समुचित व्यवस्था नहीं थी, हमारे दल के डेढ दर्जन विधायक सम्बन्धित डाक्टर से मिले और कहा कि अच्छे वार्ड में इन्हें रखिये, अच्छी व्यवस्था कीजिये । लेकिन उसके बाद चार पांच दिन शफा-

(श्री जयनारायण सालोदिया)

खाने में एडमिट रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। लाश को २४ घण्टों तक पटका रखा गया उसको घर वालों को नहीं दिया गया। इससे हम यह अन्दाज लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के इन्चार्ज, मंत्री जी और डाक्टरों का जन प्रतिनिधियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार रहता है, वे किस भावना से उनका इलाज करते हैं।

(३.२० म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत सभानेत्री पदासीन)

माननीय सभानेत्री महोदया, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं हमारे जो सरकारी मुलाजिम होते हैं उनको डाक्टरी सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। उसके लिए एक दो डाक्टर नियत हैं, उनके कमरों के सामने कतार की कतार में लोग खड़े रहते हैं। जब उनसे बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि किन्हीं २ को तो तीन तीन दिन हो जाते हैं उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। कुछ लोगों ने मुझे यह भी कहा कि यदि आज उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिला तो उनको सर्विस में नहीं लिया जायगा सर्विस के योग्य नहीं समझा जायगा। इस तरह की हालत सर्टिफिकेट लेने में होती है।

अब मैं भरती के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ किसी मरीज को भरती होना होता है तो यह एक प्रकार की प्रेक्टिस चल पड़ी है कि जिन डाक्टर के वार्ड में उनको भरती होना होता है, उसके घर पर उससे मिला जाता है, दिखाने के नाम पर फीस दी जाती है और उसके बाद वह चिट लिख देता है कि वार्ड में भरती कर लिया जाय। इस प्रकार की डाक्टरों की भावना जन जीवन के साथ खिलवाड़ करने की है उससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि इस विभाग के द्वारा हमारे स्वास्थ्य की रक्षा किस प्रकार हो सकती है। आज किसी भी डाक्टर के वार्ड में भरती होना हो तो पहले उसको घर पर जाकर फीस देनी पड़ती है, दिखाने के नाम पर, टेस्ट के नाम पर उसके बाद वह भरती किया जाता है। यह जो प्रक्रिया चल रही है वह बहुत ही हानिकारक है।

इसी तरह से निवाई शफाखाने की मुझे अच्छी तरह से जानकारी है। वहां जो कीमती दवाइयां या इन्जेक्शन्स आते हैं दूध के डिब्बे आते हैं वे सब स्टाफ में ही बंट जाते हैं। कोई डाक्टर उनको प्राइवेट प्रेक्टिस में लेता है कोई बेच देता है। दूध के डिब्बे या तो अपने काम मे लेते हैं या बेच देते हैं इस तरह से गांव के लोगों के लिए जो दवाइयां आदि दी जाती है उनको डाक्टर, कम्पाउन्डर और स्टाफ के लोग हीं अपने काम में ले लेते है। उसके बजाय पानी मिला हुआ तरह तरह के रंग का पानी लोगों को दवाई के रूप में दिया जाता है जिसमे कोई फायदा नहीं होता। मैं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूँ आप कम से कम आपका डिस्ट्रिक्ट तो देखिये। सुखाड़िया जी ने अपने डिस्ट्रिक्ट के लिये क्या क्या नहीं किया। इसलिये आपसे प्रार्थना करता हूँ आप पहले भी स्वास्थ्य मंत्री थे अब की बार भी स्वास्थ्य मंत्री बन गये कम से कम आप अपने इलाके के भले के लिए कोई काम तो करिए। आपके

(श्री जयनारायण सालोदिया)

इलाके में दवाइयों के अभाव में औरतें मर जायें दवाइयां लोग बांट खायें तो फिर आपका मंत्री महोदय रहना निरर्थक है।

इसी तरह से आपके डिस्ट्रिक्ट में उनियारा भी एक कस्बा है उसके लिए निवेदन करना चाहता हूँ उनियारा में अस्पताल है वहां पहले दो कम्पाउन्डर थे, स्टेट का जमाना था तो कम्पाउन्डर थे आज उसमें से एक को हटा दिया गया। एक कम्पाउन्डर है वह दो सौ तीन सौ रोगियों को जो रोजाना आउट डोर में आते हैं, नहीं देख पाता। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि पहले जो दो कम्पाउन्डर थे उनको तो वापिस नियुक्त किया जाय। आपसे बढ़ाने की उम्मीद न करें तो कम से कम जो आलरेडी हैं उनको तो आप रखिये। वहां पर डाक्टर की भी पोस्ट है वह दो दो तीन तीन महीने छुट्टी चला जाता है उसकी जगह कोई आता नहीं इस तरह से डाक्टर के अभाव में मरीज परेशान होते हैं। इसके बारे में मैं कन्क्रीट उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूँ आप पूर्ण विचार करके अपने उत्तर में उसके लिए आप कुछ कहेंगे।

अब मैं परिवार नियोजन के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। हमारे हिन्दुस्तान में और उसी अनुपात में राजस्थान की जन-संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है यह बढ़ती हुई जनसंख्या खेद का विषय है। बढ़ती हुई जनसंख्या के परिणामस्वरूप आज हमें खाने के लिए अन्न की प्राप्ति के लिए हर राष्ट्र के सामने भीख मांगनी पड़ती है। ऐसी महत्वपूर्ण और निर्लज्ज समस्या को हम बरदाश्त कर रहे हैं और कोई कारगर कदम नहीं उठा रहे हैं और जो कदम उठाये जाते है उसमें अव्यवस्था और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है।

सभापति महोदया, हमारी निवाई में परिवार नियोजन केन्द्र लगा वहां पर टोंक के सी० एम० ओ० साहब ने एक औरत का आपरेशन किया वह आपरेशन ठीक नहीं हुआ उस औरत को छः महीने में चार बार आपरेशन करवाना पड़ा तीन दफा तो टोंक के सी० एम० ओ० के द्वारा किया गया। बाद में उस आपरेशन में कुछ खराबी हो गई। उस खराबी के कारण अभी एक महिला पहले उस औरत को यहां मानसिंह अस्पताल में भरती कराया गया। यहां डाक्टरों ने उसका दुबारा आपरेशन किया यहां आकर उस औरत की हालत ठीक है। इस प्रकार यदि परिवार नियोजन के आपरेशन होने लगें तो इसके प्रति लोगों की आस्था कहां रहेगी। आज यही कारण है कि लोग आपरेशन या लूप के लिये तैयार नहीं होते। यह एक उदाहरण ऐसा है जिसकी मुझे अच्छी तरह से जानकारी है उस औरत को मैंने कई दफा टोंक में देखा है। हमारे चेयरमेन के मुनीम की औरत थी इसलिये मुझे इसकी खास तौर से जानकारी है। वह परिवार नियोजन के आपरेशन से मरते मरते बची।

सभापति महोदया, अब मैं जन स्वास्थ्य के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। निवाई में जल की योजना की स्कीम पहली योजना से विचाराधीन है। हमेशा चुनाव के समय उसको पूरा करने की घोषणा हो जाती

(श्री जयनारायण सालोदिया)

है। जब कभी सुखाड़िया जी पदार्पण करते हैं यह घोषणा कर देते है निवाई में जल की व्यवस्था कर दी जायगी। मैंने वहां की जल योजना के बारे में वहां के लोगों की पिटिशन पिटिशन कमेटी के सामने भी रखी। वहां भी सरकार ने मन्जूर किया। यह जो निवाई को पाइप लाईन की व्यवस्था है उसके लिये भारत सरकार से एप्रूवल हो चुका है लेकिन अभी तक व्यवस्था नहीं हो पायी। कुछ दिनों पहले नगरपालिका निवाई के पास नोटिस भी मिला एक साल पहले निवाई की पानी की स्कीम एप्रूव हो चुकी है। इसलिये काम जल्दी से जल्दी शुरू किया जावे। जनस्वास्थ्य की दृष्टि से पहली योजना में इस चीज को प्राथमिकता दी गई थी भारत सरकार से एप्रूवल हो चुका नक्शा और प्लान बन चुका है लेकिन काम शुरू नहीं हुआ।

उनियारा के लिये भी इसी तरह क स्कीम थी वहां भी गवर्नमेंट से एप्रूव होने के बाद भी काम शुरू नहीं किया गया।

तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह अपने उत्तर में इस बारे में अपने विचार व्यक्त करें।

एक मिनट के लिए मैं आयुर्वेदिक विभाग के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। उस विभाग में जितनी गड़बड़ी और अवस्था है, उसकी तो पराकाष्ठा है....

(समाप्त सूचक घंटी)

श्रीमती सभा नेत्री : आप ज्यादा बोलते हैं तो फिर आपकी पार्टी वालों को समय नहीं मिलेगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं। इस विभाग में ८–६ महीनों तक वैद्यों को वेतन नहीं मिलता है। जो दवाइयां बनती है उनकी जांच की व्यवस्था नहीं है कि हिरण्यटिक में, मुक्तापजामृत में कितनी दवाइयां मिलनी चाहिए। जनता के जन जीवन के साथ इस विभाग के द्वारा खिलवाड़ किया जाता है इस विभाग के निकम्मापन इससे साबित होता है। बदकिस्मती से आज जितने मंत्री हुए है वे कमजोर और लूज मंत्री हुए हैं मंत्रियों का इस विभाग पर असर और नियंत्रण नहीं है। वहां के जो सचालक हैं, उनका बोलबाला है और उनकी मर्जी से सारा काम होता है और उनकी मर्जी गलत मर्जी है। उनके विषय में कई बार चर्चायें होने के बाद भी आज तक वह अपनी मर्जी में नहीं सुधार कर पाए हैं। इसके कारण आज आयुर्वेद विभाग पार्टीबाजी का विभाग बन रहा है ग्रुपबाजी का विभाग बन रहा है और प्रगति के बजाय अवनति हुई है जिसके कारण जनता पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मैं माननीय आयुर्वेद मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि अगर उसमें थोड़ी भी मजबूती है तो इस विभाग को अपने हाथ में ले। मैं उनसे बड़ी आशायें करता हूं कि वह योग्य और स्ट्रांग व्यक्ति हैं। अगर उन्होंने योग्यता नहीं दिखाई तो उनका नाम भी उसी ब्लैक लिस्ट से होगा जो आज तक आयुर्वेद मंत्रियों का रहा है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) सभानेत्री महोदया, यहां हुक्त से कटौती के प्रस्ताव आए हैं । राजस्थान में पानी अमृत है । यहां पर जवाई से जो पानी निकलता है उनके लिये आप पक्की नालियां बनाएं । रास्ते में पानी कितना खराब हो जाता है । मैंने कई बार कहा है कि गांवों को जहां पानी जवाई देता है वहां कि सारी नालियां सीमेंट की होनी चाहिये । दूसरी बात आपने पाली के अन्दर स्कीम १९५१ में बनाई और लागू हुई है १९६१-६२ में । पाली के अन्दर पानी की जो अव्यवस्था हो रही है उसका कारण यह है कि स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है । जब नहर बन्द हो जाती है तो पीने के पानी की समस्या खड़ा हो जाती है । पाली जिला एक महत्वपूर्ण जिला है । मेरे ख्याल से आमदनी की दृष्टि से पाली जिले से राजस्थान में आमदनी मिलती है उतनी आमदनी और कोई जिला नहीं देता । लेकिन अफसोस है कि पाली के अन्दर अभी तक अव्यवस्था है । उसके कारण जो पैसा हमको मिलना चाहिये था वह नहीं मिला ।

नगरपालिका के नल जो जगह जगह पर लगे हैं, उनको योजना के अनुसार काम करना चाहिये तो ज्यादा लोग प्राइवेट कनेक्शन्स ले सकें और आमदनी बढ़ा सकें क्योंकि सामाजिक आधार पर वितरण होना चाहिये । पानी का वितरण जहां मालदारों की बस्ती हो वहां कम पब्लिक नल लगने चाहिये और उनके बजाय ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : पब्लिक टैप्स सरकार नहीं लगाती ।

श्री मूलचन्द डागा : नगरपालिका लगाती है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप चेयरमेन रहे हैं, क्यों मालदारों की बस्ती में ज्यादा नल लगाए ?

श्री मूलचन्द डागा : मैंने गरीबों के लिये ज्यादा नल लगवाए ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : जिन्होंने चुनाव का चंदा दिया होगा !

श्री मूलचन्द डागा : आपकी जल प्रदाय योजना के जो नियम है और जिस प्रकार पानी का वितरण करते है उनके अनुसार सब जगह पर पानी का वितरण होना चाहिये ।

डाक्टरों के लिए मेरा एक सुझाव यह था कि पाली में जो अस्पताल है उसमें न तो सरजन है और न आई स्पेशलिस्ट है ।

यह भी आप व आश्वासन देते हैं कि कम्पाउंड वाल बनायी जायगी । डाक्टरों के लिए जो बातें यहां कही हैं वे सही हैं उनके कारणों में नहीं जाना चाहता लेकिन एक दो बातें कहूंगा ।

अक्सर डाक्टरों के लड़के ही डाक्टर बनते है । मालदारों या ऊंचे क्लास के लड़के होते हैं उन लोगों में हम आदत नहीं डाल सकते सेवा करने की । जिन्होंने जिन्दगी भर हकूमत की है, वे बड़े बड़े परिवारों से आते हैं और मिडिल क्लासेज और छोटी फैमिलीज से नहीं आते हैं । इसलिए सरकार को चाहिये कि जो छोटी जाति के विद्यार्थी हैं उनको कम नम्बरों

(श्री मूलचन्द डागा)

पर ही पास किया जाय और उनको ज्यादा महता दी जाय। अगर आप चाहते हैं कि सेवा हो तो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं पिछड़ी जाति के जो लोग हैं उनके लड़कों को आप ६० या ४० प्रतिशत नम्बरों के बाद ही अलाऊ कर दें। इससे जो डाक्टर पैदा होंगे वह गरीबों की सेवा कर सकेंगे। आज जो डाक्टर्स और इंजीनियर्स होते हैं वे ठीक तरह से सेवा नहीं कर पाते क्योंकि वे बड़े परिवार से आते है।

दूसरा तरीका यह है कि आप अपने अस्पतालों के अन्दर काटेज वार्ड हटा दें। सारे अस्पताल में एक प्रकार की खाटें होनी चाहिये। आपने काटेज वार्डस अलग रखे हैं, डाक्टर उनको ज्यादा समय देते हैं। हमारा सबसे पहले मूल उद्देश्य यह है कि भेदभाव को खत्म किया जाय।

तीसरे डाक्टरों की निजी प्रेक्टिस बंद होनी चाहिये। हम लोग बराबर आवाज उठाते है, आप उस आवाज को पहचानने की कृपा करें। जो डाक्टर बनना चाहते है उनको बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ता है। १५-२० हजार का खर्चा करने के बाद वे डाक्टर बनते हैं। इसलिए वे अपना एक संसार बनाते है, वे उस संसार के चक्कर में फंस जाते हैं. वे अपनी योजना बनाते हैं, अपने विकास की जिससे वो देश की सेवा करना भूल जाते हैं। ज्योंही वे मेडीकल कालेज से बाहर निकलते है. वे अपने लक्ष्यों को आगे रखते है वे यह नही समझते कि गरीबों की सेवा करनी है। अगर मेडिकल कालेज के अन्दर छोटी जाति के लड़के आए, उन पर आप खर्चा करें तब डाक्टरों से मिशन के रूप में काम ले सकते हैं।

मैंने गांव गांव में देखा है, अक्सर नारु की शिकायत है। पानी में इसके लिए भी इलाज होना चाहिये।

जैतपुर के तालाब में पानी इतना गन्दा होता है कि पीने लायक नहीं रहता। वह गांव पानी तहसील में है। जन स्वास्थ्य विभाग और डाक्टरों को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

जब कभी अलवर वाले माननीय सदस्य बोलते हैं या जयपुर वाले बोलते हैं, पानी की बड़ी रकम जो लाखों में दी हुई है, वह शहरों में खर्च करना चाहते हैं। राजस्थान में जो ७० प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं वे प्यासे मर जाते हैं, उन पर खर्च न करके शहरों में चाहते हैं कि २०-२०, १८-१८ गैलन एक एक आदमी के लिए पानी शहर में होना चाहिए और हम कहते हैं कि आपकी एक शहर की योजना कम से कम ३०० गांवों की मांग को पूरा कर सकती है, मैं अर्ज करता हूँ कि गांव वाले बोलने वाले कम होते हैं, उनकी ताकत कम होती है....

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : आपने विरोध किया।

श्री मूलचन्द डागा : चोर की दाढ़ी में तिनका।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने विरोध किया, योजना नहीं हुई। गाँव में औरतें पानी भरने जाती हैं, आपने उनके केस को प्लीड किया।

श्री मूलचन्द डागा : पंपिंग सेट से पानी निकाल कर गांवों को सप्लाई करना चाहते हैं। गांव गांव में नल योजना लागू करना चाहते हैं उसका विरोध करते हैं। पानी निकलने के लिये ड्रेनेज भी साथ में होनी चाहिये। इसको आप लागू नहीं करते हैं। सिवेज और ड्रेन स्कीम साथ साथ होनी चाहिये और वाटर सप्लाई के। पाली में प्रोबलेम है ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उदयपुर में एक करोड़ की वाटर स्कीम का प्रोविजन बजट में दिया है आप उसका विरोध कर रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : वह टूरिट्स के लिये है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तुम्हारा नम्बर नहीं आने वाला है मंत्रिमंडल में। शंकरलालजी बैठे हैं। हिम्मत करके कहो ना कि वहां यह नहीं होनी चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : शहरों की बात कहने लगा तो उनको यह बात लगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सुखाड़ियाजी का नाम आते ही चौकड़ी भूल जाते हो।

श्री मूलचन्द डागा : यहां पर सुखाड़ियाजी की क्या बात है। लोकतन्त्र में सुखाड़ियाजी है। Everybody is expected to become a Sukhadia.

सुखाड़ियाजी में और आप में कोई डिफरेन्स नहीं है।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य आप अपने विषय पर आ जांय।

श्री मूलचन्द डागा : सभानेत्री महोदय..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसी डाट पनघट पर पड़ती है।

श्री मूलचन्द डागा : सभानेत्री महोदया कहने का मतलब यह है कि गांवों के अन्दर ज्यादा धन राशि खर्च की जाय। लिस्ट दी है मैंने गांवों की उनमें पानी पहुंचाना और टैंक बनाने की योजना जरूरी है बनिस्बत शहरों में बड़ी बड़ी योजनायें बनायीं जाय पहले गांवों में खर्चा किया जाय यही मेरा सुझाव है।

श्रीमती सभानेत्री : श्री लाभचन्द वैद।

श्री लाभचंद वैद (सुजानगढ) : सभापति महोदया, चुरू जिले में सुजानगढ एक प्रमुख स्थान है। वहां पर जल का बहुत संकट है। जनता द्वारा बहुत अर्से से प्रयत्न किये जा रहे लेकिन अभी तक वहां जल योजना अधूरी पड़ी है। वहां के प्रसिद्ध व्यापारी श्री सूरज मल जी कंदारी ने एक विदेशी फर्म से कान्ट्रेक्ट करके बोरिङ्ग कराया था लेकिन सफलता नहीं मिली। खेतानजी ने लाडनू से जल योजना बनाकर सरकार की मांग के अनुसार रुपया जमा कराया उसके बाद वहां जल योजना शुरू हुई। दुःख के साथ कहना पड़ता है कि चुनाव के दिनों में यह योजना बहुत जोर शोर से चली। सुजानगढ़ में रास्तों में चौड़ाई कम होने से आमने सामने मोटर खड़ी हो जाय तो पास नहीं हो सकती, फिर भी वहां पर चुनाव के समय में सड़कों में

(श्री लाभचन्द)

नल बिछाने का काम शुरू किया। चुनाव के दिनों में मोटरों के आवागमन में दिक्कत रही जल योजना में जल की टंकी बने बगैर नल बिछना कोई महत्व नहीं रखता फिर भी नल बिछाने का काम किया और टंकी बनानी चाहिए थी वह नहीं बनायी। चुनाव समाप्त होते ही सारे काम समाप्त कर दिये गए। आज जनता पानी के लिए तड़फ रही है। दिन के १२ बजे चिलचिलाती धूप में जाकर देखिये तो लाइन में लगे हुए हैं और रात के १२ बजे तक लगे हुए हैं और फिर सुबह ३ बजे जाकर देखिये तो पानी के लिए कतार लगी हुई है। हर साल जबकि सरकार जल वितरण के लिए बराबर सहायता देती रही है और इस साल बन्द कर दी गई है। इससे अधिक और क्या संकीर्णता हो सकती है। इससे मुझे बड़ा दुःख होता है। जिस बात को मुझे कहते लज्जा लगती है सरकार उसे व्यवहार रूप में लाने में नहीं शर्माती। अतः मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह योजना जल्दी से जल्दी वापिस चालू हो, मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देकर इसको चालू कराने की व्यवस्था करें। यही बात मैं अपने कटौती प्रस्ताव के द्वारा रखता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्रीमती सभानेत्री : मा० श्री हंसराज।

श्री हंसराज आर्य (मादरा) : सभापति महोदया, मैं........

कई माननीय सदस्य : सुनाई नहीं देता।

श्री हंसराज आर्य : यह मेरा दोष नहीं है, माइक का दोष है।

एक माननीय सदस्य : आप तो गंगानगर से आये हैं। जोर से बोल सकते हैं।

श्री हंसराज आर्य : मैं निवेदन करूंगा कि इस बीस साल की आजादी के अर्से में हम गांव के आदमी को पीने का पानी नहीं दे पाये हैं। आज राजस्थान के २६ में से ८ जिले ऐसे हैं जिनमें ५० लाख आदमी ऐसे हैं जिनके भर पेट मनुष्य और मवेशी को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। न केवल गांव के पास बल्कि मीलों तक पानी नहीं है। एक तरफ हमारी सरकार यह नारा लगाती है कि किसान को अधिक से अधिक अन्न पैदा करना चाहिए लेकिन इस ओर सरकार का ध्यान नहीं गया। जिस किसान के पास पीने का पानी नहीं है जिसको मवेशी के लिये पीने का पानी नहीं है, मीलों तक नहीं है, वह जिन्दा कैसे रह सकते हैं। खेती करने का तो प्रश्न ही नहीं रहता। खेती करने वाले जानते हैं कि खेती करते समय पानी की कितनी आवश्यकता होती है सिंचाई के लिये नहीं केवल मनुष्य और मवेशी के पीने के लिये पानी चाहिये। हमारे यहां तीन तरह का पानी है। पीने के लिए पानी, और मवेशी के लिए पीने का पानी और स्नान करने के लिये जिस पानी पर वे जी रहे हैं उनसे यह आशा करें कि वह अधिक अन्न उत्पादन करे यह संभव नहीं है। मीलों तक पानी नहीं होने से बहुत सारा समय उनका किसान का पानी जुटाने में ही लग जाता है। सरकार का इस

(श्री हंसराज आर्य)

इस ओर ध्यान नहीं गया है। बजट पास होने जा रहा है। बजट का ध्यान से देखा गया उस में ३४ हजार गांवों के ५० लाख ऐसे आदमी हैं जिनको पीने का पानी नहीं मिलता। आप ने गाँवों के लिये एक पैसा नहीं रखा है। कहने के लिये तो कहा गया कि ३० लाख की बजाय ८० लाख रुपया रखा है। चन्द गाँव हैं। जिनमें चुनाव के दिनों में वाटर वर्क्स की नींव रख दी हो किसी मन्त्री महोदय ने। ८० लाख रुपया चार पांच गांवों में बाँट दिया जावेगा। वे गाँव तो वैसे ही रहेंगे। मैं इसको बुरा नहीं मानता कि शहरों को क्यों सुविधा दी जाय। देनी चाहिये। उसके मुकाबले गांवों को भी देखना चाहिये। २० लाख की आबादी में शहरों को २ करोड़ रुपया दिया गया है वहां ५० लाख की आबादी में एक पैसा भी नहीं दिया गया है। मैं हैल्थ मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि पीने के पानी के लिये विशेष इन्तजाम करना चाहिये। पीने के पानी का ही इन्तजाम न रहा तो खेती का प्रश्न तो दूर रहा। मवेशी को और मनुष्य को जिन्दा रखना मुश्किल हो जावेगा। हमें स्कूल न मिलें, सड़कें न मिलें और बिजली न मिले लेकिन पीने के पानी की पहले व्यवस्था होनी चाहिये।

दूसरी बात है भादरा में ६० हजार रुपया लगाकर प्रसूतिगृह बनाया गया लेकिन आज तक वहाँ पर लेडी डाक्टर नहीं है। लेडी डाक्टर के अभाव में भवन बेकार पड़ा है और उस पर ताला लगा हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि उधर भी ध्यान जाना चाहिये और शीघ्र लेडी डाक्टर भादरा भेजनी चाहिए।

इसके अलावा मैं आयुर्वेद विभाग के लिये निवेदन करूंगा। इसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये। ये आयुर्वेद औषधालय और वैद्य ही हैं जो वहां जाते हैं, जहां डाक्टर जाना पसन्द नहीं करते। रेगिस्तान के इन्टीरियर के गांवों तक वैद्य जाते हैं और वर्षों रहते हैं सेवा करते हैं मीलों तक पानी नहीं है, सड़कें नहीं हैं, आवागमन के आधुनिक साधन नहीं हैं ऐसे ऐसे क्षेत्रों में सेवा करने की क्षमता इन वैद्यों की ही है। पर उनको किसी प्रकार की सहूलियतें आपकी ओर से नहीं हैं। इस ओर भी मन्त्री महोदय का ध्यान जाना चाहिये।

डाक्टरों को रिटायर होने की एज में रियायत दे रहे हैं तो यह रियायत वैद्यों को भी मिलनी चाहिये वैद्यों के साथ ज्यादती होगी यदि वैद्यों को ५५ साल में रिटायर कर दिया जो सभापति महोदया मैं अधिक समय आपका नहीं लूंगा। अन्त में यही निवेदन करूंगा कि पीने के पानी की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका असर उत्पादन पर भी पड़ेगा, उत्पादन बढ़ने के बजाय घटेगा। पानी आप उनको दीजिये, ताकि वे स्वयं जिन्दा रह सकें और अपने मवेशी को पाल सकें। पानी के लिए जैसे कहावत भी है।

जहां पीवन पाणी और है,
वहाँ न्हावन पाणी और।
धन धामणने और है,
वाहरे नन्द किशोर।

(श्री हंसराज आर्य)

जब किसान हल चलाता है और पानी उसके पास खत्म हो गया और बादल आकाश में उठता है तो वह हल रोक देता है और बादल से प्रार्थना करता है ऊपर देखकर कि-

ऐ आभे उड़ती बादली मरुधर कानी जोय।
छण एक बूंदां नाख दे तो भव मानूं तोय।।

इस तरह वहां के लोग पानी के लिए लालायित हैं। उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो यह सरकार की उनके प्रति घोर उपेक्षा वृत्ति का ही परिचायक होगा। मैं आशा करता हूँ इधर मन्त्रीजी अवश्य ध्यान देंगे।

श्रीमती सभानेत्री : श्री मनोहरसिंहजी मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभानेत्री, अब कोई सदस्य यह न कहे कि इस विभाग में भ्रष्टाचार बहुत है। भ्रष्टाचार का तो अब प्रश्न ही नहीं है। यह तो तब होता है जब १०० में से पांच आदमी करें। लेकिन जब सौ में से पिच्यानवें करने लग जायं तो वह भ्रष्टाचार बन जाता है। तो इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन नहीं करूंगा।

दुर्भाग्य से मै उस उप जिले से आ रहा हूँ जहां छः डिस्पेन्सरियां हैं पर डाक्टर एक में भी नहीं है। जीवित आदमी को दवा न मिले तो कोई बात नहीं है पर एक्सीडेन्ट से कोई मर जाय और दो दो दिनों तक उसकी लाश सड़ती रहे तो ऐसा तो न करें। एक्सीडेन्ट होते रहते हैं उधर उससे आदमी मर जाते हैं तो दो दो दिनो तक लाश गरमी में उसकी सड़ती रहती है पर पोस्ट-मार्टम करने के लिये डाक्टर नहीं मिलता। जो औरते कष्टी हो जाती है उन्हें भीलवाड़ा ले जाना पड़ता है। लेकिन पी. डब्लू. डी. मिनिस्टर साहब की कृपा से रास्ते में ही बच्चा हो जाता है या औरत मर जाती है सड़क में गड्ढे पड़े हैं रास्तों में एक एक फुट के

डाक्टर गांवों में जाना नहीं चाहते। तो मेडिकल कालेज भले ही कम खोलिये पर पढ़ाने वाले आचार्य उपाचार्य ऐसे रखिये जो चरित्रवान् हो सेवा भावी हों। फिर उनसे शिक्षित डाक्टर निकलेंगे तो वे सेवा भावी और चरित्रनिष्ठ हो सकेंगे।

तीसरी बात निवेदन करना चाहूंगा कि कृपा करके आप चिता से हाथ न सेकें। और कामों में रिश्वतें लें यह समझ में आ सकता है। पर किसी की चिता से हाथ सेकें यह दर्दनाक है आप अपने आजादी से पहले के कौल याद करिये। आपने कौल किये थे, आप पूरा खाना देंगे, पीने को पानी देंगे, दवा दारु का उचित प्रबन्ध करेंगे। रिश्वतें नहीं लेंगे।

कौल याद कर, भूल मत, देख चकाणा खोल।
घूंस बढ़ी सोल गुणी, घुसी सौ गुणी पोल।।

जब मैं भीलवाड़ा जाता हूं तो वहां की नालियों में बदबू आती है। घर वालों के लिये रहना भी मुश्किल हो जाता है। आयुर्वेद के डायरेक्टर बैठे हैं एक वैद्य है उनका मकान है वहां नाली के पास में नरक के नज्जारे सामने नजर आते हैं। शहरों में पानी होते हुए भी यह हाल है। फिर गांवों में तो पानी नहीं। सफाई कैसे हो वहां?

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

मेडिकल में आप कटौती न करें। मुझे विश्वास दिलाया है कि जल्दी वहां डाक्टर भेज रहे हैं। छः में नहीं तो कम से कम एक दो में भेजे ही दें ताकि मरने वाले को तो गति मिल सके। जिस दिन हमारे यहां एक्सीडेन्ट।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, कृपया आप गैलरी में बैठे हुओं की तरफ मुखातिब न हों। अफसरों की तरफ हाथ करके इशारा करके न बोलें। आप मेरी तरफ मुख करके बोलें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : नया आदमी हूं इशारे विशारे तो करता नहीं हूं।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : नये आदमी नहीं बुड्ढे भी हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं बुड्ढा नहीं हूं। आपके मन में जितनी सेवा की तमन्ना है उससे कम तमन्ना मेरे मन में नहीं है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : यहां बात इसारे बाजी की चल रही है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : तो आपका अधिक वक्त नहीं लेकर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य और आयुर्वेद डिस्पेन्सरियों में रहो बदल आवे इसका प्रयास करें ताकि लोगों को राहत मिल सके।

(३५४ म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : (हवामहल, जयपुर) उपाध्यक्ष महोदय, बड़े संयोग की बात है कि हमारे सामने आज दोनों लूप और नल कूप मन्त्री जी साथ साथ विराजमान है।

फैमेली प्लानिंग में हमारे देश के प्रधान मन्त्री जी की लूप एक प्रिय योजना है तो इस दृष्टि से स्वास्थ्य मन्त्री जी को या कि चिकित्सा मन्त्री जी को लूप मंत्री कह दूं तो अनुपयुक्त नहीं होगा।

अब जन स्वास्थ्य का जहां सवाल है वहां पीने को पानी नहीं मिलता तो नल और कूप की बहुत मांग है। तो इस दृष्टि से दूसरे मन्त्री जी हमारे नल और कूप मंत्री भी है। तो ये दो मन्त्री यहां उपस्थित हैं। वैसे अक्सर दो मन्त्री ऐसे अवसरों पर मिला नहीं करते एक साथ। पर आज सौभाग्य से दोनों लूप मन्त्री जी और नल कूप मन्त्री जी विराजमान हैं।

मैं तो इतनी सी बात निवेदन करना चाहता हूं कि चिकित्सा में भ्रष्टाचार का जहां तक सम्बन्ध है मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि आप के ही कार्यकर्ताओं के द्वारा आज उस भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बता दिया गया है। पैसा लेकर काम करना यह तो आजकल एक साधारण सी बात हो गई है।

मैं तो दो चार मोटी मोटी मुद्दे की बातें रख देना चाहता हूँ। हमारे यहां दो करोड़

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

जनता है। अब आप आंकड़ों से देख लें कि उनके लिये कितने चिकित्सालय हैं और यह भी देख लें कि क्या वे राजस्थान की दो करोड़ जनता के लिये पर्याप्त हैं क्या ? अगर अपर्याप्त मानते हैं तो विचार करना पड़ेगा कि उनमें औषधियों की व्यवस्था करने का प्रश्न उत्पन्न होता है और डाक्टर भेजने के प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं तो उनमें जन साधारण की मांग व आवश्यकता के अनुसार औषधियों आदि की व्यवस्था करते हैं या राजनैतिक कारणों से या दबाव के कारणों से सारी व्यवस्थाएं करते हैं।

प्रश्न काल में इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल सका। नौ नौ साल से डाक्टरों की व्यवस्था आप नहीं कर सकते।

दूसरी प्रधान चीज यह है कि लाखों करोड़ों रुपया गांवों के लिये आप खर्च करते हैं इसके लिये बधाई के पात्र हो सकते हैं। पर यह भी आप देखें कि उनका प्रोपर यूटीलाईजेशन भी होता है या नहीं। गांवों में छोटी मोटी डिस्पेन्सरियों में आप नये नये पढ़े लिखे डाक्टरों को भेजते हैं। कालेज से वे नये नये निकले होते हैं, सेवा का उनमें अभाव होता है। शहरी वातावरण में पले-पोसे होते हैं वहां गांवों में वे फिट नहीं होते। पर आप उनका सीधा अपोइन्टमेंट कर देते हैं। इसका परिणाम क्या होता है ? उनका मन वहां नहीं लगता। वे शहरों की तरफ उन्मुख रहते हैं। मेरे अनुभव की बात है। व्यक्तिगत रूप से किसी की आलोचना करने का स्वभाव मेरा नहीं है। शाम का टाइम हुआ कि वे स्कूटर पर बैठकर शहर में जायें और सिनेमा देखेंगे। इतवार को भी वहीं रहेंगे। छुट्टियों में भी वहां ठहरेंगे। गांवों में आप सेवाभाव से रखना चाहते हैं उनको। पर वे वहां नहीं ठहरते।

आप तो रिटायर्ड पुराने डाक्टरों को वहां भेजिये दो चार पांच साल के लिये वे गांवों की जनता की सेवाभाव से सेवा करेंगे। वे उस वातावरण में फिट भी हो सकेंगे। नये नयों को शहरों में रहने दीजिये।

(४ म. प.)

दूसरा यह सुझाव है क्योंकि डाक्टरों का अभाव बताते हैं। जब कभी समस्या आती है तो कहते हैं कि डाक्टर कहां से दें डाक्टर मिलते ही नहीं हैं। तो जो पुराने डाक्टर हैं और वह आपको मिल भी सकते हैं और जो सेवाभाव भी रखते हैं जिन्होंने जनता की सेवा के लिए अपने हृदय को तल्लीन करने की कोशिश की है ऐसे डाक्टरों को आप गांवों में लगायेंगे तो आप सही माने में सेवा कार्य कर सकते हैं।

जहां तक फेमिली प्लानिंग का सवाल है इस प्रश्न को लेकर बहुत विवाद चलता है। इसके लिए दोनों प्रकार से तर्क दिये जा सकते हैं। कोई इसके पक्ष में बोलेगा, कोई विपक्ष में बोलेगा लेकिन राष्ट्र की इस समस्या को लेकर में उचित समझता हूं कि इसमें राज्य सरकार को अग्रसर होना चाहिए अब लूप की व्यवस्था को लेकर चलते हैं तो इसमें दो दोष हैं। इन दोषों में से प्रधान दोष यह है कि लूप जब लगाई जाती है तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स कुछ ब्लीडिंग वगैरह के या वेदना के होते हैं और कुछ लोगों के उपर उसका दुष-

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

प्रभाव पड़ता है। तो जो सब्सीक्वेन्ट यूनिट है अगर वह जाकर चैक करे और लोगों के अन्दर इस प्रकार की भावना को समझाने की चेष्टा करे कि इसके क्या सद्परिणाम और दुष्परिणाम निकलने वाले हैं और उसके बारे में लोगों को समझाने की चेष्टा करे तो हो सकता है कि आपकी योजना आगे चल सकती है। लेकिन कोई स्टेप राज्य सरकार की तरफ से नहीं लिया जा रहा है इस सब्सीक्वेन्ट यूनिट के बारे में इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए....

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आप तो लूप की बात करते हैं यहां तो आपरेशन्स ही फेल हो जाते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : वह तो १०-२० परसेन्ट केसेज फेल हो जाते हैं।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आपका तो सेन्ट परसेन्ट ही फेल हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के साथ मुझे बड़ी सहानुभूति है। आपरेशन करवाया और १३ बच्चे हो गये उसके बाद में।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह अनुभव उनको भी है।

तो मेरा निवेदन करना यह था कि जहां तक वन एक्ट प्ले चलते हैं सिनेमा में रील्स चलती है इनकी व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि जहां आपका वह यूनिट जाता है साथ ही साथ वह फालो प्रोग्राम के रूप में भी सब्सीक्वेन्ट यूनिट जायेगा तो मैं आशा करता हूँ कि इसका प्रभाव सही रूप से पड़ सकता है।

रहा सवाल यह कि जहां तक जयपुर शहर की समस्या है स्थानीय सदस्य होने के नाते मैं इतना सा निवेदन कर देना चाहता हूँ कि जयपुर की पापुलेशन जो आज से ५ वर्ष पहले थी उसकी तुलना आज आप कीजिए। होस्पीटल में कई बार मरीजों से मिलने जाने और दूसरे कामों से जाने का इत्तफाक मुझे मिलता है। मैं यह देखता हूँ कि बरामदे में भी बैड्स की जगह नहीं है नीचे बिस्तर लगाये जाते हैं और आजकल जो आपकी व्यवस्था है चिकित्सा मन्त्री जी मेरे साथ आप चलकर देखिये जो बिस्तरों पर चद्दरें हैं वह काले रंग की होती है। क्या पता वहां के धोने का तरीका ऐसा हो गया है कि सफेद चद्दरें आपको वहां नहीं मिलेगी। स्टेट के जमाने में भी हम शफाखानों को देखते थे और अब तो आपको लाखों रुपयों की मशीनरी धोने की मिली हुई है वह आपने लगा रखी है फिर भी आपकी इस प्रकार की दुर्व्यवस्था होती है कि कोई भी आदमी जो उसको देखेगा कहेगा कि इतनी गन्दगी है। उसको शफाखाना कहें या क्या कहें समझ में नहीं आता। एकामोडेशन की आपको व्यवस्था करनी चाहिए। बजट में उसका प्रावधान रखना चाहिए और इसकी मांग यों करनी चाहिए कि जन-स्वास्थ्य और चिकित्सा यह मानव के जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव डालने वाली चीजें हैं।

शरीरया खलु धर्मार्थराय मोक्ष साधनम्
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों को

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

कोई व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है भारतीय संस्कृति के माफिक प्राप्त कर सकता है तो उसके लिए शरीर को स्वस्थ रखना परमावश्यक है और इसके लिए आपको चिकित्सा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा प्रभाव करने वाली यह चारों चीजें हो सकती हैं। स्वतन्त्रता से पहले आप लोगों ने इस देश से वादा किया था कि हम लोगों को फ्री मेडीशन्स देंगे। लेकिन आप देखिये। स्टेट के जमाने में मुझे याद है कि जो इन्डोर पेशेन्ट्स होते थे उनको दवाइयां बाहर से नहीं खरीदनी पड़ती थीं। लेकिन आज ६० परसेन्ट आपको केसेज ऐसे मिल जायेंगे कि डाक्टर लोग इन्डोर पेशेन्ट्स को भी पर्चा लिखकर दे देते हैं और गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है उसको डाक्टर की लिखी हुई प्रेस्क्रीप्शन से बाहर बाजार से खरीदना पड़ता है। इन्डोर पेशेन्ट्स के लिए आप दवाई मुहैय्या नहीं कर सकते और दावा करते हो लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का। आप कहते हैं कि हम फ्री मेडीशन्स का इन्तजाम करते हैं, चिकित्सा का इन्तजाम करते हैं पर आपको ६० परसेन्ट केसेज ऐसे मिलेंगे कि जिनको दवाई नहीं मिलती है। आखिर यह दवाई कहां जाती है। लाखों रुपयों का बजट खर्च होता है लेकिन इन गरीब मरीजों को कितनी दवाइयां बाँटी जाती है वह कहाँ जाती है। इसलिए दो मुख्य प्रश्न सामने पैदा होंगे। एक प्रश्न का सम्बन्ध नीति से है और दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध व्यवस्था से है। जहाँ तक नीति का सम्बन्ध है हम स्टेट की पालिसीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं लेकिन जहां तक व्यवस्था का सवाल है, व्यवस्था के सवाल के अन्दर कोई घोटाले होते है, गबन होते हैं, दवाइयां खरीदी जाती हैं लेकिन मरीजों को नहीं मिलती और दूसरों को चली जाती हैं तो यह व्यवस्था का प्रश्न है और इसको आप नहीं संभाल सकते तो हम आपको क्या कहें। या तो यह कहें कि आप इतने काबिल नहीं है या फिर यह कहें कि आपकी भी बेईमानी में साजिश है। इसके दो हो रास्ते हो सकते हैं। अगर आप कन्ट्रोल नहीं कर सकते तो नाकाबिल हो इसलिए कुर्सी पर बैठने के अधिकारी नहीं हो और अगर आप काबिल हैं समझते हैं, सारी बातें आपके ध्यान में आती हैं और फिर नियंत्रण नहीं कर सकते तो दृष्टिकोण एक ही है वह यह है कि आपकी उन लोगों के साथ साजिश होनी चाहिए। दोनों ही बातें आपकी आलोचना की हो सकती हैं। मैं एक एक चीज को लेकर समयाभाव के कारण नहीं कह सकता। मैं कान्क्रीट इन्स्टान्सेस देकर और ऐसे केसेज भी आपके सामने वक्त आने पर पेश करूंगा आज समय नहीं है कि यह सारी बातें आपके सामने कहूं, यह सब आपके सामने हो रहा है और आपको ध्यान देना चाहिए।

जनस्वास्थ्य मंत्री जी में जयपुर के लिए बहुत असें से निवेदन कर रहा हूं। जहां तक जयपुर में पीने के पानी की समस्या का सवाल है उसके लिए पहले भी सुझाव दिये और इस संबंध में आपको अब भी यह सुझाव देना चाहता हूं कि कम से कम इस जयपुर शहर में ऐसे बहुत बड़े गहरे कुए हैं जिसकी आपको करोड़ों और लाखों की योजना बनाने का सवाल नहीं है थोड़े से हेंड पम्प और थोड़े से पम्पों से कनेक्शन देकर पानी का कनेक्शन

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

दे दें तो यह समस्या काफी हल हो सकती है। आप केवल दो घन्टे पानी देते हैं और उसमें भी आपका प्रैशर नहीं है। माननीय जन-स्वास्थ्य मंत्री ने मेरी इस समस्या का उत्तर दिया तो मेरा हृदय दुःख से विदीर्ण हो गया, मेरा हृदय रो उठा कि लोक कल्याण कारी राज्य के यह मंत्री आज जयपुर के नागरिकों के साथ बदले की भावना लेकर यह उत्तर देने की कोशिश करते हैं और मेरे सवाल का उत्तर दिया वह कोई भी लोक कल्याणकारी राज्य का मंत्री उत्तर नहीं दे सकता। मंत्री महोदय ने जयपुर की समस्या को लेकर कहा है कि राजस्थान में ऐसे भी गांव हैं जहां बीस—बीस मील से लोग पानी लाते हैं। हम जयपुर की जनता को २ घन्टे तो पानी देते हैं। इस मंत्रिमण्डल के लिए शर्म की बात है। मैं तो कहता हूं कि यह आपका पुनीत कर्त्तव्य है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जनता के साथ यदि इस प्रकार की भावना को लेकर आप चलना चाहते हैं तो आज नहीं कल नहीं समय आयेगा कि जिस मंत्री मण्डल की कुर्सी पर आप गौरव से बात करना चाहते हैं वह आपके पांव के नीचे नहीं होगी। कुर्सी और के अधिकार में होगी। आप इस कुर्सी पर बैठने के अधिकारी उसी समय हो सकते हैं जब कि लोक कल्लाणकारी राज्य को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। माननीय जन-स्वास्थ्य मंत्री थोड़ा आप ध्यान दीजिए। इस जयपुर की योजना विशेष के लिए पहले भी आपने एक कमेटी इस प्रकार की बनाई थी कि जिसमें जयपुर के नागरिकों को, यहां के इन्जीनियर्स को और सबसे कन्सल्टेशन करने के बाद में जो बड़े बड़े अच्छे कुए थे जिनमें अच्छा अच्छा पानी मिल सकता था उनमें हैंड पम्प लगाने की व्यवस्था की थी वह योजना रह गयी। कमेटी ने कार्य किया नहीं और पता नहीं वह कागजात कहीं रह जाते हैं और आप अपनी पार्टी के ही लोकल वर्कर्स को ले लीजिए लेकिन जनता की सेवा करने की कोशिश तो कीजिए। इसी तरह से होस्पिटल के बारे में, अव्यवस्था के बारे में, इस मंत्रि-मण्डल और अफसरान के नोटिस में लाने के बारे में, इर्रेगुलेरिटीज के बारे में रिपोर्ट करने के लिए लोकल कमेटीज ऐसी होनी चाहिए कि जिससे थोड़ा नियंत्रण रहे, थोड़ा इस प्रकार का ध्यान रहे। इन छोटे छोटे सुझावों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बहस समाप्त करता हूं।

श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी): उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामों में चिकित्सा की सुविधा देने के लिए सरकार ने प्राईमरी हेल्थ सेंटर्स की योजना बनाई। जब यह योजना बनी इसको हम लोगों ने भी, कार्यकर्त्ताओं ने भी और ग्रामों के लोगों ने भी बहुत पसन्द किया। हम सोचते थे कि यह योजना जब क्रियान्वित होगी तो इससे जन साधारण को बड़ा लाभ होगा, लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि इस योजना से सरकार का खर्चा बढ़ गया और गांव वालों को कोई लाभ नहीं पहुंचा। मैं आपको इसका उदाहरण दूं कि मेरे क्षेत्र के अन्दर प्राईमरी हेल्थ सेंटर है, इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। मेरे क्षेत्र में सबसे पहले राजस्थान में जो पंचायत समिति बनी तो सबसे पहले चिड़ावा के अन्दर

(श्री मूलचन्द कटेवा)

पंचायत समिति में बैठ करके एक ऐसे इलाके को चुना जहां दस दस मील तक किसी भी दवाखाने की, हौस्पिटल की व्यवस्था नहीं है और सुल्ताना में प्राईमरी हेल्थ सेंटर कायम हुआ और उस सेंटर को कायम हुए लगभग नौ साल हो गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि नौ साल के अन्दर एक दिन के लिए भी वहां डाक्टर नहीं भेजा गया। पंचायत समिति ने कम से कम भी बीस, पच्चीस रिजोल्यूशन भेजे। हम बराबर उसके लिए पत्र देते रहे हैं लेकिन एक भी डाक्टर वहां पहुंचने का आज तक सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि डाक्टर वहां पर है नहीं और सरकार के आदमियों पर बीस हजार रुपया सालाना का कम से कम खर्चा है। तो फिर इस खर्चे की आवश्यकता क्या है। मैंने इसके लिए प्रश्न भी पूछा था और मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि वहां फर्स्ट ग्रेड का कम्पाउण्डर है इसलिए इस कमी की पूर्ति होती है। लेकिन मुझे अफसोस है कि मंत्री महोदय को इस बात का ज्ञान नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड का कम्पाउण्डर आखिर होता क्या है। वह पेनेसिलीन का इंजेक्शन तो डाक्टर के बिना लगाने का अधिकारी नहीं होता है। तो इस तरह से तीस हजार का खर्चा तो वहां पर कर देंगे लेकिन एक डाक्टर तक नहीं देंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि यह बात क्यों है और मंत्री महोदय यहां से उठकर चले गए हैं। मैं तो उनसे यही निवेदन करूंगा कि यदि कोई वोट-व[illegible]गड़ा हो तो मैं तो एक ही वादा करूंगा कि वे डाक्टर लगा दें मैं उस शहर से कभी जिन्दगी में वोट नहीं मांगूंगा। मैं आगे चुनाव लड़ूंगा तो दूसरी जगह से वोट का इन्तजाम कर लूंगा।

लेकिन इस तरह से एक वोट के सवाल को लेकर जब चुनाव आयें तब उस समय कहा जाय कि तुम हमको वोट दो हम डाक्टर भिजवा देंगे और उसमें से कुछ आदमी वोट दे देते हैं और ज्यादा नहीं देते तो फिर डाक्टर नहीं भेजा जाता है। मैं समझता हूं कि अगर डाक्टर भेजने में यही एक बाधा हो तो उसके लिये मैंने इस हाउस के इतने मेम्बरों के बीच में कह दिया है कि अगर दुबारा मैं चुनाव लड़ूंगा और आप वहां डाक्टर लगा देंगे तो मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा। इससे बड़ा त्याग मैं और क्या कर सकता हूं। मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय भी अपनी बात को छोड़ेंगे और सुल्ताना में जल्दी से जल्दी डाक्टर रखेंगे और डाक्टर नहीं रख सकते तो राजस्थान के हित के लिए एक बात करें कि जो १४ आदमी वहाँ पर बिठा रखे हैं उन्हें यहाँ पर वापिस बुला लें। हम वहां पर ग्राम सेवक या और किसी कोटिंचर आयोडिन वगैर देकर बिठा देंगे और वही काम करता रहेगा। वही काम वे लोग कर रहे हैं। बस मुझे इतना ही निवेदन करना था।

श्री गंगासहाय (कठूमर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव देता हूं अभी चिकित्सा के सम्बन्ध में अनेक लोगों ने अपने विचार रखे। और लोगों ने कहा कि आज चिकित्सा बहुत मंहगी हो गई है और लोगों ने भी यह सुझाव दिया कि डाक्टर मिलते नहीं है और मिलते भी हैं तो गांवों में जाने को तैयार नहीं हैं।

(श्री गंगासिंह)

भारत जैसे निर्धन देश और राजस्थान जैसे गरीब प्रदेश के लिये मैं एक सुझाव देता हूँ कि क्यों नहीं राजस्थान भी अन्य प्रदेशों की भांति होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता दें। यहां पर भी होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता दी जाय। मैं आपको निवेदन करूंगा कि यह चिकित्सा पद्धति बहुत ही सरल है और सस्ती भी है। आसानी से इस चिकित्सा पद्धति के द्वारा गरीब जनता को राहत पहुंचाई जा सकती है। मैं आपको बताता हूँ कि राजस्थान में सैकड़ों ही नहीं हजारों की तादाद में आपको होम्योपैथिक चिकित्सक गांवों में जाने के लिए मिल जायेंगे।

इसी के साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि....

श्री उपाध्यक्ष : आपने तो भाषण आरंभ कर दिया है। आप तो सुझाव दे रहे थे। अच्छा थोड़े में दे दीजिये।

श्री गंगा सहाय : साथ ही साथ मैं यह निवेदन करूं कि टीबी जैसे रोग के लिए एलोपैथिक चिकित्सा में जहाँ दो हजार रुपया खर्च होता है वहाँ होम्योपैथी में केवल दो सो रुपये में ही इलाज हो सकता है। इसी प्रकार और भी कठिन से कठिन चिकित्सा हो सकती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को अन्य प्रदेशों की भांति मान्यता दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीलाल यादव।

श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती के प्रस्ताव मेडिकल एण्ड हैल्थ के बारे में और नल योजना के बारे में दो हैं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। यह आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे पांच सात मिनट का समय दे दिया।

हमारे यहां नीमराणा पंचायत समिति का हैडक्वार्टर है और एक वहां पर डिस्पेन्सरी है। उसमें लगभग तीन चार साल से कोई डाक्टर साहब नहीं गए हैं। इससे अच्छा मैं यह समझता हूँ कि यहां जो जिस तरह से डिस्पेन्सरी खोल दी है, उसके लिए मुझे एक मोटी सी कहावत याद आती है कि जैसे कि मूली के पत्ते दिखा दिखा कर काम निकालते हैं, एक गरीब आदमी था उसके पास में एक बकरी थी वह उससे काम लिया करता था, उस पर वह मूली के या दूसरे पत्तों का बोझ बांध दिया करता था और उसको देखते देखते वह चलती रहती थी और वह आदमी अपना काम निकाल लिया करता था। इसी प्रकार से गांवों के अन्दर जब आप कोई योजना चलाते हैं और उसका खाली नाम करके उसको टला देते हैं और उसमें कोई साधन नहीं जाते है तो इससे कोई फायदा नहीं है। मैं बहुत संक्षेप में कहता हूँ कि आप वहां पर डाक्टर भेजिए।

इसी प्रकार हमारा बहरोड़ कस्बा है, वहां पर सारे सब डिविजन में एक ही लेड़ी डाक्टर का प्रावधान है लेकिन अफसोस है कि वह जितना महत्वपूर्ण इलाका है, एडवांस इलाका है, सब लोग डाक्टर का इलाज कराना चाहते हैं और अपने बच्चों को भी अस्पताल के अन्दर ही पैदा करवाने के लिए ज्यादा लोग उत्साही हैं लेकिन इसके बावजूद भी कोई लेड़ी डाक्टर वहां पर नहीं है। इसलिए

श्री अमीलाल यादव)

मेहरबानी करके बहरोड़ के अन्दर लेडी डाक्टर भेज देनी चाहिए।

दवाइयों के बारे में मैं अर्ज करूं कि दवाइयां भी वहां पर बिल्कुल नहीं है। आप जाकर देख लीजिए, स्वयं मैं वहां की डिस्पेन्सरीज में गया हूँ। यहां तक मैंने हालत देखी है कि यदि पट्टी ले जायेंगे तो पट्टी बांध देंगे। यदि पाउडर ले जायेंगे तो पाउडर छिड़क देंगे और कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। एक रोज तो यहां तक हुआ कि एक एक फोड़े का आपरेशन करने के लिए उनके पास ब्लेड तक नहीं थी। उन्होंने कहा कि चार पैसे की ब्लैड खरीद लाओ तो ओपरेशन कर दें। इसलिए मेहरबानी करके गांवों में कम से कम यदि हम किसी बात की व्यवस्था न करें, गांवों के अन्दर गेंहूँ नहीं दें, गांवों के अन्दर चीनी नहीं मिले तो चीनी मत दीजिए और भी चीजें जो देते हों वह भी मत दीजिए, लेकिन कम से कम जो तन्दुरुस्ती के लिए चीजें देनी होती है वह तो कम से कम भिजवा दीजिए। इसलिये मेडिशन्स तो कम से कम भिजवा दीजिए। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि किसी भी औषधालय में चाहे पूतोना में हो चाहे दोगोद में हो, कहीं पर भी कोई दवाइयां नहीं है। दो तीन औषधालय देखें कि जहाँ पर खट्टा मिट्टा चूर्ण है उसके अलावा मैंने कोई दूसरी दवाई नहीं देखी। इसलिए जो कुछ भी आप करें लेकिन जो ८५ फी सदी जनता देहातों में रहती है उसका तो आपको ख्याल रखना चाहिए। मेरी शहरों से दुश्मनी नहीं है लेकिन कम से कम मेरी यह समझ में नहीं आता कि यहां जयपुर में बैठ कर देहातों को कैसे भूल जाते हैं। आखिर हम यहां पर देहातों से ही तो आए हैं। मेरी शहरों से दुश्मनी नहीं है, इनको खूब सहूलियतें मिलनी चाहिए लेकिन उनको भी नहीं भूलना चाहिए जो रूरल एरिया में हैं।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करूंगा कि हमने तीन जगहों पर साढ़े सात हजार और पांच हजार रुपये नल योजना के लिए जमा करा रखे हैं। गीगलाने और पूतोना के लिए। वहां पर पौने दो सो फिट गहरा पानी हैं। अदि आप में से कोई वहां पर पधारे हों, जज साहब को मालूम है कि वहां पर कितना गहरा पानी हैं। इसलिए मैं उसके लिए खास तौर पर सुझाव दूंगा कि न तो वहां पर कोई सड़क है और वहां पर मिलिट्री के लोग भी रहते है तो इतनी बड़ी महत्वपूर्ण जगह पर किसी तरह से किसी तजबीज से पानी पहुँचाने की व्यवस्था कीजिए। इसीलिए वहां पर हमने रुपया भी जमा करा दिया था और वह रुपया सन् ६३ से जमा पड़ा है इसलिए नल योजना वहां पर चालू होनी चाहिए।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि १९६३ में जो सब सेन्टर की बिल्डिंग बनाने के लिए जो रुपया जमा कराया गया था, उसकी अभी बिल्डिंग नहीं बनी है। दस हजार रुपया, तेतीस सौ रुपया करके तीन सब सेन्टर के लिए जमा कराया था, ढूंडोली, मादरा और गुड़िया जयपुर की—यह तीनों की बिल्डिंग अभी नहीं बनी हैं। इनको बनवाने के लिए जल्दी से जल्दी टेन्डर वगैरह इन्वाइट कर दें। जनता जब पैसा देती है और उससे जब कन्ट्रीब्यूशन ले लिया है तो

(श्री अमीलाल यादव)

में अर्ज करूंगा कि हमारे यहां की जनता बिल्डिंग के लिए पूरा का पूरा पैसा भी दे सकती है यदि आप बिल्डिंग का निर्माण करें।

साझापुर के लिए हमने एक प्रस्ताव पास किया था। किशनगढ़ बास में एक पब्लिक हैल्थ सेन्टर खोला गया है, वहां पब्लिक हैल्थ सेण्टर खोले जाने की वजह से यहां की डिस्पेन्सरी को शिफ्ट करना है और वहां का स्टाफ वहां से उठ कर अलवर के अन्दर आ गया है। हमने एक प्रस्ताव पास किया था कि साझापुर के अन्दर डिस्पेन्सरी खोल दी जाय। साझापुर की आबादी छः हजार की है, वह पहले पंजाब का इलाका था और वहां छः सात मील के दायरे में मेडिकल एड की कोई व्यवस्था नहीं है, किसी स्थान पर भी एक भी औषधालय या डिस्पेन्सरी नहीं है। नीमराल और उधर जाकर रेवाड़ी है। इसके लिए एक जिला परिषद ने प्रस्ताव पास किया था कि जो स्टाफ पब्लिक हैल्थ सेन्टर का उठ कर अलवर में आया है, इसलिए वहां पर एक डिस्पेन्सरी खोल दी जाय। इसके कागजात आपके यहाँ पड़े हैं। मेरा निवेदन है कि यह गाँव डिजर्व करता है क्योंकि इसकी आबादी छः हजार की है। मैं निवेदन करूंगा कि यह जो मैंने दो तीन बातें कहीं हैं कि बहरोड़ में दवाइयाँ चाहिए, लेडी डाक्टर चाहिये नीमराल में और मांढन में दवाइयाँ नहीं हैं और औषधालय नहीं हैं, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और इसके साथ ही मैंने बिल्डिंग के लिए रुपया जमा कराने की बात कही है।

नल योजना के बारे में मैंने निवेदन किया कि वहाँ रुपया जमा है। महरबानी करके आप स्कीम को पूरा करवाइये। कितने ही गाँवों में तो हम पूरा का पूरा रुपया देने को तैयार हैं। परतापपुर में तो पूरा रुपया हम दे दें यदि आप डिस्पेन्सरी खोल दें। आप देखिये कि स्वास्थ्य के लिए पैसा देने वाले बहुत से दानी हैं, लोग दान देना चाहते हैं। हम आपसे केवल इतना दान चाहते हैं कि आपकी ओर से स्ट्रीट वर्डस में यदि आर्डर जारी हो जाय तो आपकी मेहरबानी होगी।

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य जैसे मसले में बोलने के लिए समय नहीं रहते हुए भी आपने जो मुझे समय दिया है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : चिकित्सा मंत्री।

श्री श्रवण लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय न लेकर बहुत संक्षेप में मोटे मोटे तौर पर जो हमारे यहाँ कमी हैं उनके बारे में निवेदन कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : समय हो गया है और दो माननीय मंत्री महोदय को उत्तर देना है इस लिए समय अब नहीं दे सकता।

श्री श्रवण लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। केवल पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

Page No. 132

श्री श्रवणलाल : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं ....

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय जवाब देंगे अब ।

श्री चुन्नीलाल (नोखा) : उपाध्यक्ष महोदय, कल भी मेरे कट मोशन थे लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं मिला । आज मेरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है उस पर पाँच मिनट का समय बोलने के लिए दे दें तो............

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल को जितना समय दिया गया, उसका उपयोग आपके दूसरे माननीय सदस्यों ने कर लिया है ।

श्री चुन्नीलाल : सिर्फ दो मिनट ।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी स्थिति है कि समय का अभाव है इसलिए समय नहीं दिया जा सकता ।

श्री चुन्नीलाल : केवल दो मिनट । इसमें दल का सवाल नहीं है, इसमें अधिकारों का सवाल है । मैं जिस जगह से आया हूं वहाँ पानी की क्या समस्या है, यह आप जानते हैं, इसलिए दो मिनट का समय मैं आपसे हाथ जोड़ कर माँगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नी लाल ।

श्री चुन्नीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक कटौती का प्रस्ताव जसरासर, जो नोखा तहसील में है, उसकी पेयजल समस्या के सम्बन्ध में है । जसरासर में जो पेय जल की समस्या है, वहाँ उस समस्या को दूर करने के लिए एक स्कीम लागू कर दी है और कुए को पाइपों से भर दिया गया है । वह गाँव बहुत बड़ा है और वहाँ पानी की समस्या ऐसी है, जिसे आप खुद जानते हैं कि हजारों औरतें कतारों में खड़ी रहती हैं और उनको दूसरे गांवों से पानी लाना पड़ता है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस गांव में इस प्रकार की स्थिति है कि वहां पर हरिजनों के चार मोहल्ले हैं लेकिन उन चार मोहल्लों में आज तक पाइप की लाइन नहीं दी गई है । पानी की समस्या वहां खास तौर से गर्मी के दिनों में अधिक रहती है । लेकिन गर्मी के दिनों के बाद में जिस समय सर्दी आ जाती है, उस वक्त हरिजन लोग कुओं पर जाते हैं तो ऊपर से पानी बाल्टी से उनके बरतनों में डाला जाता है । इस प्रकार की जो हालत पेय जल के सम्बन्ध में बना रखी है और जो भेदभाव को नीति बना रखी है, उसके लिए मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इन चार मोहल्लों में करीब दो सौ हरिजनों के घर हैं जिनको पांच पांच फलांग से जाकर पानी लाना पड़ता है........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : शेम !

श्री चुन्नी लाल : इसी प्रकार से बेरासर, जो नोखा तहसील में है, में ऐसी समस्या है । मैं जसरासर के बारे में एक बात कहना भूल गया । यह एक बहुत बड़ा गांव है लेकिन पानी को इकट्ठा करने के लिए न तो कोई हौज है और न कोई कोठी है । इससे पानी की समस्या ज्यादा खराब हो जाती है । इस गांव में

(श्री चुन्नी लाल)

कम से कम छः हजार आदमी रहते हैं और करीब छः हजार से ऊपर पशु हैं। मैंने खुद ने पिछले साल सरकार को तार दिया था कि पानी की समस्या के कारण छः-सात गायें मर गई हैं। लेकिन उसकी आज तक कोई इन्क्वायरी नहीं हुई है। इसी तरह से पांचू गांव है, जिसकी आबादी साढ़े सात हजार के करीब है, वहां पिछले दिनों करीब ११ गायें मर गई। मैंने उसके बारे में तार दिये तो उसके बारे में इन्क्वायरी हुई। लेकिन आज भी वहां पानी की ऐसी समस्या है, आप उस गांव से परिचित हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि उस गांव में एक घड़े का एक रुपया, दो रुपया तक देना पड़ता है। आप चाहें तो इसकी इन्क्वायरी कर लें, पांचू में पानी नहीं है........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल शेम-शेम !

श्री चुन्नी लाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पशु जो पानी पीते हैं उसके लिए भी पचास पैसे देने पड़ते हैं....

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल शेम-शेम !

श्री चुन्नी लाल : इस प्रकार एक आदमी को करीब पन्द्रह रुपया पानी के लिए देना पड़ता है। दरअसल में यह समस्या पानी की वहां है। अगर यह बात झूंठी साबित हो जाय तो मैं इस्तीफा दे सकता हूं।

श्री मदन सिंह दांता : यह भावना नहीं है, मंत्री महोदय की !

श्री दामोदर लाल व्यास : ठाकुर साहब पहले दें।

श्री चुन्नी लाल इंदलिया : उपाध्यक्ष महोदय, आप इस से परिचित हैं कि जसरासर नोखा तहसील में जो है उसकी यह हालत है। इसके अलावा इस सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि एक परवाल के पानी पर पांच रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से लिये जाते हैं। दूसरा सवाल है कि एक घड़े पानी का एक रुपया लगता है। इस प्रकार की जब पानी की हालत है और आदमी को पीने का पानी नहीं मिलता है। यह बड़े खेद की बात है। हम सपने यह ले रहे थे कि हमारा देश आजाद होगा और हमारा राज्य आयेगा तो पीने के लिए पानी हमको मिलेगा, खेती करने के लिए जमीन मिलेगी लेकिन हमारे सपने अधूरे रह गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आज जनतंत्र डेमोक्रेसी के वक्त में पब्लिक का इस प्रकार से गला घोंटा जा रहा है, एक तरफ तो पीने के लिए पानी नहीं है दूसरी तरफ खस की टाटियों में और बाग-बगीचों में इतना पानी खर्च किया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इन्सान पानी के लिए त्राहि त्राहि करके रो रहे हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान मेरे इलाके की तरफ दिलाना चाहता हूं कि कोलायत तहसील के अन्दर जो गांव है उनमें से ८४ गांव अकाल ग्रस्त घोषित किये गये थे, लेकिन वहां पर केवल चार काम चलते हैं। इसके अलावा पानी की समस्या है, दूसरे वह बोर्डर एरिया है, जहां

Page No. 134

(श्री चुन्नीलाल)

पर फौजें रहती हैं और आर. ए. सी. के लोग रहते हैं। वह लोग गांव के लोगों के पास जाते हैं तो उनको पीने का पानी तक नहीं मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, आप इस एरिया से परिचित हैं, इसलिए मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां जो पानी की समस्या है, वह गम्भीर समस्या है, जिसके कारण वहां पशु मर रहे हैं और केवल पशु ही नहीं, पानी की समस्या बनी रही तो इन्सान भी मरेंगे। ऐसी हालत वहां है। आपने जो मुझे पांच मिनट का समय दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें लोगों की पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए।

श्री मदन सिंह दांता : मैं समझता हूं कि अठारह सौ रुपया पानी के लिए जो खर्चा होता है, आपके एरिया के लिए वह बन्द होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : चिकित्सा मन्त्री ?

श्री दामोदर लाल व्यास (चिकित्सा मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्यों ने अपने कटौती के प्रस्तावों के द्वारा बहुत सारे विचार इस मेडिकल डिपार्टमेंट में सुधार के लिए दिये, उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं। उन्होंने अपने क्षेत्र की आवश्यकतायें बतलाई, जो इस डिपार्टमेंट में कमी है या इन्स्टीट्यूशन्स में जो कमी है वह बतलाई और जो जनता को आम तकलीफें हैं, उनके बारे में इस सदन को जानकारी दी। उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। जितने भी कटौती प्रस्ताव हैं उनको अलग अलग डील करना मेरे लिए सदन में बहुत मुश्किल है।

श्री श्रवण लाल : वैसे भी सोने से फुर्सत नहीं मिली।

श्री दामोदर लाल व्यास : जी हां।

परन्तु मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितने प्रस्ताव या सुझाव दिये हैं, चाहे उन्हें मौका मिला है सदन में पेश करने का या नहीं मिला है-मैं उनके उत्तर आपके पास भिजवा दूंगा जिससे मालूम हो जायगा कि डिपार्टमेंट उसमें क्या कर सकता है और आगे क्या करने की नीति है। जहां तक कुछ मुद्दों को लेकर कुछ माननीय सदस्यों ने इस डिपार्टमेंट के बारे में नुक्ता चीनी की है, कमियों को बतलाया है, पहले भी सदन में जब कभी मौके आये, तो माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं........

लेकिन वह एक डिपार्टमेंट डेवलपिंग डिपार्टमेंट है और सन् १६५०-५१ के बाद से यह डिपार्टमेंट बराबर डेवलप होता जा रहा है। हर तरह से क्यूरेटिव साइड में जिस तरह से बीमारियों के इलाज में काम किया है उसके साथ साथ प्रीवेन्टिव साइड की तरफ भी ज्यादा ध्यान दिया है। इसी का कारण है कि हमारे यहां स्माल पोक्स या मलेरिया आदि एपेडेमिक की रोक थाम हुई है। नेशनल प्रोग्राम्स पिछले सालों में किये गये हैं और उनमें काफी मेजर्स लिये गये हैं जिससे राजस्थान में बीमारियों की रोक थाम में काफी प्रगति हुई है। यही वजह है हमारे

(श्री दामोदरलाल व्यास)

यहां होस्पिटलों की संख्या बढ़ी है और प्राइमरी हैल्थ सेन्टर भी बढ़े हैं। यह सही है कि बीमारों की संख्या बढ़ी है मगर जहां एक तरफ बीमारों की संख्या बढ़ी है वहां दूसरी तरफ हमें टेक्निकल हैंड्स नहीं मिलते है और डाक्टरों की बहुत कमी है। ट्रेंड नर्सेज की भी कमी है और उसकी वजह से हमें यह दिक्कत पेश आ रही है।

कई माननीय सदस्यों ने इस बात को बताया कि प्राइमरी हैल्थ सेन्टरों में डाक्टर नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि कई जगह प्राइमरी हैल्थ सेन्टरों पर डाक्टर नहीं है लेकिन आप जानते हैं कि हमारे यहां पर डाक्टरों की कमी है जैसा मैंने आपसे पहले निवेदन किया है। इसके अलावा फेमिली प्लानिंग में काम शुरू होने से ७०० से ज्यादा डाक्टरों की कमी हमारे यहां पर है और यही बात है कि बहुत सारी डिस्पेंसरीज में और पब्लिक हैल्थ सेन्टरों को हमें बिना डाक्टरों के रखना पड़ रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डाक्टरों की कमी है तो आप सी ए एस. का रीक्रूयूटमेंट क्यों नहीं करते। आपने उसे बन्द कर दिया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बन्द नहीं किया है। मैं आपको बताऊंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने बन्द कर दिया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : बन्द नहीं किया है। अगर आपके पास १०, २०, ४० डाक्टर हों तो आप हमें दें हम भर्ती करते हैं। उनके लिये रीक्रूयूटमेंट खुला है। उनके लिये पी. एस. सी. में जाने की जरूरत नहीं है। जितने डाक्टर जहां मिल सके आप लाए हम लेने को तैयार हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या नर्सों के लिये.... ..

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अपनी बात समाप्त कर दूं उसके बाद में आप मुझे पूछें मैं आपको संतोषजनक उत्तर दूंगा।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे पास टेक्निकल स्टाफ की कमी है और इस कारण कई प्राइमरी हैल्थ सेन्टरों में डाक्टर नहीं हैं।

अभी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कई बातें बताई कि हमारे यहां यह कमी है, यह नहीं है और कमी तो यहां पर रहनी नहीं चाहिये। मैंने जैसा अभी बताया कि हमारे यहाँ ७०० से ज्यादा डाक्टरों की कमी है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस कमी को पूरा करने के लिये हम प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे यहां पर जितने कॉलेजेज हैं उनमें पहले जितनी भर्ती होती थी उससे ज्यादा भर्ती की है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस साल भर्ती कम कर दी गई है?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह मैं आपको बता दूंगा।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जी हां, कम कर दी गई है और इसकी वजह भी आपको बताऊंगा। लेकिन जो डाक्टर एम. बी. बी. एस. पास करके आते हैं उनसे बोन्ड लिखवाया जाता है और जितने निकलते हैं राजस्थान में, उनसे भी यह लिखाया जाता है कि वे राजस्थान में रहें। इसके लिये पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। फिर भी जितनी जरूरत है वह पूरी नहीं होती।

जैसा मैंने अभी कहा कि फेमिली प्लानिंग को एक्सटेन्ड करने के बाद हमारे यहां ७०० से ज्यादा डाक्टरों की कमी है। इस तरह से मैं समझता हूं कि बहुत से माननीय सदस्य इस बात को देखेंगे तो हमारी दिक्कत है उसको महसूस करेंगे।

बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात की शिकायत की है कि होस्पिटल्स में बेड्स की संख्या बहुत कम है और मरीजों के सोने का प्रबन्ध नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि आज बड़े बड़े होस्पिटल्स ओवर लोडेड हैं और बेड्स की संख्या कम है परन्तु आप यदि सन् ५१ से ६७ तक बेड्स की संख्याओं को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वह राजस्थान में दुगनी से भी ज्यादा हुई है।

सन् १९५१ में टोटल बेड संख्या ५,२५७ थी और आज वह संख्या १२,२४१ है। इसी तरह से आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि सन् १९५१ में केवल डिस्पेन्सरी की संख्या १५१ थी वह आज २११ है और उसके अलावा २३० प्राइमरी हैल्थ सेन्टर है। इसके साथ साथ मेटरनिटी सेन्टर्स २७ थे वह आज ७६ हैं। पहले फेमिली प्लानिंग ५१ में तो नहीं थे मगर ५६ में सात थे वहां आज २८७ हैं।

इसी तरह क्लास वन. सन् ५७ में ४ थे वहां अब ७ हैं।

क्लास सेकिन्ड सन् ५७ में ४ थे वहां ६ हैं और जहां २ थे वहां अब ५ हैं।

दूसरे जहां २१३ थे वहां अब ३०७ हैं।

इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितने प्राइमरी हैल्थ सेन्टर वगैराह इस पीरियड में खोल दिये गये हैं और साथ साथ हमको इतना टेक्निकल स्टाफ नहीं मिल रहा है। फेमिली प्लानिङ्ग के प्रोग्राम को हमें वार लेवल पर चलाना है। इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसलिये हमें ज्यादा ट्रेन्ड डाक्टरों की जरूरत है। मैंने ये फिगर्स आपको इसलिये दिये हैं कि आपको इससे अन्दाजा हो सके कि वास्तव में कितनी प्रोग्रेस हुई है। एन्टी रेबिट कट्स पहले २८ थे आज १०७ हैं। इसी तरह टी० बी० और डेन्टल क्लीनिक्स में भी आप देखेंगे तो मालूम होगा कि दुगुनी और तिगुनी बढ़ोतरी हुई है। एक तरफ मैंने कहा कि प्रिवेन्टिव साइड में बहुत काम हुआ है, मलेरिया स्मालपोक्स, बी० सी० जी०, ट्रोकोमा आदि में काफी कामयाबी हुई है। दूसरी तरफ हमारे पास ट्रेन्ड पर्सन्स की कमी है मगर फिर भी काफी क्यूरेटिव साइड की तरफ काम हो रहा है।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि फेमिली प्लानिङ्ग की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया

(श्री दामोदरलाल व्यास)

गया है। मैं इस बात को मानता हूं कि इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और इसकी वजह यह है कि कुछ लेडी डाक्टरों की कमी है और इसके साथ साथ में यह भी कहूंगा कि कुछ जनता का कोआपरेशन भी हमें नहीं मिला है। अजमेर में फेजड प्रोग्राम शुरू किया उसमें काफी कामयाबी मिली। अब उसे तमाम जिलों में स्टेट लेवल पर ही नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आर्गेनाइज किया जायेगा। पंचायत समितियों के प्राइमरी हैल्थ सेन्टर हैं उन पर इस बात की कार्यवाही कर रहे हैं कि इसके लिए प्रोपेगेंडा करें और इसके लिये सब प्रकार का स्टाफ रेक्रूट करके ग्रामीण जनता को शिक्षित बनाया जावे। उनमें विश्वास पैदा कराया जावे जिससे वे फेमली प्लानिंग में विश्वास करें। इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसमें कामयाब होंगे। वैसे भी आप पिछले सालों के आंकड़ों से देखेंगे तो मालूम होगा कि कुछ हुआ है।

स्टरलाइजिंग ओपरेशन्स को अगर आप देखेंगे तो सन् ६६ में ७,०३२ स्टरलाइजेशन के ओपरेशन्स हुए, लूप का इन्सर्शन ६६ में २८,५६० हुआ। डायोग्राम, जेली आदि का लाखों की तादाद में उपयोग....

श्री मदनसिंह दांता : इनके बाद ये लड़के किन किन के हो गये ?

श्री दामोदर लाल व्यास : यह तो ठाकुर साहब, कहना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। मैं माननीय सदस्य से मिल कर मालूम करूंगा कि वे वह तरकीब बतायें कि मुझे बैठे हुए मालूम हो जाय कि किन किन के लड़के हुए।

श्री मदनसिंह दांता : इनके बाद में कइयों के लड़के हुए हैं।

श्री दामोदर लाल व्यास : वे चले गये, दुर्गालाल जी बाढ़दार....

श्री श्रवण लाल : गिरधारी जी के तो आपस में घर में झगड़ा हो गया साहब।

श्री दामोदर लाल व्यास : वह आप उनसे निवट लेवें।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मैं जल्दी ही समाप्त करने वाला हूं, माननीय सदस्यों ने बड़ी मेहरबानी की है, इस डिपार्टमेंट के बारे में कुछ कहा नहीं है।

श्री आलम अली : मन्त्रियों में से कितनों ने आपरेशन करवाये, लीडर वही होता है जो हर काम में लीड दे।

श्री दामोदर लाल व्यास : मैं बिलकुल नहीं समझा हूं, जो माननीय सदस्य ने फरमाया है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं भी नहीं समझ सका।

श्री दामोदर लाल व्यास : खास तौर पर माननीय सदस्यों ने इस डिपार्टमेंट की बदइन्तजामी की बात कही कि कहीं सफाखानों में दवाइयां हैं पर मरीजों को नहीं दी

Page No. 138

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जाती है। मैं इससे इन्कार नहीं करता मान-नीय सदस्य शिकायत करते हैं तो इसमें तथ्य होना चाहिये। पर मैं अर्ज करूं कि अगर इस तरह की बात होती है तो मैं आपका सहयोग चाहूंगा, आप सलाह दीजिये ताकि इस इविल को दूर किया जा सके।

श्री प्रेमसिंह (छबड़ा): जो बीमार सफाखानों में जाते हैं उनको डाक्टरों की तरफ से कहा जाता है कि दवाइयां सरकारी कर्मचारियों के लिए हैं।

श्री दामोदर लाल व्यास: सरकारी कर्मचारियों के लिये नहीं हैं, आपने विधान सभा की बहस सुनी, कितनी शिकायतें की गई हैं कि सरकारी कर्मचारियों के बिल्स पर इतना खर्चा हो गया। फिर भी निवेदन करूंगा कि अगर इस प्रकार की शिकायत है तो बताइये।

श्री प्रेमसिंह: हम कहते हैं उस पर विश्वास नहीं, हम पर विश्वास नहीं?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यों का प्रश्न पूछने हों तो, मन्त्री महोदय उत्तर दे दें, उसके बाद में पूछें।

श्री दामोदर लाल व्यास: एडमिशन्स के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि जो हैड आफ दी यूनिट्स हैं वे ही एडमिट कर सकते हैं, एडमिट करने के पावर्स उन्हीं को है दूसरों को नहीं हैं। मैं निवेदन कर दूं कि यह बात नहीं है। हो सकता है कि किसी केस में यूनिट हैड्स ने मकान पर उन्हें प्राइवेट दिखाया हो और एडमिट करने के लिये लिख दिया हो, इसमें तो बुरी बात नहीं है। पर यह बात अगर है कि बगैर प्राइवेटली दिखाये एडमिशन ही नहीं हो तो यह बहुत ही बुरी चीज है, ऐसा मेरे ध्यान में नहीं है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि आप-रेशन टेबिल पर फीस चार्ज की जाती है, तो मैंने पहले ही निवेदन किया कि कोई शिकायत की जाय, पूरे डिटेल्स दिये जायें तो एक्शन लिया जा सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह प्रिविलेन्ट प्रेक्टिस है, एडमिट करना यूनिट हैड्स के हाथ में है।

श्री दामोदर लाल व्यास: मैंने यह नहीं कहा कि एडमिशन के पावर उनके हाथ में नहीं है। केवल उनके हाथ में हो हां तो बताइये, मैं कल ही छीन लूंगा। पर स्थिति यह है कि हर आदमी एडमिशन चाहता है। हमारे यहां लिमिटेड बैड्स हैं, हर आदमी को एडमिशन दे दिया जाय यह बड़ा मुश्किल है। आज भी हमारे होस्पिटल्स बहुत कन्जे-स्टेड हैं, किसी न किसी को डिटरमिन करना पड़ेगा कि इसको एडमिट करना चाहिये या नहीं। जिनका बाहर इलाज हो सकता है आउटडोर में ट्रीटमेंट हो सकता है, वे भी चाहते हैं कि उन्हें एडमिट कर लिया जाय तो ऐसी हालत में उन लोगों का हक मारा जायगा जिनको जरूरत है कि एडमिट हो कर इलाज करायें। आपने कहा कि यूनिट हैड्स को इस प्रकार के पावर्स हैं। मैं आपके साथ एस.एम.एस. हास्पिटल में चलो को तैयार हूं इमर्जेन्सी में डाक्टर है, वह उचित सम-

(श्री दामोदरलाल व्यास)
भता है कि एडमिट करने लायक केस है तो वह उसे एडमिट कर लेता है। यूनिट ग्राफिसर्स ग्राउट डोर में बैठते हैं और जब उनका टर्न होता है तो एडमिट करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उन्हीं को एडमिट करने का अधिकार है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एस. एम. एस. होस्पिटल में यह प्रिवेलेन्ट प्रेक्टिस है कि ग्राउटडोर में बैठते हैं वे एडमिट नहीं करते, यूनिट इंचार्ज ही को एडमिट करने के पावर हैं। यह सिस्टम है, यूनिट इंचार्ज के हाथ में एडमिशन की सारी पावर्स आ गई हैं, यह ठीक नहीं है, जो डाक्टर्स ग्राउटडोर में बैठते हैं, उनको पावर्स होनी चाहिये कि एडमिटेबल केस को एडमिट करें।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने माननीय सदस्य को सारी बात बतलाने की कोशिश की, फिर भी कहते हैं कि इस तरह की प्रेक्टिस है एस० एम० एस में। मेरी जानकारी में है वह मैंने बता दिया। अगर आप कहते हैं कि यूनिट हैड्स के सिवा किसी को पावर्स एडमिट करने की हैं ही नहीं, तो मैं यह मानने को तैयार नहीं। मेरा खुद का अनुभव है, कइयों को भेजता हूँ, इसलिए मैं यह मानने को तैयार नहीं। ऐसे रेयर केसेज हो सकते हैं कि यूनिट हैड्स ने देख लिया और एडमिट कर लिया। फिर भी आप ऐसा महसूस करते हैं कि कोई खराबी है तो आप सहयोग कीजिये। यह कोई नहीं चाहता कि खराबी को दूर नहीं करें; कितना ही बड़ा डाक्टर हो, ऐसी बात है तो दूर करने की कोशिश की जायेगी। जरूरत इस बात की है कि पूरे डिटेल्स हों, एलिगेशन्स हों, कम्प्लेन्ट हों।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्राइमरी रेस्पोन्सिबिलिटी किसकी मानते हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : इमर्जेन्सी का केस है तो इमर्जेन्सी वालों की प्राइमरी रेस्पोन्सिबिलिटी है। वैसे ग्राउटडोर वालों की है। जयपुर से आये हुए माननीय सदस्य को मालूम है कि इमर्जेन्सी में हमने सी० एम० परमानेन्ट डाक्टर को वहां रख रखा है। डिस्किशन तो किसी न किसी लेवल पर करना ही होगा। Whether this is a fit case for hospitalisation or not.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मानते हैं, जयपुर में दो महीनों में सुधार हुआ है।

श्री दामोदरलाल व्यास : धन्यवाद। लेडी डाक्टर्स के लिये माननीय सदस्यों ने शिकायत की, बाड़मेर से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा, सही नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की........

श्री रघुनाथ विश्नोई : जालौर में नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जालौर में नहीं है। वहां दिक्कत यह है कि लेडी डाक्टर्स की कमी है, लेडी डाक्टर्स वहां जाने को तैयार नहीं हैं। ग्रसलियत यह है कि किसी को जाने के लिए मजबूर करें तो इस्तीफा देने को तैयार रहती है। वैसे ही लेडी डाक्टर्स की कमी है, हम इस स्थिति में नहीं हैं कि उनका इस्तीफा मंजूर करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कोई स्पेशल फेसेलिटीज देनी चाहिये।

श्री दामोदर लाल व्यास : आपने अच्छा सवाल उठाया कि डाक्टरों को विशेष सुविधायें दी जानी चाहिए। आप जानते हैं कि पिछले साल डाक्टरों की कमी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

को देखते हुए उनकी पे स्केल्स रिवाइज की गई। आज राजस्थान की पे स्केल्स डाक्टरों की हिन्दुस्तान में केवल सेंट्रल हेल्थ सर्विस को छोड़कर सबसे अच्छी और ज्यादा हैं। इसलिए यह उनको टेंटेशन वेतन के अन्दर दिया। ऐसे डाक्टर्स जो टेक्नीकल काम करते है प्रिवेन्टिव साइड में, उनको स्पेशल पे दी जाती है। रूरल एरियाज के लिए स्पेशल पे दी जाती है। लेडी डाक्टर्स को परिवार नियोजन में काम करने के लिए १००) अलग दिये जाते हैं। जहां तक इन्सेन्टिव का सवाल है, हमने यह देने में कमी नहीं रखी परन्तु कमी इस बात की है कि सारे देश में लेडी डाक्टर्स की कमी है तो राजस्थान को भी भुगतना पड़ता है।

भारत सरकार को लेडी डाक्टर्स के लिए लिखा। उन्होंने ४० डाक्टर्स देने का वायदा किया है। ६ तो दे दिए हैं और बाकी सब परिवार नियोजन के अन्दर काम करेंगी। इस तरह से डाक्टरों की रिवाइज्ड पे स्केल्स, नान-प्रेक्टिसिंग अलाउंस और स्पेशल पे दूसरी जगहों से बहुत अच्छी है। रहा सवाल इस बात का कि राजस्थान की मेडिकल सर्विसेज को बिल्कुल नान-प्रेक्टिसिंग बना दें और प्रेक्टिस करने की इजाजत न दें, मैं इस विचार से सहमत हो सकता हूं और यह अच्छा होगा अगर ऐसा हो जाय। लेकिन आप जानते हैं कि राज्य के साधन और आर्थिक स्थिति इस योग्य नहीं है कि इस बात को एडाप्ट कर सकें। केवल एक सेंट्रल हेल्थ स्कीम ही है जिसके अन्दर आप यह बात कह सकते हो, वहां नान-प्रेक्टिसिंग अलाउंस देकर उनकी प्रेक्टिस को बन्द किया है और उनका अनुभव जो मुझे मिल पाया है वह अच्छा ही है। परन्तु और किसी राज्य ने ऐसा नहीं किया। इसका कारण यह है जैसा जोधपुर से आने वाले डाक्टर साहब ने कहा कि उनके वेतन का ५० प्रतिशत उनको नान-प्रेक्टिसिंग अलाउंस दिया जाता है। इस समय राजस्थान की बहुत ही टाइट आर्थिक स्थिति है, हम कैसे इतना पैसा दे सकते हैं?

जहां तक एडमिशन्स और इलाज का सवाल है, चाहे प्राइवेट वार्ड्स का सवाल हो, चाहे जनरल वार्ड्स का सवाल हो, एक माननीय सदस्य ने कहा कि एक्सरे और लेबोरेटरी चार्जेज किये जाते हैं। जहां तक जनरल वार्ड्स का सवाल है बिल्कुल फ्री होते हैं कुछ भी चार्ज नहीं होता है। अगर प्राइवेट वार्ड्स के अन्दर चार्ज किया जाता है तो कोई बेजा बात नहीं है। जो आदमी पेइंग वार्ड्स के अन्दर रह सकते हैं तो वे ये चार्जेज भी दे सकते हैं।

जनरलो राजस्थान के अस्पतालों को देखें तो वहां जिस तरह का इलाज होता है और जिस तरह से प्राइवेट वार्ड्स से किराया लेते हैं और दूसरी जो सुविधायें मरीजों को हैं, इसका मुकाबला अगर दूसरे राज्यों से करें तो यहां की सुविधायें सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया मिलेंगी। हर राज्य के अन्दर हर बात के लिए चार्ज किया जाता है चाहे कमरे का किराया हो। आज काटेज वार्ड का किराया हमने ५ से बढ़ाकर सात किया परन्तु अगर आप एक छोटा सा कमरा विलिंगडन अस्पताल दिल्ली में लें तो २५) रोज लेते हैं।

श्री अर्जुनलाल : अपने २० सालों में जयपुर में जो सवाई मानसिंह अस्पताल की बिल्डिंग है, ऐसा एक भी भवन खड़ा किया?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप यह कहते हैं कि भारत में सबसे अच्छी पे स्केल्स हमारी हैं सेंट्रल हेल्थ सर्विस को छोड़कर, यह सब होने के बाद भी, आपने जांच कराई है कि यहां जो एम. बी. बी एस. हैं वे राजस्थान में क्यों नहीं ठहरते हैं ? मैं आपको एक दो साल पुराने आंकड़े बताता हूं : मद्रास में ३२६ अस्पताल हैं और डाक्टर्स १३,०१६ राजस्थान में ३२३ अस्पताल हैं और डाक्टर हैं १,१५२ । आखिर डाक्टर्स इतने अच्छे इमोल्यूमेंट्स होने के बाद भी यहां क्यों नहीं ठहरते, आप बोंड भी भराते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको ध्यान होगा कि पिछली बार मैंने सदन के अन्दर कहा था कि बोंड को एन्फोर्स कर रहे हैं और हमने वाकई एन्फोर्स किया है । मैं आपको बताऊं १९६५ में सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज से १२५ लडके पास होकर निकले ! ५६ को नौकरी मिली, २९ को हाउस जाब, ६ सेना में गए और बाकी ३० को नोटिस दे रखा है, कार्यवाही कर रहे हैं । १९६६ में १२४ पास हुए, ६८ ने नौकरी जोइन की, ३२ हाउस सर्जन बने, ८ सेना में गये और बाकी १८ रह गए, जिनके लिए कार्यवाही कर रखी है, नोटिसेज दे रखे हैं । बीकानेर कालेज में १९६५ में ७१ लड़के पास हुए, १६ को नौकरी मिली, ३९ हाउस सर्जन बने, बाकी के खिलाफ कार्यवाही हो रही है । १९६६ में ७६ पास हुए, ४२ ने सर्विस ज्वाइन की, २८ हाउस सर्जन बने और बाकी ६ के खिलाफ कार्यवाही जारी है ।

इस तरह दो साल से बराबर हम इस बात को एन्फोर्स कर रहे हैं कि जो एम. बी. बी. एस. पास करेंगे वे हमारी नौकरी में रहें The number is negligible जितने लड़के पास होते हैं उनमें से अगर १०-१५ रह गए तो नम्बर नेग्लीजबल है । पोस्ट ग्रेजुएट सुविधाओं की वजह से चले जाते हों, ऐसी बात नहीं है । हमारे यहां पे स्केल्स ऐसी हैं और उनको बाहर टेम्प्टेशन हो फरदर स्टडीज का, ऐसी बात नहीं है ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सबसे ज्यादा परेशानी यह है कि डाक्टरों के तबादले में घोटाला होता है और प्रमोशन्स में रिट्स में जाना पड़ता है इसलिए राजस्थान की मेडिकल सर्विस असन्तुष्ट है । एक डाक्टर को तो जैसलमेर भेज दिया और जिस पर मन्त्री महोदय की मेहरबानी है तो ११ वर्ष से एक ही डाक्टर सिरे ड्योढ़ी डिस्पेन्सरी में काम कर रहा है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : पुराने लोगों को प्रमोशन देते हैं । आप कहते है कि हाई कोर्ट में जाते हैं, जाना चाहिए । Every-body has a right. इसमें बुरा क्या होता है

श्री भैरोंसिंह : मन्त्री महोदय इसका भी स्पष्टीकरण करें कि मेडिकल विभाग में इन्डियन मेडिकल सर्विसेज का गठन होने

(श्री भैरोंसिंह)

वाला है और सिलेक्शन हो रहा है, मेरी जानकारी के अनुसार अभी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की बैठक नहीं हुई और कई डाक्टर्स ऐसे हैं जो उस बैठक के बाद में अपनी सब्सटेंटिव पोस्ट पर कन्फर्म हो जायेंगे। दुर्भाग्यवश अगर उनका सिलेक्शन और कन्फरमेशन नहीं हुआ तो इन्डियन मेडिकल सर्विसेज के अन्दर राजस्थान के डाक्टरों का बहुत कम नम्बर आएगा और राजस्थान का नुकसान होगा। डाक्टरों में इस कारण बेचैनी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : डाक्टरों में बेचैनी है, इससे मैं पूर्ण रूप से परिचित हूं। आपके ख्याल से इन्डियन मेडिकल सर्विसेज बन जाने से अपने यहां डाक्टरों को डिसएड-वान्टेज रहेगा और वे कन्फर्म नहीं हुए और एडहोक बेसिस पर काम कर रहे हैं, ऐसी पोजीशन पैदा नहीं होने वाली है। आपका ख्याल है कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी नहीं बैठी है, वह वीकली बैठ रही है। जिन डाक्टरों ने आपको कहा है, उनको हमने सूचना दी है और मैंने कल ही दो डाक्टरों के डिपार्टमेंटल प्रमोशन के केस पर दस्तखत किये है....

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि डाक्टरों ने मुझे सूचना दी है....

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको भी किसी ने सूचना दी होगी। मुझे सूचना नहीं दी। यह जो उनकी एंग्जाइटी है कि वे अनकन्फर्म्ड रहेंगे तो हमारी सर्विसेज को डिसएडमेंवान्टेज रहेगा, यह उनकी एंग्जाइटी सही है परन्तु उनकी एंग्जाइटी को दूर करने के लिए डी. पी. सी. हर सप्ताह बैठ रही है और सब केसेज निकाल रही है, कन्फर-मेशन्स हो जायेंगे और हम कन्फरमेशन्स की वजह से अपनी सर्विसेज को डिसएडवांटेज में जाने नहीं देंगे।

(५ म० प०)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रीडर की पोस्ट एबोलिश कर देंगे तो प्रोफेसर कैसे बनेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से जब तक मांगें स्वीकृत न हो जाय तब तक के लिये सदन का समय बढ़ाया जाता है।

श्री दामोदर लाल व्यास : मैं दो तीन मिनिट में ही समाप्त करने वाला हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने रीडर की पोस्ट एबोलिश की या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी पहले नसीराबाद से आये माननीय सदस्य को जवाब दे दूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रीडर की पोस्ट एबोलिश कर दी क्या ?

श्री दामोदर लाल व्यास : वह है साहब। आपको कब मालूम हो गया कि पोस्ट एबोलिश कर दी ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप मालूम कर लीजिये।

श्री दामोदर लाल व्यास : माफ कीजिये। मुझे इतना तो मालूम है कि रीडर की पोस्ट है। मुझे मेरे विभाग का अधिक ज्ञान है। ज्यादा बढ़ना चाहिये या कम होनी चाहिये इसके लिये एक कमेटी बिठा रखी है। आल इन्डिया पोस्ट ग्रेजुएट कालेजेज को देखकर उनके स्टाफ और अपने स्टाफ का मिलान किया जायगा कम है तो ज्यादा कर और ज्यादा है तो कम करें।

नसीराबाद में सरकारी डिस्पेन्सरी है। परन्तु उसके साथ साथ और भी होस्पिटल्स हैं। मिलीटरी का होस्पिटल है और दूसरी मिशन होस्पिटल है। मिलीटरी का १०२ बेड का है और मिशन होस्पिटल २४ बेड का है। इस तरह से जो स्टाफ वहां पर है वह नाकाफी नहीं है। एक दफा इस प्रश्न को एक्जामिन भी कराया था कि नसीराबाद डिस्पेन्सरी में जो स्टाफ है वह काफी है या नहीं। यह मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त सारी बात को देख कर दूसरी फेसेलिटी अवेलेबल है मिलीटरी होस्पिटल की या मिशन होस्पिटल की उसको काफी समझा है।

धोलपुर, नसीराबाद और दूसरे स्थानों के होस्पिटल्स को 'बी' ग्रेड का किया जाय। मैं मानता हूं कि इनका अपग्रेडेशन होना चाहिये। डिस्पेन्सरी में बेड और बढ़ाये जाने चाहिये। मैंने जैसा कहा कि इस साल में जैसा फाइनेन्शियली टाइट पोजिशन है उसमें यह मुमकिन नहीं है कि किसी अस्पताल को अपग्रेड करें और ज्यादा फेसेलिटी दें। नसीराबाद के लिये इतना हो कह सकता हूं कि जब भी इस पोजिशन में आवेंगे इस साल नहीं अगले साल हम कोशिश करेंगे कि इसको अपग्रेड करें और कुछ फेसेलिटी बढ़ाने की बात करें। लेकिन यह कहना कि फेसेलिटी नहीं है यह उचित नहीं है। आल्टरनेट फेसेलिटी मौजूद है। लोगों को आज से नहीं शुरू से ही वहां फेसेलटी मुहैया होती रही है। धोलपुर और भरतपुर के और अन्य जगहों के अस्पतालों को अपग्रेड करने का विचार है लेकिन फाइनेन्शियल पोजिशन को देखते हुए यह संभव नहीं है।

श्री विजयसिंह रावत : मंत्री महोदय ने फरमाया इसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं। मैं उनकी इन्फोर्मेशन के लिये बताऊं। राज्य सरकार ने एक कमेटी बिठाई थी, डाइरेक्टर, मेडीकल ऐड हैल्थ विभाग वहां गये थे। उस रिपोर्ट में यह लिखा था कि नसीराबाद में 'बी' ग्रेड होस्पिटल होना जरूरी है। केन्द्रीय सरकार ने दो लाख रुपया स्वीकृत किया। जमीन ठीक समय पर न मिलने के कारण वे दो लाख रुपये लेप्स हो गये। राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करे कि दो लाख की स्वीकृति पुनः दें। पापुलेशन तो कम से कम २॥ लाख को है।

श्री दामोदर लाल व्यास : माननीय सदस्य ने बताया कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट से दो लाख रुपया मिला है। न मेरी जानकारी में है और न ही डिपार्टमेंट की जानकारी में है। आप बतायेंगे तो मैं देखूंगा। जितने अपग्रेडेशन के केसेज हैं वे वाजिब हैं। आवश्यकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। किन्तु जैसी मैंने पोजिशन बतायी कि फाइनेन्शियल पोजिशन के कारण इनको अपग्रेड नहीं किया जा सकता।

अलवर से आये माननीय सदस्य ने कहा था कि एडवाइजरी कमेटी बनायी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

गयी थी उसकी मीटिंग नहीं हुई। यह बात सही है कि एडवाइजरी कमेटी बनाने की बात की थी और सदन के माननीय सदस्यों को भी उसमें रखे जाने की बात थी। जब बनी तो तुरन्त जनरल इलेक्शन आ गये। उस एडवाइजरी कमेटी को दुबारा रिकान्स्टिट्यूट कर देंगे। उसमें सदन के माननीय सदस्य होंगे।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : डिजिटस कमेटी के लिये भी कहा था। राजस्थान के सिटी लेवल बक कमेटी बनायी और यह एश्योर किया था कि सारे डिस्ट्रिक्स हैडक्वार्टर्स के लिये भी कमेटी बनाई जावेगी उसमें एम० एल० ए० को रखा जावेगा।

श्री दामोदर लाल व्यास : डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर मिली जुली कमेटी बनाने के लिये मुझे ऐतराज नहीं है। मैं चाहता हूं कि सुधार तेजी से आये। डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर के लिये कमेटी का मुझे याद नहीं है। यदि पहले नहीं भी कहा हो और कहा तो भी आज मैं कहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर ऐसी कमेटी होनी चाहिये।

श्री जयनारायण सालोदिया : टोंक डिस्ट्रिक्ट के लिये ?

श्री दामोदर लाल व्यास : निवाई के माननीय सदस्य ने कुछ बात बतायी। निवाई में एक एम० सी० डब्ल्यू० खोलने के लिये मैंने कह रखा है। कल परसों सवाल था तब भी कहा। हम चाहते हैं कि खोलें। इस वक्त नहीं खोल सकते। इस साल एक भी एम० सी० डब्ल्यू० खोलने का प्रश्न रखा ही नहीं है।

एक माननीय सदस्य : छबड़े में पैसे जमा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं उस पर आ रहा हूँ। I have not yet finished.

प्राइमरी हैल्थ सटर और सब सेन्टर नहीं बने है और पंचायत समितियों ने कई जगह पैसा जमा करा दिया है। उनका पैसा जमा है। इस साल फाइनेन्शियल स्ट्रिन्जेन्सी से बना नहीं पाये हैं। अगले साल बनाना शुरू कर देंगे। रुपया हमारे पास जमा हो गया है। चाहे पंचायत समिति में जमा हो गया है। हम उसको युटिलाइज करने की कार्यवाही करेंगे ताकि सरकारी रुपया खर्च हो जाय। नेक्स्ट ईयर और इस साल पब्लिक के खर्च से काम शुरू हो जाय।

ज्यादा समय आपका न लेकर एक बार आप सबका आभार प्रदर्शित करते हुए जिन जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव भेजे हैं और उन पर जो डिपार्टमेंट का दृष्टिकोण है वह उनके पास भेज देंगे।

श्री मनोहर सिंह मेहता : आपने प्रोग्राम काफी अच्छा बताया। स्टार्ट कहां से करते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : स्टार्टिंग उनका २८५ है। पर जब तक डाक्टरों की कमी है उनकी इनीशियल पे ३३५ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान में प्रति व्यक्ति दवाइयों पर कितना खर्चा है

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

और हिन्दुस्तान में प्रति व्यक्ति कितना खर्चा है ?

श्री भैरोंसिंह : सब से कम है।

श्री दामोदरलाल व्यास : बेड्स हमारे यहां हिन्दुस्तान में सबसे कम हैं. That is not a fact.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं बेड्स की नहीं पूछ रहा हूं। दवाइयों पर कितना खर्चा है प्रति व्यक्ति यह पूछ रहा हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह रैडिली मेरे पास अवेलेबल नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने बेड्स नहीं कहा, मेरे पास सबके आंकड़े मौजूद हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने नहीं कहा, किसी ने कहा था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप वीक पोइन्ट पकड़ कर सदन का समय खराब मत करिये। आप पोइन्ट का जवाब दिया करिये।

जहां तीन डाक्टर की जरूरत हैं, वहां एक है। जहां २५ हैं वहां.......

श्री दामोदर लाल व्यास : कम हैं, यही तो मैं कह रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रिक्वायरमेंट कितनी है टोटल राजस्थान की।

श्री दामोदरलाल व्यास : होस्पिटल्स और डिस्पेन्सरियों में ७५० की कमी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं कमी नहीं पूछना चाहता। मैं टोटल रिक्वायरमेन्ट पूछना चाहता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह मैं बता दूंगा आपको।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इस पर प्रकाश नहीं डाला कि लड़कों की एडमिशन की तादाद कम क्यों कर दी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : लिखिये साहब। सी० ए० एस० १,८.७ की रिक्वायरमेन्ट है। जिसमें से इस वक्त जो हैं वर्किंग १,०६३। कम हैं ८१६ जिसमें से १०० में 'ए' ग्रेड कम्पाउन्डर्स चल रहे हैं। इस लिहाज से मैं बता रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह डाक्टरों की कमी पूरी हो जावे तो एक होस्पिटल पर कितने डाक्टर हो जावेंगे ? यह रिक्वायरमेंट आपने किस आधार पर लगाई ? आल इण्डिया एवरेज क्या है ? ६२६ पर १३ हजार डाक्टर हैं और ८०० पर २२ हजार हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह कहां लिखा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह इसमें लिखा है।

Page No. 146

श्री दामोदरलाल व्यास : मिसप्रिन्ट है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट है। कमाल करते हैं आप। This is a report of the Finance Commission.

श्री उपाध्यक्ष : मद्रास की पोपूलेशन कितनी है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं अर्ज करता हूं कि सही है आपका फरमाना कि पोपूलेशन का परसेन्टेज लगाएं आप। पर हास्पिटल ८६२ और डाक्टरों की संख्या है २२,४३६।

श्री उपाध्यक्ष : प्राइमरी हैल्थ सैन्टर भी होंगे इसमें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सब कन्सीडर करने के बाद ही लिखा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : It can be a hospital or a dispensary. There is no comparison.

आप तो अपनी स्टेट की रिक्वायरमेंट पूछिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें सवाल यह है कि फाइनेन्शियल कमीशन की रिपोर्ट है जिसके आधार पर आप सेन्टर से पैसा लेकर आते हैं। ८६२ अस्पतालों पर २२ हजार डाक्टर हैं और मद्रास में ३२६ पर १३ हजार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : डिस्पेन्सरीज वगैरह।

श्री दामोदरलाल व्यास : अरे साहब, ३४४ डिस्पेन्सरियां अलग हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मद्रास में भी अलग हैं। मैंने जोड़े नहीं हैं यहां भी।

श्री दामोदरलाल व्यास : टीचिंग स्टाफ है वह भी बिलकुल शामिल नहीं है। वह एक बटालियन अलग है। वह मैंने शामिल नहीं की है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये आल इण्डिया के आंकड़े हैं। मेरे घर के नहीं हैं। इसमें भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने बात कहीं, मन्त्री महोदय ने उसका उत्तर दे दिया। फिर यह भी है कहीं कोई अस्पताल छोटा है बड़ा है, मानसिंह अस्पताल जयपुर का एक ही काफी बड़ा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो सब जगह सब कहानी एक ही है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : डाक्टरों की कमी है तो एडमिशन में लड़कों की संख्या कम क्यों कर रहे हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप बैड्स की बात करते है, आपके यहां १० बैड्स पर एक डाक्टर है जब कि बंगाल में एक बैड पर एक डाक्टर आता है। बाकी सब जगह का एवरेज लगा लीजिये।

फिर बैड्स के हिसाब से लेंगे तो पर-कैपिटा एक्सपेन्डीचर मेडिकल का राजस्थान में सबसे कम आता है।

श्री उपाध्यक्ष : ये सारे तथ्य यहां नहीं निर्णीत हो सकते। आप इसके लिये आपस में बैठकर विचार-विमर्श कर सकते हैं। अभी तो डिबेट में जो प्रश्न उठाये गये थे उनका जवाब देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि डिमाण्ड हम पास करना चाहते हैं, करोड़ों रुपया हम इसके लिए सरकार को देने जा रहे हैं। तो कम से कम सदन को यह तो मालूम पड़े कि राजस्थान में साढ़े सात करोड़ की जो वे सेंक्शन देंगे उसका उपयोग कितना कितना कहां कहां होता है? कितने हमारे यहां पर अस्पताल हैं, कितने उनमें बैड हैं, पर-कैपिटा एक्सपेन्डीचर क्या है? ये सारी बातें सदन अगर नहीं जानेगा तो डिमाण्ड्स पर क्या सेंक्शन देंगे?

श्री उपाध्यक्ष : यह डिबेट में अच्छी तरह से कहा जा सकता था। पर.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, हर कोने से लोगों ने बातें कही हैं। सरकार अब उनका जवाब नहीं देती तो क्लेरिफिकेशन के सिवाय और क्या रास्ता है। सरकार कहती है, डाक्टरों की कमी है, अस्पतालों की कमी है। दवाइयां नहीं है, और सरकार आंकड़े बताती है। ६५ में इतने थे। अगले साल इतने थे। सवाई मानसिंह अस्पताल की बात कहते हैं।

श्री दामोदर लाल व्यास : आंकड़े ही तो बता दिये गये हैं।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : आपके ताऊ यहां बैठे हैं, जवाब देना हो तो ठीक से दो।

श्री दामोदर लाल व्यास : पिछले वर्षों का अनुभव है हमारा कि ज्यादा लड़के क्लासों में नहीं पढ़ सकते। फिर इण्डियन मेडिकल कौंसिल का स्टेण्डर्ड जो प्रेस्क्राइब किया है उसके हिसाब से यह ठीक है। पहले हमने इमर्जेन्सी की वजह से सीटें बढ़ाई थी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ी हुई सीटों के लिए असिस्टेन्स भी बन्द कर दी इसलिए सीटें अब कम कर दी गई है।

एक माननीय सदस्य : लड़के देहातों से ज्यादा आने लग गये हैं अब, इसलिए कम कर दी हैं।

श्री दामोदर लाल व्यास : हम उनके दुश्मन हैं? कौन से हम शहर के रहने वाले हैं?

श्री मदनसिंह दांता : मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन डाक्टरों के सम्बन्ध में आपके पास शिकायतें आ गई जिन्होंने सरकारी दवाइयां बेच बेचकर अपने घर बनाये ऐसे डाक्टरों के बारे में सबूत सदन में चाहें तो सदन में, कमरे में कहें तो कमरे में देने को तैयार हैं। तो ऐसे डाक्टरों के लिए हम चाहते हैं जानना कि आपने क्या एक्शन लिया?

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : वे इस राज्य में प्रमोशन के हकदार हैं।

श्री दामोदर लाल व्यास : मैंने कहा आप बतलावें, मैं एक्शन लूंगा उनके खिलाफ।

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, पांच पांच सौ तार उनके खिलाफ आये

(श्री मदनसिंह दांता)

हैं। गरीब लोगों की दवाइयों को बेचकर पैसे खा जाते हैं आप एक अरब रुपया खर्च कर दें पर उसका लाभ जनता के पास नहीं पहुंचता, बीच में ही ये लोग खा जाते हैं। यह कारण है असन्तोष का और आप उनके प्रति कुछ करना नहीं चाहते। भ्रष्ट अफसर हो गये हैं। आप कुछ उनका बिगाड़ नहीं सकते। इसी कारण आपके प्रति भी जनता में असन्तोष है। सही है कि आप अस्पतालों के लिये खर्चा करते हैं। पर बीच में खाने वालों को सजा नहीं देते आप।

श्री दामोदरलाल व्यास : खाने वाले मसले बहुत विवादास्पद हैं। जब से सदन बना तब से ये बातें कही जा रही हैं और जब तक सदन चलता रहेगा ये बातें भी कही जाती रहेंगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और आज जब तक रहेंगे तब तक यही चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : एक डिबेट के उत्तर में जितना कहना था कहा जा चुका है।

श्री मदनसिंह दांता : सीकर के डाक्टर को क्यों नहीं हटाना चाहते? हजारों तरह की शिकायतें उनके खिलाफ हैं। आंकड़े पहुंचा दिये हैं। रिपोर्ट पहुंचा दी हैं। आज क्या कारण है आप क्यों नहीं हटाते। कमरे में जाकर कहने की बात कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यह मसला डिबेट में आया नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : कैसे नहीं आया है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, हम तो जो हमें कहना है, यहीं सदन में कहेंगे। मन्त्रीजी के दरवाजे पर जाकर उनकी गुलामी करके कुछ कहने वाले नहीं हैं। सदन हमारा घर है। भ्रष्ट अफसरों के बारे में हम यहां कहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इसीलिये तो बार बार निवेदन करता हूं कि जब कट मोशन का अवसर आवे तो उसका उपयोग आम चर्चा में न करके इस तरह के विषयों पर वाद विवाद करने में उसका उपयोग करें। उससे मन्त्री महोदय भी बाध्य होंगे कि जो आपने प्रश्न उठाये हैं उसका वे उत्तर दें। पर इस स्टेज पर सवालात पूछते हैं तो मिनिस्टर कह सकते हैं कि आफ हैण्ड हमारे पास जवाब नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इत्तला दी उनके भी जवाब नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह आप पूछ सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : अजमेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने ई. एस. आई. स्कीम के बारे में बताया पर उसका मन्त्री महोदय की ओर से उत्तर नहीं आया। ई. एस. आई. स्कीम में दवाइयां आती हैं बाजार में वे सब बिकती हैं। झूठे इन्डेन्ट देकर दवाइयां इश्यू करवाते हैं। मजदूरों को ये मिलती नहीं।

(श्री भैरोंसिंह)

बातें डा० अम्बालाल ने बताई हैं। मन्त्री महोदय को याद होगा कि पिछले सत्र में भी जब इस तरह की बातें कही गई थीं तो उनकी आज तक जांच ही नहीं हो पाई है तो फिर आप कह रहे हैं कि जवाब वे दे रहे हैं तो जवाब तो नहीं मिल रहा है।

यह हाल तो उनकी बातों का है जो उनके बहनोई के मामा हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : दवाइयों का दुरुपयोग होता है इसकी शिकायतें और लोगों ने भी की हैं पर इसमें आपके सहयोग की जरूरत है। आप हम मिलकर ही इसमें कुछ कर सकेंगे।

श्री भैरोंसिंह : आपको हमारे सहयोग की तो दरकार ही नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : केवल शिकायतें करने से तो मैं किसी के खिलाफ एक्शन ले नहीं सकता।

श्री भैरोंसिंह : शिकायत तो मैंने पहले भी की है। कोलम्बो प्लान के मातहत दो दवाइयां आती है वह दवाइयां बिकती हैं और पिछली बार सदन से प्रत्यक्ष रूप में यह प्रश्न उठाया गया है और इसके प्रमाण दिये गये लेकिन कोई जांच नहीं हुई।

श्री दामोदरलाल व्यास : कौनसी दवाइयां आई थीं ? ऐसी कोई दवाई नहीं आई।

श्री विजयसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो प्रश्न थे। टी० बी० होस्पीटल से जो पेशेन्ट्स क्योर होकर नहीं आते हैं ...

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि टी० बी० की बीमारी के लिए अब इतनी प्रोग्रेस हो गयी है कि यह जरूरी नहीं है कि पेशेन्ट को होस्पीटल में रखा जाये जब तक कि वह कोई आपरेशन का केस नहीं हो क्योंकि यह ट्रीटमेंट घर पर भी हो सकता है। इसलिए आपका यह कहना कि मरीजों को ३ महीने से ज्यादा रखने को तैयार नहीं हैं दरअसल बात यह है कि पेशेन्ट्स को होस्पीटीलाइज करने की जरूरत तब ही है जब कि आपरेशन का केस हो वर्ना घर पर ट्रीटमेंट हो सकता है।

श्री भीमसेन : मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि टी० बी० के पेशेन्ट्स को सरकार की तरफ से क्या दवाइयां फ्री देते हैं या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सब टी० बी० पेशेन्ट्स को दवाइयां फ्री दी जाती हैं।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, शाहबाद क्षेत्र इतना पिछड़ा इलाका है कि वहां पर डाक्टर नहीं है। बामला जैसी जगह डाक्टर नहीं है वहां पर मरीज बेमौत मरते हैं। न तो कम्पाउन्डर ही उनको देखता है और भगवान के भरोसे पर मरीज वहां आते हैं और मर जाते हैं। आप डाक्टर नहीं भेज सकते हैं तो क्या जरूरत थी वहां पर होस्पीटल खोलने की ? आज वहां के

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

लोगों ने बिल्डिंग बनाई, पूंजी लगाई और फिर भी लोग बेमौत मरते हैं। एक शाहबाद अकेले क्षेत्र में १५० बच्चे बेमौत मर गए... ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर.

श्री विजयसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से नहीं दिया गया है। मैं यह पूछ रहा था कि जो ओपरेशन के केसेज़ और मेजर केसेज़ हैं उन्हीं को होस्पीटल में भर्ती किया जाता है लेकिन किसी ऐसे एरिया में जहां डाक्टर सजेस्ट करता है कोई स्पेशल डाइट उसको दिलाने का क्या कोई प्रबन्ध है? एक तो यह है। दूसरे पेशेन्ट्स के लिए जो कि गवर्नमेंट के खाते में डिस्एबल्ड हो जाते हैं या एग्जीमा की बीमारी से लूले, लगड़े हो जाते हैं और उनको सड़कों पर पड़ना पड़ता है और जिनकी विदेशी फोटो खींचकर ले जाते हैं उनके लिए मैंने सुझाव दिया था उसके लिए कुछ न कुछ प्रबन्ध करना चाहिए जिससे कि........

श्री दामोदर लाल व्यास : माननीय सदस्य को यह मालूम नहीं है कि डिस्एबल्ड के पेन्शन के रूल्स हैं और डिस्एबल्ड जितने हैं वह अधिकारी हैं कि कलेक्टर के यहां से अपनी पेन्शन ले लें।

श्री विजयसिंह रावत : दूसरा मेरा प्रश्न और रह गया कि जो गांवों का एरिया है और वहां डिलीवरी केसेज होते हैं और वहीं पर जच्चाखाना नहीं होने की वजह से गांव की गरीब महिलायें मौत का शिकार होती है डिलीवरी के केसेज़ में—उसके लिए आपने कुछ नहीं कहा?

श्री दामोदर लाल व्यास : उसके लिए मेरा निवेदन यह है कि जिस किसी गांव में कोई दाई की ट्रेनिंग लेने के लिए कोई तैयार है तो हम उसको ट्रेण्ड कराने के लिए तैयार हैं और ट्रेनिंग दिलाने के बाद में हम उसको उसी गांव में भेज देंगे। आप भिजवा दीजिए यदि कोई ट्रेनिंग लेना चाहे तो।

श्री श्रवण लाल : जहां २० हजार की आबादी है वहां आपके हैल्थ सेन्टर्स हैं और वहां पर डाक्टर को कम से कम चार-चार, पांच-पांच दिन बाहर टूर पर जाना पड़ता है और मरीजों को तकलीफ होती है, इसके लिए आपको क्या कहना है?

श्री दामोदर लाल व्यास : मेरा यही कहना है कि डाक्टरों की कमी है

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक बात कही थी कि डाक्टरों का जो अनपेशेन्ट-लाइक और इनडिफरेन्ट एटीट्यूड मरीजों के प्रति रहता है उसका क्या कारण है और इस एटीट्यूड को मिटाने के लिए मेडिकल विभाग ने कौन से कदम उठाये हैं? इसके अलावा मैंने सुझाव दिया था कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लड़के हैं और जो मिडिल क्लास के लड़के हैं उनका प्रवेश कम मार्क्स आने पर भी किया जाये ताकि मिडिल श्रेणी के डाक्टर ज्यादा हों और जनता की अधिक सेवा कर सकें, इसके लिए आपका क्या कहना है?

Page No. 151

श्री दामोदर लाल व्यास : रूल्स के अन्दर प्रोवीजन है। उनके लिए रिजर्वेशन है और कम नम्बर आते हुए भी उनको एडमिट किया जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : कितने पर किया जाता है ?

श्री दामोदर लाल व्यास : ४५ परसेन्ट से कम तो किसी की भी भर्ती नहीं होती और दूसरों का परसेन्टेज यदि ५४ पर आता है तो उनको ४५ परसेन्ट पर भी एडमिट कर लेते हैं।

श्री श्रवण लाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और पूछना है........

श्री उपाध्यक्ष : बार बार आप सवाल नहीं पूछेंगे। आप कई बार पूछ चुके हैं।

जन स्वास्थ्य मन्त्री !

श्री नारायणसिंह मसूदा (जन स्वास्थ्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जल की कमी होती चली जा रही है। एक तरफ तो आबादी बढ़ रही है और आबादी आज भी आस्ट्रेलिया की जितनी आबादी है उससे ज्यादा आबादी हमारे राजस्थान की है। जहां आस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल भारतवर्ष से भी तिगुना और चौगुना है और राजस्थान में उनके अनुपात में आबादी आस्ट्रेलिया से द्विगणित है इसको देखते हुए और उसके साथ जब हम देखते हैं करीब करीब सभी जगह पानी की कमी इस प्रकार से होती चली जा रही है कि जैसे सारा ही राजस्थान धीरे धीरे जैसलमेर बन जायेगा तो वास्तव में बड़ी चिन्ता तो होती ही है। सारे कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत हुए हैं उनकी साधारणतया यही शिकायत और ट्रेण्ड रहा है कि कहीं तो अपर्याप्त पानी मिल रहा है और कहीं नयी स्कीम शीघ्र कार्यान्वित नहीं हुई है, कहीं गांवों में स्कीम के क्रियान्वयन में देरी हुई है और वाटर सोर्सेस ठीक प्रकार से नहीं मिले हैं तो कहीं एन्फोर्समेंट की कमी है इत्यादि इत्यादि। इन्हीं सब बातों को लेकर यह कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं और इनके अन्दर साधारणतया जो बातें कही जा सकती हैं वह यही है कि स्थान स्थान पर जो योजनायें बनीं वह मिनिमम स्टेन्डर्ड को लेकर सन् ६१ की सेन्सस रिपोर्ट के आधार पर जो आबादी थी उसके आधार पर कुछ बनीं और उसके बाद में जहां तहां आबादी कहीं द्विगणित हुई तो कहीं तिगुनी हुई और उसके कारण से योजनाओं का फिर से पुनरावेक्षण करना पड़ा और उसको बदलकर लाना पड़ा। यह भी देरी का कारण बना। इन स्कीमों के लिए टेक्निकल स्वीकृति भी गवर्नमेंट आफ इण्डिया से ली जाती थी और गवर्नमेंट आफ इण्डिया कई कारणों से उसमें तकनीकी सुझाव देकर उनको वापस लौटा देती थी। वह आज तक हुआ है और उसमें परिवर्तन करने का और फिर उन स्कीमों को पीछे भेजने का तरीका रहता था। अब यह हुआ है कि इस विषय में राज्य सरकार स्वयं उसको पूरा कर सकेगी और यह सारा चक्कर मिट जायेगा। लेकिन आज तक इस गवर्नमेंट आफ इण्डिया के द्वारा परिवर्तन और परिवर्द्धन द्वारा जो स्कीमें आतीं उनको पीछा बनाकर भेजने में देरी होना स्वाभाविक है। मास्टर प्लान जो राजस्थान का बनाया गया है वह भी १९६६ में बनाकर भेजा

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

गया है, वह भी एप्रूव होने को है और इस तरह से ये सारी दिक्कतें सामने आई हैं। कई न्यू स्कीम्स, हैं करीब करीब ११६ न्यू स्कीम्स हैं और पुरानी भी चालू हैं और उनके साथ ही साथ में यही निवेदन कर दूं कि जो प्रेसीडेंट रूल हुआ उस समय कम्पलीशन आफ स्कीम्स जो कि थर्ड फाइव ईयर प्लान से पुल ओवर हुई उन स्कीम्स के लिए १८ लाख का प्रावधान रखा गया है। एस्टेब्लिशमेंट के लिए, ट्रेनिंग वगैरह के लिए १२ लाख का प्रावधान रखा गया और वेल्स के लिए एक लाख का प्रावधान है और राजस्थान केनाल में डिगिंग के लिए चार लाख रुपया रखा गया है। उसमें परिवर्तन होकर अब चालीस लाख का प्रावधान कम्प्लेशन आफ स्कीम्स जो कि थर्ड प्लान से पुल ओवर हुई हैं और ६६-६७ की जो नई स्कीमें हैं उनके लिए ३० लाख रुपया रखा है एस्टेब्लिशमेंट के लिए दस लाख रुपया रखा गया है। इसी तरह से एक लाख रुपया वेल्स के लिए और डिगिंग इन राजस्थान केनाल में, इसके लिए चार लाख रुपया रखा गया है। इस तरह से ८५ लाख का प्रावधान किया गया है ३५ लाख की जगह पर। पर फिर भी मैं आपसे निवेदन करूं कि यह जो कुछ अलाटमेंट रखा गया है, आज की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को देखते हुए यह सारी स्कीमें जो हैं जो कि थर्ड फाइव ईयर प्लान से पुल ओवर की तरह आई हैं अथवा नई स्कीमें हैं उन सबको पूरा करने के लिए १७५ रु० लाख की आवश्यकता है। इसी प्रकार मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करने में भी ७० करोड़ रु० की आवश्यकता पड़ेगी। १९६६-६७ में भी अरबन स्कीम्स जो भी हैं उनके लिए भी रु० १५० लाख की मांग थी और उसकी बजाय ५८ लाख रुपया मिला है। रूरल स्कीम्स के लिए १२० लाख का वर्किंग प्लान बनाकर मांग की गई थी उसके लिए ७५ लाख रुपया मिला है। मैं इसकी शिकायत नहीं प्रस्तुत करना चाहता परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे आर्थिक साधन सीमित हैं। हमको केन्द्र की तरफ भी इसके लिए झांकना पड़ता है और इन सब सीमाओं को देखते हुए हमें सारी योजनाओं को कार्यान्वित करने का विचार करना पड़ता है। यह बात मैं मानता हूं कि कहीं फाउण्डेशन स्टोन रख दिए गए हैं, कहीं पर फाउण्डेशन लगा दी, कहीं कुछ हुआ और इस प्रकार से और कई जगहों पर जल के बढ़ते हुए संकट को देखते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन भी आवश्यक हो गया। यह....

श्री भैरोंसिंह : माननीय मंत्री महोदय कृपया यह बतायें कि जो मास्टर प्लान के लिए ७० करोड़ की आवश्यकता है और उसके लिए इस साल आपने प्रावधान रखा है १ करोड़ २५ लाख का....

श्री नारायणसिंह मसूदा : क्या १ करोड़ २५ लाख का।

श्री भैरोंसिंह : यह जो आपने इस साल प्रावधान रखा है १ करोड़ २५ लाख का और आप कह रहे हैं कि मास्टर प्लान के लिए ७० करोड़ की आवश्यकता है। यदि दो करोड़ साल का खर्चा किया जाय तो यह मानना चाहिए कि आपका मास्टर प्लान ३५ साल में जाकर पूरा होगा और ३५ वर्षों के

(श्री भैरोंसिंह)

बाद लोगों के सामने जो पानी का संकट है वह दूर होगा ।

राव श्री नारायणसिंह : मैं यह निवेदन करूं कि आर्थिक स्थिति यह है और ७० करोड़ तक का मास्टर प्लान है । अगर हम सब जगहों पर सारी स्कीमों को कार्यान्वित कर सकें तो हमें ७० करोड़ का खर्चा करना पड़ेगा लेकिन हमें आर्थिक सीमाओं को भी देखना पड़ेगा और उनके अनुसार ही आगे बढ़ना होगा ।.......

श्री भैरोंसिंह : ३५ वर्ष में जाकर ।

राव श्री नारायणसिंह : ३५ वर्ष का प्रश्न नहीं है । हर एक जगह पर एक योजना बनाकर व्यापक रूप से सबको पानी मिल जाय एक स्टेंडर्ड के अनुसार तो उस सब स्टेंडर्ड को पूरा करने के लिए इतना बड़ा मास्टर प्लान है ७० करोड़ का । अब जो कमियां हैं वे भी कुछ वक्त तक तो रहेंगी लेकिन सारे मास्टर प्लान की जो योजना है उसके अन्दर इतने खर्चे की आवश्यकता होगी । यहां हमारे सीमित साधन इस प्रकार से हैं और उन सीमित साधनों को देखते हुए हमें कुछ अर्से तक कष्ट भोगना पड़ेगा और इसके अलावा आज प्राकृतिक प्रकोप भी सामने मौजूद है । इस वक्त तक जंगलों की कमी होना, आबादी का बढ़ना यह एक और कारण है तो दूसरी ओर वाटर लेवल कम होता जा रहा है । एक तरफ हम योजना बनाते हैं, कुए नए खुदवाते हैं, ट्यूब वैल्स का सहारा लेते हैं, इत्यादि काम करते हैं और दूसरी तरफ जो वाटर लेवल है वह नीचे उतरता चला जा रहा है । इधर विद्युत के मामले में भी आप देखें कि चम्बल की जो योजना है उसमें भी, चम्बल में भी पानी नीचे चला जा रहा है । ये सब कारण तो हैं ही । इन सब स्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा ।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री जी को मलूम है कि सरकार ने ट्यूब वैल्स खुदवाये थे वे सब बेकार पड़े हुए हैं ।

राव श्री नारायणसिंह : कुछ ट्यूब वैल्स ऐसे हैं जिनमें या तो खारा पानी आ गया....

श्री रघुनाथ विश्नोई : ऐसे सक्सेसफुल ट्यूब वैल्स कितने हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी अर्ज यह है कि इस बजट सेशन के दरम्यान करीब करीब हर अवसर पर माननीय सदस्यों ने कहा है कि ये ट्यूब वैल्स चार साल, तीन साल या दो सालों के अर्से से तैयार किए हुए पड़े हुए हैं लेकिन उनको चालू नहीं किया गया है, इसके इसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण कर दें कि स्थिति क्या है ?

राव श्री नारायणसिंह : मैं इस विषय पर आगे प्रकाश डालूंगा । आप चाहें तो मैं अभी निवेदन कर दूं कि जो ट्यूब वैल्स का कंस्ट्रक्शन हुआ था वह बीकानेर, चुरू, बाड़मेर, नागौर और जैसलमेर में हुआ था और वहां पर २५९ ट्यूब वैल्स खुदवाये थे जिनमें से १४३ तो सफल हुए और बाकी ११६ छोड़ दिए गए, यह मेरी सूचना के

(राव श्री नारायणसिंह)

अनुसार है और ये भी अभी टेस्टिंग के अन्तर्गत है। इस सारे विषय पर मैं आगे आ रहा हूं। इसके पहले मैं यह निवेदन करूंगा कि....

श्री भैरोंसिह : १४३ में से चालू कितने है और बन्द कितने हैं ?

राव श्री नारायणसिंह : १४३ में से चालू कितने हैं यह मेरे पास सूचना अभी नहीं है, बाद में मैं आपको सूचना दे दूंगा, इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सब ही बन्द पडे हुए हैं।

राव श्री नारायणसिंह : सब ही तो बन्द नहीं हो सकते।

श्री भैरोंसिह : ६० चालू हैं और १२३ बन्द हैं।

राव श्री नारायणसिंह : इसके अलावा मैं यह निवेदन करूं कि अरबन वाटर सप्लाई स्कीम्स के लिए २६० लाख की अलाटमेंट हुई है और अगर इसकी सारी आवश्यकता को फैलायें तो करोड़ों के अन्दर यह चला जाता है। इन सब को मद्देनजर रखते हुए आज जो हमको यह अरबन वाटर सप्लाई स्कीम के लिए ४० लाख रुपया मिलना है और इसके ऊपर हम दो करोड़ रुपया एल. आई. सी. से लोन का प्रयत्न कर रहे है और उसके लिये गवर्नमेंट ने सप्लाई भी कर दिया है और आशा यही है कि लोन भी उपलब्ध हो सकेगा यथासमय, लेकिन उसके अन्दर भी समय लगेगा। अगर यह दो करोड़ ४० लाख रुपया मिल जाता है तो इस २४० लाख रुपयों से काफी अरबन स्कीम्स कार्यान्वित हो सकेंगी। इसके पहले भी कई स्कीमें कार्यान्वित हुई हैं और कुछ चालू भी हैं। अब इस सारी स्थिति को देखते हुए काफी सख्ती से प्राथमिकताएं निर्धारित करनी पड़ेंगी जिसके अन्दर जो नई स्कीमें हैं उनमें, मुझे आशा तो यही है कि बीस पच्चीस लाख या जितनी भी आवश्यकता है उसके बराबर कुछ अनुपात में केन्द्रीय सरकार से कहा सुनी करके रकम उपलब्ध की जा सकेगी परन्तु यदि जो आज की स्थिति है उसके अनुसार अगर रहना पड़ता है तो जो नई स्कीमें हैं उनमें जो तीन चौथाई हो चुकी हैं पहले उनको प्राथमिकता दी जानी होगी.... उसके बाद में आधी और उसके बाद में उससे नीचे। तो यह आवश्यक होगा, यद्यपि कई जगहों पर उसके हिसाब से कठिनाई भुगतनी पड़ेगी लेकिन मुझे आशा है कि हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे कि जहां तक भी हो सके, इसमें केन्द्रीय सरकार से हमें पूरे के पूरे साधन मिल सके....

श्री विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक जानकारी मैं करना चाहता हूं।

राव श्री नारायण सिंह : मैं पहले बोल जाऊं, उसके बाद में आप कहें तो ठीक होगा। नहीं तो तारतम्य बिगड़ जाता है।

श्री विजयसिंह रावत : आप कह रहे हैं कि आपकी ये ये योजनायें हैं और सारी बातें

(श्री विजयसिंह)

कह रहे हैं लेकिन जड़ मूल को बात कहने के लिए तैयार नहीं हैं, उस पर आपने कोई प्रकाश नहीं डाला है। मैं आसन से निवेदन करूंगा कि आप जितनी योजनायें गठित कर रहे हैं वह आप किस किस आधार पर कर रहे हैं और किस किस आधार पर आपने योजनायें गठित की थी ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : ७० करोड़ की हैं ?

श्री अमीलाल यादव : किस आधार पर की हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर दिया जाना मुश्किल है कि किस आधार पर की है। किसी योजना के लिए आप पूछना चाहें तो उसके लिए पूछ लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : और इन्ट्रप्ट करने से एक और बात होती है कि मंत्री महोदय पहली वाली बात भूल जाते हैं।

श्री विजय सिंह रावत : मंत्री महोदय ! आपने अजमेर के लिए जल प्रदाय योजना बनाई है वह किस आधार पर बनाई है, उसका आधार आपने क्या लिया था बनाने से पहले ?

राव श्री नारायण सिंह : आधार का आशय आप समझा दें, मतलब क्या है।

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय ने कहा कि अर्बन एरिया में २ करोड़ ४४ लाख लगेंगे....

राव श्री नारायण सिंह : आधार का जहां तक सम्बन्ध है, आधार वही है, सबसे बड़ा आधार यह है कि सारी योजनायें बनाने के लिए अ इडियल यह है कि ४० गैलन पर-कैपिटा सबको पानी मिल सके। उसके अन्दर करीब २० गेलन का आधार रखा जाता है। यह आधार मोटे रूप में है और इस आधार पर सारी योजनायें बनाई जाती हैं। अब कहां तक पूरा हो सकता है यह बढ़ती हुई आबादी और साधनों की उपलब्धि पर मुनहस्सर है।

श्री विजय सिंह रावत : मन्त्री महोदय जानते हैं इस बात को कि अजमेर में गनहेड़ा की योजना बनाई गई, उस वक्त उन इंजीनियरों ने आपको क्या यह संकेत किया था कि इन योजनाओं के द्वारा अजमेर के सामने आने वाले बीस-तीस साल में जल कष्ट नहीं आयेगा। नई योजनाओं के ऊपर पांच करोड़ का खर्चा सारे राजस्थान में करेंगे तो क्या इसके अन्दर आप आश्वासन दे सकते हैं कि अगले बीस तीस साल में जल कष्ट नहीं आयेगा। आप आधार बता रहे हैं, पोपूलेशन, पर -कैपिटा यह बिल्कुल गलत है। बनास से लेकर जो आप आ रहे हैं उसके अन्दर यह आधार नहीं लिया गया है कि बीस कुओं का पानी खत्म हो जायगा तो आपकी योजना फैल हो जायगी तो फिर...

राव श्री नारायण सिंह : ऐसी बात नहीं है कि आधार नहीं हो। आधार रखा गया है।

श्री विजय सिंह रावत : गनहेड़ा की योजना कैसे फेल हो गई ? आपको जानकारी है ।

राव श्री नारायण सिंह : गनहेड़ा की योजना के अन्दर वाटर लेवल नीचे गिरता गया ।

श्री विजय सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि इन्जीनियर्स ने...... ...

राव श्री नारायण सिंह : और इसके अलावा आबादी भी बढ़ी ।

श्री विजय सिंह रावत : इन्जीनियर्स ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा था कि गनहेड़ा के कुओं का पानी गिर जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार से प्रश्न और उत्तर का तो कोई अन्त नहीं हो सकता हैं । आप किसी योजना के बारे में पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं ।

श्री विजय सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव इस बारे में है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपके कटौती प्रस्ताव में यह आता नहीं है इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं । आपके कटौती प्रस्ताव मेरे पढ़े हुए हैं उनमें नहीं है ।

श्री विजय सिंह रावत : जल संकट के बारे में है ।

श्री उपाध्यक्ष : जल संकट का तो लम्बा चौड़ा प्रश्न है । आप किसी एक जल प्रदाय योजना के बारे में पूछ लीजिये । प्रश्न-उत्तर बराबर चलते रहेंगे तो उसका अन्त नहीं है ।

श्री विजय सिंह रावत : आपको बताऊं कि जितनी योजनायें हैं वह सब योजनाएं बिना आधार के बनती है । क्योंकि इनका आधार नहीं होता है इसलिए यह फेल होती हैं । यह बात हमको बार बार कहनी पड़ती है और मजबूर होकर कहनी पड़ती है ।

राव श्री नारायण सिंह : जिस समय आप मन्त्री बनेंगे उस समय आधार ठीक हो जायगा । इस समय जो आधार है वह मैंने निवेदन कर दिया है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

राव श्री नारायणसिंह : इसका एक और कारण पावर शार्टेज का होता है । हमने चम्बल से आशा की थी कि काफी पावर प्राप्त हो सकेगी लेकिन घटती हुई वर्षा के कारण चम्बल का फ्लो बहुत कम हो गया है । इस कारण जो पावर की उपलब्धि है वह भी कम हुई है । उसको सप्लीमेंट करने के लिये भाखरा से लाइन इत्यादि लाई गयी और सब कार्य किये गये, और इस तरह से पावर की जो दिक्कत थी उसको काफी हद तक दूर कर दिया गया है । मैं यह निवेदन करूंगा कि विद्युत विभाग की तरफ से काफी सहयोग इस विषय में दिया जा रहा है लेकिन

(राव श्री नारायणसिंह)

फिर भी जो उपलब्धि पावर की है उसको देखते हुए जितनी प्रगति वाटर सप्लाई के अन्दर जिस प्रकार से होनी चाहिये थी उतनी पूरे प्रकार से नहीं हो पाती।

अब जो बड़े बड़े शहरों के अन्दर मौजूदा पानी का सङ्कट है उसके अन्दर जो सप्लीमेंट्री अरेन्जमेंट्स किये गये हैं उन पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। अजमेर के अन्दर जिस प्रकार का जल सङ्कट है....

श्री विजय सिंह रावत : नसीराबाद।

राव श्री नारायणसिंह : उसको देखते हुए ४५ हजार रुपया फेमिन विभाग से लेकर डिस्टिलिङ्ग, कुओं की सफाई इत्यादि के लिए कुओं को गहरा करने के लिये लगा कर जो वहां की २० गैलन पर-कैपिटा पानी की उपलब्धि है उसको २३ गैलन पर-कैपिटा तक लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। जयपुर के अन्दर जो शहर के अन्दर कुए हैं, उसके लिये योजना को कार्यान्वित करके दस ट्यूब वैल्स, १० ओपन वैल्स-इन वैल्स से और दूसरे साधनों से पन्द्रह लाख गैलन प्रति रोज शहर को वाटर सप्लाई करने का प्रयत्न किया जा रहा है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी कितना मिल रहा है ?

राव श्री नारायणसिंह : इतने स्टेटिस्टिक्स मुझे याद नहीं हैं, आपको याद हैं तो आप फर्मा दें। जो पहले के फिगर्स हैं उनमें पन्द्रह हजार गैलन जोड़ दीजिये।

श्री जयनारायण सालोदिया : हमें तो इतना याद है कि कई बार साबुन लगा कर रह जाना पड़ता है।

राव श्री नारायणसिंह : वह तो रहना पड़ेगा। बीकानेर में इतना जल संकट है। (विराम) वैसे कभी तो साबुन भी उपलब्ध नहीं होता था, आज इतने साधन उपलब्ध हैं।

श्री भैरोंसिंह : साबुन की बात छोड़िये। आप इतना बता दीजिये कि जयपुर में जो जल संकट है उसके निराकरण के लिए बनास योजना जो आपके विचाराधीन है उसके बारे में क्या कर रहे हैं ?

राव श्री नारायणसिंह : मैं उस पोइन्ट पर आ रहा हूं।

इसके अलावा जो सप्लीमेंट्री स्कीम्स हैं, वह भरतपुर में भी हैं। जयपुर के विषय में मैं एक बात और कह दूं। अभी जैसा कि माननीय बाढ़दार ने सुझाव रखा कि हैंड पम्प लगाये जायं। यह प्रश्न भी विचारणीय है और इसको भी देखा जा सकता है।

श्री विजयसिंह रावत : बाल्टी और रस्सी भी रख दें।

राव श्री नारायणसिंह : भरतपुर में कस्बों के कुओं में से पानी लिया जाकर ७५ हजार गैलन एक दिन के अन्दर बढ़ा कर किया गया है।

अलवर में दो ट्यूब वैल्स और बनाये जा रहे हैं....

Page No. 158

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप बनास योजना से अलवर पर कहां पहुँच गए।

राव श्री नारायणसिंह : आप अभी जयपुर पर ही अटके हुए हैं। बनास योजना आगे आने वाली है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपको तो सारे राजस्थान को देखना है।

राव श्री नारायणसिंह : बीकानेर के....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर। आर्डर।। श्री महोदय को कृपया जवाब देने दें, उसके बाद में कोई प्रश्न हों तो पूछ लीजिये।

श्री अमोलाल यादव : फिर भूल जायेंगे जैसे बीच में अलवर को ले आये। अलवर के विषय में बता देना चाहिये, फिर डिस्ट्रिक्ट-वाइज बता देना चाहिये।

राव श्री नारायणसिंह : आप शांति-पूर्वक सुनने का प्रयत्न करेंगे तो मैं भूल नहीं पाऊंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको जैसा लिख कर दिया वह आप पढ़ दीजिये।

राव श्री नारायणसिंह : जो सदस्य पुराने हैं उन्होंने मेरे दिमाग की शक्ति को समझ रखा है। आप अभी नये परिचित हो रहे हैं।

बीकानेर के....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब सब आपके दिमाग की जांच कर रहे हैं।

राव श्री नारायणसिंह : बीकानेर के अन्दर जिस प्रकार की व्यवस्था है उसको देखते हुए वहां भी फेमिन डिपार्टमेंट को लिखा गया है कि कुछ और सहायता मिले जिससे वहां जल प्रदाय योजना ठीक हो सके।

अब मैं, जिस बात की आपको उतावली हो रही है, उस विषय पर आता हूँ कि जल का परमानेन्ट अरेन्जमेंट किस शहर के लिये किस प्रकार से होगा... जयपुर के लिए बनास का रेफरेन्स करते हैं और जोधपुर (बोरूंदा) गांवों से ट्यूबवैल्स की स्कीम है। बीकानेर में राजस्थान केनाल से पानी फिल्टर करके लाने की स्कीम है। अलवर में ३७ लाख की स्कीम है। जयसमन्द से ट्यूबवैल्स आदि से आदि जल प्रदाय की स्कीम है और इससे १२ लाख गैलन मिल रहा है वह उससे ३० लाख गैलन प्राप्त होगा। यह परमानेन्ट एग्रीमेंट का है इसलिये भी जिस प्रकार से साधन उपलब्ध होंगे वह होगा....

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौनसी स्कीम कब से लागू होगी? फाइनल पोजीशन क्या है?

राव श्री नारायणसिंह : यह तो एकदम नहीं कहा जाता है। यह तो साधन उपलब्ध होते रहेंगे उसके अनुसार करते रहेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब तक साधन उपलब्ध नहीं होंगे तब तक यह सब आपके खयाली पुलाव ही रहेंगे?

राव श्री नारायणसिंह : जब तक साधन उपलब्ध नहीं होंगे खयाली पुलाव ही बने रहेंगे। बिना साधनों के तो कैसे हो सकता है।

एक माननीय सदस्य : दो तीन साल से कुवेरा के लोगों ने ७।। लाख रुपया जमा कराया है क्या वहां पर कार्य शुरू होगा या नहीं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : बहुत से कटौती के प्रस्ताव आये हैं अगर आप आज्ञा दें तो अलग अलग का उत्तर दूं अन्यथा जितने भी कटौती के प्रस्ताव आये हैं और जिनका जवाब नहीं आये उनका सबका जवाब माननीय सदस्यों को लिखित रूप में पहुंच जावेगा और जिन जिन बातों पर मैं आ रहा हूं उनमें मैं समझता हूं कि करीब करीब सारी बातों की उपलब्धि होगी।

श्री भैरोंसिंह : जयपुर में पानी सप्लाई के लिए आप बतावें कि बनास योजना बनाई है उसके लिये कितने रुपयों का प्रावधान रखा है ?

एक माननीय सदस्य : जिन लोगों से घर घर से चन्दा मांग कर पैसा इकट्ठा किया गया है उसका क्या होगा ?

राव श्री नारायणसिंह : इस समय कुछ भी प्रावधान नहीं रखा है।

श्री भैरोंसिंह : जब आप जानते हैं कि जल सकट है, जयपुर में पानी का संकट है उसी अनुपात में सब जगह जैसे आपने बीकानेर में रखा है और दूसरी जगह भी रखा है यहां के लिये क्या रखा है ?

इस सदन में सरकार की ओर से कहा गया था कि दो वर्षों बाद पानी के जो स्रोत हैं वह जयपुर की आधी जनता के लिये पर्याप्त नहीं होंगे और बनास की योजना के लिये आप कुछ नहीं कर रहे हैं इसका परिणाम यह निकलेगा कि दो वर्ष बाद यहां पर पानी लोगों को नहीं मिलेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने अलवर के लिए २ करोड़ ४० लाख का प्रावधान रखा है उसका ब्रेक-अप तो बताने की कृपा करें कि कौन कौन सी योजनाओं को आप ले रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : आप इनसे चैम्बर में जा कर मिल लें।

राव श्री नारायणसिंह : यह धनराशि जब उपलब्ध हो जावेगी तब इस बात की सूचना भी मिल सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य प्रश्न नहीं पूछें। पहले मन्त्री महोदय को उत्तर देने दें उसके बाद यदि कोई आपको शक रह जाय तो आप प्रश्न कर सकते हैं वे उसका उत्तर दे देंगे। पहले आप इनकी सुन लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आप २ करोड़ ४० लाख का ब्रेक-अप नहीं बता सकते हैं कि क्या ब्रेक अप है

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जिस काम को आप हाथ में लेने वाले हैं तो दूसरों का क्या बतावेंगे ?

एक माननीय सदस्य : वह कटौती प्रस्ताव के द्वारा पूछा नहीं गया था।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर। आप पहले माननीय मन्त्री को जवाब देने दें बाद में जो भी प्रश्न आपको पूछने हों पूछ लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इधर से या उधर से जलप्रदाय योजना के लिए जो बातें रखी हैं, यदि ब्रेक-अप बता दें तो सब मामला साफ हो सकता है।

श्री मदनसिंह दांता : अगर एल. आई. सी. लोन्स के बारे में आप उत्तर नहीं देंगे तो सारी बात अधूरी रह जावेगी। और लोगों को संतोष नहीं होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेमोरेन्डम में इस बात का हवाला नहीं दिया है ' समझ में नहीं आता कि इस बात को छुपाया क्यों जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

राव श्री नारायणसिंह : यह आपकी सूचनार्थ में सूची पढ़ देता हूं। राजगढ़ सीकर में.... ......

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : ब्रेक अप सूची बहुत लम्बी है। प्रश्नों के द्वारा पूछी जा सकती है यह सदन की मेज पर रखी जा सकती है।

श्री मनोहर सिंह मेहता : सदन की मेज पर रख दो जाए।

श्री मदनसिंह दांता : क्या हम अपना भाषण करना शुरू कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप मन्त्री महोदय को कहने दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप कागज पलट लें।

राव श्री नारायणसिंह : ब्रेक-अप के बारे में सदन की मेज पर सूची रखता हूं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा) पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसके लिए प्रश्न सभी सदस्यों ने उठाये हैं। इस साल में कितने रिजरवायर हो सकते हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। हमने बजट में देखा.......

राव श्री नारायणसिंह : जैसा मैंने कहा कि दो करोड़ रुपया एल. आई. सी. से मिल जाता है तो उसी प्रकार से कार्य हो सकता है और अगर एल. आई. सी से पैसा नहीं मिलता है तो नहीं होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब यह हुआ कि अगर दो करोड़ रुपया नहीं मिलेगा तो यह कार्य नहीं होगा और कोई योजना हाथ में नहीं लेंगे।

Page No. 161

राव श्री नारायणसिंह : हमें नहीं मिलता है तो फिर ऐसा ही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर नहीं मिलता है पैसा तो कोई योजना नहीं होगी। और साल भर में जनता तकलीफ पाती रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष : साल भर में वर्षात हो जावेगी।

राव श्री नारायणसिंह : अब दो करोड़ मिलेंगे ऐसी उम्मीद हैं। पहले भी दो करोड़ मिले हैं उसका उपयोग इसलिये नहीं हो सका कि पहले रिजोल्यूशन नहीं आये। पहले मिला जरूर था इसलिये अब भी यह मिलेगा। तो यह सारे कार्य की ब्रेक-अप की सूची में रख रहे हैं।

श्री मदनसिंह दांता : एक करोड़ उदयपुर के लिये और एक करोड़ दूसरों के लिये।

राव श्री नारायणसिंह : इसके अलावा रूरल वाटर सप्लाई वर्क बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर, नागौर में १४३ ट्यूब वैल्स सफल हुए और बाकी छोड़ दिये और १९ ऐसे हैं जिनका टेस्टिंग हो रहा है। राजस्थान अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के द्वारा ३७ वैल्स ड्रिल हुए हैं और उन पर खर्चा १२८ लाख का ६६-६७ में हुआ है। उसके अलावा जो कुछ रूरल वाटर सप्लाई में एचीवमेंट हुए हैं वह मैं निवेदन करूंगा।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में ९३ स्कीमें, ८९ स्कीमें फोर्थ ईयर प्लान में व १५ स्कीमें ६६-६७ में कम्पलीट होनी थी। ७१ तीसरी पंचवर्षीय योजना में पूरी हो गईं और १५ स्कीमें ६६-६७ के दौरान।

(९ म. प.)

इस तरह से कुल आवश्यकता २ करोड़ २९ लाख की सारी स्कीम को पूरा करने के लिये रह जाती है।

जो कटौती प्रस्ताव विभिन्न माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किये हैं, उनके अन्दर भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री मुकुट बिहारीलाल ने भरतपुर की योजना के लिये कहा, योजना बनाई थी पर योजना के विरोध के कारण केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री श्री के. एल. राव के पास भेजा, सिफारिश भी गई, पर माननीय सदस्य और सुझाव देना चाहें तो उस पर विचार किया जा सकता है। बांध बारेठा की स्कीम हाथ में ली गई, धौलपुर बनास नदी से, २० लाख की स्कीम बाकी है, ४ लाख रुपये पिछले साल तक व्यय भी हो चुके हैं, एल. आई. सी. से १६ लाख की मांग की है।

एक माननीय सदस्य : पास वाली योजना के लिये कुछ नहीं कहा ?

राव श्री नारायणसिंह : १७५ हजार की है, पिछले साल के अन्त तक ७२ हजार लग चुके हैं।

इसके अलावा श्री गिरधारीलालजी ने दौलतगढ़ और बदनौर की जल योजना के बारे में कहा, इसके लिये मंजूरी ली जा चुकी है, कुछ खर्चा भी पिछले साल हो चुका है, जो बचत में रहेगा, उसी के अनुसार इस पर खर्च किया जायगा।

(राव श्री नारायणसिंह)

माननीय रामानन्द जी ने मीटर्स के बारे में बात की, मैंने इस बारे में जानकारी की। माननीय रामानन्दजी ने ७० परसेन्ट मीटर खराब होने की बात कही। मैंने जानकारी की, ७० परसेन्ट मीटर खराब होने की बात में तो अतिशयोक्ति है, कुछ मीटर्स खराब हैं। जो खराब हैं, रूल्स के मुताबिक पिछले साल के अनुसार रीडिंग कर के वसूली की जाती है। इसके अलावा यह भी कहा कि मीटर पड़े हैं, बिलकुल खराब हैं, मुझे जो सूचना मिली है उसके अनुसार सारे खराब नहीं है, अच्छी हालत में चालू पड़े हैं, उनको खरीदा जा सकता है जहां आवश्यकता हो....

श्री रामानन्द अग्रवाल : इश्यू नहीं किये जा रहे हैं....

(विराम)

राव श्री नारायणसिंह : डिपार्टमेंट से सूचना मिली है कि मीटर हैं और खरीदे जा सकते हैं। एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा....

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : सचिव और मन्त्री महोदय के बीच में नल लगा दिया जाय ताकि वे मन्त्री महोदय को बताते रहें और मन्त्री महोदय बोलते रहें।

राव श्री नारायणसिंह : प्रावधान होगा तो वह भी लगा दिया जायगा। मन्त्री कोई चलती फिरती एन्साइक्लोपीडिया तो है नहीं, विशेषतया नया मन्त्री हूं तो विशेष जानकारी आफिस से करना जरूरी है, मुझे समय लगेगा, आप भी यहां आकर विराजते तो आपको भी आफिस से जानकारी लेनी पड़ती।

श्री मदनसिंह दांता : मैं वहां बैठता और इस तरह मन्त्री जवाब दे दें और मन्त्री बने रहें....

राव श्री नारायणसिंह : मैं आपके लिये नहीं कहता, जानकारी तो करनी ही पड़ती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : गांवों के लिये कितना रखा है ?

राव श्री नारायणसिंह : गांवों में परसेन्टेज काफी रखा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों में ४० लाख जो तृतीय पंचवर्षीय योजना का पुल ओवर आ रहा है, उसके लिये रखा है, ३० लाख नई के लिये रखा है, हमें आशा है कि और ज्यादा प्राप्त हो सकेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : २४५ लाख शहरों के लिये दिया है, और ८० प्रतिशत से ज्यादा राजस्थान गांवों में बसा हुआ है, क्या यह गांवों के साथ अन्याय नहीं है ?

श्री जयनारायण सालोदिया : निवाई के लिये मेरा कटौती प्रस्ताव था, प्रथम पंच वर्षीय योजना से विचाराधीन है, उसके लिये आपने कुछ नहीं कहा ?

राव श्री नारायणसिंह : यह योजना बन चुकी है और एल. आई. सी. से लोन मिलने पर इसे हाथ में ले सकेंगे।

श्री विजयसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : बार बार डिबेट में बाधा उपस्थित नहीं करें, मन्त्री महोदय को उत्तर देने दें, फिर कोई प्रश्न पूछना हों तो पूछ सकते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई गांवों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है, यह गांवों के साथ न्याय नहीं किया है।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय मैंने जो बातें रखी थीं, उनका संतोषजनक जवाब नहीं दिया है, हमारे गांवों में पानी के अभाव में गायें मर रही हैं।

राव श्री नारायणसिंह : सरकार ने गांवों और शहरों के लिए अलग अलग परसेंटेज की फलावट नहीं की है, सारे राजस्थान के लिये किया है, गांवों की आबादी को अलग मान कर नहीं चलते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अगर यह सोचते तो गांवों के लिये पैसा रखते, वहां के लोगों को भूल नहीं जाते। गांवों के लोग बोल नहीं सकते इसलिये उनके साथ न्याय नहीं किया गया है।

राव श्री नारायणसिंह : आप बोलने वाले हैं, कई बोलने वाले हैं, मैं स्वयं गांवों की जनता के लिये बोलने वाला हूं।

श्री विजयसिंह रावत : आप गांवों की जनता के लिये बोलने वाले हैं तो आपने आज तक गांवों की जनता के लिये क्या किया है ?

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय के उत्तर को सुन लें, उसके बाद आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मन्त्री महोदय ने २५० लाख के ब्रेक-अप की लिस्ट दी है इसमें बड़े बड़े शहर कोई शामिल नहीं हैं तो उस पर जो खर्चा हो रहा है या खर्च का प्रावधान रखा है या नहीं रखा है, अगर रखा है तो किस मद में है, इसमें देखें तो कुछ नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स का है...

राव श्री नारायणसिंह : २ करोड़ की स्कीम है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : खर्चा कर रहे हैं या नहीं ? वास्तविकता यह है कि कुछ खर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जो कटौती के प्रस्ताव जिस भी माननीय सदस्य के हों, उन पर अगर उत्तर नहीं आया है तो मन्त्री महोदय से बाद में भी आप पूछ सकते हैं। आपका कटौती प्रस्ताव जयपुर जोधपुर के बारे....

श्री रामानन्द अग्रवाल : अलवर के बारे में है इतना टेक्नीकली तो मत लीजिए। सभी माननीय सदस्य जानना चाहेंगे कि आखिर आप क्या करने जा रहे हैं। कम से कम फैक्ट्स के बारे में तो गलतफहमी नहीं रहे और न ही मन्त्री महोदय गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करें। जो योजनायें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर अलवर और अजमेर की हैं जिनके बारे में आपने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कहा था कि करोड़ों की योजनायें हैं। इस साल में क्या प्रावधान है ?

राव श्री नारायणसिंह : इस साल में मैंने बताया कि सप्लीमेंटरी की व्यवस्था की गई है। उसके अनुसार दो ट्यूब वैल्स अलवर के अन्दर....

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने टेम्परेरी मेजर्स के लिए फरमाया था इनको रोकने के लिए। आप परमानेन्ट स्कीम्स बताएं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : परमानेन्ट स्कीम्स मैंने अलग पढ़कर बताईं और टेम्परेरी स्कीम्स अलग बताई हैं। आप केवल प्रश्न पूछकर मेरी जांच के लिए इन दोनों को कन्फ्यूज कर रहे हैं। मैंने दोनों अलग अलग बताए हैं।

श्री मदनसिंह दांता : मैं समझता हूं सारे सदन में एक ही महत्वपूर्ण सवाल था, जिसका जवाब आपको देना चाहिए था। जहां एक एक डोल पांच रुपये का पानी का मिलता है, और एक रुपया देकर पानी का गिलास लिया जाता है, उनके लिए क्या कर रहे हैं ? उसका कोई जवाब नहीं दिया। जहां बिलकुल पानी नहीं है, गायों के लिए पानी नहीं....

राव श्री नारायणसिंह : ७० लाख की स्कीम्स गांवों के लिए हैं और उनके अन्दर जितना भी प्राथमिकता के हिसाब से जहां जहां पर भी कार्य आवश्यक होगा, उसको देखते हुये कार्य कराया जायगा। एकदम जो कमी है वह एकदम जादू से ठीक तो नहीं हो सकती।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपको आबादी के हिसाब से प्रावधान रखना चाहिए।

श्री विजय सिंह रावत : साढ़े ६ करोड़ रुपया तो आप शहरों के लिए खर्च कर रहे हैं शहरों के लिए, यह क्या अनुपात है ? खेद की बात है कि शहरों में साढ़े बारह प्रतिशत लोग रहते हैं उनके लिए साढ़े ६ करोड़ या साढ़े पांच करोड़ रखना चाहते हैं....

राव श्री नारायणसिंह : आप जनता का अनुपात लगाया क्या ? क्या अनुपात नहीं लगाए ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : सरकार को लगाना चाहिए।

श्री विजयसिंह रावत : गर्भवती महिलाएं, हमारी माताएं और बहनें ५-५ मील से मटकी लेकर दूर पानी के लिए गांवों में जाती हैं लेकिन सरकार को इसका ध्यान नहीं है, उसका आपके पास कोई जवाब नहीं। सरकार गांवों के लिए तो ३५ लाख रखे और शहरों के लिए साढ़े ६ करोड़, यह अनुपात है आपका ?

राव श्री नारायणसिंह : सरकार की यह जिम्मेदारी है कि सभी जगह ट्यूब वैल्स लग जायं, रेडियोज लग जायं, ट्रांजिस्टर्स लग जायं, अमरीका की तरह...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रेडियो को कुए में जाने दो, आप...

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रश्न पूछें, मन्त्री महोदय बता देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रेडियो, फोन, कूलर और फ्रिज का सवाल नहीं है। राजस्थान को जनता चाहे वह शहर की हो या गांव की हो, जनता को विभाजित मत कीजिए, पानी सब को चाहिए। राजस्थान की आबादी २.२५ करोड़ है. सरकार उनको पानी देने में असफल रही है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। आपके पास इस साल कोई योजना नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : मैं निवेदन करूं कि एक महत्वपूर्ण बात हुई थी एक माननीय सदस्य के इलाके के लिए, वह बात बिलकुल बहस में पड़ जाती है, उसका जवाब अभी तक नहीं आया। मन्त्री महोदय ने कहा कि हम देखेंगे। वह फरमाया कि जादू नहीं हो सकता लेकिन मन्त्री महोदय को जादू जैसे काम करना पड़ेगा, गर्मी पड़ रही है। यहां लोगों ने पहले भी राज किया है, वे रेलवे से भी पानी लाते थे। हो सकता है कि जयपुर में दो तीन दिन लेट हो जाय, नए साल में हो जाय लेकिन जो सदस्य चेलेंज देते है कि विधान सभा को सदस्यता से त्यागपत्र दे सकते हैं अगर उनकी बातें गलत हों कि पानी नहीं मिल सकता ऐसे सदस्यों को आप उचित ढंग से जवाब दें और मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह जवाब जब तक स्पष्ट न हो जाय और बातों की बहस में न पड़ें।

श्री उपाध्यक्ष : आपने बीकानेर की बात कही, वहां पानी बहुत आ रहा है। पानी बहुत गहरा है। मन्त्री महोदय क्या योजना बना रहे हैं उनको सुनें....

(शोरगुल)

श्री चुन्नी लाल (नोखा) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब सुनने को तैयार हैं नहीं। आर्डर प्लीज।

राव श्री नारायणसिंह : कोलायत के पानी के विषय में माननीय सदस्य ने यहां बात उठाई कि पांचों ग्रामों के अन्दर मोटर लगी और वह जल गई। दरअसल पंचायत समिति के मार्फत जल प्रदाय योजना की व्यवस्था होती है। मोटर जलने के बाद फिर भेज दी गई, वह भी जल गई इसलिए सारी व्यवस्था ठप्प हो गई। एकदम दूसरी मोटर आना भी मुश्किल है....

(शोरगुल)

श्री रामानंद अग्रवाल : यह तो बड़ा ही अजीब जवाब है कि मोटर नहीं आ सकती, जल गई लोग प्यासे मरेंगे। इमर्जेन्सी बेसिज पर मोटर मिल सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। मन्त्री महोदय को कृपया जवाब देने दें।

श्री मदन सिंह दांता : अगर आपके पास मोटरों की कमी है तो कम से कम यह

(श्री मदनसिंह दांता)

बताइए ताकि और व्यवस्था की जायगी ? जो ही बनते हैं उनकी व्यवस्था की जायगी ? यह कह देना कि लोग मरते रहें लेकिन मोटर नहीं है....

राव श्री नारायणसिंह: यह मैंने कभी नहीं कहा ।

श्री मदनसिंह दांता : आपने कहा कि मोटर नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप मन्त्री महोदय के उत्तर को सुनलें। आप बीच में हस्तक्षेप न करिए ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : योजना मन्त्री बता दें कि राजस्थान में पानी की समस्या कब हल होगी पांच वर्ष में या दस वर्ष में ?

श्री मथुरा दास माथुर (योजना मन्त्री) में निवेदन करूं कि विभिन्न हैड्स के अन्दर हम वाटर सप्लाई समस्याओं को हल करते हैं। अरबन वाटर सप्लाई की जितनी स्कीम्स हम लोगों ने यहां बनाईं टेक्नीकली एप्रूव्ड हुई और उनको प्लानिंग कमीशन में भेजा गया। वहां टेक्नीकली एप्रूव होने के बाद वे स्कीम्स जिनकी लिस्ट आपने देखी है उनके लिए एल. आई. सी. लोन देती है। राज्य सरकार के मार्फतनगरपालिकाओं को भी लोन्स देते हैं। हमने उन स्कीम्स के लिए २ करोड़ का लोन एल. आई. सी. से ले रखा है। वे स्कीम्स पूरी तो साढ़े चार करोड़ की हैं लेकिन इस साल २ करोड़ रुपयों का लोन लेने की बात हो चुकी है, उसके मिलने के बाद वह लोन नगरपालिकाओं की अर्बन वॉटर सप्लाई स्कीम के अन्दर देता हूं। जयपुर या अलवर की सप्लाई हैं ये टेक्नीकली एप्रूव होने के बाद एल. आई. सी. को एप्रोच करने के बाद हमको लोन मिलेगा और इन स्कीम्स को अंडरटेक कर सकते हैं ।

कई जगह रूरल वाटर सप्लाई चालू करने की कोशिश कर रहे है। फेमिन फंड में है ७० लाख का वाटर सप्लाई को अगार-मेंट करने के लिए। दूसरे साल भी हमने ७० लाख की जैसे मन्त्री महोदय ने कहा, ७० लाख इस काम के लिए रखे हैं वह सिर्फ पाइप्स स्कीम्स के लिए है, ७० लाख वह खर्च हो चुका है और ये ७० लाख, कुल १४० लाख। उसके साथ साथ मन्त्री महोदय ने बताया कि जो ट्यूब वैल्स हैं बोर्डर पर बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर और नागौर एरियाज के अन्दर, जो ट्यूब वैल्स खोद रहे हैं उनमें २०० तो सक्सेसफुल हो चुके हैं। यह भी रूरल वाटर सप्लाई में है। माथुर कमेटी की रिपोर्ट के पार्ट्स हैं और वह रूरल वाटर सप्लाई को मिलता है। उसके साथ साथ यहां पर कम्यूनिटी डेवलपमेंट में नाडी नाते की बात आपने कही, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फंड की बात कही। भारत सरकार प्लान सीलिंग के बाद पैसा देती रही है वह पैसा गांवों के अन्दर पंचायत संस्थाओं को कुओं के लिए देते हैं, वह रुपया उधर से भी आता है। तो कभी कभी ५०-६० लाख रुपया मिल जाता है। टोटल रुपया फेमिन लोकल डवलपमेन्ट सी. डी. की मार्फत खर्च कर रहे

(श्री मथुरादास माथुर)

हैं। वाटर सप्लाई या एक्सप्लोरेटरी ट्यूब वेल्स के जरिये कर रहे हैं। मैं खुद मानता हूं कि १२ करोड़ रुपये का मास्टर प्लान था। उसमें से बहुत कम मिला है रूरल वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी के लिये ६० लाख रुपया गत वर्ष मिला। प्लान खत्म हो जावेगा तब ढाई तीन करोड़ रुपया रूरल वाटर सप्लाई स्कीम में खर्च कर पायेंगे। एल. आई. सी. का लोन तब ही मिलता है जब एप्रूव होती है स्कीम। म्युनिसिपेलिटी को वह दिया जाता है। गवर्नर की स्पीच के वक्त भी यह बात आयी और बजट के वक्त भी आयी है। माननीय सदस्यों को यह बताया गया था कि लोन के लिये नेगोशियेट किया जावेगा, म्युनिसीपेलिटीज् को दिया जावेगा और जो योजना टेक्निकली साउन्ड है उसकी स्वीकृति होने पर एल. आई. सी. से लोन मिल सकेगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार यह जरूरी नहीं समझती है कि जिन इलाकों में भयंकर संकट है पानी का उसके निवारण के लिये एल. आई. सी. से रुपयों की मांग करें? १ करोड़ रुपया बिना प्रावधान के ही उदयपुर में खर्च करने के लिये जा रहा है उसके बजाय पहले यह रुपया उन इलाकों में खर्च किया जाय जहां कि पानी का भयंकर संकट है। क्या आपको इस प्रकार उदयपुर में खर्च करना अनुचित नहीं लगता ?

श्री मथुरा दास माथुर : कतई अनुचित नहीं लगता। उदयपुर में भी पीने के पानी की समस्या है। एक करोड़ रुपया उदयपुर में नहीं रखा है। इस साल से २० लाख रुपया रखा है। जयपुर के लिए लाखों रुपया खर्च ट्यूब वेल खोद करके किया है....

श्री भैरोंसिंह : एक लाख भी नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : अब तक बड़ी स्कीम पर.......

श्री भैरोंसिंह : उदयपुर की स्कीम के लिये २० लाख रुपया दिया और मास्टर प्लान में प्रायोरिटी में जयपुर की स्कीम आती है यह कैसे डिफरेन्शियेट कर लिया ?

श्री मथुरादास माथुर : जयपुर राजस्थान की राजधानी है और यहां पर वाटर सप्लाई की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। ९ करोड़ की स्कीम है और उसके लिये जब तक टेक्निकली स्कीम साउन्ड होकर एल. आई. सी. तक न करे और इन्स्टालमेंट में तय नहीं हो जाती है, बड़ी स्कीम में समय लगता है, छोटी स्कीम तो राज्य सरकार खुद अपने एक्सपर्ट से कर सकती है, तब तक यह संभव नहीं है हालांकि राज्य सरकार इस के लिये बहुत ही इच्छुक है कि स्कीम को अमली जामा पहना दें। रामगढ़ में पानी डाल डाल कर पानी पहुंचा रहे हैं। ९ करोड़ की स्कीम बनाने में भी टाइम लगता है। एक प्लान पीरियड में उसको पूरा करना कठिन हो जाता है। ९ करोड़ की स्कीम यहां पर कर रहे हैं। जगह जगह पर डिमान्ड है। सी. डी. फन्ड है। अलग अलग जगह से हम टेकल कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : देहात की जो स्कीम है उसके लिये क्या एल० आई० सी०

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लोन नहीं देती है। एल० आई० सी० से लोन लेकर उन स्कीम्स को ज्यादा प्रेस क्यों नहीं करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अनुदान है। गांवों में ५ परसेन्ट जनता का कान्ट्रिब्युशन है।

श्री रामानंद अग्रवाल : अपने अनुमान रखा था उसमें यह ही था कि ७५ लाख रुपया देहातों के लिये और शहरों के लिये २ करोड़ रुपया एल० आई० सी० से लेकर खर्च करेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने यह नहीं कहा कि शहरों के लिये एक पैसा नहीं रखा है। २ करोड़ एल० आई० सी० का था। बाकी ७० लाख खर्च होंगे। सी० डी० ट्यूब वैल्स आदि का है।

श्री रामानंद अग्रवाल : वही टोटल २ करोड़ ५० लाख रुपया।

श्री मथुरादास माथुर : टोटल मिलता है दो करोड़ बन जाता है। २ करोड़ राज्य सरकार खर्च कर रही है। और रुपया रूरल वाटर सप्लाई के लिये मिलेगा तो प्रोब्लम हल होगी।

श्री रामानंद अग्रवाल : जयपुर, अलवर और अजमेर की परमानेन्ट स्कीम बतायी उसके लिये इस वर्ष प्रावधान नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : आज बताया उसमें नहीं है। भारत सरकार से स्कीम एप्रूव हो जावेगी तो एल० आई० सी० से लोन नेगोशियेट करके देंगे। कामर्शियल है उन्हीं को देती है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर) : जयपुर अलवर उदयपुर की स्कीमें उनके पास हैं। राजस्थान का ३।४ हिस्सा है रेगिस्तान उसके लिये कोई स्कीम नहीं। भले ही मरे वो पानी के बिना।

श्री मथुरादास माथुर : जयपुर के लिये सवाल पूछा था।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आप जयपुर के रहने वाले हैं इसलिये इसके लिये जागरूक हैं।

श्री मथुरादास माथुर : बीकानेर के लिये भी जागरूक हैं। राजस्थान के कोने २ के लिये जागरूक हैं। जब तक आपका मत है यहां बैठे हैं।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : उनके लिये आप क्या कर रहे हैं?

श्री मथुरादास माथुर : जवाई से सौ मील से पानी लाकर पिलाया जाता है। सादी का प्रोजेक्ट प्लान में रखा गया है। रनसीसर, बोरूंदा गांवों से कनेक्ट करने के लिये स्कीम बनी हुई है। यह जोधपुर का है। बीकानेर का राजस्थान केनाल से पानी लाकर फिल्टर करने देने का है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आप पानी पिलाने की बात कर रहे हैं। राजस्थान केनाल

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

का बजट साफ हो गया । आप इसको दस साल में भी नहीं कर पायेंगे ।

श्री मथुरादास माथुर : बीकानेर में पहले से ही पानी की समस्या है । कुओं में पानी की समस्या नहीं है ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आप कैसे कहते हैं । दो दो, ढाई ढाई गैलन पानी प्रति व्यक्ति नहीं मिलता है । जनता त्राहि माम त्राहि माम कर बैठी है ।

श्री मथुरादास माथुर : बीकानेर में पर-केपिटा १३।। गैलन पानी मिलता है ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : तीन सौ आदमियों को ४ लाख गैलन पानी देते हैं । सिविल लाइन्स में १४ लाख गैलन पानी देते हैं । १।। लाख आदमी जहां बसते हैं वहां पर ८ लाख गैलन पानी देते हैं जिनसे वह १।। लाख आदमी काम चलाते हैं । गवर्नमेंट आफिशियल्स, राजा महाराजा उनको पानी अलग देते है । शहर वाले पानी के लिये तड़-पते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि पिछले महीने एक एक मंत्री ने नौ नौ सौ रुपये का पानी खर्च किया है । न मालूम मंत्री इतने पानी से क्या करते हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : बीकानेर में २५ लाख गैलन पानी दिया जाता है । राज्य सरकार इसके लिये जागरूक है । प्रोजेक्टस बने हुए हैं । बड़ी बड़ी स्कीम्स बतायीं । उनका टोटल २० करोड़ का आता है । इसको पूरा कर लेना मुश्किल है । स्टेगर करके करना पड़ता है ।

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय .

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री मदनसिंह दांता : Very important.

श्री उपाध्यक्ष : आपने प्रश्न तो पूछ लिये । ६।। बज गये हैं । मेरे खयाल से इस प्रस्ताव को अब ले लिया जांय ।

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सवाल उठा था । न वह शहर का था न जयपुर का था । रूरल एरिया का था जहां नल लगा दिये हैं और केवल मशीन खराब हो जाने के कारण पानी बन्द कर दिया गया । गांव के जानवर प्यास के मारे मर गये । पर सरकार पानी नहीं पहुंचा पाई ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : कोई प्रोब्लम आपका हो तो अर्ज कर दीजिये । मशीनें भिजवा दी जावेंगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी तक क्यों नहीं भिजवाईं ?

श्री नारायणसिंह : मसूदा भिजवाई थीं, मगर जल गईं ।

श्री मदनसिंह दांता : जसरांसर गांव का किस्सा है ।

श्री चुन्नीलाल : जसरासर गांव में कुए पर बिजली लगाई गई। बिजली की मशीन जल जाने से पानी मिलना बन्द हो गया और पानी के अभाव में बहुत से जानवर प्यासे मर गये। आदमियों के लिये भी भारी कठिनाई हो गई है। तो जसरासर और बांच गांव में कितनी गायें मर गईं क्या सरकार के ध्यान में है ?

श्री जसवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : चूंकि काफी समय हो गया है अब डिबेट के लिये क्लोजर मूव किया जावे।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं निवेदन कर दूं। मैंने असल स्थिति तो निवेदन की। समिति द्वारा ही सारी व्यवस्था इसकी होती है। मोटर वहां भेज दी गई थी, पर जल गई। पर अगर वहां विशेष कारणों से मोटर के जल जाने से विशेष स्थिति पैदा हो गई है तो और कोई व्यवस्था तुरन्त की जावेगी जिससे यह चीज हल हो सके।

श्री मथुरादास माथुर : अब तो आयुर्वेद पर आ जाओ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो श्री नाहर ने क्लोजर मूव किया है....

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : यह कैसे ? न प्रस्ताव रखा न कुछ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव रखा है।

श्री सतीशचंद अग्रवाल : क्या प्रस्ताव ? किसी ने कह दिया ठंडा पानी पी लो तो क्या इस पर भी वोट होगा ? इसके बाद तो डिबेट चालू है। मंत्री जी ने जवाब दिया है। वह कोई मोशन है ?

श्री मथुरादास माथुर : क्लोजर मोशन नहीं है।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : चलते चलते किसी ने जिक्र कर दिया तो क्लोजर हो गया क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : मांगों पर मतदान।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी आयुर्वेद विभाग है।

श्री उपाध्यक्ष : वे बैठ गये। वे जवाब नहीं देना चाहते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार को कुछ नहीं कहना है। कोई कस्तूरी का घोटाला हुआ हो चाहे कुछ हुआ हो।

श्री नारायणसिंह मसूदा : आयुर्वेद के विषय में जो कटौती के प्रस्ताव आये हैं और जिन पर यहां बहस हुई खास करके माननीय डाक्टर अम्बालाल जी ने बताया कि यहां एक आदर्श आयुर्वेद महाविद्यालय की कमी है। उसका प्रयत्न किया जा रहा है और उसके अलावा आयुर्वेद की एक फेकल्टी विश्व विद्यालय में खोल दी गई है। और उसके अनुसार आयुर्वेद की परीक्षाएं भी शुरू हुई हैं। आयुर्वेदाचार्य की डिग्री दी जावेगी।

इसके अलावा एक प्रश्न यह भी आया कि उनका वेतन स्तर बढ़ाया जावे। इस विषय में निवेदन कर दूं कि 'ए' श्रेणी के

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

वैद्यों को १७०) से ४८५) के ग्रेड के स्थान पर २८-५)८००) कर दी है।

'बी' श्रेणी के लिये १३०) से ३००) के स्थान पर २२५) से ४८५) कर दी है। 'सी' ग्रेड के लिये १५०) से २४०) था उसकी जगह १५०) से ३८५) कर दिया है। भिषग्वर्ग डिप्लोमा के लिये १२०) से ३८५) कर दिया है। प्रोफेसर, मैनेजर, इत्यादि के लिये भी ग्रेड विचाराधीन हैं।

इसके अलावा यह भी प्रश्न उठा कि औषधियों के वितरण के अन्दर कई प्रकार के दोष हैं। मैं यह नहीं कहता कि दोष नहीं हैं। अब उपलब्ध बजट के अनुसार हम सब जगह देते हैं। कुछ औषधियां रसायनशाला की मांग पर निर्भर हैं जो परचेज कमेटी के द्वारा स्वीकृत नमूनों के अनुसार खरीदी जाती हैं। टेण्डर काल किये जाते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप तो इतना बता दीजिये कि राजस्थान में वैद्यों की कमी तो नहीं है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : जी नहीं।

श्री रामानंद अग्रवाल : फिर डाइरेक्टर साहब को छुट्टी दे दें।

श्री नारायणसिंह मसूदा : कमी है तो डाइरेक्टरों की, I am sorry. डाक्टरों की कमी है।

श्री रामानंद अग्रवाल : इन डाइरेक्टर साहब को छुट्टी दे दें।

श्री नारायणसिंह मसूदा : दे रहे हैं। यदि आप सुनना चाहें तो निवेदन कर दूं कि औषधालय कितने खोलना चाहते हैं। ३० इस साल इस प्रकार के होंगे प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के ऊपर के हैं उनको परिवर्तित करना होगा और २५ नये खोलने की योजना है ये हमेशा ही १४ हजार की जनसंख्या के आधार को लेकर खोले जाते हैं। पर शिड्यूल्ड ट्राइब इत्यादि एरिया में इससे कम का भी आधार लिया जाता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): On a point of order, Sir समय अधिक हो रहा है और लोगों को शादियों में जाना है। कई लोग कुंवारे रह जावेंगे।

श्री नारायणसिंह मसूदा : यदि सदन के माननीय सदस्यों को जल्दी है तो जितने कटौती प्रस्ताव आये हैं उन पर जो उत्तर रह गये हैं वे लिखित रूप से सबके पास पहुंचा सकते हैं, यदि उनके अन्दर कोई खास बात हो।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये ७,११,६४,०००) तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १७—मुख्य शीर्षक ३०—जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ३१

Page No. 172

(श्री उपाध्यक्ष)

मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु० ६,०४,११,०००) तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ९४—जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु० १,३०,५१,०००) तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ६ बजकर ४२ मिनट पर बुधवार दिनांक १४ जून के म०पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

———

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ४४५ का उत्तर देखिये ।)

राजस्थान में माह फरवरी ६५, ६६ व ६७ में सरकार को शराब के विक्रय से निम्न रुपयों की आय हुई ।

१९६५	रुपये	५३,०८,०९९.७५
१९६६	रुपये	६९,१५,४९६.३०
१९६७	रुपये	७०,४४,१०९.२८

———

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न सं० ४६१ का उत्तर देखिये)

विधान सभा प्रश्न सं० १२७।क्र० सें० के प्रश्न नं० २ व ३ की सूची

नाम गांव	नाम दूकान	आबादी वोटर सन् १९६७	नाम व्यापारी	फरवरी ६७ आवंटित गेहूं बोरी	फरवरी ६७ आवंटित ज्वार बोरी	फरवरी ६७ ले गये गेहूं बोरी	फरवरी ६७ ले गये ज्वार बोरी	मार्च ६७ आवंटित गेहूं बोरी	मार्च ६७ आवंटित ज्वार बोरी	मार्च ६७ ले गये गेहूं बोरी	मार्च ६७ ले गये ज्वार बोरी	अप्रेल ६७ आवंटित गेहूं बोरी	अप्रेल ६७ आवंटित ज्वार बोरी	अप्रेल ६७ ले गये गेहूं बोरी	अप्रेल ६७ ले गये ज्वार बोरी	मई ६७ आवंटित गेहूं बोरी	मई ६७ आवंटित ज्वार बोरी	मई ६७ ले गये गेहूं बोरी	मई ६७ ले गये ज्वार बोरी
सेंदड़ा, कदाती, घोलिया, रामसलतुरा, कोटरी रारेगड़,चाना, खेडा सेंदना, कानपुरा, भूठा, साखिया, बावन, सबलपुरा ।	सेंदढ़ा	२६४७ ——— १८००	श्री नथमल रामरतन श्री ग्राम सेवा सहकारी समिति	६०	१५०	५२	१५०	६०	१५०	४८	२१	६०	८०	६०	८०	७०	—	३५	—
बिराटिया खुर्द, जीतपुरा, आसन, तिलीरिया ।	बिराटिया	१८३२ ——— १७०३	श्री पनराज	४०	१२०	२५	२५	१२८	३००	७०	१४८	—	—	—	—	४०	—	—	—
हाजीवास, फुल कोट, नबामाली, बसवासन, विराटिया कला, बांगास, पवासनी कला, बिसावास खुर्द ।	विराटिया कला	१८७० ——— १८६४	श्री बाबूलाल	५५	१७५	३०	.१००	—	—	५०	१००	१००	१६०	१००	१६०	४०	—	—	—

गिरी	गिरी	२५२४ / १६६२	श्री जीवराज	५०	२००	५	१०३	८०	५००	८०	१२५	—	—	—	—	४०	—	—	—
सुमेल	सुमेल	२२४६ / २३३६	श्री नथमल रामरतन	८०	२४०	७०	१३०	८०	२००	११०	१५८	६०	११०	६०	११०	७०	—	—	—
बाबरा	बाबरा	२४६३ / ३३१२	श्री लालचन्द विजय	१००	३००	८०	८०	१५०	२५०	१५०	८०	६०	१२५	६०	१२५	६०	—	६०	—
सिरमा	कोट	१३७२ / १२८५	श्री चम्पालाल सम्पतराम	५०	१००	—	—	५०	१२०	५०	३०	—	—	२०	४०	४०	—	—	—
कलालीया, बगरी, बेलपना	कलालीया	१८३६ / १५०७	श्री लालचन्द बोहरा	५०	१५०	—	—	६०	१३०	—	—	६०	१२५	४०	४०	४०	—	१५	—
देवली खुर्द, चमपुरा, नानना, सांपबसिबट, दांतरि.।, बास, अमरगढ़, रामगढ़ ।	बुटीवास नानना	६६६२ / ४६२१	श्री गजराम अमरचन्द	१२५	४८०	७५	२५	६०	१००	१६०	३०५	१६०	२००	१६०	२००	८०	—	४५	—
देवलीखुर्द, चमपुरा, नानना, सापुरा, बूटीवास मावास ।	बेटीवास नानगा	६६६२ / ४६२१	श्री गजराज अमरचन्द	१२५	४८०	७५	२५	६०	४००	१६०	३०५	१६०	२००	१६०	२००	८०	—	४५	—

रूपा, बसिया, रातरीया, चाँग, अमरगढ़, रामगढ़ ।	चांग	३७७९ / ३४१६	श्री कृष्णलाल / अमरलाल	१२०	३६०	१८०	२२०	१८०	३००	१७३	१३०	१२०	२५०	१२०	२५०	१२०	-	१२०	—
अमरपुरा, लालपुरा, जगमालपुरा ।	अमरपुरा	१५०० / ५१३	श्री ग्राम सेवा सहकारी समिति	१५१	३५	१५	३५	२१	५८	२८	५६	४०	४०	४०	४०	४०	—	३०	—

सूची प्रश्न ४

आबादी

पंचायत सर्किल सेन्दड़ा	आबादी १९५१	वोटर १९६७	पंचायत सर्किल रायपुर	आबादी १९५१	वोटर १९६७
गिरी	२५२४	१९९२	देवली	२४५०	२०६६
बाबरा	२४६३	२३१२	रामपुरा	१९७१	१३१९
पिराटिया कला	१८६९	१८६९	निम्बाकला	१७५४	१४५६
बुटीवास	२४९१	१५५०	मेहराकला	२०१५	१५६१
सुमेल	२२४९	२३८६	बसिया	१३०४	९९०
नानना	२०३८	१५७४	पिपलीया	२२८९	१७४१
रेलड़ा	१६३३	८८७	सबलपुरा	१३०१	११३२
डिगरीया खुर्द	१८३२	१७०३	कुगालपुरा	४६७३	३०२३
कीट किराना	१३७२	१२८५	लिसम्बा	१८४१	१५२०
कलालीया	१८३६	१५०७	बर	२१४१	१७३५
बाग	२१३१	[illegible]	रामपुरा	४८२६	३३७१
अमरपुरा	१५००	५१३	झूठा	२२२९	१४४०
चिनार	२२५३	१८१२	कालूजा	१५७१	९८२
सेन्दडा	२०४२	१५९८	दिपावास	१५५६	१००८
			पचाणपुरा	२४६०	१७९५

Page No. 178

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ४६३ का उत्तर देखिये)

क्र० स०	नाम ग्राम	हानि होने वाला क्षेत्रफल एकड़ों में				
		पूरा	।।।)	।।)	।)	योग
१.	अरन्डखेड़ा	—	१६२	२१०	६१	४३३
२.	चारनहेड़ी	—	१२	१८२	५९	२५३
३.	अडलिया	—	—	—	३	३
४.	पाड़लिया	—	४२	३७	४८	१२७
५.	बनियानी	—	—	१९	—	१९
६	दीपपुड़ा	—	८	२५६	१०७	३७१
७.	पीतलहेड़ा	—	—	६५	२१	८६
८.	शेकरपुर	—	१३	५४	७०	१३७
९.	पीपलाहेड़ी	—	—	१४	—	१४
१०.	छिमनहेड़ी	—	=	७४	५२	१२६
११.	सिमतहेड़ी	—	६०	७	—	६७
१२.	मण्डाना	४६	१८	१५२	२४	२८०
१३.	जोधपुरा	—	—	५७	—	५७
१४.	मुकन्दपुरा	—	—	१०	३	१३
१५.	मान्जलिया	—	—	४५	—	४५
१६.	हीरापुर	—	७४	—	—	७४
१७.	हानोतिया	१८१	१३	५८	११	२६३
१८.	कसार	—	—	—	७	७
१९.	रेनकिया खेड़ी	—	—	१३५	—	१३५
२०.	सारंगपुर	—	—	४८	—	४८
२१.	सानपुरिया	—	—	४	—	४
२२.	ढानी	—	—	—	८६	८६
२३.	आलनियां	—	—	—	१८	१८
		२२७	४०८	१४२७	६१०	२६७२

परिशिष्ट ४

(समयाभाव के कारण समय में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

सवाई चक भूमि का अनुसूचित जन जाति को आवंटन

४६४. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) राजस्थान में कुल सवाई चक भूमि कितनी है ?

(२) इस भूमि में से कितनी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों को दी गई है, जिलेवार बतायें।

उत्तर

(१) राजस्थान में कुल सिवाय चक भूमि ३६,५४७६४-६४ एकड़ है।

(२) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लोगों को दी गई भूमि की जिलेवार सूचना की प्रति संलग्न है।

(सूचि विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखो गई)

होल सैल उपभोक्ता भंडार द्वारा कोटा जिले में शक्कर वितरण

४६५. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि कोटा जिले के शक्कर के वितरण का कार्य होल सेल उपभोक्ता भंडार को दिया हुआ है ? अगर हां, तो कब से ?

(२) जब से उक्त उपभोक्ता भंडार को शक्कर का कार्य दिया गया तब से अभी तक कोटा जिले के लिये कब कब कितनी कितनी शक्कर की वेगन एलाट हुई ? कृपया तालिका देने का कष्ट करें।

(३) उपरोक्त एलोटेड वेगन में से कब कब कितनी कितनी वेगन शक्कर की प्राप्त की ?

(४) क्या यह सही है कि कई बार एलाटेड कोटा की शक्कर लेप्स हुई है ? अगर हां, तो किस किस माह की कितनी कितनी व क्यों ?

(५) क्या यह सही है कि माल गोदाम के देर से बिल्टी छुड़ाने के कारण कई बार डेमरेज देना पड़ा ? अगर हां, तो कब कब, कितना कितना व कुल कितना देना पड़ा ?

(६) क्या यह सही है कि डेमरेज से बढ़ी हुई शक्कर की कीमत को उपभोक्ताओं से वसूल किया गया ? अगर हां, तो कितना कितना।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(७) क्या यह सही है कि शक्कर के सम्बन्ध में कोई चेरिटी फंड बना हुआ है ? अगर हां, तो यह किस प्रकार प्रति बोरी लिया जाता है ?

(८) उपभोक्ता भंडार से अभी तक कुल कितना चेरिटी फंड देय है व कितना कितना कब कब प्राप्त हो चुका है ?

(९) क्या यह सही है कि चेरिटी के लिए प्राप्त की हुई राशि का भार भी उपभोक्ता पर डाला जाता है ?'

उत्तर

(१) जी नहीं, होल सेल उपभोक्ता भंडार जून, जुलाई, सन १९६४ से नवम्बर, ६६ तक केवल कोटा सब-डिवीजन के शक्कर वितरण का कार्य करता था। अब नवम्बर, दिसम्बर १९६६ से यह भंडार केवल कोटा सिटी को शक्कर वितरण के होल सेल का कार्य कर रहा है, समस्त जिले का नहीं।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) इस भण्डार ने एलोटेड वेगन्स में से २८८ बी० जी० वेगन्स तथा ९७ एम० जी० वेगन्स शक्कर प्राप्त की है।

(४) इस भण्डार को विभिन्न समय पर आवंटित शक्कर में से केवल एक बार माह दिसम्बर, ६६ जनवरी, ६७ के कोटे में से केवल १३ वेगेन्स शक्कर लेप्स हुई, जिसका कारण भंडार द्वारा समय पर अग्रिम धनराशि नहीं भेजा जाना था।

(५) जी हां, इस भण्डार को गोदाम से माल छुड़ाने में देरी होने के कारण विभिन्न समय पर कुल १२१८५-८० डेमरेज के पड़े हैं। तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(६) जी नहीं।

(७) चूंकि चीनी लाईसैंस्ड कमोडिटी है, लाईसेन्सड कमेडिटीज चेरेटी फण्ड १९६१ के अनुसार अलग अलग ग्रेड क्वालिटी को शक्कर का एक सा थोक व खेरूंज भाव कायम करते समय पैसे के हिस्सों को राउन्ड ग्रोफ करने के लिये जो रकम बेशी वसूल होती है वह लाईसेन्सड कमोडिटीज चैरीटी फण्ड में जमा करवाई जाती है। चैरीटी फण्ड के नाम से कोई कीमत वसूल नहीं की जाती अत: प्रति बोरी के हिसाब से चैरिटी फण्ड लिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

(७) सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार से चैरीटी फ़ण्ड को कोई रकम लेना बाकी नहीं है। इस फण्ड में होलसेल भण्डार से अब तक २,६३,६१४-१३ रुपये जमा हो चुके हैं।

(९) जी हां।

(सूची वितृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील दूदू में कृषि सहकारी समितियों को भूमि आवंटन

४६६. श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) तहसील दूदू में किस किस ग्राम में कृषि सहकारी समितियां हैं और किसको कितनी जमीन अलाट की गई है ?

(२) क्या यह जमीन सहकारिता के आधार पर काश्त होती है ?

(३) लगान किस किस सहकारी समिति ने जमा करा दिया है ? अगर नहीं तो किसमें कितना बाकी है ?

उत्तर

१—तहसील दूदू में ग्राम पालूकला, सेवा, इटाखोई, अखेपुरा, पावनाफला, पडासोली तथा उरसेवा में कुल सात कृषि सहकारी समितियां हैं। भूमि अलाट की जाने संबंधी सूचना सदन की मेज पर रखी है।

२—सूची सदन की मेज पर रखी है।

३— सूचना सदन की मेज पर रखी है।

प्रश्न १८३ रा० मं० श्री सुवालाल चौधरी से सम्बन्धित सूचना

तहसील

नाम कृषि सहकारी समिति १	आवंटित रकबा २	वर्तमान स्थिति ३	लगान बकाया ४	वसूली न होने के कारण ५
१-पालूकलां	३६५।।।) बीघा	रजिस्ट्रार सहकारी समिति अजमेर खण्ड मुख्यालय के आदेश दिनांक ५-७-६५ द्वारा अवसायन (Liquidation) में लाई जाने के कारण आवंटित भूमि के पुनर्ग्रहण के आदेश १८-५-६७ को प्रसारित कर दिये।	२०४६.५६ पै०	दो वर्ष से अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित होने के कारण वसूली बन्द है।
२-ईटाखोई	३१५।।) बीघा	सहकारिता के आधार पर कार्य कर रही है।	५१३.०७ पै०	दो वर्षों से अकाल पीड़ित घोषित होने के कारण वसूली बन्द है।

१	२	३	४	५
३-अलेपुरा	३८२।।) ३ बीघा	,,	१४१४.१६ पै०	,,
४-पानवा कलां	१६०।।) २ बीघा	कार्य रूप में न आने अथवा भंग होने के कारण अलाटमेंट की गई भूमि को अन्य भूमिहीन लोगों को अलाट कर दिया गया है।	५२.२० पै०	,,
५-सेवा	२११।।।) बीघा	कार्य रूप में न जाने अथवा भंग होने के कारण अलाटमेंट की गई भूमि को अन्य भूमिहीन लोगों को अलाट कर दिया गया है।	—	,,
६-पड़ासोली	३०३) ४ बीघा	,,	—	,,
७-उरसेवा	२३५) १ बीघा	,,	—	,,

बूंदी सहकारी शक्कर फैक्ट्री

४६७. श्री केशरीसिंह-(हिन्डोली) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या जिला बूंदी में सहकारी शक्कर फैक्ट्री की योजना है ?

(२) इस फैक्ट्री के अब तक कितने शेयर्स बिक चुके हैं, और उनकी कितनी धन राशि सहकारी समिति के पास कब से जमा ?

(३) बूंदी रोड स्टेशन के पास वाली जमीन की कीमत समिति ने कितनी और किस किस को दे दी है और कितनी देनी बाकी है ?

(४) इस फैक्ट्री का काम अब तक शुरू नहीं होने का क्या कारण है ?

(५) सरकार की ओर से इस फैक्ट्री को कितना कर्ज कब दिया गया ?

उत्तर

(१) जी हां

(श्री सहकारी मंत्री)

(२) अब तक ४२०० शेयर्स सदस्यों तथा सहकारी समितियों को बेचे जा चुके है जिसकी धनराशि दस लाख पचास हजार रुपये प्राप्त हो चुके है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को दस हजार शेयर्स पच्चीस लाख रुपये के बेचे जा चुके हैं। ये शेयर्स १० नवम्बर, १९६५ से बेचना प्रारम्भ किया था जो अब तक बेचे गये हैं।

(३) मिल के लिए जमीन मण्डी कमेटी कोटा से रु. २,०८,६१४.८० पैसे में ली गई है जिसका भुगतान मण्डी कमेटी को करना बाकी है।

(४) मिल का कार्य मशीन का ऑर्डर हो जाने पर आरम्भ होगा। मशीन के कोटेशन मंगा लिए गये हैं तथा ये कोटेशन नेशनल फेडरेशन आफ कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लि०, नई दिल्ली के पास उनकी छंटनी के लिए भेजे गए हैं। जब फेडरेशन की सलाहकार समिति यह तय कर देगी कि मशीन किससे खरीदनी होगी तब उस मैन्यूफैक्चरर से मशीन खरीदने का आर्डर दिया जायेगा। जैसे ही मशीन का आर्डर दे दिया जायेगा तो मिल का निर्माण कार्य चालू कर दिया जायेगा। मशीन के फाइनल होने के पहले कोई कार्य चालू नहीं किया जा सकता क्योंकि मशीन के ले आउट के अनुसार ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(५) इस फैक्ट्री को सरकार की ओर से कोई कर्ज नहीं दिया गया है।

कोटा जिले में अकाल स्थिति

४६८. **श्री देवीदत्त गाड़िया-(बारां)** क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कोटा जिले में किस किस तहसील के किस किस गांव में अकाल पड़ा है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या सरकार ने जिन गांवों में अकाल पड़ा है उनमें अकाल राहत कार्य प्रारम्भ कर दिये हैं ? यदि हां, तो अब तक अकाल राहत कार्य क्या क्या शुरू किये गये हैं ?

(३) कोटा जिलाधीश ने जिन गांवों में अकाल पड़ा है उनके सम्बन्ध में जो रिपोर्ट सरकार को भेजी हैं उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

१—सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

२—सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

३—उक्त प्रति बहुत बड़ी है व उसमें कई स्टेटमेंट हैं, अतः उसकी प्रतियां नहीं कराई जा सकती हैं। माननीय सदस्य यदि चाहें तो मन्त्री के कक्ष में देख सकते हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति लाडनूं द्वारा निर्माण एवं विकास कार्यों पर व्यय

४६९. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)** क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति लाडनूं, जिला नागौर द्वारा दिनांक १-१-६५ से ३१-३-६७ तक जो धनराशि निर्माण कार्यों के लिए तथा अन्य विकास कार्यों के लिए पंचायतों को दी गई है वे समय पर उक्त कार्यों पर खर्च नहीं की गई और न राशि नियमानुसार बैंक में जमा हो रही है ? यदि हां, तो उक्त राशि कहां कहां पर किन किन व्यक्तियों के पास रही और उनके खिलाफ अनियमित तौर पर रकम रखने के अपराध में क्या कार्यवाही की गयी ?

(२) उपरोक्त धनराशि में से बैंक को छोड़कर किन किन व्यक्तियों के पास कितनी कितनी राशि कितने समय तक रही है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

एम्युनिशन फैक्ट्री भरतपुर हेतु अप्राप्त भूमि का मुआवजा

४७०. श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) भरतपुर में एम्यूनिशन फैक्ट्री बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने जो भूमि ली थी, क्या उस भूमि के मुआवजे की धनराशि राजस्थान सरकार को केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हो गई है ?

(२) यदि हां, तो राज्य सरकार ने ये धनराशि उस भूमि के काश्तकारों को अभी तक मुआवजे के रूप में वितरित क्यों नहीं की है ?

उत्तर

(१) जी हां, धन राशि प्राप्त हो गई है।

(२) प्राप्त धनराशि का वितरण हो चुका है, वितरण के लिये कोई धनराशि शेष नहीं है।

घाटोल पंचायत समिति क्षेत्र में कुओं का निर्माण

४७१. श्री विट्ठल (पीपलखूंट) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति क्षेत्र घाटोल (जिला बांसवाडा) में सन् १९६२ से अब तक पीने के पानी के कुओं के निर्माण के लिये किस किस गांव में कितनी कितनी धनराशि खर्च की गयी है ?

(२) कितने कुओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और कितने कुओं का कार्य अभी अपूर्ण पड़ा है ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(श्री विकास मंत्री)

. . . .

(२) ३० कुओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा १८ कुओं का निर्माण कार्य चालू है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

वाणिज्य कर की बकाया

४७२. **श्रीमती कान्ता कथूरिया** (कोलायत) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) सरकार का वाणिज्य कर पेटे कितना रुपया ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले साल में करदाताओं से बाकी लेना निकलता था?

(ख) इस कर वसूली के लिये सरकार क्या उचित उपाय कर रही है?

(ग) इस कर वसूली में अब तक कितना रुपया वसूल किया जा चुका है?

उत्तर

(१) ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले साल के प्रारम्भ में राज्य सरकार का बिक्री कर तथा यात्री एवं माल कर में विभिन्न कर दाताओं से लगभग रु० १७५.१७ लाख बाकी लेना निकलता था।

(२) इस राशि की वसूली के लिये राज्य सरकार द्वारा जो कार्यवाही की जाती है वह मुख्यतया यह है—

(क) विभागीय अधिकारियों द्वारा वसूली के प्रयास।

(ख) साधारण कोशिश से वसूली न होने पर सम्बन्धित कर अधिनियमों के अन्तर्गत प्रदान किये गये अधिकारों द्वारा कर दाता की चल सम्पत्ति कुर्क किये जाने की आज्ञा जारी करना।

(ग) आवश्यक होने पर भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वसूली के लिए जिला अधिकारियों को लिखना।

(३) उपरोक्त रु० १७५.१७ लाख की राशि में से दिनांक ३१-३-६७ तक रु० ६३.५४ लाख की राशि या तो वसूल की जा चुकी थी या अपील आदि के कारण कम कर दी गई थी।

राजाखेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में ट्यूब वैल्स

४७३. श्री **प्रद्युम्नसिंह** (राजाखेड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजाखेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में कुल कितने ट्यूब वेल्स खोदे गये तथा उनमें से कितने सफल हुए?

(२) क्या यह सही है कि सफल होने वाले ट्यूब वैल्स भी पिछले सात वर्षों से चालू नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(३) क्या सरकार का इरादा राजाखेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में और नये ट्यूब वैल्स खोदने का है?

Page No. 186

उत्तर

(१) ५ ट्यूब वेल्स खोदे गये जिनमें से ३ सफल हुए।

(२) ये ट्यूब वेल्स एक सहकारी समिति के लिये खोदे गये थे लेकिन उन्होंने इनको काम में नहीं लिया। १९६५-६६ में इन ट्यूब वेल्स को चालू करने के लिये राज्य सरकार ने प्रावधान किया। पम्प आदि सामान खरीदा जा चुका है और जल्दी ही इनको चालू कर दिया जावेगा।

(३) हाल में नये ट्यूब वेल्स खोदने का कोई प्रावधान नहीं है।

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक १३ जून १९६७)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
५	१३	श्री लच्मण सिह	श्री लक्ष्मण सिंह
१०	अन्तिम	सवाल	सवाल है।
१६	,, १४	मूसलमान	मुसलमान
२९	२	तूरिया	कथूरिया
३४	२	प्राईभरी	प्राईमरी
५८	अन्तिम से ४	माडको	माइलो
६०	१	ओलाश्रभ	ओला
९९ से १००	शीर्षक	व १७	व १७ व ३८
९०	१५	शिषक	शीर्षक
९१	शीर्षक	संवया	संख्या
९१	अन्तिम से ८	येथ	पेय
९५	,, ७	खोतने	खोलने
१०५	,, ६	ओदने	खोदने
१२२	,, ६	अ ाएवं	अतएव
१४८	१५	ल्लड	ब्लड
१४४	६	केसइ लिये	इसके लिए
१४४	१४	ढाक्टर	डाक्टर
१४९	१२	विचेप	विशेष
१५१	९	मशा	मंशा

१	२	३	४
१५२	८	भरपुर	भरतपुर
१५२	२१	भ्रिछली	पिछली
१५५	५	बीचारणीय	विचारणीय
१५७	१७	जाता है	जाती है।
१५७	२२	तासरा	तीसरी
१[illegible]६	५	चीजें	चीजें
१ [illegible]२	४	प्राय	प्राये
१६५	३	भ	भी
१६७ अन्तिम से	१०	दिलवार्ये	दिलवायें
१७०	१६	हृटं	हार्ट
१७१	१६	क्योकि	क्योंकि
१७१	६	उनकी	उनकी
१७३	३	बच	बीच
१७४ अन्तिम से	२	चहता	चाहता
१८१	१	व्यक्त	व्यक्ति
१८१ अन्तिम से	६	औषधयों	औषधलयों
१८२	,, १४	व्यवस्था	व्यवस्था
१८४	५	निग्लकट	निग्लेक्ट
१८५	अन्तिम से ३	कहकमों	महकमों ने
१८६	१५	शहरों	शहरों
१६०	अन्तिम	चाहता हूँ कि इस बारे में कानून बनाये कि	×
१६१	७	स्टोरीलाइजेक्शन	स्टेरीलाइजेशन
१६४	अन्तिम से ३	एडिमिशन	एडमिशन
१६६	अन्तिम से १२	veg	beg
२१३	,, २	ठाउन	टाउन
२१५	११	प्रस्ताव को	प्रस्ताव को
२२०	१७	सुनने	×

१	२	३	४
२३०	१४	महिला	महीना
२३१	४	ग्रवस्या	ग्रव्यवस्था
२३२	८	पंजामृता	पंचामृत
२३२	६	ि काग	विभाग
२३२	ग्रन्तिम से ७	उसमें	उनमें
२३३	२	हुबत	बहुत
२३७	१३	टूरिट्स	टूरिस्ट्स
२३८	१०	गराया था	कराया था
२५०	ग्रन्तिम से २	शरीरयां	शरीरम्
,,	,,	धर्मार्थराय	धर्मार्थकाम
२५३	शीर्षक	संक्या	संख्या
२५४	,,	१५	१७
२५६	१	डाम्बर	डाक्टर
२५८	२	दो हैं।	दी हैं।
२६०	३	खूम	खूब
,	११	पदि	यदि
२६३	ग्रन्तिम से ६	पचाल	मचान
२६६	३	उपाध्याक्ष	उपाध्यक्ष
२८३	ग्रन्तिम	डिग्एडमेंग्रान्टेज	डिसएडवान्टेज
३१२	१२	साव	राव
३२५	१४	श्री नारायर्णसिह	श्री नारायणसिंह
३३६	६	माथुर	माथुर